राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06]   पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का चौथा दिवस   [संख्या: 04

शनिवार,

13 फरवरी 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री ज्ञानचंद पारख।

औद्योगिक इकाई को प्रदूषित जल उपचार हेतु देय अनुदान

57. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा एकल प्रदूषित जल उपचार संयंत्र हेतु औद्योगिक इकाई को कितना अनुदान दिये जाने का प्रावधान है?

(2) वर्तमान में सरकार के पास अनुदान हेतु किस-किस औद्योगिक इकाई के प्रकरण कितने-कितने समय से किस-किस स्तर पर किन-किन कारणों से लंबित हैं तथा उक्त लंबित प्रकरणों का निस्तारण कितनी-कितनी अवधि में किया जाकर अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा?

(3) क्या सरकार उक्त संयंत्रों हेतु अनुदान की राशि का राज्यांश प्रतिशत बढ़ाने एवं अधिकतम अनुदान राशि की सीमा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत एवं कितनी राशि तक व नहीं, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा प्रदूषित जल उपचार हेतु ईटीपी स्थापित करने पर राजस्थान एमएसएमई सहायता योजना, 2015 के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त योजनान्तर्गत पात्र लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा ईटीपी की स्थापना करने पर पूंजीगत लागत की 50 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(उद्योग मंत्री)

(2) वर्तमान में लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा ईटीपी की स्थापना पर देय वित्तीय सहायता हेतु राजस्थान एमएसएमई सहायता योजना, 2015 प्रभावी है। उक्त योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले के 14 प्रकरण, चित्तौड़गढ़ जिले के 3 तथा जालोर जिले के 2 प्रकरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों में कमी पूर्ति बाबत इकाइयों को वापस लौटा दिये गये। अन्य 5 प्रकरण बाड़मेर के तथा पाली के 2 प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं। इन 7 प्रकरणों में से बाड़मेर जिले के 5 प्रकरण तथा पाली जिले के 2 प्रकरण संबंधित इकाइयों के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों में कमी पूर्ति पश्चात् फरवरी माह में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय समिति की बैठक में निर्णय हेतु रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन हैं। इन प्रकरणों में राज्य स्तरीय समिति के निर्णयों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(3) राजस्थान एमएसएमई सहायता योजना, 2015 की संचालन अवधि 31, मार्च 2021 तक है। उक्त योजना में इन संयंत्रों हेतु अनुदान की राशि का राज्यांश प्रतिशत बढ़ाने एवं अधिकतम अनुदान की राशि की सीमा बढ़ाने संबंधी संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 दिनांक 17.12.2019 को प्रभावी की गई थी तथा इसकी प्रभावी अवधि 31.03.2026 तक है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत टैक्सटाइल व वस्त्र निर्माण उद्योगों द्वारा निर्मित किये जाने वाले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बेस्ड ई.टी.पी. पर देय अनुदान की सीमा पूर्व में प्लाण्ट की लागत का 20 प्रतिशत, अधिकतम एक करोड़ रुपये थी।

वित्त विभाग द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 में आदेश दिनांक 23.09.2020 द्वारा संशोधन करते हुए टैक्सटाइल व वस्त्र निर्माण उद्योगों द्वारा निर्मित किये जाने वाले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बेस्ड ई.टी.पी. पर देय अनुदान की सीमा अधिकतम एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरा प्रश्न देखें। मैंने सरकार से क्या पूछा है और सरकार का उत्तर भी आप देखें कि सरकार ने उत्तर क्या दिया है। आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि पैरा एक में भी सरकार ने कहा 25 लाख की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। पैरा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

3 में सरकार खुद कह रही है कि एक करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। पैरा 2 में किस-किस औद्योगिक इकाई का प्रकरण कितने-कितने समय से, किस-किस स्तर पर, किन-किन कारणों से लम्बित है, बहुत ज्यादा प्रकरण नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र सात प्रकरण हैं, सूची देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने समय से हैं, किन कारणों से हैं? तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, यह अपूर्ण उत्तर है। आप इस पर कम से कम एक बार आधे घंटे की चर्चा करवा दें तो ठीक रहेगा क्योंकि उत्तर बिलकुल ही गोलमाल दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बैठें। आधे घंटे की चर्चा में, ये जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, इसमें पूछा है कि अनुदान हेतु किस-किस औद्योगिक इकाई, किस-किस का, पर्टिकुलर औद्योगिक इकाई के नाम पूछे हैं। उत्तर में यह नहीं लिखा। उत्तर में लिख दिया कि बाड़मेर में इतने, चित्तौड़ में इतने, इसमें इतने, उनका जो उद्देश्य था, वह था कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछकर...

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत देंगे तो माननीय सदस्य को संतुष्ट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: न-न। माननीय मंत्री जी, उत्तर तो सरकार के रिकार्ड में आता है। यदि उत्तर ठीक नहीं है तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की बनती है। जो उत्तर दिया गया है, वह प्रश्न के संदर्भ का उत्तर नहीं है, इसलिए मैं इसको आधे घंटे की चर्चा के लिए स्थगित करता हूं।

अगला प्रश्न, स्थगित। माननीय सदस्य ने चिकित्सा विभाग में पूछा, डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का है। इसलिए अगला प्रश्न भी स्थगित है।

ढीपरी चम्बल (इटावा) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवन का निर्माण

58. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढीपरी चम्बल (इटावा) जिला कोटा के घटिया भवन निर्माण बाबत संवेदक एवं निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले विभागीय अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीना)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 186.70 लाख राशि की आवश्यकता मानी जाकर प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो उक्त तकमीने के आधार पर कब तक स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को पत्र क्रमांक 2020/100-106 दि. 23-10-2020 भिजवाकर उक्त भवन को नाकारा घोषित करने हेतु लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त भवन को नाकारा घोषित करने हेतु लिखा गया है?

यदि हां, तो उक्त भवन के लिए स्वीकृति कब तब जारी कर दी जाएगी?

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत। आप संख्या तो बोलो, आप श्रीमान, माइक पर आ जाओ, आगे आ जाओ, देवनानी जी के पास आ जाओ।

अजमेर में पटवारी एवं गिरदावरों के रिक्त पद

59. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में पटवारियों एवं गिरदावरों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पटवारी पटवार मुख्यालय पर नहीं बैठकर तहसील मुख्यालय से ही कार्य कर रहे हैं जिससे काश्तकारों एवं आम जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए तहसील मुख्यालय आकर कार्य करवाना पड़ता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार जनहित में पटवारियों के रिक्त पदों को भरते हुए पटवारियों को पटवार मुख्यालय पर ही उपस्थिति देकर कार्य करने के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) अजमेर जिले में पटवारी एवं गिरदावर के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, राजस्व)

पटवारी		गिरदावर	
स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
600	305	198	0

(2) अजमेर जिले में पटवारी अपने सर्कल के पटवार भवन/अटल सेवा केन्द्र पर बैठकर कार्य कर रहे हैं। पटवार सर्कल पर नहीं बैठने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पटवारी के 4421 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 17.01.2020 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्राथमिकता से पदों को भरा जाएगा।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.06.2017 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 12(1) में संशोधन कर प्रावधान किया गया है कि हर एक पटवारी अपने क्षेत्र के उस गांव में निवास रखेगा जो कि कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय मुकर्रर किया गया हो तथा पटवारियों को पटवार मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किये जाने के संबंध में राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक 2(34)राज-1/2017 दिनांक 25.11.2019 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान को निर्देशित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: मदन दिलावर जी और प्रताप सिंह जी को अलग-अलग बिठाना पड़ेगा मुझे। माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 600 पदों में से 305 रिक्त, मतलब 50 परसेंट से भी कम पद स्वीकृत हैं। आप मुख्यालय पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पटवारी को एक-एक को तीन-तीन जगह का चार्ज दिया हुआ है और चार-चार जगह का चार्ज दिया हुआ है, अब वह एक पर कैसे बैठेगा? चाहते हुए भी नहीं बैठ पाएगा, इसलिए आपकी रिपोर्ट, जवाब गलत है।

दूसरा निवेदन यह है कि उनको एक-एक पटवार हलका दे दिया जाए तो वह ठीक रहेगा। पटवारियों की भर्ती आप करें, कब तक करेंगे और दूसरा जब तक तीन-तीन, चार-चार जगह का दे रखा है, उनको कोई मानदेय या ऐसा कोई दे दिया जाए ताकि यह रोजाना की हड़ताल भी बंद हो जाए। हमारे कामकाज सारे प्रभावित हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): नम्बर दूसरा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आप तो सजेशन बता रहे हो। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह अपने आपमें ही एक तरह से सरकार ने 2017 में भी आदेश निकाल रखा है, 2019 में भी आदेश निकाल रखा है, कलेक्टर को डायरेक्शन दे रखे हैं कि आपको पटवार केन्द्र जो है, वहां बैठना है और आप स्वयं उत्तर दे रहे हो और विधायक ने जब सवाल पूछ लिया तो आप इतना ही बता देते कि इतने तो पटवार सर्कल पर बैठते हैं और इतने पटवार सर्कल पर उपलब्ध नहीं होने के कारण से उसके पास के किसी एरिये पर बैठते हैं। आपने तो प्रश्न का उत्तर एकदम नकारात्मक दे दिया कि अजमेर जिले में पटवारी अपने सर्कल में, पटवार भवन केन्द्र में बैठकर कार्य कर रहे हैं। पटवार सर्कल पर नहीं बैठने के संबंध में कोई शिकायत, अब प्रश्न पूछ लिया, आपके सरकारी आर्डर हैं तीन-तीन और अब आपको और क्या चाहिए था जो पूछे और कौन शिकायत करे, जब कलेक्टर को स्वयं को निर्देश दे रखा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इसमें कोई उत्तर नहीं। सीधा है कि जब पटवारी की संख्या कम है, एक पटवारी को एक से ज्यादा सर्कल दे रखे हैं तो वहां पर किस सर्कल पर रहेगा, उसके लिए तो कलेक्टर को बाध्य भी कर दें और उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसका हैडक्वार्टर यहां है और बाकी जगह जहां चार्ज है, वहां इस समय मिलेगा। इस तरह के आदेश आप कलेक्टर के थ्रू हर जिले में भिजवाने का काम करें।

बाकी खाली है, यह तो प्रश्न है, सबको मालूम है खाली है, विज्ञप्ति कर रहे हो। लेकिन जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक पटवार सर्कल को, एक पटवारी को तीन सर्कल दे रखे हैं तो रहेगा तो एक ही जगह पर, आपके सर्कल के हिसाब से, दो जगह तो रह नहीं सकता वह, तो किस जगह पर रहेगा, वह पटवार सर्कल मैंशन हो जाए और उसके अंदर में जो दूसरे सर्कल हैं, किस समय मिलेगा, उसकी सूचना सबको मिल जाए। अगला प्रश्न।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट

(श्री शंकर सिंह रावत)

और रह गया, प्लीज। मेरा निवेदन है कि दो गांवों का सीमा विवाद जो काफी समय से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं। न, इससे रिलेवेंट नहीं है, प्रश्न पूछ ये रहे हो, इस पर आ जाते हो।

प्रश्न संख्या 60

अगला प्रश्न, श्री धर्मनारायण जोशी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा भूमि का आबंटन

61. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या किसी विश्वविद्यालय परिसर की भूमि किसी धार्मिक संस्थान को अपने धर्म के प्रचार व सभागार निर्माण हेतु आबंटित की जा सकती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(2) क्या यह सही है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने वर्ष 2015 में श्री दिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान को भूमि प्रदान की है? यदि हां, तो कितनी व इसका विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों से क्या संबंध है?

(3) क्या श्री दिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान व वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के बीच कोई लिखित समझौता हुआ है? यदि हां, तो उक्त समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कुल सचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने अपने पत्र क्रमांक एफ-2/वमखुवि/2020 के बिन्दु संख्या-1 में स्पष्ट लिखा है कि श्री दिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान से विश्वविद्यालय का कोई संबंध नही है? यदि हां, तो जब कोई संबंध नहीं है तो भूमि क्यों आबंटित की गई? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी नहीं।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015 में श्री दिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान को जमीन प्रदान नहीं की गई है, वरन विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के चैप्टर-II नियम 4 (xii) (संलग्नक-1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को चल-अचल सम्पत्ति बाबत दान, भेंट, अनुदान एवं सहायता प्राप्त करने के अधिकारों के तहत श्री दिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान को विश्वविद्यालय परिसर में सभागार निर्माण की सहमति व्यक्त की गई। निर्माण कार्य के पश्चात् उक्त भूमि एवं उस पर निर्मित भवन पर विश्वविद्यालय का ही स्वामित्व रहेगा। उक्त भवन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सेमिनार, व्याख्यानमालाओं के आयोजन एवं दीक्षांत समारोह आदि के उपयोग में आ सकेगा।

(3) जी नहीं। श्री दिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सभागार का निर्माण करवाये जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव की संवीक्षा एवं परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अभिशंसा (संलग्नक-2) को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 91वीं बैठक दिनांक 14.03.2015 में रखा गया था। प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव 91/6 में आंशिक संशोधन कर अनुमोदित किया गया (संलग्नक-3) जिस पर श्री दिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान द्वारा सहमति व्यक्त की गई (संलग्नक-4) अलग से कोई समझौता नहीं किया गया है।

(4) जी हां। श्री दिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान, कोटा को भूमि आबंटित नहीं की गई है, वरन विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के चैप्टर-II नियम 4 (xii) (संलग्नक-1) के अन्तर्गत दान स्वरूप सभागार आदि के निर्माण करवाये जाने हेतु दिये गये प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। उक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्नक-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला प्रश्न मैं एक बार पढूंगा ताकि सदन के सब सदस्य उसको जान लें। क्या किसी विश्वविद्यालय परिसर की भूमि किसी धार्मिक संस्थान को अपने धर्म के प्रचार व सभागार निर्माण हेतु आबंटित की जा सकती है? इसका उत्तर स्पष्ट है- जी नहीं। मैंने एक और प्रश्न इसी में आखिरी में पूछा था कि क्या

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

जो संस्था को जमीन दी गई है उसका विश्वविद्यालय से कोई संबंध है? उसका भी उत्तर है- जी नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी, जो कारण बताये हैं उसमें उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय दान ले सकता है, यह प्रकरण दान देने का है इसलिए मेरा प्रश्न इनसे है कि विश्वविद्यालय के पास कुल भूमि कितनी है तथा क्या अनुदान एवं सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अपनी ही भूमि पर सभागार निर्माण को दान मानती है? क्या विश्वविद्यालय को इस प्रकार की स्वीकृति देने का अधिकार है? क्या सभागार का कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो इसकी राशि किसने खर्च की? इसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान, कोटा के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था विश्वविद्यालय में एक भवन बनाये जाने के लिए, तो उसमें स्वामित्व पूरी तरह से विश्वविद्यालय का रहेगा। मैंने अभी जिस प्रकार से माननीय सदस्य महोदय को निवेदन किया है और इस भवन के निर्माण के बाद में स्वामित्व के साथ-साथ पूरी तरह से किसी भी आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और यदि एक ही दिन में दो कार्यक्रम होते हैं और इसमें दिगंबर जैन भगवान महावीर संस्थान का भी कार्यक्रम होता है तो पहले उसमें विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को प्राथमिकता रहेगी। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कोई भी विश्वविद्यालय के रिसोर्सेज को डवलप करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि आपकी जो भावना है वह भावना यह है कि किसी धर्म को करने के लिए किया है, यह नहीं किया है, वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाकर उसको हैंडओवर किया है, तो वहां पर बच्चों के लिए काम आयेगा इसलिए इसमें कोई मोटा इश्यू नहीं है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, इसीलिए तो मैंने प्रश्न लगाया है। इतना तो मूर्ख मैं नहीं हूं कि इस प्रकार से सदन का समय बेकार करूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको मूर्ख नहीं कह रहा हूं। आप अपने आपको मूर्ख क्यों ले रहे हैं? आप बैठिए आराम से। मैं भी खुद विश्वविद्यालय से संबंधित रहा हूं। विश्वविद्यालय एक्ट को मैंने बहुत ढंग से

(श्री अध्यक्ष)

पढ़ा है। विश्वविद्यालय एक्ट में इस तरह के प्रोविजन हैं जिस प्रोविजन के अंतर्गत हम किसी संस्था से लेकर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में संस्कृत का बहुत बड़ा कैंपस बना रखा है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर कोई कैंपस नहीं बना रखा है इसलिए मैं समझता हूं कि आपकी जो भावना है उस भावना को...

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): मेरी भावना आपने नहीं समझी अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न करने का, यह जो इन्होंने परिपत्र लगाया है, यह धार्मिक संस्था को किस उद्देश्य से दिया गया है, इन्होंने जो उत्तर दिया है उसमें है, 'विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार जैन परंपरा प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा एवं साहित्य, जैन धर्म दर्शन, जैन जीवन दर्शन के बारे में दो व्याख्यानमाला एक या दो दिवसीय आयोजित करेगा...' यह धार्मिक काम है और यह पैसा, माननीय अध्यक्ष जी, संस्था ने नहीं लगाया है। एक विधायक कोष और एमपी कोष से पैसा विश्वविद्यालय को दिया गया है। विश्वविद्यालय ने वह निर्माण नहीं किया है। अपनी भूमि पर एक संस्था धार्मिक संस्था को पैसा दे दिया गया एमएलए लैड का और एमपी लैड का, उसका भी दुरुपयोग किया गया है। खुद की भूमि पर जो पैसा इसको दिया गया है यूनिवर्सिटी ने अपने आप नहीं बनाया है, एक संस्था को दे दिया है, वह अपने धर्म का प्रचार करेंगे। आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं क्या ऐसा हो सकता है?

श्री अध्यक्ष: Please, I am extremely sorry for this. कैंपस में इतने इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई दूसरे नाम पर वहां कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा कोई कैंपस नहीं है जहां कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आपकी भावना ठीक है, विश्वविद्यालय यह एश्योर कर ले जो आपकी भावना है, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करने के लिए इसको किया जाना चाहिए लेकिन जिस परपज के लिए विश्वविद्यालय को दे दिया है, उसके बाद टाइटल विश्वविद्यालय के पास रहना चाहिए और इस व्यवस्था को करने के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करने के लिए सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा। आपकी भावना ठीक है धर्म के लिए नहीं किया गया है। दूसरा संप्रदाय आकर दूसरा बना दे, कोई मना नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि एक्ट के अंदर प्रोविजन है। अगला प्रश्न।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I'll not allow it. I'll not allow it.

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): This is really very unfortunate.

कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त पदों पर भर्तियां

62. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना से आज तक कितनी बार भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये गये तथा उक्त भर्ती प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) उक्त भर्ती प्रक्रियाओं में कितने लोगों ने आवेदन किया?

(3) उक्त भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदकों से आवेदन और परीक्षा शुल्क के नाम पर कितनी राशि एकत्र हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदकों को उक्त शुल्क नहीं लौटाया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में कोरोना काल में परिक्षाएं आयोजित नहीं होने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लिया है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त परीक्षा शुल्क को विद्यार्थियों को लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा के स्थान पर): (1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना से अभी तक निम्न वर्षों में भर्ती हुई विवरण निम्नानुसार है:-

1. वर्ष 2008
2. वर्ष 2011
3. वर्ष 2012
4. वर्ष 2013

(श्री भंवर सिंह भाटी)

5. वर्ष 2014

6. वर्ष 2018

वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 06 में अंकित है।

(2) इन भर्ती प्रकियाओं में किये गये आवेदन संबंधी विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या-04 में अंकित है।

(3) उपरोक्त भर्ती प्रक्रियाओं से विश्वविद्यालय को रुपये 1,06,20,286 (अक्षरे एक करोड छह लाख बीस हजार दो सौ छियासी रुपये मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त हुए। विवरण परिशिष्ट1 के कालम संख्या 05 में अंकित है। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क के नाम से कोई राशि एकत्र नहीं हुई है।

(4) जी हां। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा विज्ञापित पदों की विज्ञप्तियों को निरस्त नहीं किया गया है, साथ ही भर्ती विज्ञापन में आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं होने की बात स्पष्ट कर दी गई थी।

(5) मार्च, 2020 से देश में उत्पन्न कोविड-19 महामारी परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में सम सेमेस्टर परीक्षा 2020 के केवल मध्यवर्ती सेमेस्टरों की मुख्य परीक्षा के छात्रों/ परीक्षार्थियों को बिना सैद्धान्तिक परीक्षा आयोजन के अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम सेमेस्टर के समस्त छात्रों व मध्यवर्ती सेमेस्टरों के समस्त बैक छात्रों की सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा समस्त सम सेमेस्टर छात्रों से अन्तिम समय तक परीक्षा फार्म भरवाने पर किसी प्रकार का विलम्ब शुल्क नहीं लिया गया जिससे छात्रों को काफी राहत प्राप्त हुई, साथ ही छात्रों को लगभग 8 माह का समय भी दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त छात्रों के लिये परीक्षा फार्म भरवाने, मिडटर्म परीक्षा आयोजन, प्रायोगिक परीक्षा आयोजन, ऑनलाइन अंक भरवाने का कार्य, परीक्षा परिणाम तैयार करने का कार्य, परीक्षा परिणाम प्रकाशन का कार्य, अंकतालिकाओं का मुद्रण, टेबुलेशन रजिस्टर मुद्रण का कार्य आदि अनेक परीक्षा प्रक्रियाएं/कार्य सम्पादित किये गये हैं, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस का उपयोग किया गया।

मध्यवर्ती सेमेस्टरों की मुख्य परीक्षा के छात्रों/परीक्षार्थियों को बिना

(श्री भंवर सिंह भाटी)

सैद्धान्तिक परीक्षा आयोजन के अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा केवल सैद्धान्तिक परीक्षा आयोजन को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियों को सम्पादित किया गया है। अत: विश्वविद्यालय द्वारा उक्त गतिविधियों को सम्पादित करने के लिये परीक्षा शुल्क लिया जाना आवश्यक था।

(6) जी नहीं। प्रश्न के भाग संख्या-5 के प्रत्युत्तर में वर्णित गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा शुल्क लौटाया जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, अटरू एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कालेज है और इसकी समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं और इसकी अनियमितताओं की अखबारों में भी खबरें आती रही हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है विश्वविद्यालय प्रशासन सही कार्य कर सके, इसके लिये क्या सरकार इस पर मोनिटरिंग रखेगी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न क्या किया है और पूछ क्या रहे हैं I'll not allow it, please. अगला प्रश्न, श्री मदन दिलावर।

कोटा में डीएमआईसी द्वारा अवाप्त भूमि

63. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर के अन्तर्गत जिला कोटा में भूमि अवाप्त की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां, किस-किसकी, कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई तथा अवाप्त की गई भूमि का किस दर से मुआवजा दिया गया है? खातेदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कोरिडोर के अन्तर्गत उक्त जिले में क्या-क्या निर्माण कार्य किस-किस विभाग द्वारा किया जा चुका है व कितना कार्य शेष है व शेष कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) दिल्ली-मुबंई इंडस्ट्रियल कोरिडोर विभाग के अन्तर्गत कोटा जिले की भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

(उद्योग मंत्री)

(2) चाही गई सूचना शून्य है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर में नवीन पदों का सृजन

64. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेन्टर, बीकानेर में वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक कितने मरीजों का इलाज किया गया तथा कितने मरीजों की रेडियोथैरेपी व कितने मरीजों की कीमोथैरेपी तथा कितने मरीजों का दोनों थैरेपी से इलाज किया गया? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कीमोथैरेपी कराने वाले मरीजों की उक्त सेन्टर में संख्या बढ़ी है? यदि हां, तो क्या सरकार कैंसर पीड़ित मरीजों के सुलभ इलाज हेतु DM (ONCOLOGY) RPSC से चयनित सहायक आचार्य एवं आचार्य के नवीन पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि मुफ्त दवा योजना में कैंसर के इलाज में कीमोथैरेपी में उपयोग होने वाली दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम) (चिकित्सा शिक्षा मंत्री के स्थान पर) : (1) आचार्य तुलसी रीजनल कैन्सर सेन्टर, बीकानेर में वर्ष 2015 से वर्ष 2020 में मरीजों का रेडियोथैरेपी (RADIOTHERAPY), कीमोथैरेपी (CHEMOTHERAPY) एवं दोनों रेडियोथैरेपी व कीमोथैरेपी से इलाज किया गया है, की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। कीमोथैरेपी से इलाज लेने वालों की पूर्व वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है।

वर्तमान में मेडिकल कालेज बीकानेर में कैंसर के इलाज हेतु आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेन्टर के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। यहां टर्सरी कैंसर केयर सेन्टर 45 करोड़ रु. की लागत से विकसित किया

(श्री टीकाराम जूली)

जा रहा है। इसके अतिरिक्त दानदाताओं के माध्यम से कैंसर सर्जरी के लिये अलग बिल्डिंग के निर्माण का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। टर्सरी कैंसर केयर सेन्टर एवं कैंसर सर्जरी भवन विकसित होने पर आवश्यकतानुसार चिकित्सक शिक्षकों के पद सृजित किये जायेंगे।

(3) जी हां। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह था कि मेडिकल आंकोलोजिस्ट के पद आप सृजित करेंगे या नहीं करेंगे? अब आप यह जवाब दे रहे हो कि आवश्यकतानुसार, जबकि आपके ही जवाब में यह है कि 2015 में इस सेंटर में 89262 पेशेंट एडमिट हुए और 2019 में 127199, 40 परसेंट बीमारों की संख्या बढ़ी है, जिसमें 30171 को विभाग द्वारा कीमोथैरेपी लगाई गई, 4666 को रेडियोथैरेपी, 4497 को दोनों। विषय यह है कि जब कीमोथैरेपी ज्यादा लगाई जा रही है और मेडिकल आंकोलोजिस्ट उसके लिये काम्पीटेंट पर्सन है तो नोर्थ इंडिया के सबसे बड़े सेंटर में मेडिकल आंकोलोजिस्ट का एक ही पद क्यों सृजित है जब 40 परसेंट बीमार बढ़ रहे हैं, प्रश्न यह है कि क्या आप अतिशीघ्र वहां पर आरपीएससी द्वारा मेडिकल आंकोलोजिस्ट के पद सृजित कर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ करायेंगे?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि आरपीएससी को मेडिकल आंकोलोजी विशिष्टता में चार और सर्जिकल आंकोलोजी विशिष्टता में दो सहायक आचार्य के रिक्त पद भरने के लिये अर्थना भेजी जा चुकी है और वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में मेडिकल आंकोलोजी विशिष्टता में सहायक आचार्य का सिर्फ एक ही पद रिक्त है।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): मंत्री जी, मैं पूछना चाहूंगा कि यह जो वर्तमान में उस कैंसर सेंटर के डायरेक्टर हैं, वह रिटायर्ड डाक्टर हैं और 68 साल की उम्र है, जबकि हमेशा परम्परा यह रही है कि जो एचओडी है वह वहां का डायरेक्टर रहता है तो जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं वह व्यवस्था संभाल पा रहे हैं, काम्पीटेंट हैं और यदि हैं तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि सेंटर में पूरे उत्तर भारत के रोज मरीज आते हैं और जो असाध्य रोग से

(श्री सुमित गोदारा)

ग्रसित हैं, एक-एक दिन उनकी डायरी बनाने में लग रहा है? एक ही काउंटर है, तो वहां पर व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से फेल हो चुकी हैं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर डायरेक्टर एचओडी को बनाया जाये ताकि व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चल सकें और जो उत्तर भारत का कैंसर का सबसे टाप सेंटर है, वह और आगे बढ़े।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा कि अभी वहां पर जो डाक्टर कार्यरत हैं, वह काफी अनुभवी हैं और 68 वर्ष उनकी उम्र है और अनुभव के आधार पर ही उनको वहां पर रखा गया है और वहां पर अभी तक इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है। सिर्फ एक शिकायत 2017 में आई थी, वह भी उसमें कोई स्पेसिफिक अनियमितताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, एक कामन शिकायत करके उनके खिलाफ शिकायत की गई थी, उसके बाद आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। फिर भी माननीय सदस्य ने कहा है तो हम निश्चित तौर पर वहां जिनको मेडिकल डायरी में समय लग रहा है, उनकी जांच करा लेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि डायरी में या किसी भी प्रकार की लोगों को परेशानी न हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): डाक्टर्स की कमी के कारण एक रिटायर्ड पर्सन को एचओडी लगाने के लिये तो आप एक सर्टेन ऐज तक काम में ले सकते हैं लेकिन एचओडी पर आपने ऐज लिमिट कर रखी है और आपका आदेश निकला हुआ है। उस ऐज लिमिट के आधार पर ही एचओडी रह सकता है, भले ही कोई डाक्टर जूनियर होगा तो भी कोई बात नहीं लेकिन उसकी 62 ऐज लिमिट कर रखी है, तब तक वह एचओडी रह सकता है, 68 साल का व्यक्ति काम कर सकता है, आपको उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह एचओडी नहीं रह सकता।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आर्डर हैं यह मेडिकल कालेज के प्रोफेसर के लिये है न कि प्रोपर इस इंस्टीट्यूट के लिये है। इसमें हम 62 साल से अधिक के लोगों को लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह सेंटर का अलग पार्ट है, उसके साथ। अगला प्रश्न, सतीश पूनियां।

सिरसली ग्राम (आमेर) में गाड़िया लुहार परिवारों को स्थायी रूप से बसाने की योजना

65. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू के ग्राम सिरसली में अस्थायी रूप से लंबे समय से निवास कर रहे गाड़िया लुहार परिवारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 14.08.2020 के अनुक्रम में जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव विभाग को भिजवाया गया है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अब कब तक उक्त गाड़िया लुहार परिवारों को बसाने हेतु कार्यवाही कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी हां। विभागीय पत्र क्रमांक प.4(146)राज-3/20 दिनांक 14.08.2020 द्वारा गाड़िया लुहार परिवारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु उपयुक्त सिवायचक भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव चाहे गये थे। (परिशिष्ट-अ)

उक्त क्रम में जिला कार्यालय, जयपुर के पत्र क्रमांक 960 दिनांक 08.02.2021 द्वारा तहसील आमेर स्थित राजस्व ग्राम सिरसली के खसरा नम्बर 1360/560 रकबा 6.24 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर खसरा नम्बर 542/1353 रकबा 0.07 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.25 हैक्टेयर चरागाह भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने एवं उक्त अधिनियम की धारा 102क के तहत संबंधित ग्राम पंचायत सिरसली को आबंटित किये जाने संबंधी उप खण्ड अधिकारी, आमेर से प्राप्त प्रस्ताव को विभाग को प्रेषित किये हैं। प्रकरण में आवेदित भूमि चरागाह श्रेणी की प्रतिबंधित भूमि है। (परिशिष्ट-ब)

गोचर किस्म की भूमियों पर बसे गांव की आबादी को नियमित करने के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषक, जिनको पूर्व में पट्टे जारी किये जा चुके हैं, उक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को ही योजना बनाकर नियमित किया जा सकता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत सिरसली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त गाड़िया लुहार परिवार लगभग 30 वर्षों से इस भूमि पर

(राज्य मंत्री, राजस्व)

बसे हुए हैं। इनके पास अन्य आवासीय/खातेदारी भूमि नहीं है। जिला कार्यालय, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में प्रस्ताव का विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है। प्रकरण में प्रशासनिक अनुमोदन उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गाड़िया लुहार वह कम्युनिटी है जिसने मेवाड़ के संघर्ष में बड़ा योगदान दिया और 422 वर्षों से यह लोग घुमंतू के रूप में हैं। 32 जातियां हैं, 90 लाख लोग हैं, 10 लाख परिवार गाड़िया लुहार हैं। यह पूरे राजस्थान के लोक महत्व का प्रश्न है। चरागाह में बस नहीं सकते, गोचर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इनको क्या सरकार कहीं वैकल्पिक भूमि देने की कोई मंशा रखती है? यह 9 महीने पहले अतारांकित प्रश्न लगाया था, उसका जवाब भी यही था कि परीक्षण करवाया जा रहा है तो 9 महीनों में तो उन गाड़िया लुहारों के बच्चे भी पैदा हो गये, आबादी बढ़ती जा रही है, बसायेंगे कब?

दूसरा, इसमें सरकार ने महाराणा प्रताप आवासीय अनुदान की योजना लगाई थी, तो कितने ऐसे गाड़िया लुहारों के निर्माण हुए हैं और क्या उनकी अनुदान राशि देने की सरकार की मंशा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जालसू तक का संबंध है। सरकार परीक्षण करवा रही है। आप यह पूछो कि परीक्षण कितना जल्दी करवा लेगी, तभी रास्ता निकलेगा।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रश्न का जवाब दिया है कि गोचर में बस नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, मैंने इसीलिए इसको पढ़ा है। इसमें देखो ऐसा नहीं है। प्रकरण में ग्राम पंचायत सिरसली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त गाड़िया लुहार परिवार लगभग 30 वर्षों से इस भूमि पर बसे हुए हैं। इसके पास अन्य आवासीय/खातेदारी भूमि नहीं है। ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके अंतर्गत इसको परीक्षण करवाया जा रहा है। इसलिए आपका प्रश्न यह होना चाहिए कि इसको जल्दी डिस्पोज करके इनके बारे में फैसला करें,

(श्री अध्यक्ष)

बाकी आप पूरे गाड़िया लुहार का प्रश्न करेंगे तो, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न भी पूछ लिया, तारांकित प्रश्न भी पूछ लिया, आप खुद मान रहे हो कि ये इनके नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंतर्गत इसका परीक्षण करवाकर इनको पट्टा देने की कार्यवाही करें।

अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल जी।

झाडोल में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों को देय अनुदान

66. श्री बाबु लाल (झाडोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल में विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को आवासीय छात्रावासों हेतु अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किन-किन छात्रावासों का कितनी अनुदान राशि का भुगतान बकाया है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आवासीय छात्रावासों हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र झाडोल में स्वयंसेवी संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति, झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर द्वारा संचालित (1) गैर आवासीय विद्यालय, बाखेल (कोटड़ा) (2) शैक्षणिक परिसर, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (शिक्षण एवं आवासीय सुविधा सहित), बीडा (झाडोल) को जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सीधे ही अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा साफ थी कि जिन बच्चों के या तो माता नहीं है या पिता नहीं है या फिर इन दोनों में से दोनों ही नहीं है, साया उठ गया, ऐसे बच्चों को भोजन का अधिकार है या नहीं है? अगर है तो राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो संस्थाएं ऐसे बच्चों का पालन-पोषण करती हैं, शैल्टर होम चलाती हैं, मेरे झाडोल में लवीना एक संस्था है, मैं खुद जाकर देखकर आया हूं, 32 बच्चे ऐसे हैं जिनके मां-बाप नहीं हैं और उनका

(श्री बाबु लाल)

पालन-पोषण कर रहे हैं, आपके विभाग में उनका रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्होंने अनुदान के लिए आवेदन किया होगा, अगर वे सीधे केंद्र सरकार को करते हैं या फिर आपके यहां से प्रस्ताव सीधा केंद्र सरकार को जाता है, यह बताएं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयंसेवी संस्थाएं भारत सरकार को आनलाइन आवेदन करती हैं, उसका वैरिफिकेशन माननीय जिलाधीश महोदय करते हैं। उसके बाद यहां की सैक्रेटरी लेवल की कमेटी उसको फारवर्ड करके भारत सरकार को भेजती है। उसके बाद जनजाति विभाग का उसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं है। पैसा सीधा उनके खातों में ट्रांसफर होता है और न ही हमको किसी तरह के आदेश हैं कि हम उसकी जांच करें या उसकी देखरेख करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका और विभाग का उत्तरदायित्व है। इस सारे केस को वैरिफाई करके आपके यहां से फाइल जब केंद्र सरकार को जाती है, तब केंद्र सरकार उसको अनुदान दे सकती है। कोई सीधे भी एप्लाई करेगा, वैरिफाई आपके यहां से होगा। बच्चे हैं या नहीं हैं, कहां हैं? किस तरह हैं? कितनी संख्या में हैं? मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि इस संस्था के आपके विभाग में कागज कितने साल से पैंडिंग है, यह बता दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि संस्था आनलाइन आवेदन करती है। कलेक्टर, जिलाधीश महोदय जहां के हों, वे उसका वैरिफिकेशन करते हैं। हमारी कमेटी सिर्फ फारवर्ड करने का काम करती है, जो कि सैक्रेटरी लेवल की कमेटी होती है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा किसी तरह की कोई भी गाइडलाइन या कोई भी ऐसे आदेश नहीं हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता के पास ऐसा हो तो हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, विभाग के पास इस तरह की रिकमंडेशन के कोई कागज पेंडिंग तो नहीं हैं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): बिलकुल नहीं है, सर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बाबु लालजी, आप जिन 32 बच्चों के बारे में कह रहे हैं, सरकार को लिखकर भेजें। ये इसका पता लगाकर इसकी क्या कार्यवाही कर सकते हैं, इसमें मदद करने का काम करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इस केस से थोड़ा संबंधित रहा, क्योंकि इस केस पर आपके सैक्रेटरी से मेरी तीन बार बात हुई। जो व्यक्ति संस्था चलाता है, वह व्यक्ति भी यहां पर आया है। उसका केस आपके यहां विभाग में ही घूम रहा है। यहां से रिकमंड होकर जब तक नहीं जाएगा, तब तक.. मैंने इसके लिए केंद्र में भी बात की है, क्योंकि यह दो-तीन साल से चला रहा है। वास्तव में बच्चे ऐसे असहाय हैं कि उसकी अब खर्चा बर्दाश्त करने की सीमा भी नहीं है, जन सहयोग से भी कितना चलाएगा? इसमें मेरी दिल्ली में भी बात हुई है, आपके यहां भी दो बार सैक्रेटरी से बात हुई। यह फाइल आपके यहां पैंडिंग है। मानवीय दृष्टि से इस फाइल को निकालकर केंद्र सरकार को, जो भी प्लस या माइनस पाइंट हों, वह वैरिफाई करके भेज दें, ताकि उन बच्चों को सहायता मिले।

श्री अध्यक्ष: अब इसमें कोई तकलीफ थोड़े ही है? फाइल को ट्रेस करके पता लगाकर भारत सरकार को भेजने का काम करें। सात दिन में हो जाएगा?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): बिलकुल हो जाएगा। मेरे ध्यान में नहीं है, फिर भी आपका आदेश है तो दिखवाकर उसको फारवर्ड कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री राजेन्द्र राठौड़।

बुहाना (झुन्झुनूं) में महाविद्यालय की स्थापना

67. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) (श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़) के स्थान पर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा पंचायत समिति मुख्यालयों पर महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो कितने पंचायत समिति मुख्यालय महाविद्यालय से वंचित हैं? जिला झुन्झुनूं की पंचायत समितियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सर्वे के आधार पर पंचायत समिति बुहाना जिला झुन्झुनूं में महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी नहीं। इस संदर्भ में सर्वे नहीं कराया गया है।

(2) जी नहीं। इस संदर्भ में सर्वे नहीं कराया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खंड में कहा कि आपने महाविद्यालय खोलने के लिए कोई सर्वे नहीं कराया है, तो आपने सत्र 2019-20, 2020-21 में जो 80 विद्यालय खोले, वे किस आधार पर खोले? क्या प्रदेश में जिन उपखंडों में कोई भी सरकारी क्षेत्र में वर्तमान में महाविद्यालय संचालित नहीं हैं, वहां महाविद्यालय खोलने की आपकी क्या कोई नीति या मंशा है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, जैसा मूल प्रश्न में माननीय सदस्य को अवगत कराया कि पंचायत समिति स्तर पर इस तरह का कोई सर्वे नहीं कराया गया है। राज्य सरकार की कार्ययोजना में राजस्थान में उपखंड स्तर पर महाविद्यालय खोलने की हमारी योजना है, उसके तहत पिछले दो सालों में 2019 और 2020 के बजट में भी करीब 88 कालेज राजस्थान के अलग-अलग उपखंडों में खोले गये। पिछले दो साल में हमने राजस्थान में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कालेज खोले हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की मंशा है कि उच्च शिक्षा का प्रसार गांव तक, उपखंड और तहसील स्तर तक हो, उस दिशा में काम किया जा रहा है और आगामी समय में भी उपखंड स्तर पर हमने तीन कैटेगरी बनायी हैं। पहले तो उन उपखंडों पर कालेज खोलने का विचार किया जा रहा है, जिसमें एक भी न सरकारी राजकीय महाविद्यालय है, न निजी राजकीय महाविद्यालय है। ऐसे पूरे राजस्थान में आठ उपखंड हैं। उसके अलावा जहां निजी महाविद्यालय हैं और गवर्नमेंट का नहीं है तो उनको दूसरी वरीयता में रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सरकार की पूरी मंशा है कि उच्च शिक्षा का प्रचार-प्रसार हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा हो और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने कालेज खोले भी हैं और आने वाले समय में कालेज खोले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं को सातवें वेतन आयोग का लाभ

68. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं को सातवें वेतन आयोग का लाभ-परिलाभ अब तक नहीं दिया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा के स्थान पर): (1) विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के पोलीटेक्निक महाविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं गैर अभियांत्रिकी सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रवक्ता एवं अन्य पदों पर शैक्षणिक कार्मिक कार्यरत हैं। इन शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान दिये जाने हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:-

(i) राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 से शासित होने वाले कार्मिकों हेतु ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 के अनुसार सातवें वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ii) राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 से शासित होने वाले महिला पोलीटेक्निक के शिक्षकों हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(7)एफडी/रूल्स/2008 पीटी.।। दिनांक 31.07.2020 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) नियम 2017 द्वारा सातवें वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं। इन्हें ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 के अनुसार वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। वर्तमान में सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधन उपरान्त इनको 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकेगा।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगी कि पोलीटेक्निक महाविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ताओं को सातवें वेतन आयोग का लाभ कब तक देंगे? प्रक्रियाधीन तो सब है, लेकिन प्रक्रियाओं का अंत कब तक लगता है कि हो पायेगा?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही अभी चल रही है, ये कार्यवाही पूरी होते ही अतिशीघ्र सातवां वेतन आयोग देने का कार्य किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना है?

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौडगढ़ में सीएसआर मद में विकास कार्य

69. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में संचालित विभिन्न सीमेंट फैक्ट्रियों एवं हिन्दुस्तान जिंक द्वारा सीएसआर मद से विकास कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में उक्त मद से कराये गये कार्यों का पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्रियों द्वारा विगत दो वर्षों से सीएसआर मद से विकास कार्य नहीं करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की उक्त फैक्ट्रियों से प्रभावित गांवों में सीएसआर मद से विकास कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में संचालित विभिन्न सीमेंट फैक्ट्रियों एवं हिन्दुस्तान जिंक द्वारा सीएसआर मद से विकास कार्य करवाये जाते हैं, जिनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार विगत 3 वर्षों में सीएसआर के तहत किये गये व्यय एवं कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

यह उल्लेखनीय है कि सीएसआर के दायरे में आने वाली कम्पनियों को उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्वों में कम्पनी की सीएसआर कमेटी द्वारा निर्धारित नीति अनुसार शिड्यूल-VII में सम्मिलित सीएसआर गतिविधियों पर ही व्यय किये जाने का प्रावधान है। सीएसआर व्यय की सूचना सीएसआर कम्पनियों द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को ही प्रेषित की जाती है तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर फण्ड की मानिटरिंग हेतु राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

(2) जी नहीं। खण्ड-1 के अनुसार कार्य करवाये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। क्योंकि कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 01/2016 दिनांक 12.01.2016 के बिन्दु संख्या 18 में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि कंपनियों द्वारा सीएसआर के कार्यान्वयन की निगरानी में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार विकास कार्य करने हेतु उक्त फैक्ट्रियों को मात्र प्रोत्साहित कर सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त उद्यमों तथा कंपनियों के प्लांट चित्तौड़गढ़ में संचालित हैं, जिसके दुष्प्रभाव से स्थानीय निवासियों को प्रदूषण एवं बीमारियों की मार झेलनी पड़ रही है, जबकि इन उद्यमों का सीएसआर फंड का उपयोग इनके कार्यक्षेत्र के बाहर अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में करवाया जा रहा है। कंपनियों व फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को रोजगार दें और यह काम उसी जिले में करें क्योंकि ज्यादातर फंड बाहर के जिलों में, बाहर के स्टेट में लगाकर वहां काउंट करवाये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जो भी दो परसेंट, जो पैसा खर्च होता है, उसी एरिये में खर्च करें, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है और उसी जिले में करें, ऐसा सरकार उनको पाबंद करे। वहां के युवा बेरोजगार हैं, उनको वहां रोजगार मिले, इस तरह का आप प्रावधान कीजिए।

श्री अध्यक्ष: सीएसआर की गाइडलाइंस में कुछ नहीं कर सकते।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की इसमें न तो स्वीकृति में भूमिका है, न मानिटरिंग में है, न उनकी कोई जांच कर सकती है। सब भारत सरकार के अंतर्गत आता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

अजमेर व जोधपुर के होम्योपैथिक महाविद्यालय को भूमि का आबंटन

70. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अजमेर व जोधपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त की स्वीकृति कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त महाविद्यालयों के लिए भूमि आबंटित कर दी गई है? यदि हां, तो किस-किस महाविद्यालय को कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों होम्योपैथिक महाविद्यालयों में छात्रों ने प्रवेश लिया है? यदि हां, तो उक्त दोनों होम्योपैथिक महाविद्यालय में कितने-कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम) (आयुर्वेद मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। वित्त विभाग द्वारा दोनों महाविद्यालय खोलने की सैद्धांतिक सहमति आई डी क्रमांक 152000702 दिनांक 31.08.2020 द्वारा जारी करने के पश्चात् इस विभाग द्वारा महाविद्यालय खोलने हेतु नियामक संस्था केन्द्रीय होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् के निर्धारित प्रपत्र 4 में राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

(2) जी हां। होम्योपैथी महाविद्यालय केकड़ी (अजमेर) हेतु जिला कलेक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक 42 दिनांक 27.07.2020 द्वारा कुल किता 2 रकबा 2.00 हैक्टेयर भूमि निःशुल्क आबंटित हो चुकी है।

होम्योपैथी महाविद्यालय जोधपुर हेतु राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के करवड़ स्थित परिसर में उपलब्ध भूमि में से 04 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय के मास्टर प्लान से चिन्हित कर ली गई है।

(3) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा इन दोनों नवीन होम्योपैथी महाविद्यालयों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को आवेदन कर दिया गया है। साथ ही

(श्री टीकाराम जूली)

इस विभाग द्वारा दोनों होम्योपैथी महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 22.12.2020 को अपनी अण्डरटेकिंग भी प्रेषित कर दी गई है। अत: कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान में कोई भी विद्यार्थी प्रवेशरत नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की बजट घोषणा थी और बजट घोषणा के उपरांत अभी तक एक ही महाविद्यालय के लिए आपने जमीन आबंटित की है। क्या 2021-22 में आपकी सरकार की मंशा है कि भूमि आबंटन का काम और बजट आबंटन का काम, क्योंकि आपने कहा है कि फाइनेंस से सैद्धांतिक सहमति मिली है, बजट आबंटन नहीं हुआ, क्या दोनों काम करने की मंशा है?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): अध्यक्ष महोदय, एक जगह भूमि का आबंटन हो गया है। दूसरी जगह भूमि चिह्नित कर ली गई है, जिसका शीघ्र ही आबंटन हो जाएगा। दूसरी बात बजट आबंटन की है तो इसी बजट के अंदर 50-50 लाख रुपये दोनों का बजट भी आबंटन हो गया है। चूंकि आपको पता है कि महाविद्यालय खुलने पर कम से कम एक साल पहले अस्पताल चलना जरूरी है, हमने वहां पर अस्पताल का संचालन भी शुरू कर दिया है। ओपीडी के अंदर सौ-सवा सौ लोग लगभग प्रतिदिन अंदर आ रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अंडरटेकिंग भी भेज दी है। भारत सरकार के द्वारा जो भी जानकारी चाही गयी है, वह भी उनको भिजवा दी गयी है। इसके बाद भारत सरकार का दल वहां पर दौरा करेगा, उसके बाद महाविद्यालय वहां पर शुरू हो पायेगा। बजट का प्रावधान भी इसी बजट के अंदर है। चूंकि ये इसी बजट की घोषणा थी और 50-50 लाख रुपये दोनों ही महाविद्यालयों के लिए बजट का आबंटन भी हो चुका है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि अभी 2020-21 के सत्र में एक भी विद्यार्थी को आपने प्रवेश नहीं दिया, क्या सरकार की मंशा है कि आने वाले 2021-22 के अंदर तो आप विद्यार्थियों को एडमिशन दे देंगे या उसे भी 2022-23 में लेकर जाएंगे?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही महाविद्यालय शुरू होगा उसी में तो प्रवेश मिलेगा। यह सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में होटल खड़ताल के स्थान पर टाउन हाल का निर्माण

71. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार वर्षों से बंद पड़ी होटल खड़ताल पर्यटन काम्प्लेक्स जो कि खण्डहर में तब्दील हो रही है, के आबंटन को जनहित में निरस्त कर सरकार की बजट घोषणा के तहत टाउन हॉल निर्माण करने हेतु नगर सुधार न्यास, बाड़मेर को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री भंवर सिंह भाटी): जी हां। इस संबंध में जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा पत्रांक 9013 दिनांक 12.10.2020 द्वारा नगर विकास न्यास, बाड़मेर की मांग पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2019-20 की पालना में बाड़मेर शहर में नवीन टाउन हाल निर्माणार्थ पर्यटन काम्प्लेक्स हेतु पर्यटन विभाग, भारत सरकार को नि:शुल्क आबंटित भूमि के आबंटन को निरस्त कर आडिट आक्षेप के क्रम में राशि वसूली संबंधी मार्गदर्शन एवं उक्त भूमि को नगर सुधार न्यास, बाड़मेर को हस्तान्तरित किये जाने संबंधी प्रस्ताव वास्ते राजकीय स्वीकृति विभाग को प्रेषित किये हैं। परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त विषयक में कार्यकारी निदेशक, आर.टी.डी.सी. के पत्र दिनांक 07.01.2021 द्वारा होटल खड़ताल, बाड़मेर का संचालन वर्ष 2004 तक निगम द्वारा किया जाना एवं उसके निर्माण पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 30.65 लाख तथा भारत सरकार द्वारा 12.91 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा 3.16 लाख, कुल 46.72 लाख रुपये व्यय होने एवं पर्यटकों की कमी तथा संसाधनों के अभाव में बन्द होने से अवगत कराते हुए इस इकाई को शीघ्र ही मरम्मत करवाकर पर्यटकों की सुविधार्थ संचालित किये जाने एवं आबंटन निरस्त नहीं किये जाने हेतु विभाग को लिखा है। परिशिष्ट-ब संलग्न है।

प्रकरण में जिला कलेक्टर, बाड़मेर एवं राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में विभाग स्तर पर विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है। विधिक प्रावधानों के आलोक में शीघ्र ही प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये खड़ताल होटल है, करीबन 17-18 साल से बंद पड़ी है, दरवाजे चोरी कर ले गये, बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण है, बबूल की झाड़ियां चारों तरफ भरी हैं, आवारा पशु और शराबी अंदर ठहर रहे हैं। ये किसी काम नहीं आ रही है और जिला कलेक्टर ने भी लिखा है इस जगह...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि ये आरटीडीसी का भवन किसी काम नहीं आ रहा है। यूआईटी जो लागत के पैसे लगे हैं, वह देने को तैयार है। आप इस भवन को वापस यूआईटी को सुपुर्द कर दो। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी जो बजट...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप तो प्रश्न पूछिए। आप क्या चाहते हैं?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं यही चाहता हूं कि क्या यह भवन, उनकी जो लागत है, उनके जो पैसे लगे हैं, वह यूआईटी इनको पे करने के लिए तैयार है? आप वापस यूआईटी को या राजस्व विभाग को देने के लिए तैयार हैं? यही मेरा प्रश्न है। बीस साल से बंद पड़ा है, किसी काम का नहीं है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, होटल खड़ताल जो वर्तमान में बंद है, लेकिन पर्यटन विभाग, राजस्थान और पर्यटन विभाग, भारत सरकार के द्वारा यह पत्र लिखा गया है कि वे होटल को पुन: मरम्मत करके शुरू करना चाहते हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर बाड़मेर से प्राप्त प्रस्ताव है, उसमें टाउन हाल के लिए माननीय विधायक महोदय ने जो बात कही है, तो जिला कलेक्टर बाड़मेर से प्राप्त प्रस्ताव का विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है। प्रकरण में शीघ्र ही नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि पर्यटन विभाग व राजस्व विभाग दोनों से संबंधित है, इसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, यह पैसे देने के लिए तैयार है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

गोगुंदा में मां-बाड़ी केन्द्र पुन: खोलने की कार्ययोजना

72. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार शिक्षा से वंचित ढाणियों में मां-बाड़ी केंद्र खोलने का विचार रखती है?

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा के उबरीखुणा, नदी फला, खोखानाडी वालोलिया एवं वालरा मां-बाडी केंद्र को बिना नोटिस दिए बंद कर दिया है, जिससे करीब 150 बच्चे प्रभावित व 5 व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं? क्या सरकार उक्त को पुन: खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) शिक्षा से वंचित ढाणियों में मां-बाड़ी केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनका निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण करा, बजट की उपलब्धता एवं उपादेयता के आधार पर नवीन केन्द्र खोले जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा के उबरीखुणा, नदी फला, खोखानाडी, वालोलिया व वालरा मां-बाड़ी केन्द्रों के दिनांक 19.06.2019 एवं 20.06.2019 को जांच कमेटी द्वारा किये गये निरीक्षण में संचालन संतोषप्रद नहीं पाये जाने के आधार पर इन केन्द्रों को बन्द किया गया था।

इन केन्द्रों को पुन: खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदण्डों अनुसार परीक्षण करा, बजट की उपलब्धता एवं उपादेयता के आधार पर केन्द्रों को पुन: खोलने का विचार किया जा सकता है।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): मंत्री जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि यह हटाये गये हैं, पुन: जांच कब करेंगे? आप कह रहे हैं अनियमितता पाई गई, कौनसी कमेटी जांच करने गई, कब गई? आप रोजगार देने का काम करते हैं, कहते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार बदलते ही जिन 5 व्यक्तियों का रोजगार छीना गया है, क्या मंत्री जी पुन: जांच करके उनको रोजगार देने का काम करेंगे?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है, कमेटी गठित करके उसकी जांच कराकर, परीक्षण करके, अगर नोर्म्स के अनुसार है तो चालू करा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। लक्ष्मण मीणा।

बस्सी के राजकीय महाविद्यालय के भवन-निर्माण हेतु बजट का आबंटन

73. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय महाविद्यालय, बस्सी के भवन निर्माण के लिए कब तक बजट आबंटित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

(2) उक्त महाविद्यालय में वर्तमान में किस-किस संकाय में कितने-कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है?

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र में कला संकाय में अन्य अतिरिक्त विषय तथा विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) राजकीय महाविद्यालय, बस्सी के भवन निर्माण के लिए राशि रुपये 5.35 करोड़ की DMFT Fund से स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा दिनांक 12.01.2021 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। जिला कलेक्टर द्वारा बजट आबंटित करने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) राजकीय महाविद्यालय, बस्सी में संचालित कला संकाय में सत्र 2020-21 में कुल 789 विद्यार्थी (328 छात्र व 461 छात्राएं) अध्ययनरत हैं।

(3) वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय, बस्सी में कला संकाय में अन्य अतिरिक्त विषय तथा विज्ञान संकाय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): धन्यवाद, सर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा में पैट्रो केमिकल व टैक्सटाइल कालेज खोलने की कार्ययोजना

74. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन प्रजापत)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने एवं युवाओं में स्किल हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पचपदरा में रिफाइनरी एवं उनके प्रोडक्ट तथा कपड़ा उद्योग को देखते हुए बालोतरा मुख्यालय पर पैट्रोकेमिकल टैक्सटाइल एवं पर्यावरण सहित अन्य संकायों के इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा के स्थान पर): (1) तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभाग के अधीन संचालित पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में आई.आई.आई. सेल में स्टूडेंट एडवाइजरी एवं गाइडेंस ब्यूरो चालू कर दिये गये हैं। सत्र 2020-21 से सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में लागू किया गया है। विद्यमान ब्रांच की क्षमता में परिवर्तन करते हुए व्यवसाय उन्मुख नवीन ब्रांच रोबोटिक्स, मैकेट्रोनिक्स, साइबर फोरेंसिक एंड इनफोर्मेशन सिक्योरिटी सत्र 2020-21 से 19 पोलीटेक्निक में नवीन ब्रांच शुरू की गई तथा तीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में Artificial Intelligence & Data Science, Machine Learning, Internet of Things प्रारम्भ कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा आटोकैड, रेफ्रिजरेशन, अनुरक्षण विषयक कोर्स कराये जा चुके हैं। समय की मांग के अनुसार संबंधित संस्थाओं से निरन्तर समन्वय व सामन्जस्य स्थापित किया जा रहा है। पोलीटेक्निक महाविद्यालयों द्वारा I.I.I. Cell के माध्यम से उद्योगों के साथ एमओयू किये गये। राज्य के 4 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नवीन ब्रांच AI&DS, IoT एवं मशीन लर्निंग प्रारम्भ की गई हैं।

(2) वर्तमान में बालोतरा मुख्यालय पर पैट्रोकेमिकल टैक्सटाइल एवं पर्यावरण सहित अन्य संकायों के इंजीनियरिंग कालेज खोलने बाबत प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में जिला बाड़मेर में विभाग के अन्तर्गत संचालित इंजीनियरिंग कालेज में पैट्रोलियम इंजीनियरिंग सहित अन्य शाखाओं का संचालन होने से तकनीकी शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके

(श्री मदन प्रजापत)

मार्फत निवेदन है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जब रिफाइनरी आई तो लाखों लोगों को उम्मीद जगी कि हमें रोजगार मिलेगा, इंजीनियरिंग कालेज, पेट्रोकेमिकल टैक्सटाइल, अगर शुरू नहीं होगा तो स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, बाहरी लोग आएंगे तो इससे आक्रोश फूटेगा। मैं यह निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी बाड़मेर, बालोतरा में खोलने का विचार है या नहीं है? अगर नहीं है तो युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न में भी निवेदन किया है और माननीय सदस्य के द्वारा पेट्रोलियम से संबंधित कोर्स शुरू करने की बात रखी गई है। इस संबंध में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज बाड़मेर है, उसमें इस तरह के कोर्सेज प्रारम्भ किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में भी, जिन कालेजों के भवन नहीं बने हैं, वह कब तक बनेंगे, बजट आबंटन होगा या नहीं?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी बस्सी के राजकीय महाविद्यालय के बारे में मैंने निवेदन किया, राजस्थान में करीब ऐसे 24 कालेज हैं, DMFT मद के तहत जिनके भवन बनाना तय किया गया है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही DMFT की राज्य स्तरीय मीटिंग हुई, उसमें राजस्थान के 8 कालेजेज को DMFT मद के तहत 6-6 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। आगामी समय में DMFT की जो मीटिंग्स होंगी, उसमें तमाम कालेजेज के लिए भवन की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ-साथ जो अल्पसंख्यक विभाग है, उसके माध्यम से भी, राजस्थान के करीब 8 कालेज ऐसे हैं जिनका भवन उस विभाग के द्वारा दिए जाने वाले बजट से बनाया जाना है। रीको के द्वारा भी एक कालेज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भामाशाहों द्वारा भी भवन निर्माण के लिए विभाग के पास प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो कालेज राजस्थान में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खोले हैं, वह भी अस्थायी भवनों में चल रहे हैं। आगामी समय में शीघ्र अतिशीघ्र उन तमाम कालेजेज के लिए भवन निर्माण का कार्य करवाया जाएगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी हज़ारों लोग बाहर के काम करते हैं। लोगों में आज पूरा आक्रोश नहीं है लेकिन समय रहते इंजीनियरिंग में युवाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया तो बाहरी लोगों का विरोध होगा। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पहले से व्यवस्था हो ताकि स्थानीय को जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुसार रोजगार मिल सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट बाकी है, इसलिए मैं ही प्रश्न पूछ लेता हूं। माननीय मंत्री जी, आप कालेज खोल रहे हैं, वित्तीय संसाधनों के कारण भवन नहीं बन रहे हैं, फैकल्टी की कमी है, तो क्वालिटी आफ एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए क्या सरकार इस तरह का निर्णय करने की स्थिति में है कि जो बच्चा स्लेट और नेट पास है, उसको पर क्लास आनरेरियम फिक्स करके, कालेजेज को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए सरकार कोई योजना बनाने की इच्छा रखती है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष जी, जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी कालेज शिक्षक की पूरी योग्यता रखते हैं ऐसे लोगों के लिए हमने, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में कालेजेज में शिक्षकों के पद रिक्त होने की वजह से हमारी शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो हमारे विभाग द्वारा यह कार्य किया जा रहा है कि जो निर्धारित योग्यता धारक विद्यार्थी हैं उनको पर लैक्चरर, गैस्ट फैकल्टी के रूप में जो मानदेय दिया जाता है, उसको हम बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे विद्यार्थी गांवों में जाकर भी कालेजेज में पढ़ा सकें।

श्री अध्यक्ष: The respectable amount, the issue है, जैसे डाक्टर की कमी के कारण एक सबस्टेंशल अमाउंट दे रहे हैं। पर क्लास आपका जो आनरेरियम है उसका आमउंट बढ़ाएं, जिससे वह नेट-स्लेट पास लड़का, आपकी भर्ती नहीं हो रही है तो नेट-स्लेट इलिजिबल तो है, पढ़ाने का काम कर सकता है।

(12.00 बजे)

यदि आप उसका आनरेरियम 5 हजार पर-क्लास करें, 2 हजार पर-क्लास करें तो बच्चे पढ़ाने का काम कर सकेंगे। यह काम आप प्रिंसिपल पर छोड़ दें। उस डिस्ट्रिक्ट में जो कालेज के प्रिंसिपल हैं, वहां पर जितने भी नेट, स्लेट के बच्चे पास हैं, उनको यह इंसेंटिव दें कि यदि वे क्लास लेंगे तो पर-क्लास हम इतना पैसा देंगे। मैं समझता हूं इससे आंशिक रूप से वह पढ़ाई का काम हो सकेगा। इस बारे में सरकार योजना बनाये।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से मालपुरा नगरपालिका क्षेत्र में विगत दो वर्षों से विभिन्न निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री उपयोग में लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ में आदित्य बिरला (अल्ट्रा टेक) सीमेंट प्लांट से प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में सिंचाई हेतु कृषि कनेक्शन दिये जाने तथा रात्रि के समय विद्युत सप्लाई किये जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में अधिकांश श्मशानों के राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नदी नाला दर्ज होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से कुशलगढ़ के लोहारिया बड़ा डूंगला पानी गांव के निवासी बाबू कलारा ने अपने चार मासूम बच्चों की हत्या कर स्वयं भी आत्महत्या कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड ट्रस्ट की राशि का जन उपयोगी कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से नोखा शहर में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ठेकाकर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में निविदाओं में हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र के रामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में किसानों को रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में कृषि के विद्युत कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में विभिन्न जगह क्षतिग्रस्त सड़कों से हो रहे गम्भीर सड़क हादसों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से जालौर जिले में मादक पदार्थ एम.डी. और स्मैक की हो रही तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से कोटा उत्तर नगर निगम की अनुसूचित जाति की महिला पार्षद के साथ किये गये दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में आयोजित NTT भर्ती में अभ्यर्थियों द्वारा अन्य प्रदेशों से फर्जी डिग्रियां व अंक तालिकाओं के आधार पर आवेदन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामप्रताप कासनियां एवं 03 अन्य सदस्यों की ओर से पंजाब सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नहर में कम पानी छोड़े जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों का नाम जोड़ने वाली साइट को लॉक कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से खैराबाद पंचायत समिति क्षेत्र में निर्माणाधीन बांध डूब क्षेत्र के किसानों को जमीन के मुआवजे का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से अम्बुजा सीमेंट कम्पनी द्वारा गलत तथ्य पेश कर नागौर जिले के मूण्डवा में स्थापित किये जा रहे सीमेंट प्लांट के लिये औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में जन प्रतिनिधियों से फिरौती मांगने की बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ठण्डी-ठाकरी, NP के किसानों को कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना देवी, श्री रामलाल शर्मा, श्री रामप्रताप कासनिया, श्री ज्ञानचंद पारख, श्री मदन दिलावर, श्री नारायण बेनीवाल, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री बलवीर सिंह लूथरा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से जवाई बांध की जल वितरण समिति में जैतारण विधान सभा क्षेत्र के विधायक को शामिल करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री महेन्द्र बिश्नोई, सदस्य की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणी में पेयजल लाइन से लिये गये अवैध कनेक्शन नहीं काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौरासी के राजकीय महाविद्यालय, सीमलवाड़ा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री किसनाराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में ऊंट के संवर्धन, पोषण, इलाज व ऊंट के दूध से बने उत्पादों के लिये योजनाएं क्रियान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से मुण्डावर, नीमराणा, बानसूर एवं बहरोड़ को नवसृजित ए.डी.एम. कार्यालय, भिवाड़ी के अधीन करने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

38] नियम 295 के अ. प्राप्त-13 फरवरी 2021-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कनिष्ठ सहायक, पटवारी एवं पुलिस कांस्टेबलों की ग्रेड-पे 2400 से बढ़ाकर 3600 नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से पंचायती राज विभाग में लम्बे समय से कनिष्ठ लिपिकों के 19200 रिक्त पड़े पदों पर भर्ती नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से नगरपालिका आबूरोड के गांधी नगर स्थित 132 समपार फाटक पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से नदबई के उच्चैन कस्बे में नवीन औद्योगिक क्षेत्र (रीको) खोलने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से फतेहपुर के ग्राम हरसावा बड़ा में रेलवे लाइन पर अण्डरपास बनाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री रामप्रसाद, सदस्य की ओर से लोडेश्वर बांध की नहर का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराने के सम्बन्ध में।

(15) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती कल्पना देवी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कोटा उत्तर नगर निगम की अनुसूचित जाति की महिला पार्षद के साथ दुव्यर्वहार

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि 11 फरवरी, 2021 को कोटा उत्तर नगर निगम की नवनिर्वाचित बोर्ड की बैठक हुई। उस दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद अपनी बात रखना चाहती थीं, यानी अपने वार्ड की समस्या की कोई बात रखना चाहती थीं। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने उसे घेरकर हाथापाई की, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और उसके गाल पर थप्पड़ भी मारकर अपमानित किया।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार इस तरीके से अपनी महिलाओं या खास करके पिछड़ी जाति की महिलाओं का ऐसा संरक्षण करती है? हमारी सब जनता हर जन प्रतिनिधि से यह उम्मीद रखती है कि वह उनकी बात आगे रखें ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। अगर जन प्रतिनिधि ही अपनी बात नहीं रख सकते तो क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जो कि निंदनीय भी है। इस प्रक्रिया का जो पूरा अपराध है, जिसमें थप्पड़ मारने का भी प्रकरण है, यह वीडियो में भी प्रमाणित है। ये जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, ये आई.जी. के पास भी गये थे। उनकी बात रखी पर इनकी एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग रखती हूं कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो और इस महिला पार्षद को न्याय मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति की महिला के साथ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, अलाउ नहीं करूंगा। कोई रिकार्ड नहीं होगा। मैं आपको बोलने का मौका भी नहीं दूंगा। मैं आपको मौका भी नहीं दूंगा। मैं इसमें भी आउट कर दूंगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। कोई रिकार्ड नहीं होगा। मैं आपको कोई भी, किसी पर भी बोलने का मौका नहीं दूंगा। I will not allow you. Please. मैं आपको किसी भी स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं दूंगा। I will not allow you. आपने ठेका ले रखा है क्या, आपने ठेका ले रखा है क्या? I will not allow you. (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: I will not allow you. I will name you. यह रोज का तरीका है, सीनियर आदमी हो। हर-एक चीज पर बोलना जरूरी है? उस सदस्य को भी मौका नहीं देंगे। हर चीज में अपहोल्ड करना चाहते हैं।

श्री रामलाल शर्मा।

NTT भर्ती में अन्य प्रदेशों की फर्जी डिग्रियों व अंक-तालिकाओं के आधार पर अभ्यर्थियों के आवेदन

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर पूर्व प्राथमिक शिक्षक और प्रशिक्षण वर्ष 2010 के अंदर बंद कर दिया गया। 2012 के अंदर 500 पदों की भर्ती निकाली गयी और 2012 में जो 500 पदों की भर्ती निकली उसकी एवज में 4500 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। 2013 के अंदर 500 पदों की फिर भर्ती निकली, उसके अंदर 5512 पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त हुए। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के आने के बाद में एक हजार पदों की भर्ती हुई, उसके बाद में जब 2010 के अंदर यह प्रशिक्षण बंद किया गया, उस समय सिर्फ पूरे राजस्थान में 2700 विद्यार्थी ही ऐसे थे जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा था लेकिन जब 2018 के अंदर वैकेंसी आयी तो 2018 की वैकेंसी के अंदर 24 हजार आवेदन प्राप्त हुए और 2018 की वैकेंसी में 24 हजार आवेदन प्राप्त होने के बाद में सिर्फ 17 हजार विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल हो गये, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत जब परिणाम जारी किया गया, 24 फरवरी, 2019 को यह परीक्षा हुई, 31 जुलाई, 2019 को यह परिणाम जारी हो गया। 31 जुलाई, 2019 को अधीनस्थ बोर्ड ने यह परिणाम जारी किया। परिणाम के बाद में जब भौतिक सत्यापन के लिए डाकूमेंट्स मंगवाये गये तो उसके बाद में सिर्फ 450

(श्री रामलाल शर्मा)

विद्यार्थी ही ऐसे पाये गये जो उस परीक्षा के अंदर योग्य थे, बाकी के जो दस्तावेज पाये गये, वह फर्जी पाये गये। अंक-तालिकाएं फर्जी पाई गईं, डिग्री फर्जी पाई गई तो मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि 450 की भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में 550 पद अभी भी रिक्त हैं। क्या अधीनस्थ बोर्ड शेष जो विद्यार्थी रहे हैं, जिनकी अंक-तालिका सही है, ईमानदारी के साथ परीक्षा दी है, क्या उन 550 पदों के ऊपर भर्ती करने की मंशा रखते हैं? जो दूसरे राज्यों से यह फर्जी डिग्री लेकर आये हैं, ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ, जो फर्जी अंक-तालिकाएं लेकर आये, फर्जी डिग्री लेकर आये, उनके खिलाफ क्या आप एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की मंशा रखते हैं? ताकि न्याय मिल सके। राजस्थान के रहने वाले जो विद्यार्थी कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कम से कम उनको जल्द ही 550 पदों की जो भी आपकी मैरिट है, उस मैरिट के अंदर संशोधन जारी करके इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनियां।

पंजाब द्वारा इंदिरा गांधी नहर में कम पानी छोड़े जाने से किसानों को परेशानी

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आई.जी.एन.पी. और भाखड़ा के अंदर काश्तकारों की प्रथम वरीयता की पारियां पिट गईं। आगे कुआं और पीछे खाई। आगे 70 दिनों की बंदी 6 मार्च से आ रही है और वर्तमान के अंदर जो फसल है, वह तबाह होने के कगार पर है। सरकार और सरकार के इंजीनियर आंख मींचकर बैठे रहे। सरहिंद फीडर और आई.जी.एन.पी. के बीच का पटड़ा जो है, वह टूट गया और टूटने का कारण भी बताऊंगा। पहले पंजाब ने अपना हित साधने के लिए सरहिंद फीडर के अंदर बंदी थी तो सरहिंद फीडर का पानी राजस्थान कैनाल में कट करके पटड़े में सीधा पानी डालकर आर.डी. 380 से निकालकर सरहिंद फीडर में लिया। उसी जगह पर यह नहर टूटी है और अब 20 फरवरी, 2021 तक सरहिंद फीडर की बंदी है और राजस्थान कैनाल में 5146 क्यूसेक्स के लगभग पानी चल रहा है। इससे सारी नहर पिट रही है,

(श्री रामप्रताप कासनियां)

भाखड़ा, आई.जी.एन.पी. और सरकार ने जल्दी से पानी बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, अगर आप पंजाब की तरफ हाथ ही जोड़ते रहोगे, आपकी सरकार है पंजाब में, वहां पर दबाव डालकर पानी पूरा चलाओ। 7 हजार क्यूसेक्स के लगभग पाकिस्तान में पानी जा रहा है, हमारा पानी बर्बाद हो रहा है। सरकार इस पर समय रहते अपना ध्यान दे नहीं तो काश्तकार बर्बाद हो जाएंगे और मैं आपको यह चेतावनी देना चाहता हूं, लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तब जाकर आपकी आंख खुलेगी और इस विधान सभा के अंदर कोई भी बात उठाओ तो कोई अहमियत नहीं है। सरकार सोए हुए रहती है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): कितना ही ज्वलंत विषय हो, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं समय रहते हुए सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पानी बढ़ाने की कार्यवाही करें अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों का नाम जोड़ने वाली साइट को लॉक कर दिया जाना

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई और उस पर गरीबी, सरकार ने ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने का प्रावधान कर रखा है और उसमें कई सारी पात्रताएं भी तय कर रखी हैं परंतु जो पात्र परिवार हैं, प्रक्रिया क्या है कि अपनी पात्रता के दस्तावेज के साथ वह एस.डी.एम. कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करे और बाद में एस.डी.एम. कार्यालय से जांच होती है। जांच में उसकी पात्रता सही पाई जाती है तो एस.डी.एम. उसको ओ.के. करता है, पर ओ.के. करने के साथ ही उसका नाम जुड़ नहीं जाता है। जो जयपुर स्थित मुख्यालय की वेबसाइट है, वहां पर वह नाम जाता है और वहां पर जब ओ.के. होता है तब कहीं जाकर खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट में उसका नाम जुड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पर बड़ी विडंबना है, कोरोना के चलते एक तरफ तो रोजगार का संकट है, लोगों को आवश्यकता है कि सरकार मदद करे। आठ महीने हो गये, आठ महीने, जयपुर स्थित जो वेबसाइट है, उसको सरकार

(श्री ज्ञानचंद पारख)

ने लॉक कर दिया और जो पात्र व्यक्ति भी हैं, जिसने सारे दस्तावेज लगा रखे हैं, उसकी जांच हो रखी है, पर जयपुर से सिस्टम लॉक कर देने की वजह से उस व्यक्ति को आठ महीने से इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विडंबना यह भी है कि इसकी सीमा निर्धारित कर रखी है कि शहरी क्षेत्र में 53.04 परसेंट लोग ही जुड़ सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 परसेंट व्यक्ति। अब अनेक स्थानों पर यह हुआ कि यह सीमा पूरी हो गयी, पर सीमा पूरी होने के बाद भी सरकार ने जो पात्रताएं तय कर रखी हैं, ऐसे हजारों परिवार एक जिले में आपको मिल जाएंगे, तो मेरा सरकार से यह आग्रह है कि जिस प्रकार से आपने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपनी ओर से एक कदम आगे बढ़कर जो परिवार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए थे, उनके सारे के सारे नाम जोड़कर उन लोगों को भी राहत देने का काम किया या आप करोगे कि जो पहले राहत या सहयोग पा रहे थे, तो इसमें भी मेरा यह आग्रह है कि अगर भारत सरकार की सीमा आपकी 53.04 और 69.09 है तो राज्य सरकार ऐसे पात्र परिवार, उनको अपने मद से दो रुपये किलो गेहूं और फ्री इलाज की सुविधा कर देंगे तो अनेकों पात्र परिवार इस योजना में लाभान्वित हो जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी आपसे आग्रह रहेगा कि यह जो गेहूं वाला सिस्टम है न, इसमें एक गरीब के बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा। अगर पांच परिवार की यूनिट है और खाद्य सुरक्षा योजना में उसका नाम जुड़ जाता है तो 25 किलो गेहूं उसको प्रति माह मिलता है 50 रुपये में और मार्केट में यदि वह 25 किलो गेहूं लेता है तो लगभग 500 रुपये से भी ज्यादा रुपये उसके खर्च होते हैं और साथ में इलाज की भी लंबी राशि उसके लगती है तो राज्य सरकार ऐसे पात्र परिवार जहां सीमा आपकी पूरी हो गई, जब बजट हो न तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा यह आग्रह रहेगा कि पात्र परिवार तो कम से कम, चाहे इस राज्य सरकार की मद से भी जोड़ने पड़े तो जोड़कर उनको खाद्य सुरक्षा योजना में मिलने वाले लाभ दिलवा दें, यह मेरा सरकार से आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

खैराबाद पंचायत समिति क्षेत्र में निर्माणाधीन ताकली बांध के डूब क्षेत्र के किसानों को जमीन के मुआवजे का भुगतान

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें करंट आ गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। कोटा जिले की रामगंज मण्डी क्षेत्र में ताकली बांध के नाम से एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 51 करोड़ 81 लाख रुपये की 09.07.2006 को हुई थी। अब इसकी जो संशोधित स्वीकृति हुई है 14.12.2016 को, वह 285 करोड़ 73 लाख रुपये की हुई है यानी लगभग 235 करोड़ रुपये इसकी राशि बढ़ गयी है समय पर काम नहीं करने से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके 2007 में कार्यादेश प्राप्त हुए थे और 2010 में इनको पूरा होना था परन्तु सरकार की लापरवाही के कारण से और किसानों को मुआवजा नहीं देने के कारण से यह राशि निरन्तर बढ़ रही है। इस बांध की जो भराव क्षमता थी, 33.74 मिलियन घनमीटर है और इस पर अभी तक 168 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। किसानों को जो मुआवजा देना है, वह केवल 21 करोड़ रुपये देना है। 21 करोड़ रुपये नहीं देने की वजह से सरकार 235 करोड़ रुपये घाटा खा सकती है, लेकिन गरीब किसान को 21 करोड़ रुपये नहीं देना चाहती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, किसानों को यह कहकर पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा कि उनके मकान है, वह आबंटित नहीं हैं। उस भूखंड पर उनका अधिकार नहीं है, जबकि यह जो गांव बसे हुए हैं, यह लगभग 200-300 साल पुराने गांव हैं। यह बहुत पुराने गांव हैं और इनकी पुश्तैनी जमीन है। इनके ऊपर पट्टे देने का प्रावधान था, लेकिन गांव के लोगों को पट्टे नहीं दिये गये और जब इनकी डूब क्षेत्र में जमीन गयी तो यह कहा जा रहा है कि आपका इसके ऊपर अधिकार नहीं है। यह आप अतिक्रमण में हैं, इसलिए इसके लिये आपको मुआवजा नहीं दिया जा सकता। फिर भी बीच में प्रशासन ने नेगोसिएशन करके 21 करोड़ रुपया तय किया। वित्त विभाग ने इसको स्वीकृति दे दी है कि यह पैसा इनको देना है, लेकिन कई वर्षों से अटका हुआ है और इसलिए अटका हुआ है क्योंकि मंत्रिमण्डल में उसको रखकर अनुमोदन नहीं लिया गया है। क्या मंत्रिमण्डल की निरन्तर बैठकें नहीं

(श्री मदन दिलावर)

हो रही हैं? मंत्रिमण्डल की बैठकें निरन्तर हो रही हैं, लेकिन किसानों की हितैषी सरकार किसानों को 21 करोड़ रुपये नहीं देना चाहती। 235 करोड़ रुपये उसकी लागत बढ़ जाए, वह तो दे सकती है और 168 करोड़ भी खर्च हो गये हैं, वह ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। किसान उस काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वह इसलिए आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं क्योंकि उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं मंत्रिमण्डल उसको अनुमोदित करे और किसानों को मुआवजा दे और जो उन्होंने कहा कि आपका यह पुश्तैनी मकान है, इसका पट्टा आपके पास नहीं है, इसलिए आपको मुआवजा नहीं दिया जा सकता, उसको भी उसका अधिकार मानकर, उसका मालिकाना हक मानकर उनको मुआवजा देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

नागौर के मूंडवा में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट के लिये भू-रूपान्तरण में अनियमितता

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये हार्दिक धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि मूंडवा में स्थापित हो रहे अम्बुजा सीमेंट प्लांट के लिये कम्पनी ने गलत तथ्य पेश करके औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण करवाया और पर्यावरण स्वीकृति भी प्राप्त की है। सबसे पहले इस उद्योग को 12.12.1986 को जब जमीन का आबंटन किया तो इसके अंदर जिला कलेक्टर, नागौर ने शासन सचिव उद्योग (ग्रुप-1) को लिखा कि उद्योग के लिये प्रस्तावित भूमि व कस्बा मूंडवा की आबादी से चार किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने यह स्वीकृति दी, लेकिन विडम्बना की बात यह है कि आज नगरपालिका क्षेत्र के अंदर, बिलकुल नगरपालिका क्षेत्र से सटकर अम्बुजा का बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि वर्ष 2010 में अम्बुजा सीमेंट ने पर्यावरण रिपोर्ट किसी एजेंसी से बनवायी, जिसमें पृष्ठ संख्या-2 पर मूंडवा शहर जिसकी आबादी लगभग 23 हजार है, से दो किलोमीटर उत्तर में 45 लाख टन प्रतिवर्ष सीमेंट उत्पादन की क्षमता वाले कारखाने व 50 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट की योजना प्रस्तुत की। कम्पनी अपने प्लांट को मूंडवा से दो किलोमीटर दूर बता रही है, जबकि मूंडवा शहर के अंदर है।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन जरूर करूंगा कि पर्यावरण विभाग के एनवायर्नमेंट सीटिंग फोर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रूल्स, 1999 के नियमानुसार नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी सीमेंट का प्लांट नहीं लग सकता, लेकिन नगरपालिका कार्यालय के बिलकुल सामने मूंडवा शहर की आबादी में ही यह प्लांट लग रहा है। इसके अलावा इस प्लांट की दीवार से सटे सात नाड़ी-तालाब, इन्होंने लिखा है कि आस-पास कोई कैचमेंट एरिया, नाड़ी-तालाब नहीं हैं, जबकि मूंडवा इतिहास के अंदर सबसे बड़े तालाबों के क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इसके अंदर सात बड़े तालाब और कोर जोन के तीन किलोमीटर में 17 बड़े बारहमासी तालाब स्थित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यहां इन्होंने यह लिखा है कि 500 मीटर की दूरी हाईवे और रेलवे ट्रैक से होनी चाहिए किसी भी बड़े उद्योग में, लेकिन उस उद्योग के एक तरफ रेलवे का ट्रैक है और दूसरी तरफ हाईवे है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाकर जिन दोषी अधिकारियों ने पर्यावरण की गलत स्वीकृति दी या जो भूमि का गलत आबंटन किया, उनके खिलाफ कार्यवाही करके इस कार्य को तुरन्त रोका जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

जन-प्रतिनिधियों से फिरौती मांगने की बढ़ रहीं आपराधिक गतिविधियां

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक इस प्रकार का दर्द बयां कर रहा हूं सदन में, जिसके रूबरू माननीय सदस्य, जो सदन में बैठे हैं, कभी भी हो सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा हट नहीं जाए, दुर्घटना हो नहीं जाए और इसी कारण से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 194 में सदन में जो चुनकर आते हैं, उनको विशेषाधिकार भी दिया गया है ताकि वह निर्भीक और निर्बाध रूप से अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम करीब पांच लाख का प्रतिनिधित्व करते हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष हमेशा रहते हैं। सब संतुष्ट भी नहीं रहते। भगवान राम के समय में भी सीताजी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की, आपके सामने जब मैं और अलवर से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आने वाले माननीय सदस्य और मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य एक दहशतगर्दी के अंदर और एक आशंका को लेकर आये और अध्यक्ष महोदय, आशंका तब पनपती है जब वातावरण इस प्रकार का बनता है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को रात को ढाई बजे जब प्रशासन उठाकर कहता है कि कोई अनजान व्यक्ति ने सर्किट हाउस में, जहां वह रूके हुए थे 103 नंबर के कमरे में, कहा कि आपकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। क्या कारण है, आपकी किससे दुश्मनी है? इस पर नींद हराम होना वाजिब-सी बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आशंका इसलिए निर्मूल नहीं है कि मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य को बहुचर्चित टाइगर गैंग के युवराज ने व्हाट्सअप पर 20 लाख की धमकी दी। एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई, मंत्री महोदय, 181/2020 नीमराणा के अंदर और अपराधी इसी अपराध में गिरफ्तार भी हुआ। पर चिंता जब बढ़ जाती है जब ढाई महीने बाद वह कुख्यात अपराधी, जो अभी नौजवान है, बाल अपराधी कह सकता हूं मैं उसको, वह पुलिस की हिरासत से उसी प्रकार फरार हो जाता है जिस प्रकार अलवर के बहरोड़ से पपला फरार हुआ और उसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात यहीं नहीं टूटती, सोशल मीडिया पर वह अपराधी फिर सक्रिय हो जाता है और मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य के घर में एक बार फिर अनजान लोग आकर रैकी करते हैं। घबराये हुए माननीय सदस्य डी.जी. को टेलीफोन करते हैं। इस प्रकार की बात हमारे सामने है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिण्डौन से आने वाले माननीय सदस्य पर जनसभा में पिस्टल से फायर हुआ। वह मिस-फायर हो गया, बच गये, अच्छी बात है। कुशलगढ़ से आने वाली माननीय सदस्य पर जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा रही थीं, उनकी कार को साइड लेकर छोटी-सी बात पर उनकी सारी कार तोड़ दी गयी। आर.एल.पी. के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल और केन्द्रीय मंत्री पर हमला हो गया। बहरोड़ में हमारे भाजपा के प्रत्याशी पर हमला हो जाए, तारानगर में हो जाए, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अगर हम अभी भी सुरक्षित नहीं हैं, मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य के घर पर 26 जनवरी को बदमाशों ने रैकी करनी प्रारम्भ की और वहां की फोटो खींचना चालू किया तो इन्होंने डी.जी. को सूचना दी। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजगढ़ से आने वाली माननीय सदस्य को सरकार ने जेड कैटेगरी दी है, मैं स्वागत करता हूं मुझे कोई एतराज नहीं है। विष्णु विश्नोई फांसी पर लटक गया, आपने जेड कैटेगरी दे दी, पर इस प्रकार के प्रकरण हैं, उन पर विचार करें। इंटेलीजेंस से उनकी रिपोर्ट लें। अगर सदन में आने वाले माननीय सदस्य अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करते तो क्या होगा? यातायात मंत्रीजी, आपकी तो बात ही क्या करूं। आपकी मौसीजी के यहां अशोक नगर थाने के अंदर चोरी हुई। दो बार चोरी हुई। हुई कि नहीं हुई आपकी मौसी के घर चोरी नहीं हुई? इसी 8 तारीख को आपकी मौसी नन्नी काटजू, राहुल जी की मौसी आपकी मौसी नहीं है? नन्नी काटजू, नरेश काटजू के घर चोरी होती है, दो बार लगातार चोरी होती है और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होती। इतने उच्च पदस्थ लोगों के, राहुल जी की मौसी के चोरी हो जाए और, गृह मंत्रीजी, मैं शिकायत करूंगा जाकर राहुल जी को, आप उनकी मौसी को सुरक्षा नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कहां से कहां जा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें आपके संरक्षण की जरूरत है। दहशतगर्दी के अंदर मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, यह देखो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को आप देखिए, किस प्रकार कांप रहे हैं। इसलिए आप सुरक्षा प्रदान कराएं, यही मेरा निवेदन है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख की देर रात को, जैसाकि अख़बार में आपने सबने पढ़ा है, वह व्यक्ति तीन टायर पर गाड़ी चलाकर भागा है और कह रहे हैं कि वह नाहरगढ़ गया, नाहरगढ़ से हरमाड़ा क्यों गया? हरमाड़ा से फिर 70 किलोमीटर चलकर गया। 13 थानों की पुलिस उसका पीछा कर रही है। वह खासाकोठी पहुंचता है। वहां पर और माननीय सदस्यों की गाड़ियां भी खड़ी थीं और अधिकारियों की गाड़ी खड़ी थीं, मेरी गाड़ी पर आकर प्रहार करना, निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र उस व्यक्ति के माध्यम से किया जा रहा था। इसके साथ-साथ जो अलवर-किशनगढ़ नगरपालिका है, वहां के चेयरमैन के पुत्रों पर प्राणघातक हमले हुए। वहां पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। अलवर जिले का जन-प्रतिनिधि वाकई बहुत भय की स्थिति में है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप हमें संरक्षण प्रदान करें, आप हमें सुरक्षा

(श्री संजय शर्मा)

प्रदान करें। आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: सरकार इस पर ध्यान दे। श्री बलवीर लूथरा।

रायसिंहनगर के ठण्डी-ठाकरी, एनपी क्षेत्र के किसानों द्वारा खातेदारी की मांग

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ठण्डी-ठाकरी, एनपी क्षेत्र के गांवों के किसान पिछले 15 दिनों से एस.डी.एम. रायसिंहनगर के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। वे अपनी कृषि भूमि की खातेदारी देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। जिला कलेक्टर, गंगानगर द्वारा वर्ष 2008 में इनको भूमि का आबंटन किया गया था और इन्होंने एकमुश्त इनकी किश्तें भी जमा करवा दीं। कृषि भूमि देने के कारण भूमि आबंटन के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी याचिका बार-बार लगाकर बाधा उत्पन्न कर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसानों के पक्ष में 2010 में अपील अजमेर राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त भी कर दी गई। उसके बाद दूसरी याचिका अजमेर राजस्व मण्डल में दोबारा निरस्त कर दी गई। तीसरी निगरानी याचिका भी अजमेर राजस्व मण्डल द्वारा खारिज कर दी गई। सरकार द्वारा अब पुन: निगरानी याचिका के आदेश सरकार द्वारा दिये गये हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस याचिका को गैर-जरूरी मानते हुए पीड़ित किसानों को उनकी कृषि भूमि की खातेदारी देकर उनको राहत प्रदान करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री अविनाश (अनुपस्थित)। श्री महेन्द्र विश्नोई (अनुपस्थित)। श्री राजकुमार रोत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सीमलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र चौरासी के राजकीय महाविद्यालय, सीमलवाड़ा में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरासी, डूंगरपुर जिले में राजकीय महाविद्यालय सीमलवाड़ा, जो वर्ष 2016 में स्वीकृत हुआ है और यह महाविद्यालय वर्तमान में दो कमरे में चल रहा है, जिससे विद्यार्थियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर व्याख्याताओं के पद भी रिक्त हैं। इस सम्बन्ध में कई बार सरकार को अवगत कराया है परन्तु अभी तक इसकी मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है।

चौरासी विधान सभा क्षेत्र का यह एक मात्र राजकीय महाविद्यालय है और अभी तक इसका भवन स्वीकृत नहीं हुआ है। क्या यह निजीकरण को बढ़ावा नहीं है? इस क्षेत्र के विद्यार्थी निजी महाविद्यालय में अध्ययन करने को विवश हैं और कई विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से अध्ययन करना छोड़कर गुजरात मजदूरी पर जाने को मजबूर हैं।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राजकीय महाविद्यालय सीमलवाड़ा में भवन की स्वीकृति प्रदान करके विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री किसनाराम विश्नोई।

राज्य पशु ऊंट के पालन में आ रही समस्याएं

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान के ऊंट को राज्य पशु घोषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर रखा है परन्तु निम्न बिंदुओं पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय पशुपालन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा-

(श्री किसनाराम विश्नोई)

1. आज के मशीनरी युग में ऊंट की उपयोगिता नाम मात्र की रह गई है।

2. राज्य पशु घोषित होने से घायल ऊंट का मालिक कानूनी कार्यवाही के भय से अपना मानने से भी मना कर देता है।

3. बार-बार अकाल पड़ने पर इसको पालना भी मुश्किल है इसलिए इसको खुला छोड़ना पड़ता है और वह भटकता रहता है।

4. ऊंट के पैरों में गम्भीर घाव या छोटा घाव उपचार के अभाव में घाव बड़ा हो जाता है, जिससे ऊंट धीरे-धीरे तड़प कर मरता है एवं एक्सीडेंट के बाद तो बहुत ज्यादा तड़पता है, जिससे ऊंट पालक नजदीक भी नहीं आते हैं।

5. ऊंट के खरीदने एवं बेचने से भी रोक हटायी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसका दूध हो या पनीर व चाकलेट हो या रसगुल्ले, यह मात्र कागजों या बीकानेर तक ही सीमित है। इसके पोषण के लिए खर्चा अधिक, कोई उपयोगिता नहीं होना और राज्य पशु घोषित करना उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इसको राज्य पशु से हटाया जाए तो उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में संचालित योजना है वह ऊंट पालने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अलग से ब्रीडिंग सेन्टर, ऊंट पालकों के लिए प्रोत्साहन हेतु योजनाएं लागू करें ताकि ऊंट पालक इसको चाहत से पालें तथा इनकी जनसंख्या जो धीरे-धीरे घट रही है, वह भी बढ़े। दुग्ध उत्पादन का बाजार जो सीमित है, उसे भी योजना बनाकर विस्तारित किया जाए। ऊंट पालन पर ऊंट पालकों को प्रोत्साहन दिया जाए। पशु मेलों की अलग से योजना बनाई जाए, मात्र रेस करने से ऊंट पालक प्रोत्साहित नहीं होंगे।

अत: माननीय मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

मुण्डावर, नीमराणा, बानसूर, बहरोड़ को नवसृजित एडीएम कार्यालय भिवाड़ी के अधीन करने से कारित परेशानी

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मुण्डावर, नीमराणा, बानसूर, बहरोड़ के एडीएम कार्यालय भिवाड़ी से वापस एडीएम कार्यालय, अलवर के अधीन करने या नीमराणा व किसी उचित स्थान पर एडीएम कार्यालय खोलने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हाल ही में नवसृजित एडीएम कार्यालय भिवाड़ी के अधीन मुण्डावर, नीमराणा, बानसूर, बहरोड़ को जोड़ा गया है। बिना भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी के ही भिवाड़ी एडीएम कार्यालय खोला गया है, जिससे आमजन के साथ विश्वासघात हुआ है क्योंकि मुण्डावर, नीमराणा, बानसूर, बहरोड़ से भिवाड़ी के लिए आवागमन के कोई भी सीधे साधन उपलब्ध नहीं हैं तथा यहां से भिवाड़ी की दूरी भी अत्यधिक है। जैसे कि मुण्डावर से भिवाड़ी की दूरी 60 से 100 किलोमीटर, नीमराणा से भिवाड़ी की दूरी 60 से 80 किलोमीटर, बहरोड़ से भिवाड़ी की दूरी 70 से 100 किलोमीटर और बानसूर से भिवाड़ी की दूरी 120 से 150 किलोमीटर है और इन सब उपखण्ड क्षेत्रों की अलवर व नीमराणा से दूरी बहुत कम है व अलवर के लिए सीधे आवागमन के साधन भी उपलब्ध हैं। भिवाड़ी हरियाणा के बोर्डर पर है तथा अन्य कार्यालय, जैसे जिला परिषद्, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी आदि कार्यालय अलवर में हैं, जिससे क्षेत्र की जनता को केवल एडीएम कार्यालय के लिए भिवाड़ी जाना पड़ेगा व अन्य कार्यों के लिए उसे अलवर आना पड़ेगा, जिससे काश्तकारों व क्षेत्रवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा व उनके समय एवं धन, दोनों की हानि होगी।

अत: माननीय से निवेदन है कि एडीएम कार्यालय भिवाड़ी से मुण्डावर, नीमराणा, बानसूर, बहरोड़ को वापस एडीएम कार्यालय, अलवर के अधीन किया जाए या फिर नीमराणा व किसी उचित स्थान पर एडीएम कार्यालय खोला जाए जिससे आमजन को परेशानियां नहीं झेलनी पड़े। सरकार यह कार्य कर मुझे व जनता को अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल।

कनिष्ठ सहायकों (एलडीसी), पटवारी व पुलिस कान्स्टेबल की ग्रेड-पे 2400 से 3600 की वृद्धि की मांग

श्री बिहारीलाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के

(श्री बिहारीलाल)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना में बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कनिष्ठ सहायकों (एलडीसी), पटवारी व पुलिस कान्स्टेबल द्वारा लम्बे समय से ग्रेड-पे 2400 से बढ़ाकर 3600 करने की मांग की जा रही है। प्रदेश में प्रशासन के प्रमुख आधार पर रूप में कार्य करने वाले कनिष्ठ सहायकों (एलडीसी) को अल्प वेतन (ग्रेड-पे 2400) पर कार्य करना पड़ रहा है। मंत्रालयिक कर्मचारी पिछले काफी वर्षों से इस अल्प वेतन को बढ़ाकर ग्रेड-पे 3600 करने की मांग कर रहे हैं। विधान सभा चुनाव 2018 से पूर्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने प्रदेश स्तर पर आन्दोलन करते हुए मानसरोवर में शिप्रा पथ पर हजारों मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ लगातार एक महीने तक धरना-प्रदर्शन किया।

महोदय, पटवारी जो सबसे ज्यादा ग्रामीण व कृषि क्षेत्र में लगभग 18 घंटे कार्य करते हैं तथा एक-एक पटवारी दो-दो, तीन-तीन पटवार सर्कल का कार्य करता है, जबकि इनका ग्रेड-पे 2400 है, जो बहुत कम है। कोरोना काल में भी इनका कार्य सराहनीय रहा है। काफी वर्षों से इस अल्प वेतन को बढ़ा कर ग्रेड-पे 3600 करने की मांग कर रहे हैं।

इसके अलावा पुलिस कान्स्टेबल, जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और इनका ग्रेड-पे भी मात्र 2400 है, पुलिस कान्स्टेबल ने कोरोना काल के दौरान लाकडाउन में जो शानदार कार्य किया वह किसी से छिपा नहीं है।

वर्तमान में मंत्रालयिक कर्मचारी, पटवारी व कान्स्टेबल सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक आदि) के माध्यम से लगातार ग्रेड-पे 2400 से बढ़ाकर 3600 करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के कई विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों द्वारा भी इस मांग को जायज मानते हुए उनके समर्थन में राज्य सरकार को पत्र भी लिखे गये हैं। प्रदेश में कनिष्ठ सहायकों (एलडीसी), पटवारी व पुलिस कान्स्टेबल द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग को मानते हुए ग्रेडपे 2400 से बढ़ाकर 3600 करने की कृपा कराएं।

अत: उपरोक्त लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह।

पंचायती राज एल.डी.सी. भर्ती, 2013

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से पंचायती राज एल.डी.सी. भर्ती, 2013 के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पंचायती राज एल.डी.सी. भर्ती 2013 में लगभग 19,200 पदों पर एल.डी.सी. भर्ती निकाली गई थी किन्तु कुछ त्रुटिपूर्ण नियमों के कारण लगभग 10 हजार पदों पर आज दिनांक तक भर्ती पूर्ण नहीं हो सकी है। सरकार द्वारा अभी हाल ही में लोक सभा चुनावों के पूर्व भर्ती का कैलेन्डर जारी किया गया था किन्तु लोक सभा चुनावों में आचार संहिता के चलते वह समय रहते पूर्ण नहीं किया जा सका। जिसके पश्चात सरकार द्वारा निकाले गये भर्ती कैलेन्डर निरस्त कर पुन: भर्ती का नवीन कैलेन्डर जारी करने का आदेश जारी किया गया, जो कि आज दिनांक तक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। अत: मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द नवीन भर्ती कैलेन्डर जारी कर विज्ञापित सम्पूर्ण पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में निवेदन है कि पशुपालन विभाग में कार्यरत पशुधन सहायकों की ग्रेड-पे उनके समकक्ष अन्य चिकित्सा विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों की तरह बराबर की जाए जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता को कारण बताकर कम ग्रेड-पे इन्हें दिया जा रहा है जबकि इन्हें पशुओं के इलाज के समय अन्य के मुकाबले अधिक खतरा उठाना पड़ता है।

अत: इन विसंगतियों को दूर कर इन्हें भी समकक्ष के बराबर ही ग्रेड-पे व अन्य परिलाभ दिलवाए जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर शहर में एलीवेटेड रोड के निर्माण कार्य को गति

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि अजमेर शहर की यातायात समस्या के समाधान के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में सर्वाधिक यातायात दबाव वाले मार्गों पर एलीवेटेड रोड का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया। इसके लिए 220 करोड़

(श्री वासुदेव देवनानी)

रुपये का बजट स्वीकृत किया गया व दिनांक 09.05.2018 को निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। निर्माण कार्य को प्रारम्भ हुए आज पौने तीन साल हो चुके हैं परंतु कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि आगामी एक वर्ष में भी इसके पूर्ण होने की संभावना दिखाई नहीं देती जबकि सरकार ने 30 जून, 2021 तक कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित कर रखी है। उक्त एलीवेटेड रोड का निर्माण अजमेर के स्टेशन रोड, कचहरी रोड व पृथ्वीराज मार्ग पर कराया जा रहा है जो कि शहर के मध्य से गुजरते हैं। इन मार्गों पर यातायात के भारी दबाव के साथ ही सघन व्यापारिक संस्थान भी स्थित हैं। लंबे समय से एलीवेटेड रोड का निर्माण कार्य चलने से क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं तथा मार्ग हमेशा अवरुद्ध व डाइवर्ट रहने, धूल-मिट्टी उड़ते रहने से क्षेत्रवासियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

स्मार्ट सिटी योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरों में ऐसे नवनिर्माण कराना जिनसे नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, लेकिन अत्यंत ही धीमी गति से चल रहे एलीवेटेड रोड के निर्माण कार्य से अजमेरवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि अजमेर में निर्माणाधीन एलीवेटेड रोड के कार्य को गति प्रदान कराने के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं, जिससे निर्धारित तिथि 30 जून, 2021 तक कार्य पूर्ण हो सके तथा क्षेत्रवासियों व व्यापारियों को हो रही असुविधाओं से राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम कोली।

आबू रोड के गांधी नगर स्थित फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर की नगरपालिका आबू रोड के गांधी नगर स्थित 132 समपार फाटक से सुगम यातायात हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति से निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के लिए अवाप्त भूमि का आंशिक बकाया भुगतान संबंधित भू-मालिक को नहीं किये जाने से ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पिछले 4 वर्षों से लंबित चल रहा है।

(श्री जगसी राम)

इस प्रकरण में सिरोही महाराजा श्री रघुवीर सिंह जी की एक बीघा भूमि को उक्त ओवर ब्रिज हेतु अवाप्त करते हुए नियमानुसार राशि रुपये 8 करोड़ 85 लाख 82 हजार 202 देय मुआवजा राशि में से आबू रोड नगरपालिका ने 3 करोड़ 95 लाख 45 हजार 626 रुपये आंशिक भुगतान के रूप में कार्यालय उपखंड अधिकारी आबू रोड में जमा करा दिये हैं। शेष राशि के भुगतान की एवज में नगरपालिका के पास समतुल्य भूमि भी उपलब्ध नहीं है। नगरपालिका आबू रोड उक्त आंशिक मुआवजा राशि जमा कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे हालात में पिछले 4 वर्षों से विशेष लोक महत्व का उक्त ओवर ब्रिज का स्वीकृत शुदा कार्य लंबित पड़ा हुआ है। आम जन को आए दिन हो रही परेशानियों को देखते हुए 60 प्रतिशत निर्माणाधीन उक्त अधूरे ओवर ब्रिज का निर्माण पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है।

अत: सरकार से आग्रह है कि प्रकरण में बकाया अवाप्त राशि के भुगतान की व्यवस्था करते हुए आबू रोड के गांधी नगर के समपार फाटक 132 पर स्वीकृत ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाकर आमजन को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा की घनी आबादी वाले क्षेत्रों की हाई टेंशन लाइनों का स्थानान्तरण

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से 11 के.वी., 33 के.वी. एवं 132 के.वी. की लाइनें मकानों के ऊपर से गुजर रही हैं। अनेकों बार इन लाइनों में शार्ट सर्किट, तार टूटने तथा हाईटेंशन लाइन होने के कारण घरों में करंट उतरने की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। करंट की इन घटनाओं में कई नागरिक झुलस चुके हैं तथा कई नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन घटनाओं से डरे सहमे लोग अपने मकान की छतों पर जाने से भी कतराते हैं और अपने बच्चों को भी छत पर जाने से रोकते हैं।

इन विद्युत लाइनों से घटित उक्त सभी घटनाओं की जानकारी विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों को है परंतु विभाग के अधिकारियों की

(श्री कन्हैया लाल)

लापरवाही के कारण उक्त लाइनों को घनी आबादी से अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्यवाही नहीं की गई है। कई बार लोगों द्वारा इन लाइनों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग को लेकर ज्ञापन व धरने दिये गये। लेकिन इसके बावजूद भी इन विद्युत लाइनों का स्थानांतरण नहीं किया गया। हर समय इन लाइनों में होने वाले शार्ट सर्किट एवं तार टूटने की घटनाओं का डर व भय सताता है।

अत: माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों सहित शहरी क्षेत्र के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजर रही इन विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानांतरित करने या भूमिगत करवाने की कृपा करें ताकि नागरिक निकट भविष्य में होने वाले हादसों से बच सकें और अपने आपको सुरक्षित एवं भयमुक्त महसूस कर सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

उच्चैन कस्बे में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के उच्चैन कस्बे में जहां पर तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति, नगरपालिका आदि बने हुए हैं लेकिन यहां के उद्यमी अपने व्यापार को करने के लिए भरतपुर जिला मुख्यालय या बयाना में उद्योग स्थापित करने को मजबूर हैं। यहां पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होना बेहद ही आवश्यक है, जिससे कि यहां के व्यापारियों को अपने ही क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का मौका मिल सके, साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। यहां के युवाओं को रोजगार के लिए अपने घरों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है।

हमारे यहां पर ग्राम गहलऊ में 127 बीघा सरकारी भूमि अनुपयोगी पड़ी हुई है, जो कि नवीन औद्योगिक क्षेत्र (रीको) विकसित करने के लिए पर्याप्त है। सरकार को किसानों की भूमि अधिग्रहित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अत: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त जनहित के मुद्दे को मध्यनजर रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के कस्बे उच्चैन में नवीन औद्योगिक क्षेत्र (रीको) खोलने की कृपा करें।

(12.47 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना के राजकीय विद्यालयों का क्रमोन्नयन

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा माना जाता है। वैसे तो यह मध्य प्रदेश के बार्डर पर स्थित है तथा राजस्थान का 200 नंबर का विधान सभा क्षेत्र है, इसके कारण से विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद हैं। उच्च शिक्षा के विद्यालय पंचायत स्तरों पर होने और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरियां अधिक होने की वजह से छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से मांग करता हूं कि मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिल सके और वह शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां (अनुपस्थित)। श्री रामप्रसाद।

लोडेश्वर बांध की नहर का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव, रिनोवेशन आफ आर.एम.सी. एंड एल.एम.सी. आफ लोडेश्वर माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि लोडेश्वर बांध का निर्माण 1960-70 के वर्षों में हुआ था। पिछले 7-8 वर्षों से इस नहर की भौतिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। रबी सीजन में बांध से नहर में छोड़ा गया पानी 60 से 70 प्रतिशत व्यर्थ बह जाता है। इस वजह से सिंचित भूमि के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्रफल में रबी सीजन में बोई जाने वाली गेहूं की फसल नष्ट हो जाती है। खेत में लगातार सीपेज होने से कृषि भूमि का उपजाऊपन खतम हो जाता है।

(श्री रामप्रसाद)

लोडेश्वर बांध की नहरें (LMC and RMC) 6.90 किलोमीटर एवं 12.27 किलोमीटर है, जिसके जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड मद से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 386 दिनांक 15.06.2018 को राशि रुपये 114.71 लाख की प्राप्त हुई थी, लेकिन नाबार्ड मद से राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त कार्य की निविदा को निरस्त कर दिया गया था, इसलिए कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाया।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस नहर का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करवाने हेतु विभागीय प्रस्ताव के अनुसार बजट पारित करवाकर उक्त कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं तथा वर्तमान में हुए नुकसान की भरपाई कराई जाए।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

पिलानी में पेयजल संकट

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण, पूरे क्षेत्र में पेयजल की भयंकर समस्या है और आने वाली ग्रीष्म ऋतु में यह समस्या और ज्यादा गंभीर व विकट हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिलानी, चिड़ावा व मण्डरेला तथा इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचल में, अर्थात सभी गांवों व ढाणियों में पेयजल का स्तर बहुत नीचे जा चुका है और पीने के पानी की गंभीर समस्या आज भी है और आगे भी और अधिक होने जा रही है।

मैंने विधान सभा के गत सत्र में इस ओर अनेक बार प्रश्नों व ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूरा प्रयास किया था कि राज्य सरकार का ध्यान इस समस्या के निराकरण की ओर प्राथमिकता से दिलाऊं, लेकिन कोई विशेष उपाय राज्य स्तर से नहीं हुआ है।

मैंने चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल तथा जल जीवन मिशन की योजनाओं के माध्यम से पिलानी विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्र को लाभान्वित करने हेतु निवेदन किया था परंतु अभी तक इन दोनों योजनाओं में भी कार्य चालू नहीं हुआ है। कृपया उक्त दोनों योजनाओं में भी प्राथमिकता से स्वीकृति जारी की जाए। साथ ही उपरोक्त वर्णित समस्त क्षेत्र के लिए तात्कालिक

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उपाय इस प्रकार किये जाएं कि पेयजल की जो गंभीर समस्या है और जो आने वाले महीनों में और अधिक विकट होने जा रही है, उस ओर तत्काल प्रभावी उपाय कर पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए एवं आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर अनुगृहीत करें।

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न 17 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.6(2)वित्त/कर/2019-252 दिनांक 04.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(2)वित्त/कर/2019-149 दिनांक 30.03.2020 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.2(31)वित्त/कर/2019-253 दिनांक 06.11.2020 जिसके द्वारा संकर्म संविदा पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी में कमी की गई है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-254 दिनांक 13.11.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा (7) के प्रावधानों को लागू करने की तिथि निर्धारित की गई है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-255 दिनांक 13.11.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-256 दिनांक 13.11.2020 जिसके द्वारा प्रपत्र GSTR-1 को प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को बढ़ाया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-257 दिनांक 13.11.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39(1) के अन्तर्गत व्यक्तियों के वर्ग को निर्धारित किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-258 दिनांक 13.11.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39(7) के अन्तर्गत प्रथम दो माह में कर देयता की 35% राशि का भुगतान करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-259 दिनांक 13.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-152 दिनांक 30.03.2020 में संशोधन किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-260 दिनांक 02.12.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-153 दिनांक 30.03.2020 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए देय शास्ति को माफ किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-261 दिनांक 10.12.2020 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9(A) के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट/ रियायत हेतु विशेष योजना लागू की गई है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-262 दिनांक 21.12.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-177 दिनांक 18.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-263 दिनांक 28.12.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 3 से 10 एवं 13 के प्रवर्तन को दिनांक 01.01.2021 से प्रभावी किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-264 दिनांक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

28.12.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-265 दिनांक 01.01.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-266 दिनांक 04.01.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-264 दिनांक 28.12.2020 के सम्बन्ध में शुद्धिपत्र जारी किया गया है;

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/2019-267 दिनांक 28.01.2021 जिसके द्वारा पैट्रोल एवं डीजल पर वैट की दर पुनर्निर्धारित की गई है; एवं

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.2(24)वित्त/कर/2019-268 दिनांक 09.02.2021 जिसके द्वारा लाडपुरा, कोटा की कोरल पार्क योजना की डीएलसी दरों को पुनरीक्षित किया गया है।

श्री सभापति: श्री बुलाकी दास कल्ला।

ऊर्जा विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि.आयोग /सचिव/विनियम-138 दिनांक 02 नवम्बर, 2020 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2020 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री बुलाकी दास कल्ला।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न 5 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 70वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2)के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 70वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग) (वर्ष 2019-20)

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104 के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन;

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019)

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019;

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(4) राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20; एवं

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(5) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, रूल 294 के तहत मैं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आज जो वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे रखे जा रहे हैं, उसके खण्ड 3 में अभी श्रम राज्य मंत्रीजी संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के वार्षिक लेखे रख रहे हैं। रखने का अधिकार है इनको, वर्ष 2017-18, आप मुलाहिजा फर्माएं, 2017-18, 2018-19 और 2019-20.

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, यह रूटीन का प्रोसीजर है, आपके समय भी ऐसा होता रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर होता रहा तो गलत होता रहा। अगर होता था तो गलत होता था, इसका मतलब सदन की गरिमा को देखें।

श्री सभापति: आप विराजें, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस सदन को तो पहले ही छोटा कर दिया इन्होंने।

श्री सभापति: विराजें। यह रूटीन का प्रोसीजर है, विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आज सदन के हालात देख लो, ट्रैजरी बैंचेज के हालात आप देख लो और उसके बाद...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) श्री टीकाराम जूली।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल, राजस्थान के प्रतिवेदन (वर्ष 2017-2018, 2018-2019 तथा 2019-2020)

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल, राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आप एक मिनट विराजिए। वैसे तो यह रूटीन का प्रोसीजर है, बाकी मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि वे समय पर रखें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री संयम लोढ़ा।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बात रखने का मौका दिया, आपका आभारी हूं। मैं माननीय मालव्यिा साहब की ओर से प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, जनता राज बदलती है तो इस बात के लिए बदलती है कि उनके जीवन में उत्थान होगा, उनकी पारिवारिक परिस्थितियों में बदलाव आएगा, उनको एक बेहतर जिंदगी मिलेगी और आप देखिये, माननीय सभापति महोदय, जब 2018 में राजस्थान की विधान सभा का चुनाव हुआ तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मत दिए ज्यादा सीटें दीं और राजस्थान की सरकार पर काबिज किया। लेकिन इसके ठीक चार-पांच महीने बाद दिल्ली की हुकूमत के लिए चुनाव हुआ तो उसी राजस्थान की जनता ने दिल्ली के लिए 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर भेजे। इसलिए भेजे कि दोनों ही सरकारें राजस्थान के आम अवाम के हित में काम करें।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का नीतिगत वक्तव्य है, जो कामकाज सरकार कर रही है, जो भविष्य में करने वाली है, उसका खाका इसके माध्यम से जनता के सामने रखती है। हमारा यह सौभाग्य है कि इस सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में ही ऐसे वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं जिन्होंने राजस्थान की जनता की सेवा में चार दशक से भी ज्यादा अपनी जिन्दगी का योगदान किया और राजस्थान की जनता यह उम्मीद करती है कि दोनों ही सरकारें प्रतिबद्धता से उनके हित में काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा, वीर राणा प्रताप की भूमि और वो हल्दीघाटी का युद्ध जहां अनेकानेक लोगों ने अपने प्राणों की आहूति दी, लेकिन नदी के इस किनारे खड़ी हुई मुगलों की सेना और दूसरी ओर खमनोर में खड़ी राणा प्रताप की सेना और राणा पूंजा के द्वारा वह लड़ी गई लड़ाई क्या 70 साल बाद भी उस खमनोर के आदिवासी को या उसके आसपास के इलाके के आदिवासी को सरकारी नौकरी में आने का वह अवसर मिल सका?

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, दोनों ही सरकारों के विचार करने का प्रश्न है कि हमने आदिवासी आरक्षण दिया, पहले जिले को यूनिट मानकर दिया कि 50 परसेंट से ज्यादा जिस जिले में आदिवासियों की आबादी होगी उसे हम आरक्षण देंगे, टीएसपी एरिया कहा, फिर तहसील को उसका पैमाना बनाया, फिर रेवेन्यू विलेज को उसका पैमाना बनाया पर यह एक ऐतिहासिक सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है कि एक बहुत बड़े इलाके का आदिवासी, जो उसी तरह की परिस्थिति रखता है, क्या वल्लभनगर का आदिवासी प्रतापगढ़ के आदिवासी से अलग है? क्या मावली का आदिवासी वहां के आदिवासी से अलग है, क्या खमनोर का आदिवासी वहां के आदिवासी से अलग है? क्या मारवाड़ का आदिवासी उस मेवाड़ के आदिवासी से अलग है?

(13.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा ने बड़ी संख्या में भीलों को जैसलमेर जिले में बसाया था। इसलिए बसाया था, क्योंकि वह एक योद्धा कौम है और अगर कभी लड़ने की जरूरत पड़ी तो वे लोग मौका पड़ने पर मुकाबला करने में सक्षम थे, लेकिन आज जैसलमेर के उस भील आदिवासी की क्या हालत है?

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश और देश की सरकार, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि सात दशक से जो ये आदिवासी वंचित हैं, उन्हें मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। भौगोलिक पेरीफेरी के आधार पर आप आदिवासी के आरक्षण का निर्णय मत करिए। आप सांस्कृतिक आधार पर करिये कि किस तरीके से सांस्कृतिक रूप से इस पूरे इलाके के लोग जुड़े हुए थे और कैसे उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है।

मुझे बहुत खेद है बहुत अफसोस है कि मारवाड़ का एक भी आदिवासी आज 70 साल के बाद भी सीधा आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस नहीं बन सका। क्या गुनाह है उनका? यह सब हमारा दोष है। हमने इस तरह के निर्णय लिये और हमने एक परिवार में जिसके सात-सात आईएएस हैं, उससे मुकाबला करने के लिए उस मावली और खमनोर के आदिवासी को छोड़ दिया। क्या वह उनका मुकाबला कर पाएगा? क्या वह उनसे मुकाबले के जरिये नौकरी हासिल कर सकेगा?

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, समय आ गया है। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी 25 सांसद दिये हैं और आज से बेहतर अवसर नहीं होगा कि जब अशोक गहलोत जैसे मुख्य मंत्री हैं, गुलाब चन्द कटारिया जी जैसे प्रतिपक्ष के नेता हैं और डा. सी.पी. जोशी जैसे विधान सभा के अध्यक्ष हैं। चाहे कांग्रेस का ही आदमी क्यों न हो, वह गुलाब चन्द जी कटारिया का नाम सम्मान से लेगा और चाहे बीजेपी का आदमी हो, वह अशोक गहलोत और डा. सी.पी. जोशी का नाम सम्मान से लेगा। ऐसा नेतृत्व हमारे पास है। इस सदी में हमें समाज के उस सबसे वंचित तबके के हित में सोचकर एक सर्वदलीय बैठक करके मारवाड़ और मेवाड़ के इन वंचित आदिवासियों के हित में कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए। मैं तो विनती करूंगा कि इन तीनों ही लोगों को, लोक सभा अध्यक्ष भी राजस्थान के ही हैं ओम बिरला साहब, उनके माध्यम से प्रधान मंत्री से मुलाकात करके नये दरवाजे, नये रास्ते हमारे उस वंचित तबके के लिए खोलने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बहुत उम्मीद से हमारे महबूब नेता राजीव गांधी ने सोचा था कि हम ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं को अधिकार देंगे। उन्हें संवैधानिक इकाई बनाने की सोच उन्होंने दी। उनके मौजूद रहते संवैधानिक अमेंडमेंट लाये गये, लेकिन राज्य सभा में तब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं देने से वे संशोधन पारित नहीं किये जा सके। बाद में, प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव के वक्त में 73वें और 74वें संशोधन के जरिये वे अमेंडमेंट किये गये और ग्राम पंचायत और नगरपालिका को संवैधानिक इकाई का दर्जा दिया गया। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे और वेंकैया नायडू ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री हुआ करते थे, दिल्ली में उन्होंने सम्मेलन बुलाया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया गया, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी भी उसमें सम्मिलित हुईं और यह तय किया गया कि निचले स्तर पर अधिकार दिये जाएं।

आज इतने साल के बाद भी क्या दशा है? हमने इस सदन में चर्चा की थी, यह तय किया था कि हम इन्हें फण्ड, फंक्शन, फंक्शनरीज देंगे, क्या हुआ? क्या हश्र है? क्या हमारी भर्तियों के हालात हैं? माननीय सभापति महोदय, सरकार इनकी हो या सरकार उनकी हो, आये दिन पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे बेचे जा रहे हैं। क्या कारण है कि हमने जिन लोगों को यह दायित्व दिया हुआ है, वे अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते? क्यों यूपीएससी में

(श्री संयम लोढ़ा)

एक भी पर्चा लीक नहीं होता? यूपीएससी में क्यों कोई गिरोह काम नहीं करता? कमियां तो हम में हैं। हम किस आधार पर निर्णय कर रहे हैं? इन संवैधानिक संस्थाओं को जिस रूप में गिरावट की ओर ले जा रहे हैं, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। जरूरत एक नये नजरिये के साथ काम शुरू करने की है।

क्या हालात हैं अनेक जिलों के? नीति आयोग ने क्या कहा? राजस्थान के 6-7 जिले ऐसे हैं जहां बरसों से पद खाली ही खाली पड़े हैं। सरकारें आती-जाती रहती हैं, कभी इनकी और कभी उनकी, पर वे पद खाली के खाली रहते हैं। कौन सोचेगा इनके बारे में? क्यों सरकारें एक नयी सोच के साथ नहीं आती हैं कि हम स्थायी रूप से राजस्थान के इन तमाम जिलों को एक ऐसी व्यवस्था देंगे कि लोगों को सुशासन मिल सके? आज मैं जिस सिरोही जिले से आता हूं, वहां 189 पदों में से 100 से अधिक पटवारी के पद खाली पड़े हैं। इनके राज में भी खाली थे, आज भी खाली हैं। भर्ती करेंगे, लगेंगे, फिर खाली हो जाएंगे। वही के वही ग्राम सेवकों के हालात हैं, वही के वही कृषि पर्यवेक्षकों के हालात हैं, वही के वही आयुर्वेद के हालात हैं। हास्पिटल के हालात तो इससे भी ज्यादा भयावह थे, जब मुझे राजस्थान हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और वहां से आदेश करवाकर सिरोही जिले में चिकित्साकर्मियों की भर्ती करवायी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं। क्यों नहीं, आप जिला काडर बनाते, जिला स्तर पर नियुक्ति का निर्णय करते? जिसे भी नियुक्ति लेनी है, नौकरी लगना चाहता है, जिंदगी-भर उसी जिले में नौकरी करेगा। जब तक इस तरह के फैसलों के साथ आप आगे नहीं आएंगे, राजस्थान की जनता को सुशासन देना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि लोग लग जाते हैं और फिर आप और हम भी लगते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, लाओ उन्हें और वहां फिर खाली। माननीय सभापति महोदय, पढ़ाने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि इस दिशा में सोचें और एक नयी सोच के साथ में आने वाले वक्त में राजस्थान को आगे ले जाएं। इससे बेहतर समय नहीं आएगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दो-तीन दिन से मैं लगातार हमारे

(श्री संयम लोढ़ा)

सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा हूं। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अनेक बातों को लेकर सरकार पर गम्भीर आरोप लगाये, अपने तरीके से उन्होंने हालात बताने की कोशिश की, लेकिन ये परिस्थितियां क्यों बनीं? राजस्थान में विधान सभा के चुनावी नतीजे तो दिसम्बर में आये ही थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने उससे पहले ही पूरे राजस्थान में एक नारा चला दिया था, ''मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुन्धरा तेरी खैर नहीं।।'' वह रिजल्ट में भी दिखा, जब 162 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 72 पर आकर खड़ी हो गयी।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा क्यों हुआ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, राज्य की औसत आर्थिक वृद्धि दर के क्या हालात थे? 2009-10 से 2013-14 की औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.19 प्रतिशत रही थी और इनके राज में 2014-15 से 2018-19 में औसत आर्थिक वृद्धि दर घटकर के 6.86 प्रतिशत रह गयी। आप इतना नीचे ले आये। ऊपर से ये कठिन हालात, दिल्ली की सरकार ने अनेक जन-विरोधी निर्णय कर दिये- नोटबन्दी, जीएसटी, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया, तो इसे तो नीचे जाना ही है। जिस 6.86 पर आप लाये थे, वह 2019-20 में 5.05 प्रतिशत पर रह गयी, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, 2009-10 से 2013-14 में राजस्थान में प्रचलित मूल्यों के आधार पर औसत आर्थिक वृद्धि दर 16.44 थी और स्थिर मूल्यों के आधार पर 6.31 प्रतिशत थी। 2014-15 से 2018-19 में जो 16.44 थी, उसे तो 9.75 प्रतिशत पर ले आये और स्थिर मूल्यों पर जो 6.31 थी, उसे 5.18 प्रतिशत पर ले आये। पांच साल आपने किया क्या? इसीलिए आपको राजस्थान की जनता ने दण्डित किया। राजस्थान का एग्रीकल्चर का शेयर जो 2013-14 में 28.14 प्रतिशत था जीएसडीपी में, वह 2018-19 में घटकर के 25.16 रह गया। एग्रीकल्चर पर आपका यह कमिटमेंट और रिजल्ट रहा है। कृषि की वृद्धि दर 2008-09 की 4.19 से बढ़ाकर अशोक गहलोत ने 2013-15 में 8.94 प्रतिशत तक पहुंचायी, उसे आपने घटाकर 2018-19 में 4.97 प्रतिशत पर लाकर छोड़ दिया और लोन और लाइबिलिटी, जो 2013-14 में एक लाख 29 हजार 910 करोड़ रुपये छोड़कर गये, जीएसडीपी का 23.58 परसेंट, वह 2018-19 में आपने बढ़ाकर एक लाख 29 हजार से 3 लाख 11 हजार 37 करोड़ पर लाकर

(श्री संयम लोढ़ा)

खड़ा कर दिया जो जीएसडीपी का 23 से बढ़कर 33 परसेंट हो गया। अब कहते हैं कि कर्जा बढ़ गया, अब आप कहते हैं कि देनदारी बढ़ गई, अब कहते हैं कि दायित्व बढ़ गया। पांच साल तक तो आप घी पीये जा रहे थे। माननीय सभापति महोदय, प्रति व्यक्ति कुल ऋण और लाइबिलिटी, जो 2013-14 में अशोक गहलोत 18 हजार 263 रुपये छोड़कर गये थे, उसको आप वापस उनको 40 हजार 519 रुपये राजस्थान के प्रत्येक आदमी पर कर्जा पकड़ा कर गये हो। सिर्फ पांच साल में आपने 181 परसेंट ऋण और लाइबिलिटी बढ़ा दी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आपके समझ के बाहर का है यह मामला। जिनके समझ में आ रहा है वे नोट कर रहे हैं, आपकी समझ के बाहर का है यह मामला।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, ये सारे हालात मैंने आपको निवेदन किये हैं। अब इन विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत को राज मिला लेकिन दो साल में कोई कह सकता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी अशोक गहलोत ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह मोड़ा हो? एक हौसले के साथ, एक ऊर्जा के साथ राजस्थान की आम-अवाम की सेवा में उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में मजबूती से खड़े रहे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे उद्योग मंत्री जी चले गये। एग्रीकल्चर के निर्यात प्रोत्साहन की नीति लेकर गवर्नमेंट आई। एक करोड़ कैपिटल में, एक करोड़ ब्याज में अनुदान। आप कृषि आधारित अगर कोई भी इण्डस्ट्री लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने यह प्रावधान किया है और राजस्थान के अन्दर बड़ी संख्या में किसान उसका लाभ उठा रहे हैं। इण्डस्ट्री के अन्दर जितनी भी बाधाएं आ रही थीं उन सारी बाधाओं को दूर करने का काम किया। जो सिंगल विन्डो सिस्टम एक खाली दिखावटी विन्डो रह गया था, उसमें कानून के जरिये परिवर्तन करके रीको की एक ही छत के नीचे इन्वेस्टर को सारी सुविधा देने का काम और तीन साल राजस्थान गवर्नमेंट से जुड़े हुए सारे कानूनों को रिलैक्स करते हुए इण्डस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए एक मौका अशोक गहलोत की सरकार ने दिया।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्या हालात थे? हिम्मत दिखाई, यह कर्जा नहीं देखा, यह विषम आर्थिक परिस्थितियां नहीं देखीं, यह अर्थ के खराब हालात नहीं देखे और एक सपना दिया कि राजस्थान के हर

(श्री संयम लोढ़ा)

जिले के अन्दर मेडिकल कालेज हो। जहां निजी क्षेत्र का नहीं हो, सरकारी हो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): भारत सरकार ने दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भारत सरकार ने दिया है तो जालौर का प्रस्ताव भेजा हुआ है, वह एक साल से भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है। जालौर-सिरोही का सांसद जिताकर भेजा है, लगातार चौथी बार भेजा है, लाओ, मंजूर कराकर लाओ।

श्री सभापति: प्लीज, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। आप मत बोलिये। (व्यवधान) विराजिये। विराजिये, विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): असत्य बयान कर रहे हैं, भारत सरकार ने दिये हैं। आप थोथी वाहवाही लूट रहे हैं। थोथी वाहवाही लूट रहे हो।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। भारत सरकार भी अपनी ही है। सुनिये आराम से।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी का बनाया हुआ नीति आयोग कह रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन के अन्दर राजस्थान हिन्दुस्तान में नम्बर दो पर है। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रखता हूं कि गम्भीर चर्चा हो रही है तो कृपया शांति से सुनें। आपको भी बोलना है। मैं आपको बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। मैं आपको वार्न करता हूं, यह गलत आदत है आपकी। आपका कल नम्बर था, आप आराम से बोल लिये। अब आपके माननीय सदस्य बोलेंगे इसलिए कृपया आप बीच में इंटरवीन नहीं करें। मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि कृपया शांत रहें और सुनें। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, एक विजन दिया कि राजस्थान हरा-भरा कैसे बने। हरित राजस्थान कैसे हो, इसके लिए स्कूलों में नामांकन के आधार पर वृक्ष मित्र योजना दी, पूरे राजस्थान की स्कूलों के अन्दर नामांकन के आधार पर 29 लाख वृक्ष लगाये गये। हमारे जंगलात के महकमे ने एक करोड़ 21 लाख पौधे लोगों को दिये। अनेक जगह पर हमारे जिला कलेक्टरों ने जहां-जहां बच्चियां हुईं उन बच्चियों की माताओं को पौधे भेंट किये और एक वातावरण बनाने की कोशिश की कि राजस्थान हरा-भरा

(श्री संयम लोढ़ा)

कैसे बने।

माननीय सभापति महोदय, 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ा, साढ़े चार सौ के लगभग नये जीएसएस बने और इस बात का प्रयास हुआ कि राजस्थान कैसे जगमगाये।

माननीय सभापति महोदय, आपके पीछे पूज्य महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। अशोक गहलोत की सरकार सदैव, आज नहीं, जब से उनको राजस्थान की हुकूमत में मुख्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, इन्हीं महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने दिल-दिमाग में रखकर समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों के लिए अपनी सरकार को समर्पित किया। जो भिखारी अगर किसी कालोनी में घुस जाता है तो कुत्ता जिसको देखकर भौंकने लग जाता है, वह भी उसको खदेड़ने की कोशिश करता है, उस भिखारी के लिए इस सरकार ने कौशल प्रशिक्षण शिविर लगाया, हमारे श्रम मंत्री जी बैठे हुए हैं। उसके अन्दर भी क्षमता है। माननीय सभापति महोदय, परमात्मा ने हर मनुष्य को क्षमता दी है, पर मौका नहीं मिलता। कोई जन्मजात भिखारी पैदा नहीं होता, हालात उसको भिखारी बनाते हैं, लेकिन एक लोक-कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है कि वह अपने नागरिक की क्षमता को कैसे बाहर लाये। इस सरकार ने उनके लिए भी कौशल प्रशिक्षण शिविर किया।

माननीय सभापति महोदय, मैंने सात पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखे। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के सीमावर्ती सिरोही जिले से आता हूं। हमारे बहुत लोग, प्रवासी बाहर जाते हैं। कोविड के अन्दर बाहर से आये, पैदल आये, अनेक तकलीफों को देखते हुए आये। गांवों में रोजगार नहीं था। हम वे हैं, जिन्होंने चरम कोरोना काल में 14 मई को हिन्दुस्तान में सबसे पहले नरेगा का काम शिवगंज ब्लाक में शुरू किया। लोगों के दिन पूरे हो गये। मैंने प्रधान मंत्री जी को 7 पत्र लिखे कि नरेगा मजदूरों के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 करिये, पर कोई जवाब नहीं आया, न कोई निर्णय आया। लोक सभा के अध्यक्ष जी चूंकि हमारे साथ राजस्थान की विधान सभा में रहे हुए हैं और जब उनसे मिलना हुआ तो मैंने उनसे भी विनती की। यह भी कहा कि छोटे कस्बों के लिए शहरी रोजगार योजना लाइये, लोग परेशानी में हैं, पर नहीं हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को कि दिशा की पहली बैठक हुई और पहली बैठक में कथौड़ी और सहरिया जाति के

(श्री संयम लोढ़ा)

आदिवासियों के लिए उन्होंने नरेगा में 100 से बढ़ाकर 150 कार्य दिवस करने का निर्णय अपने स्तर से किया। हमारे संसाधन सीमित हैं। आज फिर आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता महोदय को मैं विनती करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी तक राजस्थान की जनता की यह भावना पहुंचाइये। आपके अपने मेवाड़ इलाके के अन्दर लाखों की तादाद में लोग इसी के भरोसे अपने बच्चों की जिन्दगी को नया आकार देने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आलोचना तो बहुत की जा सकती है, लेकिन वह लौह महिला, जिसका लोहा इस देश ने नहीं पूरी दुनिया ने माना, स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की स्मृति में जिस रसोई योजना की शुरुआत माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने की, उसमें कितना बढ़िया आठ रुपये के अन्दर स्वादिष्ट भोजन मिलता है। मैं स्वयं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां-जहां भी है, वहां जाकर आया और जितनी सरकार ने लिमिट दी हुई है उतनी संख्या में लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। इस अल्पावधि के अन्दर एक करोड़ 56 लाख लोगों ने इन्दिरा रसोई की उस थाली का उपयोग अपने भोजन के लिए किया।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या रही है पत्थर में काम करने वाले मजदूरों की। बीमारी हो जाती है, जानलेवा बीमारी है, लाचार हो जाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को कि सिलिकोसिस नीति लेकर आये और उसके जरिये पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये का उन्होंने प्रबन्ध किया। मर जाए तो उसके पीछे दो लाख रुपये उसके जरिये देने का प्रबंध किया उन्होंने, उसकी विधवा के लिए पेंशन की व्यवस्था की उन्होंने, सिलिकोसिस पीड़ित के बच्चों के लिए पालनहार योजना का लाभ देने की व्यवस्था की। इससे बेहतर किसी सरकार का मानवीय चेहरा क्या हो सकता है, माननीय सभापति महोदय। जब अशोक गहलोत ने अपने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में पेंशन शुरू की थी, ये ही बीजेपी के लोग थे, मजाक उड़ाते थे। जब सत्ता में आये तो उन्होंने बदमाशी करने की कोशिश तो की, लेकिन जनता का इतना दबाव था कि उसको बंद नहीं कर सके।

अशोक गहलोत की सरकार आने के तुरंत बाद इनकी पेंशन 500 रुपये थी, उसको साढ़े सात सौ किया। जिनकी साढ़े सात सौ थी, उसको एक हजार किया, जिसकी एक हजार थी, उसको साढ़े बारह सौ रुपये किया। वह

(श्री संयम लोढ़ा)

हमारा लघु और सीमांत काश्तकार, छोटा काश्तकार, जो जमीन के कारण इसका लाभान्वित नहीं हो पा रहा था, उसको भी अशोक गहलोत इस दायरे में लाये और राजस्थान के 2 लाख 79 हजार लघु और सीमांत काश्तकारों को पेंशन से लाभान्वित किया।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्र पिछले दो दिन से लगातार कृषि ऋण की बात कर रहे हैं। कभी यह 2014 में प्रधान मंत्री के दावेदार के रूप में नरेन्द्र मोदी जी ने भाषण दिया था 'भाइयों और बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका कर्जा नरेन्द्र मोदी का कर्जा होगा और मेरी सरकार आने के बाद यह मेरी जिम्मेदारी होगी'। नेशनलाइज बैंक का पांच रुपये का कर्जा सात साल में नरेन्द्र मोदी ने माफ किया। धन्यवाद दो मनमोहन सिंह को, जिसने वादा किया था तो 85 हजार करोड़ रुपये का कर्जा देश के किसानों का माफ किया और नेशनलाइज बैंक का कर्जा था और जो राहुल गांधी जी ने वादा किया 10 दिन का, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सरकार के बैंकों का कर्जा 10 दिन में माफ करके दिखा दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खुद का तो 14 हजार करोड़ रुपये का कर्जा तो माफ किया जो किया, आप जो जाते-जाते निर्णय करके गये थे, आपके दायित्व का 6 हजार करोड़ भी अशोक गहलोत ने उठाया, 20 हजार करोड़ रुपया दिया। आप यहां बैनर लेकर के खड़े हो जाते हैं। एक-दो-तीन-चार-पांच-छ -सात-आठ-नौ-दस, राजस्थान की जनता ने 25 सांसद आपको जिताकर के दिये हैं, उनके मुंह में जुबान डालिए, जब 2014 में आपने वादा किया था राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करने का, वह कर्जा माफ करिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बच्चे, पिछड़ी जाति के बच्चे, दलित समाज के बच्चे-बच्ची आदिवासी समाज के बच्चे-बच्ची हास्टलों में रहते हैं, उनको खाना अच्छी क्वालिटी का मिले, अच्छी गुणवत्ता का मिले, अशोक गहलोत ने फैसला किया और मैस भत्ता बढ़ाकर के 2500 रुपये किया, माननीय सभापति महोदय।

आपको याद दिलाना चाहूंगा, सभापति महोदय, अशोक गहलोत की सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को एक रुपये में

(श्री संयम लोढ़ा)

पहले गेहूं देने का निर्णय किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने आते ही उस निर्णय को निरस्त कर दिया और उन बीपीएल के लोगों को उस राहत से वंचित कर दिया। फिर से, राजस्थान के मानवता से ओत-प्रोत मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को राज मिला और आते ही उन्होंने निर्णय किया कि बीपीएल के परिवारों को एक रुपये किलो गेहूं मिलेगा, राजस्थान के लाखों परिवार इस निर्णय से लाभान्वित हुए।

माननीय सभापति महोदय, गायों की बात भले कोई कितनी करो, पर पूरे हिन्दुस्तान के अंदर अशोक गहलोत मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने 2013 के अंदर पहली बार निर्णय किया स्टेट बजट से कि हम गोशालाओं में रह रही गायों को अनुदान देंगे और 2013-14 के अंदर पहली बार गोवंश को अनुदान देने का निर्णय अशोक गहलोत ने किया। इन्होंने 2013-14 में वादा किया था, अशोक गहलोत तो तीन महीने का अनुदान दे रहा है, हम सत्ता में आए तो 9 महीने का देंगे। पूरे 5 साल भूल गये, पूरे 5 साल उनको यह याद नहीं आया कि 9 महीने का अनुदान देना है। लास्ट में जाते-जाते 2018-19 में यह शिगूफा करने की कोशिश की, लेकिन तब भी 3 महीने से ज्यादा नहीं दे पाये। यह पहली बार है हिन्दुस्तान के इतिहास में जब किसी सरकार ने इतना अनुदान गोशालाओं को दिया हो। बड़े पशु का 32 रुपये था, बढ़ाकर के 40 रुपये किया। छोटे पशु का 16 रुपये था, बढ़ाकर के 20 रुपये किया तो गोमाता का आशीर्वाद तो अशोक गहलोत के साथ है और कितने ही षड्यंत्र आप करते रहें, आने वाले तीन साल तक अशोक गहलोत का झंडा फहराता रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं हमारे पड़ोस के राज्यों में कोरोना के मरीजों को इलाज पर लाखों रुपये खर्च करने पड़े, कइयों को बड़ा-बड़ा बिल उठाना पड़ा पर राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने जो 40 हजार रुपये का जीवन रक्षक इंजेक्शन कोरोना के सीरियस पेशेंट को लगता है वह भी मुफ्त किया। रेमडेसिविर के जो पांच इंजेक्शन लगते हैं, वह भी मुफ्त किये। कोरोना की जांच है, वह भी मुफ्त की। कोई ऐसे ही नरेन्द्र मोदी ने कह दिया दूसरे राज्यों को कि अशोक गहलोत की सरकार से सीखो, पूरी दुनिया के सामने ऐसे ही राजस्थान मॉडल बन गया, ऐसे ही अमेरिका की प्रेसिडेंट की प्रेस एडवाइजर ने राजस्थान के कोरोना मैनेजमेंट को लेकर आर्टिकल लिख दिया, नहीं घंटों तक इस चीज को रिव्यू किया है, एक-एक से संवाद किया है, छोटे से छोटे आदमी से बात की

(श्री संयम लोढ़ा)

है, एमएलए हो, एमपी हो, साधु हो, संन्यासी हो, तब जाकर के राजस्थान रिकवरी रेट के अंदर सबसे बेहतर और डैथ रेट में सबसे कम रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम लगातार विनती करते रहे कि लोगों के पास संसाधन नहीं हैं कोरोना के बीच में पर राजस्थान के 33 लाख लोगों को, उनके खाते के अंदर अगर पैसे किसी ने दिये 3500 रुपये तो वह अशोक गहलोत ने दिये। 20 लाख करोड़ का वह सीतारमण जी का पैकेज, पूरे राजस्थान में किसी के खाते में 5 हजार रुपये आये हों तो कोई बता देना बीजेपी का आदमी।

माननीय सभापति महोदय, बच्चे शिक्षा में आगे कैसे बढ़ें, कैसे अपने मां-बाप का नाम रोशन करें, कैसे अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना शुरू की अशोक गहलोत ने, 1 लाख 92 हजार बच्चों को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया।

माननीय सभापति महोदय, हमारे साधारण तबके के लोग मन में ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे बच्चे, क्योंकि यह दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में गांव में बदल गई है, पूरी दुनिया एक गांव है, इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी ने सब कुछ इतना नजदीक कर दिया है, साधारण से साधारण परिवार सोचता है, उनका बच्चा कुछ करे, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करे, आगे बढ़े। अशोक गहलोत वह व्यक्ति है, जिसने अपनी सरकार के पहले साल में ही निर्णय किया कि हम महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोलेंगे। दूसरे साल में भी उस निर्णय को जारी रखा और राजस्थान के हर ब्लाक के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खुले और, माननीय सभापति महोदय, आपकी स्वयं की जानकारी में है कि कितनी बड़ी संख्या में नामांकन इन विद्यालयों के अंदर हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, ढाई लाख लोगों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता मिला और एक शिकायत हमेशा से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों की रही है कि इस तरह के नार्म्स बनाकर के रखे हुए हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना जी को जो खुद भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं समर्पित खिलाड़ी हैं, डेडिकेटेड हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं और बहुत बेहतर खेलते हैं। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए कंविंस किया कि रिलेक्सेशन देकर हमें हमारे खिलाड़ियों को नौकरी देनी चाहिए। आज राजस्थान के खिलाड़ी आउट

(श्री संयम लोढ़ा)

आफ टर्न डीवाई.एसपी बने, दूसरे पदों पर लगे। पहली बार 29 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी अशोक गहलोत की सरकार ने दी माननीय सभापति महोदय।

मैंने जैसा आपको निवेदन किया, मैंने आपके सामने ही तथ्य रखे कि ये पांच साल में कैसा भट्टा बिठाकर के गये थे, लेकिन इसके बाद भी क्या कमी रही, जो जनकल्याणकारी निर्णय किये हैं वह तो मैंने बताए ही हैं आपको लेकिन क्या राजस्थान में नयी नगरपालिकाएं नहीं खुलीं, क्या राजस्थान में नई ग्राम पंचायतें नहीं बनीं, क्या नई पंचायत समितियां नहीं बनीं, क्या राजस्थान में 90 डिग्री कालेज नहीं खुले, क्या राजस्थान में नई अदालतें नहीं खुलीं?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): ...(व्यवधान) चुनाव का ...(व्यवधान) बंटाधार कर दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या राजस्थान में रीको के नये औद्योगिक क्षेत्र नहीं खुले, क्या नये स्पेशल जोन नहीं बने? खिलौना बनाने वालों के लिए अलग जोन, कृत्रिम आभूषण बनाने वालों के लिए अलग जोन, दवाइयां वालों के लिए अलग जोन, मार्बल वालों का अलग जोन, ग्रेनाइट वालों का अलग जोन। पहली बार राजस्थान में ऐसी विशिष्टताओं के साथ रीको आया है और उसका बहुत बढ़िया रेस्पोंस है। राजस्थान का औद्योगिक जगत माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नये दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। आज राजस्थान की एक बीमारू प्रदेश की छवि नहीं रही। राजस्थान के ब्यूरोक्रेट ने भी अपनी मानसिकता हुकूमत देखते हुए बदली। वह भी पोजिटिव है। अब कोई इन्वेस्टर आना चाहता है तो कलेक्टर तुरंत रेस्पोन्ड करता है, जाता है, जमीन दिखाता है और कोशिश करता है और यह सब इसलिए हुआ है कि सरकार इंडस्ट्री फ्रेंडली है और यह नजरिया दुनिया के सामने आया है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया है आपको, मेडिकल कॉलेज, भूमिगत मैट्रो पहली बार काम शुरू होने जा रहा है। सीवरेज प्रोजेक्ट राजस्थान में जगह-जगह चल रहे हैं। टाउन हाल बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं। सीएचसी आयी है, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल आये हैं, पीएचसी आयी है। नये

(श्री संयम लोढ़ा)

जीएसएस बने हैं और इन सबके अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम जो इस विधन सभा का है, अनेक काम इस विधान सभा ने पहले भी किये हैं, अनेक प्रगतिशील कानून पहले भी लाये हैं इस विधान सभा में और इस 15वीं विधान सभा में भी राजस्थान की सरकार के माध्यम से अनेक प्रगतिशील कानून, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता को मिले हैं।

आलोचना तो बहुत हो सकती है लेकिन राजस्थान सरकार को भारत सरकार ने अनेक बार नवाजा है। अनेक अवार्ड दिये हैं, अनेक इनाम दिये हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज के अंदर 8 पुरस्कार 2020 में राजस्थान को दिये और इसके अंदर करीब दो करोड़ रुपये राजस्थान को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड 2020 का राजस्थान को दिया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2019 केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को दिया है और साउथ आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन अवार्ड 2019 में राजस्थान को दिया है और विधिक सेवा दिवस पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा के राष्ट्रीय अवार्ड से राजस्थान को सम्मानित किया है।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, अभी कोरोना काल में भी सबसे बेहतरीन लोक अदालत का काम राजस्थान ने किया है और जिसकी सराहना भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी की है। इतना ही नहीं, नेशनल वाटर अवार्ड उदयपुर जिले को वाटर कंजर्वेशन के लिए मिला। आशान्वित जिले में बारां जिले को फर्स्ट प्राइज मिला। स्वच्छ भारत मिशन में सामूहिक शौचालय निर्माण में राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2019 का फर्स्ट प्राइज राजस्थान को मिला और घाटोल पंचायत समिति को देश की सभी पंचायत समितियों में पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास के अंदर मिला जो राजस्थान की है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के लिए श्रेष्ठ राज्य के रूप में राजस्थान को सम्मानित किया गया। जोधपुर और नागौर को श्रेष्ठ जिला श्रेणी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है।

इतना ही नहीं, पोषण अभियान में भी समग्र उत्कृष्टता श्रेणी में राजस्थान को डेढ़ करोड़ रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार भी इंदिरा गांधी नहर तंत्र में तेजपुरा माइनर पर माइक्रो सिंचाई पद्धति के कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम व द्वितीय पुरस्कार से

(श्री संयम लोढ़ा)

सम्मानित किया गया। यह सभी पुरस्कार कोई एनजीओ ने नहीं दिये हैं, देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री के अलग-अलग विभागों ने और उनकी सरकार ने राजस्थान को दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। बहुत चर्चा हुई कल मैं प्रतिपक्ष के नेता के विचार सुन रहा था भ्रष्टाचार पर, हर सरकार यह कोशिश करती है कि उसके नागरिकों को सुशासन मिले, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किये होंगे और यह सरकार भी कर रही है लेकिन यह कहना कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तो अधिकारियों को पकड़ता है और राजस्थान की वर्तमान सरकार उनको छोड़ देती है, उनको मुक्त कर देती है, पूरी तरह से गलत है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अपना काम करता है लेकिन वह काम कानूनी मापदंड पर सही है या नहीं है, कितने लोगों का अभियोजन स्वीकृति देना कानून सम्मत है या नहीं है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को यह तय करने का पूरा अधिकार है। किसी आदमी को अगर झूठा फंसाया जा रहा है तो क्या राजस्थान की सरकार उसको रोकेगी नहीं? और यह जो बात कर रहे थे और इतनी बात कर रहे थे, बहुत अच्छा होता जब राजस्थान के गृह मंत्री थे तब अपनी सरकार को यह बता पाते, कह पाते कि अभियोजन स्वीकृति एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मांग रहा है, उनकी रोको मत, लेकिन तब तो रोकी। 2014 में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो राजस्थान सरकार से एनओसी मांगी, 52 ऐसे मामले हैं, जहां वसुन्धरा राजे की सरकार ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को एनओसी देने से मना कर दिया और वह मुकदमे खतम हो गये। यह 2014 का फिगर है 52 और 2015 में 69 केसेज हैं, जिनमें वसुन्धरा राजे की सरकार ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। 2016 के अंदर 68 केसेज ऐसे हैं, जिनमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को वसुन्धरा राजे की सरकार ने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। 2017 में 26 ऐसे मामले हैं, जब अभियोजन स्वीकृति एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को नहीं दी गई और 2018 में 28 ऐसे मामले हैं। इस तरीके से 244 ऐसे मामले हैं, जिनमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अपराध प्रमाणित माना, लीगल एडवाइस लेकर प्रमाणित माना और अभियोजन स्वीकृति के लिए वसुन्धरा राजे के पास भेजा लेकिन 244 मामलों के अंदर स्वीकृति नहीं दी गयी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा टाइम देखो आप। कहां समाप्त करा रहे हैं, अभी तो बहुत बोलना है मेरे को।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं। अब 25 सांसद दिल्ली भेजे हैं, क्या हुआ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का? 2018 में प्रधान मंत्री जी कहकर गये थे कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में शामिल करेंगे, उसके बाद भी 2 बजट आ गये। राजस्थान की परियोजना को दर्जा मिला नहीं और रेलवे के प्रोजेक्ट, भीलवाड़ा की फैक्टरी जिसकी जमीन सरकार ने मुफ्त दी है, आज अगर जमीन लेने जाओ तो कितना पैसा लगता है, लेकिन उसके बाद भी वह काम शुरू नहीं हो रहा है। रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, अजमेर-सवाई माधोपुर वाया चौथ का बरवाड़ा, पुष्कर-मेड़ता नई रेल लाइन, अजमेर-कोटा-नसीराबाद रेल लाइन, तारंगा हिल आबू रोड रेल लाइन और सिरोही को रेल से जोड़ने का जो सर्वे करके 15 सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बना हुआ पड़ा है, उसके लिए पांच पैसे भी भारत सरकार ने अभी तक नहीं दिये हैं। यह 25 लोग जिता कर भेजे हुए हैं, हमारे क्या काम आएंगे?

माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे डीजल-पेट्रोल की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार ने कितना डीजल-पेट्रोल पर पैसा बढ़ाया है, सभापति महोदय, उसका एक अंदाजा आप देखिए, एक्साइज ड्यूटी, नवम्बर 2014 से जनवरी, 2016 के बीच में डीजल और पेट्रोल पर 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। पेट्रोल पर 11.77 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 13.47 रुपये प्रति लीटर। 2014 में एक्साइज ड्यूटी से केन्द्र सरकार की जो आय 99 हजार करोड़ रुपये थी, वह बढ़कर 2 लाख 42 हजार करोड़ रुपये हो गई। यह हिन्दुस्तान की जनता को चूना लगाने का काम किसने किया? 160 डालर कच्चे तेल का भाव था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, आज 45 डालर भाव हो गया। हिन्दुस्तान की जनता को उसका फायदा नहीं मिले इसलिए बार-बार आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर हिन्दुस्तान की जनता को उस लाभ से वंचित कर दिया और अब एक नई चीज ले आये डीजल-पेट्रोल पर सैस और सरचार्ज। अप्रैल, 2017 में डीजल-पेट्रोल पर क्या सरचार्ज था, 12 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर। आज मई, 2020 में 30 रुपये प्रति लीटर डीजल-पेट्रोल पर सरचार्ज है और डीजल पर जो अप्रैल, 2017 में 4.83 रुपये सरचार्ज था, वह मई, 2020 में बढ़कर 27 रुपये हो गया। हिन्दुस्तान की जनता को

(श्री संयम लोढ़ा)

यह पता नहीं पड़ रहा है कि यह 100 रुपये भाव कैसे छूने जा रहा है। 50 रुपये तो तेल का भाव है और 50 रुपये नरेन्द्र मोदी का टैक्स है। माननीय सभापति महोदय, बार-बार वैट को लेकर खड़े हो जाते हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, समाप्त करें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा 45 मिनट टाइम है, आप देख लो अच्छी तरह से, 45 मिनट है, आप रुकिए अभी। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको किसान सम्मान निधि का निवेदन करना चाहता हूं। क्या हाल है किसान सम्मान निधि का? 6 लाख किसानों की प्रथम किस्त की राशि अभी तक भारत सरकार पर लंबित है राजस्थान के 6 लाख किसानों की। 8 लाख 24 हजार किसानों की सैकण्ड किस्त, 6 लाख 78 हजार किसानों की थर्ड किस्त, 8 लाख 42 हजार किसानों की चौथी किस्त, 7 लाख 79 हजार किसानों की पांचवीं किस्त और 6 लाख 77 हजार किसानों की छठी किस्त और 4 लाख 16 हजार किसानों की सातवीं किस्त उनके खातों में अभी तक हस्तांतरित नहीं हुई है। भारत सरकार में कोई देखने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) कुछ तो शर्म करो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): शर्म आप करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रिकार्ड पर क्या बात जा रही है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि में तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपया मिलता है। छठी किस्त, सातवीं किस्त, आठवीं किस्त, इतने सीनियर आदमी हो, क्या जा रहा है रिकार्ड पर?

श्री सभापति: वह बता देंगे, मंत्री जी बोलेंगे। विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जिनके बाद में हुआ है, उनकी किस्त कैसे काउंट होगी, उनकी कैसे काउंट होगी?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। प्लीज, प्लीज सहयोग करें। विराजिए, विराजिए, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट लूंगा। माननीय सभापति महोदय, अभी यह बात कर रहे थे, बार-बार इनको सपने आते हैं, जब चाहे तब मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं। बाहर

(श्री संयम लोढ़ा)

स्टेटमेंट देंगे कि जब होगा तब सरकार गिर जायेगी। आपने राजस्थान को पोलिटिकल टूरिज्म की कैपिटल बना दिया है। पूरे देश में एमएलए की खरीद फरोख्त करते हुए एमएलए की मंडी बना दिया। गुजरात में खरीद-फरोख्त करते हो, गुजरात के एमएलए यहां आते हैं। मध्य प्रदेश में खरीद-फरोख्त करते हो, मध्य प्रदेश के एमएलए यहां आते हैं। महाराष्ट्र में खरीद-फरोख्त करते हो, महाराष्ट्र के एमएलए यहां आते हैं। कर्नाटक में खरीद-फरोख्त करते हो, कर्नाटक के एमएलए यहां आते हैं। आपको कल पता चल गया होगा ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए। श्री अशोक लाहोटी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, एक शेर के साथ बात खतम कर रहा हूं। किसी नजर को ...

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, एक शेर के साथ बात खतम कर रहा हूं। 'किसी नजर को तेरे वादे का इंतजार आज भी है, कहां हो तुम कि गरीब और गरीब आज भी है। वह 15 लाख, वह अच्छे दिन कि हम सुने थे जहां, तेरी बकलौली का वहीं पर मजार आज भी है। हवाएं बिखरी, फजाएं बिखरी ...(व्यवधान) कि जिंदा तेरा जमीर आज भी है। न पूछ कितने तेरे जुमलों के जख्म खाये हैं, रहनुमा ...(व्यवधान) आज भी है, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह पिछले 55 मिनट से असत्य बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से इस सरकार ने तीसरी बार अभिभाषण करवाया। सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि राज्यपाल महोदय एक संवैधानिक मर्यादा में वह सारी बातें कह रहे हैं जो सरकार बुलवा रही हैं, लेकिन हम तो उस पृष्ठभूमि के लोग हैं जहां यह कहते हैं कि 'रघु कुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए।'

(श्री अशोक लाहोटी)

राजस्थान का आदमी तो यह कहते हैं कि जुबान का धनी है और हमने माननीय राज्यपाल महोदय से लगातार वह सारी बातें करवा दीं। इन मुख्य मंत्री जी का यह तेरहवां अभिभाषण है, मैं आपके सामने दावा कर रहा हूं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य तो अभी पता नहीं कितने-कितने असत्य आंकड़े लाये, पर मैं यह दावा कर रहा हूं कि जो 1998 में पहली बार राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था और 2019 का जो पहला अभिभाषण हुआ है, उसमें से भी कई बिन्दु आज तक भी पूरे नहीं हुए और 2019 के तो 90 प्रतिशत काम अभी तक पूरे नहीं हुए। किस बात का अभिभाषण कर रहे हैं, किस बात का धन्यवाद कर रहे हैं? सभापति महोदय, मैं आंकड़े लेकर आया हूं, मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, असत्य बोला करें आप। यह असंसदीय है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): असत्य कह दो। सभापति महोदय, आपने 2019 के माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बिन्दु संख्या 10 पर लिखा था कि यह नीतिगत दस्तावेज है और राज्य का मंत्रिमंडल 100 दिवसीय कार्ययोजना विभाग वाइज तैयार कर रहा है। सभापति महोदय, वह 100 दिन कब पूरे होंगे, राजस्थान की जनता पूछ रही है। इस अभिभाषण को पढ़ो तो इसमें न नीति है न नीयत है न सिद्धांत है न समन्वय है। समन्वय की बात तो मैं आगे करूंगा कि कौन जैसलमेर में है और कौन दिल्ली में है। न कार्यक्रम है और न क्रियान्वयन है।

सभापति महोदय, अगर मैं बात करूं तो इस सरकार से आप पूछना कि कहां है किसान कर्ज माफी, 1 से 10 गिनती, वह 10 पूरे हो गये, वह 10 दिन कब पूरे होंगे, यह राजस्थान की जनता पूछ रही है। सभापति महोदय, संविदा कर्मियों को 6 महीने में, यह अभिभाषण में था, 6 महीने में राज्य के संविदा कर्मियों के साथ न्याय होगा, वह 6 महीने कब पूरे होंगे, वह संविदा कर्मी पूछ रहे हैं। सभापति महोदय, प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते की अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बात की। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, वह सरकार के प्रतिनिधि बनकर बात कर रहे थे कि राजस्थान में 67 लाख पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं और भत्ता कितनों को मिल रहा है, मात्र 1 लाख 60 हजार लोगों को। अभी अख़बार में आया कि 2 लाख लोगों की तो वेटिंग चल रही है,

(श्री अशोक लाहोटी)

जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, आखिर यह कैसा न्याय कर रहे हैं? यह कौनसे अभिभाषण के बिन्दु पढ़ रहे हैं? एक भी अभिभाषण के किसी बिन्दु पर तीन साल चले गये, तीसरा अभिभाषण है, यदि सरकार ने पूरा किया हो तो सरकार का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि इस अभिभाषण पर हमने पूरी कर ली। औद्योगिक नीति कहां है? कौनसे औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा हो गई? कौनसा औद्योगिक क्षेत्र खुला? खेल नीति कहां गई? खेलों पर विचार कहां हुए?

बिजली के बिल, सभापति महोदय, जिन बिजली के बिलों की आप बात कर रहे थे, कोरोना काल की बात कर रहे थे, 96 प्रतिशत बिजली पैदा करने वाले राजस्थान में, गुजरात में 4.15 रुपये, दिल्ली में 4.50 रुपये, मध्य प्रदेश में 6.30 रुपये, हरियाणा में 6.30 रुपये, पंजाब में 6.34 रुपये, राजस्थान में कहते तो 9 से 13 रुपये है लेकिन मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, यह बिल की कापी है। इसमें केवल 45 यूनिट उपभोग किया है, विद्युत खर्चा 339.75, स्थायी शुल्क 600 रुपये, विद्युत शुल्क 18 रुपये, जल उपकर 4.50 रुपये, नगर उपकर 6.75 रुपये, अन्य देय 339 रुपये, कुल 1309 रुपये दो महीने का बिल है। यानी 29 रुपये प्रति यूनिट बिजली राजस्थान के किसानों को राजस्थान की घरेलू बिजली पड़ रही है। सभापति महोदय, यह कैसी संवेदनशील सरकार है?

तीन शब्द शुरू से सुन रहे हैं संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह, किसके प्रति? खुद राहुल गांधी जी की नानी जी के यहां पर चोरी हो गई यह मैं नहीं कह रहा, यह राजस्थान का मीडिया चिल्ला के कह रहा है कि राहुल गांधी जी के रिश्तेदार के यहां एक-एक दिन में दो-दो बार चोरी हो गई। सभापति महोदय, क्राइम कहां है? हमारी राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई। (व्यवधान) सांगानेर में तो आप चिंता मत करो, यह भी राजधानी का ही पार्ट है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अपराध दिन-रात बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 31 परसेंट अपराध बढ़े हैं। राजस्थान में महिलाओं पर 68 परसेंट अपराध बढ़े हैं और राजस्थान महिला अपराध में दूसरे नंबर पर आ गया है। दलित अपराध में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर आ गया और साइबर क्राइम की तो बात ही मत करो, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बजट में कहा था कि पूरे राजस्थान के थानों के आधुनिकीकरण के नाम पर मात्र चार करोड़ रुपये रखे थे और राजस्थान का साइबर क्राइम कंट्रोल कर

(श्री अशोक लाहोटी)

रहे हैं, या तो पकड़े नहीं जाते या ढूंढ नहीं पाते, ढूंढने के बाद यूपी, बिहार जा नहीं पाती, पुलिस के पास जो जीप है, वह पैट्रोलिंग करने में भी सक्षम नहीं है। राजधानी अपराध का केंद्र बन गयी है, पूरे राजस्थान की बात छोड़ें। आप एक भी दिन अख़बार उठा कर देख लें, ऐसा लगता है कि राजस्थान में नहीं, पता नहीं कौनसे प्रदेश में आ गये हैं। अपराधी बेखौफ हो गये हैं और राजस्थान में क्राइम का राज हो गया है।

सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग में मेडिकल कालेजों के लिए न जमीन है, न भवन का अता-पता है। मैंने कल ही जनता क्लिनिक की बात की थी। एक हजार जनता क्लिनिक खोलने वाली सरकार के लिए सत्ता पक्ष के लोगों ने इतनी मेजें थपथपायीं, कल ही कुछ माननीय सदस्य बाहर कह रहे थे कि अभिभाषण पर दिल पर पत्थर रखकर अब कितने दिन और बोलें। तीन साल हो गये, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो नहीं हो रहा। जनता क्लिनिक केवल 12 खुले हैं, खर्चा मात्र 1 करोड़ 48 लाख रुपये हुआ है। ये राजस्थान की जनता के साथ न्याय कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, किस बात का धन्यवाद दें?

सभापति महोदय, राइट टू हैल्थ की बात कर रहे हैं। भामाशाह को दो साल पहले अघोषित रूप से बंद कर दिया। बाद में केंद्र सरकार की योजना में आप निरोगी राजस्थान लाये। आपके पास एक पैसा नहीं था। उसके बाद आप केंद्र सरकार की योजना ढूंढकर लाये कि अब हम अलादीन का चिराग ले आये। निरोगी राजस्थान में कुछ नहीं कर पाये। जब योजना आयी, उसमें राजस्थान में महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया, लेकिन आज तक न योजना का पता है, न क्रियान्वयन का पता है। हर विधायक अपने दिल पर हाथ रखकर यह कह दे, उनके क्षेत्र से डेली ऐसे सैकड़ों फोन आते हैं, जिनको इलाज में कहीं राहत नहीं मिल रही है और लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोग बीमारियों से मर रहे हैं। जहां 3 लाख, 5 लाख रुपये बीमारी में मिलने थे, वे सरकार की नाकामी के कारण नहीं मिल रहे हैं। ये सबको जवाब देना पड़ेगा।

आज यहां टेबलें बजाने वालों की रिकार्डिंग करके इनके क्षेत्र में भेजी जाए कि वहां टेबल बजाने वाले लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में इलाज मिल रहा है। सभापति महोदय, आज उप चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस की टैंपो की सवारी नहीं आएगी। टेबल बजाने वालों की हालत खराब होगी। अभी तो चार

(श्री अशोक लाहोटी)

जिलों में पता लग जाएगा। (व्यवधान) नगरपालिका में क्या देखा? 180 का वार्ड और 1800 का वार्ड। कैसी बात कर रहे हो? थोड़ी बहुत शर्म करो। एक समाज विशेष के वार्ड बनाकर खुश हो रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, अभी पैट्रोल-डीजल की बात कर रहे थे। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य एक्साइज, क्रूड आयल और पता नहीं किस-किस की बात कर रहे थे, लेकिन मैं यह पूछ रहा हूं कि आप राजस्थान की विधान सभा में बैठे हो, राजस्थान में वैट कितना है, उसकी गणना कर लो। राजस्थान में पैट्रोल-डीजल पर देश में सबसे ज्यादा वैट है या नहीं है? आसपास के राज्यों से पेट्रोल-डीजल पर वैट सबसे ज्यादा है या नहीं, इसकी भी तुलना करवा लें।

सभापति महोदय, आपने 2019 के बजट में लिखा कि 75 हजार भर्तियां होंगी। मैं इस सदन में पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी खड़े होकर कह दें कि वे 75 हजार भर्तियां कहां हैं? यह 2019 का बजट था। अब 2021 का बजट ला रहे हो, जो कि तीसरा है। मारवाड़ी में कहते हैं कि 'ज्यादा गयी, थोड़ी रह गयी' तीसरा बजट गया, अब तो थोड़ा-सा ही और रहा है। सभापति महोदय, 2020 के बजट में 53 हजार नियुक्तियां, कर्मचारी चयन बोर्ड में 14 लाख अभ्यर्थियों की भर्ती अटकी हुई है। राजस्थान की सरकार कहां है? जैसलमेर में है या दिल्ली में है, थोड़ा पूछो तो सही।

सभापति महोदय, अन्नपूर्णा योजना को बंद करके इन्दिरा रसोई योजना चालू की। इनके अधिकारी वहां विजिट करके देखकर आये, वहां पर कुत्ते घूम रहे थे, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा अव्यवस्था है। केवल योजनाओं के नाम बदलने से योजनाएं अच्छी नहीं हो जातीं। मां अन्नपूर्णा का नाम बदलकर, आज इन्दिरा जी की आत्मा भी रो रही होगी कि मां अन्नपूर्णा का नाम बदलकर आपने किसी राजनेता का नाम रखा और वह योजना भी आप चला नहीं पाये। हजारों योजनाएं गांधी परिवार के नाम से चल रही हैं, फिर एक और जोड़ने से क्या होगा? पर सरकार बचानी थी, दिल्ली को खुश करना था। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की योजना, अभी आप कह रहे थे, लाखों फार्म वैटिंग में पड़े हैं और उनकी स्क्रूटनी करने वाला कोई नहीं है और उच्च शिक्षा में आज तक स्कूटी तक नहीं बंटी और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं।

(श्री अशोक लाहोटी)

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात आपने की। मैं यह दस्तावेज लाया हूं 'राज्य अपना अंश नहीं देने के कारण 53 करोड़ रुपये लैप्स हो गये।' माननीय मंत्री जी नहीं हैं, उनके जिले में जो 50 लाख रुपये खर्च होने थे, उसकी जगह पर मात्र 28 हजार रुपये खर्च कर पाये हैं। यह 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का उदाहरण है। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य इसमें वाहवाही लूट रहे थे।

सभापति महोदय, शिक्षा की बात कर रहे थे। शर्म आती है, जब ये आंकड़े देखते हैं। राज्य में 29 हजार 842 स्कूलों में बिजली नहीं है और उसमें भी माननीय शिक्षा मंत्री जी के क्षेत्र की 700 स्कूलें हैं। सभापति महोदय, कैसा राज है? जवाबदेही सरकार, पारदर्शी सरकार, संवेदनशील सरकार, केवल जुमलों की सरकार। सभापति महोदय, नंदी शाला कहां है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर दो साल पहले ही खुल गयी थी? कहां गये वे नवीन औद्योगिक क्षेत्र, नवीन महाविद्यालयों के भूमि आबंटन, कल ही सरकार ने कहा, अभी तक भूमि नहीं दी है। बजट का प्रावधान नहीं किया। कमरे नहीं बने हैं। एक-एक कमरे में कालेज खुल रही है। यही कांग्रेस सरकार 2013 में एक-एक कमरों में यूनिवर्सिटी खोलकर गयी थी। राजस्थान की उच्च शिक्षा की दुर्दशा उस दिन शुरू हुई थी और फिर आपने एक-एक कमरों में केवल आंकड़े दिखाने के लिए कालेज खोलने का काम किया।

सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी की बात तो मैं अभी और करूंगा। पहले जयपुर सहित अमृत योजना के काम, जल जीवन मिशन में केंद्र आपको तीन साल से पैसा दे रहा है। इस साल भी 5500 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। राज्य सरकार अपना राज्यांश नहीं मिला पाने के कारण तीन साल से राजस्थान में जन जीवन मिशन का काम बिल्कुल ठप पड़ा है। आज मैं कह रहा हूं कि अब यदि आपने टेंडर किये तो भी तीन साल तक आपका पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचेगा। अब आप सर्वे कराओगे, डीपीआर बनाओगे, टेंडर लगाओगे, कौनसे विभाग की बात करोगे? हथलेवा योजना, कहां है? उसकी घोषणा की थी। बालिकाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए बहुत तालियां बजायी थीं। प्रदेश में नये जिले की घोषणा, बालोतरा से आने वाले माननीय विधायक दिल पर पत्थर रखकर बैठे हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार कर रहे हैं कि कब बालोतरा जिला बने, नहीं तो मैं विरोध में बोलना शुरू करूं।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की बात करने वाले, कल हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूरे आंकड़े दिये थे। हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन किसी न किसी, अधिकारी बेखौफ हैं, अधिकारी बिलकुल बेखौफ हैं, कल ही जयपुर में लोगों के 50-50 गज के मकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम के अधिकारी चले गये और जहां पर अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, वहां कोई झांकने वाला नहीं है, क्योंकि वे कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में बन रही हैं। सभापति महोदय, इस भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा नाच राजस्थान के इतिहास में न कभी हुआ, न कभी होगा। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपके पेट में दर्द ज्यादा है। कृषक कल्याण कोष कहां गया? कृषक कल्याण कोष के नाम पर लोन लेकर आपने राज्य सरकार के राज्यांश की इंश्योरेंस की किस्त चुकायी। इंदिरा महिला शक्ति निधि गठन का कहां गया? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम चयन का क्या हुआ? नेहरू बाल संरक्षण कोष का क्या हुआ? राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा बोर्ड के गठन की घोषणा का क्या हुआ? राजीव गांधी जल संचय योजना का क्या हुआ? मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन का क्या हुआ?

शराब बंदी, सभापति महोदय, गांधीवादी मुख्य मंत्री, दो दिन पहले शराब बंदी पर पूरी योजना बनाने के लिए टीम रवाना होती है और दो दिन बाद अंडरटेबल डील होती है कि क्या होता है, तीस फीट की सड़कों पर बार खोलने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। इसी सदन में विरोध हुआ। योजनाओं को उलटा-सीधा किया गया। गुटके पर प्रतिबंध की बात हुई। दो दिन बाद उस फार्मूले को बदल दिया गया। सभापति महोदय, यह कौनसी पारदर्शी सरकार है? सभापति महोदय, दो बार तीस फीट पर बार खोलने के आदेश हुए। ग्राम पंचायत पर खेल मैदानों की घोषणा का क्या हुआ? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति का पता नहीं है। ग्राम पंचायत पर विकास पथ, हमें शहरों में तो खैर मिला ही नहीं है। शहर में तो दो साल में ट्यूबलाइट भी नहीं लगी है। दो दिन से मैं एक-एक विधायक से पूछते-पूछते यहां घूम रहा हूं कि किसी के यहां पर कोई विकास पथ बना क्या? नाम तो बदला। सभापति महोदय, आपके यहां बना क्या, यही बता दो। सभापति महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगी मानदेय, पारदर्शी सरकार। सरकार बनने के एक महीने के बाद से आज तक लोकायुक्त नहीं है। कल माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा। पहले पांच साल लोकायुक्त थे। कब नहीं थे लोकायुक्त? आप बताएं। 23

(श्री अशोक लाहोटी)

महीने से नहीं है, मैं बता रहा हूं। सभापति महोदय, पूरे जैन मंदिरों में चोरियां हो रही हैं। एटीएम टूट रहे हैं, लॉकडाउन के बाद राजधानी अपराधों की राजधानी बन गयी है। देश सिरमौर बन गया है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि इस बजट में कहीं एक शब्द तो जोड़ते, राज्यपाल के इस पूरे अभिभाषण में आप एक बार तो केंद्र सरकार को धन्यवाद देते। जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था यह कह रही है कि दस साल में अर्थव्यवस्थाओं की ऐसी गिरावट कभी नहीं आयी, ऐसे समय में 80 मिलियन परिवारों को गैस मुफ्त मुहैया करवायी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया। आधारभूत संरचना का विकास किया, शिक्षा और शोध को बढ़ावा दिया।

(14.00 बजे)

डेढ़ गुना किसानों की लागत बढ़ाने का काम किया। इन सबके बावजूद भी आज तक इस अभिभाषण में एक भी मुद्दा, यदि मैं 2019-20 के बिंदु सहित आपको बताऊं तो बजरी खनन रोकने के प्रयास की घोषणा की थी आपने 66 नंबर पाइंट पर, प्रदूषण नियंत्रण 26 जिलों में आपने बात की थी 67 नंबर पाइंट पर, निर्धन परिवारों के आवास उपलब्ध कराने की बात की थी 69 पर, कहां है वह?

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं दो मिनट लूंगा। आपने स्मार्ट सिटी और शहरीकरण को आगे, इन्होंने कहा कि उत्पन्न हो रही समस्याओं को दूर करेंगे। मैं केवल जयपुर की बात करूं तो पिछले दो साल में राज्य की सरकार ने, जो भाजपा की सरकार थी, वसुन्धरा जी के समय जो सड़कें बनी थीं, उनके खड्डे तक नहीं भर पा रही है ये कांग्रेस की सरकार, दो साल में। एक लाइट इन्होंने खरीदी हो तो बता दें कि किसी भी नगर निगम में एक लाइट इन्होंने अपने बजट से खरीदी है क्या? कैसे विकास की बात कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी की बात कर रहे है। केवल पौण्डरिक पार्क को उजाड़ कर वहां पर कंकरीट का जाल बना दिया जाए, यह स्मार्ट सिटी है। जो स्मार्ट सिटी का मूल सपना था, उसको आपने डीविएट कर दिया।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मर्जी आए जहां आप अपनी सुविधा के लिए लेकर जा रहे हैं। राजधानी में तार नंगे पड़े हैं, वहां स्मार्ट सिटी की जरूरत है। 1300 कालोनियों में पीने का पानी

(श्री अशोक लाहोटी)

नहीं है, उस स्मार्ट सिटी की जरूरत है। 1700 कालोनियों में सीवरेज नहीं है, उस स्मार्ट सिटी की जरूरत है और चलने के लिए सड़क नहीं है। आज राजधानी के हालात यह हैं कि आज जिधर देखो, नीचे देखो तो खड्डा है, ऊपर देखो तो बंदर है, आगे देखो तो सूअर है और पीछे देखो तो कुत्ता है, यह स्मार्ट सिटी का हाल जयपुर का हो रखा है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, किसकी बात करेंगे।

श्री सभापति: बैठिए। आप बैठिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं बात पूरी कर रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिए। तैयारी करके नहीं आए। ये कुत्ता-बिल्ली का काम नहीं है। तैयारी करके नहीं आए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): ये कुत्ता-बिल्ली का ही काम है। आप देख लीजिए। आप जहां रहते हैं वहां भी..

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 9 विभाग मुख्य मंत्री जी के पास हैं। पिछले 23 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, सरकार होने का एहसास नहीं हो रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा सरकार इधर उधर की बात न करे, खाट कैसे टूटी?

श्री सभापति: विराजिए। आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: सहयोग कीजिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रहे वाद-विवाद पर आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं। मैं माननीय विधायक जी से अर्ज करना चाहूंगा..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, ये खाट का विषय क्या आया? खाट वास्तव में कैसे टूटी, जांच तो करवाएं इसकी। आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदन की समिति बनाइये। सचिन पायलट जी की खाट कैसे टूटी? (व्यवधान) सचिन जी की खाट ही क्यों टूटी?

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा वाद-विवाद चल रहा है और..

श्री सभापति: चौमूं में खाट यूं ही टूटती रहती है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम केवल केन्द्र और राजस्थान के बारे में एक-दूसरे के पक्ष-विपक्ष की बात कर रहे हैं कि केन्द्र में हमारी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है। मैं पक्ष-विपक्ष की बात नहीं करता। एक बात कहना चाहता हूं कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी भारत को एक मानते हैं और देश का प्रधान मंत्री जिसको हमने वोट दिया है या नहीं दिया, वह हमारे देश का प्रधान मंत्री है, मेरा भी प्रधान मंत्री है तो राठौड़ साहब, आप मुख्य मंत्री जी को अपना मुख्य मंत्री क्यों नहीं मानते? सदन के नेता तो वे हैं ही क्योंकि वोट दिया है जनता ने। इसलिए कृपा करके देश को आगे बढ़ाने की, मैं नहीं मानता तो यहां बैठा होता क्या? आपने ही तो मेरी सिफारिश की थी, भूल गये आप। आप मेरे पर इतनी कृपा करते हो, आप कहते हो आप सदन में नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। आप मुझे भी ले आये और आप भी आ गये। इन सबको यह गणित पता चल गयी तो गड़बड़ हो जाएगी इसलिए ज्यादा अपने को नहीं कहना चाहिए।

राठौड़ साहब, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हम किसान की बात करते हैं। ये कृषि के ऊपर सैस किसने लगाया? पहली दफा हिन्दुस्तान में कृषि के ऊपर सैस स्टार्ट हो गया है। किसानों का गला घोंटने की जो तस्वीर सामने आ रही है, वह हमारी सरकार है, गलती से बहुमत से आ गयी, अहम आ गया और जब अहम आता है, जिद आती है तो उसका नाश निश्चित तौर पर स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है, आप तो धर्म की बात करते हैं, नारद जी का अहम खतम करने के लिए, नष्ट करने के लिए उनको बंदर का स्वरूप मिला या नहीं मिला, हालांकि उस श्राप से विष्णु को नुकसान हुआ, इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं केन्द्रीय बजट की बात करें या यहां के बजट की बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे प्रदेश को नुकसान हो।

यह जो कृषि का सैस स्टार्ट हुआ है आप किसान सम्मान निधि की

(श्री रामनारायण मीना)

बात करते हैं फिर दस हजार करोड़ का बजट केन्द्र सरकार ने कम क्यों कर दिया? ये किसानों की माइनस में उल्टी गणित कैसे स्टार्ट हो रही है? ये राजस्थान में नहीं हो, इसके लिए हम सबको मिलकर के सदन के नेता को बैठकर, समझाकर, जब बजट आए, जो खामियां केन्द्र के बजट में रही हैं, जो नुकसान हमारे देश की सरकार किसानों का करने जा रही है, उस नुकसान की भरपाई हम कितनी कर सकते हैं? कैसे हम किसान को आगे बढ़ाए? क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि पान की दुकान वाला करोड़पति हो जाता है। किसान किस्मत से कोई धंधा करने लग जाए तो बात अलग है, लेकिन वह कभी-भी लखपति नहीं होता। ये भी साफ है कि जब से देश में हमारी वर्तमान सरकार बनी है हमारी जमीन का भाव जिसका दस लाख रुपये बीघा था, तीन लाख में कोई लेने वाला नहीं है। चार साल पहले जो रजिस्ट्री हुई, उस रेट में कोई लेने वाला नहीं है। यह भी सत्य है, पालिसी ऐसी होनी चाहिए जो आम नागरिक का हित करे, आम नागरिक को फायदा पहुंचाए, आम नागरिक के पक्ष में हो।

यह समझ में नहीं आया, एक बुढ़िया 500 का नोट बदलवाने के लिए लाइन में खड़ी है तो फिर देश के सबसे बड़ी पूंजीपति, जिनकी कोरोना में सम्पत्ति बढ़ी और गरीब को नुकसान हुआ, ये तो हम धन्यवाद देते हैं राजस्थान की सरकार को और मुख्य मंत्री जी को कि राजस्थान में कम से कम कोरोना काल में जो व्यवस्था रही, हमने गेहूं भेजा, हमने अनाज भेजा, कौनसा एहसान कर दिया? जो सरकार पहले थी वह भी स्टेट गवर्नमेंट को भेजती थी। आपको पता है, पुराने आदमी है, यह कहना कि आपकी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि देश में गरीब के प्रति क्या भावना बनती जा रही है। गरीब की मजदूरी खतम है, गरीब की नौकरी खतम है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तीन-चार हजार रुपये में अनुबंध पर काम कर रहे हैं। ये पालिसी कब से बनी है? 6 साल से, 7 साल से ऐसी स्थिति क्यों आई? इस पर हमें बैठकर विचार करना चाहिए और इसका निराकरण करना चाहिए।

राजस्थान चूंकि एक स्टेट है, केन्द्र के मुकाबले लेकिन हम संघीय ढांचे में जीते हैं, इसलिए केन्द्र से भी हम मांगे तो उधार की बात करें। पैसा भी पूरा नहीं आ रहा। अब आप गणित उठाकर देख लीजिए। केन्द्र सरकार ने इतना भेजा, इतना भेजा, किसी के काकाजी की जेब का पैसा नहीं है, हमारा

(श्री रामनारायण मीना)

पैसा है। जीएसटी लगाकर सारा कलेक्शन दिल्ली में होने लग गया और वहां से कितना पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस बात की मैं आपसे क्या अर्ज करूं, आप सब जानते हैं। लेकिन एक बात नई हो रही है इस देश में। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ हुआ तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को पता होगा, पूरा पैसा माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिया। उसके बाद दस प्रतिशत दिया। अब ये 40 प्रतिशत का आर्डर भारत सरकार ने कैसे निकाला? स्टेट गवर्नमेंट 40 प्रतिशत देगी, 60 प्रतिशत भारत सरकार देगी। क्या हम एक भी सड़क बना पाएंगे? शिक्षा में 15:85 का रेशो था, आज 35:65 हो गया, जो कुछ भी हो गया, आपको पता है, आप मंत्री रहे हैं। भारत सरकार जिस तरह से हाथ-पांव बांध रही है, सब भूल गए हैं कि आज किसकी सरकार है, कल किसकी सरकार है, कोई पता नहीं है।

छबड़ा से आने वाले माननीय विधायक जी नहीं हैं। उन्होंने हमारे डिविजन से आने वाली माननीय वसुन्धरा जी के लिए कहा कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री हैं, वह बात सही है, लेकिन ये किसने सोचा था कि ऐसा व्यवहार वसुन्धरा जी के साथ बीजेपी में हो जाएगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। इधर भी किसके साथ क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। राजनीति है लेकिन देश जहां का जहां है, प्रदेश जहां का जहां है और हमें सम्मान देना चाहिए।

मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जो कोरोना काल की बात हुई है, पहली दफा, दिल्ली में आपको भी रहने का मौका मिला होगा, मुझे भी एक-दो गलियों में घूमने का मौका मिला। कुछ दिनों के लिए जनता ने भेज दिया। आईसीएमआर में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पहली दफा भ्रष्टाचार की बात सुनी है। डीआरडीओज, जो दिल्ली में हमारे, हैदराबाद में या कर्नाटक में या बैंगलोर में जहां भी हैं, इतने अच्छे डीआरडीओज में इंजीनियरों को कम करने की बात हो रही है, छंटनी स्टार्ट हो रही है। आयुध हम बाहर से मंगा रहे हैं। यह हमें प्रस्ताव पास करना चाहिए और मुख्य मंत्री जी से, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक जी हैं उनसे भी हमें अर्ज करना चाहिए कि देश में करप्शन क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वह स्थिति राजस्थान की नहीं आनी चाहिए क्योंकि राजस्थान आर्थिक दृष्टि से उतना ठीक नहीं है। हम एक दूसरे पर दोष जरूर दें कि साहब, आपने यह कर दिया, मैंने यह कर दिया।

(श्री रामनारायण मीना)

सभापति महोदय, अभी गौ-माता की बात हो रही थी। गाय के नाम पर कोई भी वोट नहीं मांगे। 14 हजार करोड़ का किसी धार्मिक संस्थान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि चंदे के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर खा गए, मैंने अख़बार में पढ़ा था। माननीय रामगंज मण्डी विधायक जी, तिरछे मत देखिए, हमें आपका डर लगता है। 10 हजार करोड़ का विश्व हिन्दू परिषद के खिलाफ। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, एक घटना हो गई, वह चंदा मांग रहे थे, चंदा मांगने का धंधा कौन करता है, आपको सब पता है। धर्म के नाम पर कौनसी पार्टी करती है, कौनसा विंग करता है, हमारा ठेका किस विश्व हिन्दू परिषद् के नेता ने ले रखा है, हमें पता नहीं, ले लेते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उस नेता से, उस धार्मिक नेता से कमजोर हम लोग नहीं हैं। हमारी मां-बहनें, घर की लक्ष्मियां, गाय की तरफ कभी चपाती नहीं फैंकती हैं। वे लोग आज धर्म का ठेका लिए हुए है, जिनके घर की लक्ष्मियां गौ-माता के बजाय पिल्ले को रोटी फैंकती हैं और वह मुंह में नहीं देती हैं। इसलिए देश की जो संस्कृति बिगड़ रही है, उसको कैसे सुधारा जाए, ताकि हम सुधरें, देश सुधरे।

देश की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान की बात कर रहे हैं। माइनस 23 परसेंट जीडीपी की एक रिपोर्ट आई, उसका खण्डन आज दिन तक नहीं हुआ। मनमोहन जी के टाइम पर हम 9 परसेंट जीडीपी की आशा कर रहे थे, हम राजस्थान में इस तरह का कोई काम कैसे करें ताकि वह और हम मिलकर इसको आगे बढ़ाएं।

सभापति महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा। राज्य सरकार के मंत्री जी यहां नहीं है, कोआपरेटिव के बारे में मैंने किसी प्रश्न के मामले में भी अर्ज किया था। कोआपरेटिव में नेहरू गांधी की आत्मा बसती है। आज भी गांव में कोआपरेटिव का प्रसार हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। कोआपरेटिव जिस तरह से खतम हो रही हैं, इंस्टीट्यूशन जिस तरह से खतम हो रही है, आज तिलम संघ जिस तरह से खतम हो गया, यह सरकारी संस्थाएं क्यों खतम हो रही है? इसका मुख्य कारण है कि करप्शन बढ़ रहा है। कौनसी पार्टी, कौनसा नेता, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, इस करप्शन को हम कैसे कम करें, हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा।

बार-बार ऋण माफी की बात आती है। हालांकि कहने को तो कहते हैं राहुल जी ने कह दिया ऋण माफी, ऋण माफ तो हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन वह ऋण नहीं मिला ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जो कहा वह (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आप तो सेठ आदमी हो, बैठो ... (व्यवधान) सेठ को नहीं बोलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं, गरीबी को यह क्या समझें...(व्यवधान) गरीबी को सेठ क्या समझें...

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइये। अपने स्थान पर जाइये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): गरीबी को सेठ क्या समझे। रामगंज मण्डी से आने वाले विधायक जी की रिटर्न देख लो, कितनी खेती है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: रामनारायण जी, एक मिनट। माननीय सदस्य श्री अमीन कागजी, जब कोई सदस्य बोल रहे हैं, आप इतनी परम्परा तो सीखो, आपको उनके सामने से नहीं गुजरना चाहिए। (व्यवधान) रामनारायण जी।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात है, आज +++ किसी देश का गृह मंत्री बन जाए, लुटेरे यदि मंत्री बन जाएं, भ्रष्टाचारी सरकार में शामिल होने लग जाएं, जनता उसको बढ़ाए, फिर एक दूसरे पर दोष देते रहें, उसकी बजाय हमें अच्छी बात पर आगे बढ़ना चाहिए। हम यह कहें कि केन्द्र सरकार में इतने मंत्री हैं, यह-यह आरोप है, राज्य सरकार में कोई है, इसलिए आरोप है।

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जितना कुछ कहा है उसके बारे में मैं एक ही बात अर्ज करना चाहूंगा कि जो ट्रस्टीशिप की बात आई है, यह बिलकुल सही है। राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है, बिजली की बढ़ोतरी मान लीजिए, सड़कों को ले लीजिए, क्या काम हो रहा है। मैं कोरोना की बात नहीं करता। कोरोना के मामले में माननीय राहुल जी ने दो महीने पहले चेताया था, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा था, उसको हमारी केन्द्र सरकार मान लेती, तो यह बढ़ोतरी इस कदर नहीं होती।

(श्री रामनारायण मीना)

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि गांव में जिस तरह का माहौल चल रहा है, गरीबी के नाते मान लीजिए, बेरोजगारी के नाते मान लीजिए, हम सबको मिलकर उस पर कुछ विचार करना चाहिए। विचार के साथ ही हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक भावना पनपे। हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया।

पैनोरमा की बात आई, मैं माननीय मुख्य सचेतक जी को सजेस्ट करना चाहूंगा, जयपुर का रिजिम टाटो का था, चांदाओं का था, पैनोरमा जिस तरह से हो रहा है, मेरा ख्याल है मेरी बात को उप लीडर भी मानेंगे, ऐसे मामले में हमें ध्यान देना चाहिए। बूंदी में बूंदा जी का पैनोरमा आपने घोषित किया, इसके बाद कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी और पैनोरमा की घोषणा का कोई अर्थ नहीं निकला। घोषणा केवल घोषणा नहीं रह जाए, यह सारी बातें देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम इस बात के लिए सदन को धन्यवाद देना चाहिए कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेट्रोल पर जो वैट घटाया है, यह राजस्थान में बहुत अच्छी शुरुआत है।

सभापति महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा। उद्योग धंधों में, वित्त निगम में, वंचित वर्ग के लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है। उनको उतने प्लाट अलाट नहीं हो रहे जितने कि होने चाहिए। जिस तरह से माफिया पनप रहे हैं, पहले पनपे, आज पनपे, मैं इसके लिए नहीं करना चाहता। आप गांवों में जाइये, आपको किसी दुकान पर रेट लिस्ट नहीं मिलेगी। एक कांट्रेक्ट किसी शॉप का है, 6-6 दुकानें वहां बनी हुई हैं, कोई अधिकारी उसके बारे में ध्यान नहीं देता। जन प्रतिनिधि भी परेशान है, गांव का माहौल भी खराब हो रहा है, उस माहौल को ठीक किया जाना चाहिए। हमारी नोनेरा या दूसरी योजनाएं हैं, उनको केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय योजना घोषित करना चाहिए, तब ही निश्चित तौर पर हम कुछ कर पाएंगे।

प्रधानमंत्री जी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की है, आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं किसान हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब प्रधान मंत्री जी ने इसका प्रचारप्रसार किया कि 1975 में गेहूं मिलना चाहिए, उससे कम में नहीं बिकना चाहिए, तो माननीय नेता महोदय, गेहूं 1500 में बाजार में कैसे बिक रहा है? कथनी और करनी में अंतर है।

(श्री रामनारायण मीना)

मैं अपनी बात को धन्यवाद देते हुए समाप्त करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो भी घोषणा की है, गरीब का मुफ्त इलाज हो रहा है, दवाई मिल रही है। एफआईआर ही नहीं बल्कि उसका द्रुत गति से अनुसंधान हो। सिपाही को अधिकार मिला शायद पहली बार पूरी कंट्री में कि सिपाही पढ़ा लिखा है तो अनुसंधान कर सकता है, अनुसंधान हो रहा है। विकास की गति के लिए हम सब को मिलकर करना चाहिए। देश के जो हालात बने हुए हैं, इस सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से भी अर्ज करना चाहूंगा कि वह प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ताकि हमारी योजनाएं बन सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, नमस्कार साहब।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वह पार्टी नारे देने वाली पार्टी है। सदैव ही देश में नये-नये नारों के साथ आती रही है। कभी पार्टी बोलती है गरीबी हटाओ, देश बचाओ, इस नारे से लोगों को गुमराह करते रहे। फिर वाजपेयी जी का शासन आया तो नया नारा दिया, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, तब पूरे देश में इनकी मजाक बनी कि आप यह नारे ही देते रहो गरीब के नाम पर, तो उन्होंने रातों-रात नारा पलटा और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, नारा दिया। ऐसा ही नारा, मारवाड़ी में कहावत है कि मन की बात मुंह पर आ ही जाती है, तो नारा दिया इनके नेता ने 'हम दो हमारे दो', दो कौन, 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): हां, वह हम दो हमारे दो वाली पार्टी के ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): हां, मैं बोल ही रहा हूं। साहब, बात ही है। जब सदन में, लोक सभा में बात उठ सकती है।

श्री सभापति: नहीं, अंकित नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): विधान सभा में क्यों नहीं होगी? लोक सभा में उठ सकती है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: यहीं तक सीमित रहिये आप।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): ठीक है। कोई बात नहीं। पर, वैसे एक बात, सभापतिजी, हुई। कल बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोरोना काल के बाद पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री जयपुर के बाहर गये। यह बड़ी बात रही कि कल जयपुर से बाहर मुख्य मंत्रीजी निकले। जब हम देखते हैं देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी, अमित शाहजी, चाहे कोरोना से अमित शाहजी खुद ग्रस्त रहे हों, जे.पी. नड्डाजी, हम हमारी पार्टी के कटारियाजी, सतीशजी और राठौड़ साहब को देखते हैं, कोरोना काल में दिन-रात जनता के बीच में गये और राजस्थान के मुख्य मंत्री एक साल बाद जयपुर से निकले तो यह बड़े दु:ख की बात है। राजस्थान की जनता यह पूछती है कि एक साल तक राजस्थान प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आमजन के हालचाल क्यों नहीं पूछे? सिर्फ यह डिजिटल टेक्नोलोजी के माध्यम से ही नहीं होता। राजस्थान की जनता, हम गांवों में जाते हैं, पूछते हैं, मुख्य मंत्री कहां हैं। गांव में लोगों के पास, हर किसी के पास डिजिटल नहीं है। आप जयपुर में बैठे हैं, कागजी साहब, आपके पास मोबाइल हो सकता है पर आम जनता के पास, सबके पास नहीं है। यह बात राजस्थान की जनता पूछती है कि आप लोग गांवों में जाते नहीं हो। जाओ भी किस मुंह से, काम आपने कराये नहीं तो यहां जयपुर में ही बैठे रहे, तो आपके पास ये बातें आती नहीं हैं। वैसे भी कल भूकम्प का झटका आया। कहते हैं कि भूकम्प का झटका लगा बताते हैं, देखा तो माचा री ईस टूट गई। भगवान भला करे, किसी के लगी नहीं, कल माचे की ईस टूटी उससे।

यह बात करते हुए कि किसानों की बात पर, कल वे इटली से जाकर नेता आये। थोड़े दिन पूर्व इटली गये और इटली से आये। राजस्थान की पहली जन सभा सम्बोधित करने के लिये वे कल सूरतगढ़ पहुंचे और डेढ़ घंटे तक हवाई अड्डे पर इंतजार करते रहे, क्योंकि वहां पर किसान इकट्ठे ही नहीं हुए। अब किसान क्यों नहीं इकट्ठे हुए, कि देश का किसान जानता है आजाद भारत में किसने किसानों के लिये सबसे ज्यादा काम किया। वह भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें गर्व है, जब हम बताते हैं कि के.सी.सी. योजना लेकर आये उस रेगिस्तान के धोरों से, जहां से हम आते हैं, के.सी.सी. ने जीवनदान के रूप में किसान की मदद की। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों से, क्या के.सी.सी. योजना में किसान की जमीन रहन की जाती है? ये जो तीन कानून

(श्री सुमित गोदारा)

आये हैं, उनमें कोई चीज रहन नहीं की जा रही, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी जा रही तो यदि आज के.सी.सी. योजना लेकर आती, मान लो काल्पनिक बात, तो आप लोग किसानों के हित में वह भी नहीं लाने देते। आप किसान के विरोधी रहे हो। विरोध क्या, सदैव विरोध है। के.सी.सी. से देखो, किसान कितना आगे बढ़ा।

फसल बीमा योजना, भादरा से आने वाले विधायक गिना रहे थे कि फसल बीमा योजना में मैंने इतना क्लेम दिलाया। वे देश के प्रधान मंत्री का तो धन्यवाद देते जो फसल बीमा योजना लेकर आये और किसानों को कितना लाभ मिला। हम बात करते हैं डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, डी.बी.टी., जो योजना मोदीजी लेकर आये, एक समय था जब देश के प्रधान मंत्री हमारे बीकानेर में बज्जू में आये। राजीव गांधीजी बोले कि दिल्ली से सौ रुपये भेजता हूं तो गांव में 15 रुपये भेजते हैं। इस कोरोना काल में हमने देखा कि मोदीजी दिल्ली से खटका बजाते और सौ के सौ रुपये गांव की ढाणी में आदमी के पास पहुंचते हैं। यह किसानों को लाभ मोदीजी ने दिया।

प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में आप लोग पूछते हो कि छह हजार रुपये कम हैं। हां, क्योंकि आप यहां पर समृद्ध व्यक्ति बैठे हो पर जो गरीब किसान, 68 परसेंट देश की आबादी का जो किसान है, जिसके पास 8 बीघा से कम जमीन है, उसका छह हजार में घर का महीने का खर्चा चलता है। यह किसान के लिये देश के प्रधान मंत्रीजी ने कार्य किया। आप कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): छह हजार रुपये साल के हैं, महीने के नहीं। (व्यवधान)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): रफीक खानजी, सुनिये। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं। आप तो शहर में रहते हैं, आपको क्या पता, क्या लाभ होता है। कृषि सिंचाई योजना, डिग्गी, आपके, हमारे, खाजूवाला से आने वाले विधायक भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है, बात सही कह रहे हैं।

कृषि सिंचाई योजना, तीन लाख रुपये से डिग्गी बनती है और उसमें पिछले दो साल से राजस्थान सरकार ने दो लाख का अनुदान नहीं दिया। केन्द्र सरकार ने एक लाख का अनुदान भेज दिया। उसे भी राजस्थान सरकार ने चार

(श्री सुमित गोदारा)

महीने तक अपने पास रखा, किसानों के खाते में नहीं दिया। पिछले दो वर्ष में एक भी डिग्गी स्वीकृत नहीं की है। किसान ढूंढ रहा है, कहां हैं राजस्थान के मुख्य मंत्री और ये कांग्रेस के नेता जो अपने आपको किसान हितैषी कह रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि जो डिग्गी हमें जीवनदान देती है, पानी का स्टोरेज होता है, किसान को कितना लाभ होता है और दो साल से राजस्थान सरकार ने एक भी डिग्गी स्वीकृत नहीं की और स्वयं अपने को किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं।

आप बात करते हैं किसानों के लिये कृषि योजना में ट्यूबवैल की, 2012 से अभी तक आपके पेंडिंग है। 2012 वाले भी अभी तक आपने कृषि कनेक्शन जारी नहीं किये हैं, नौ साल हो गये हैं। हम बात करते हैं बूंद-बूंद सिंचाई योजना की, जो राजस्थान के धोरों में और प्रत्येक जगह क्रान्ति लेकर आई, स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब यह योजना लेकर आये। ट्यूबवैल, हमारे क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की अनुशंसा की, भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने की। ये बी.जे.पी. के काम हैं।

वर्तमान में अशोक गहलोतजी मुख्य मंत्री हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अगर आप इतने ही पेट्रोल-डीजल के दामों पर बात करते हैं तो हम जब गुजरात जाते हैं तो वहां पेट्रोल-डीजल सस्ता है। हम पंजाब जाते हैं, वहां पेट्रोल -डीजल सस्ता है, हरियाणा जाते हैं, पेट्रोल-डीजल सस्ता है। पंजाब में तो आपकी सरकार है, फिर राजस्थान में आप यह बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किसान के हितैषी हैं तो फिर काम करके दिखाओ, सिर्फ घड़ियाली आंसू क्यों बहाते हैं?

माननीय सभापतिजी, कल कार्यक्रम में जो कांग्रेस के नेता आये तो उसमें भीड़ इसलिये नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ने और सरकार ने कहा था कि आई.जी.एन.पी. प्रथम चरण में हम चार में से तीन ग्रुप, जो पानी का रेगुलेशन बनाया था, उसमें चार में से तीन ग्रुप पानी का रेगुलेशन 16.11.2020 से 07.03.2021 तक, पांच बारी देने की बात की। परन्तु क्या हुआ? चौथी बारी पिट गई और पांचवीं बारी में तो हाथ खड़े कर दिये। हाथ खड़े कर दिये, किसान कह रहा है, मेरी फसल पकाव पर आने वाली है, पानी कहां है? पानी तो गया, अशोक गहलोतजी से पूछो, कभी उन्होंने काम सम्भाला। वह तो राहुल गांधीजी कल आये, पर किसानों ने उनको जवाब दे दिया कि हम

(श्री सुमित गोदारा)

आपकी बातों में नहीं आने वाले। हमें पानी चाहिए, पानी। पानी यह सरकार नहीं दे रही है। ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं। यदि आप किसान हितैषी हो तो 10 हजार, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार, वसुन्धरा जी ने किसानों के बिल में माफी दी, 833 रुपये प्रति महीना, उससे कितने गरीब किसानों को लाभ हो रहा था, वह योजना पुन: लागू करो। आप बात किसानों के हित की करते हो तो पी.एम.जी.एस.वाई. रोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 10 साल केन्द्र में मनमोहन सिंहजी की सरकार रही, उन्होंने उन सड़कों के नवीनीकरण पर कोई कार्य नहीं कराया। भला हो देश की जनता का, मोदीजी प्रधान मंत्री बने और आप देखिये, पिछले 5-6 सालों में जहां-जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पूर्व में सड़कें बनीं, उनका जबरदस्त बजट आ रहा है। पूरी सड़क को वापस खोद कर और चौड़ी करके नई सड़कें बनाई जा रही हैं। यह किसान हित में प्रधान मंत्रीजी कर रहे हैं।

राजस्थान सरकार अगर किसान हितैषी है तो मंडी की सड़कों पर आपने क्यों रोक लगाई हुई है, जिससे आम किसान को लाभ होता है। आपने मंडी की रोड पर रोक लगाई। किसान किस तरह पीड़ित है, वी.सी.आर. के नाम पर आप गांव-गांव में जाओ, लोग परेशान हैं कि वी.सी.आर. के नाम पर तो हेला मचा रखा है।

सभापतिजी, हमने सुना कि कुछ दिन पूर्व सी.एम. साहब के आगे मंत्री भी गये और बोले कि यह वी.सी.आर. को रोको। पर क्या करें, वे भी नहीं कर रहे। एक और, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बात उठाऊंगा, इसमें राजनीतिक द्वेषता भी वी.सी.आर. के माध्यम से विभाग के द्वारा निकाली जा रही है। यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वह गरीब किसान, जिसको बिजली का कनेक्शन आप दे नहीं रहे, ढाणी में लाइट आप दे ही नहीं रहे और वी.सी.आर. के नाम पर उसको आप लूट रहे हो। यह आपकी किसान हितैषी सरकार है? तभी तो आप अपने नेताओं को कहीं ले जाओ, लोग किसान के नाम पर भ्रामक नहीं होंगे। आप गुमराह करना चाह रहे हो राजस्थान की जनता को, पर राजस्थान की जनता आपसे गुमराह नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया, सवा दो साल के काल में आपने कोई कार्य नहीं करके दिखाया, जिससे जनता विश्वास करे।

(श्री सुमित गोदारा)

कल ही इस बात के समाचार आये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केन्द्र सरकार का, जिन्होंने सेन्ट्रल कमीशन ने जयपुर के लिये 270 करोड़ रुपये इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेडिसिन और इंस्टीट्यट आफ वायरोलोजी के लिये, बीमारियों के लिये केन्द्र सरकार ने जयपुर के लिये आबंटन किया है। मैं इसके लिये केन्द्र सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कोरोना, डेंगू इन बीमारियों के लिये जयपुर में बजट पास किया।

दूसरी तरफ हम देखते हैं, राजस्थान सरकार, माननीय सभापतिजी, कोरोना काल में राजस्थान सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है लेकिन हकीकत यह है कि, मैं इस चिकित्सा क्षेत्र से थोड़ा जुड़ा हुआ हूं कितने लोग मारे गये हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाया है। आपने हास्पिटल्स बंद कर दिये सिर्फ कोरोना के नाम पर। लोग कितने हादसे, कितनी बीमारियों से, किडनी से दु:खद मृत्यु हो जाये, उसका जवाब आपकी सरकार कभी नहीं दे पायी। अस्पताल बंद रखे। भामाशाह की योजना बंद रखी। भामाशाह योजना से कौन लाभान्वित हो रहा था? गरीब व्यक्ति लाभान्वित हो रहा था। आप पर यह कलंक जरूर लगेगा कि कितने लोग कोरोना में आपकी लापरवाही के कारण मारे गये। न राजस्थान सरकार के मुखिया सचेत रहे, वह तो जयपुर से, जैसे मैंने कहा, बाहर ही न निकले, और न चिकित्सा मंत्री कहीं बाहर निकले। आज सवा दो साल हो गये, बीकानेर मेडिकल कालेज है, हमने कभी चिकित्सा मंत्री को बीकानेर में नहीं देखा कि दौरे पर आये और लोगों का ध्यान रखें कि कैसी चिकित्सा व्यवस्थाएं चल रही हैं। पूरे विभागों का यही हाल है।

जो आप आबकारी नीति लाये हो, मैं कहूंगा, ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा हूं, बहुत से युवा थे जो सोचते थे हमें रोजगार मिलेगा, कि हमारे को भी कुछ न कुछ मौका मिलेगा, पर यह सरकार, यह सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाती है। जो पैसे वाले लोग हैं, वे इस आबकारी नीति में सारे के सारे भाग लेंगे। एक वर्ग विशेष को सहयोग करने के लिये राजस्थान सरकार यह योजना लायी है। युवाओं के हित का दोहन करते हुए यह आबकारी नीति का पुरजोर विरोध पूरे राजस्थान की आम जनता करती है कि यह सिर्फ पैसे वाले पूंजीपतियों की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में मैं आपको बीकानेर का एक छोटा-सा उदाहरण दूंगा कि हमारे बीकानेर में जिस

(श्री सुमित गोदारा)

तरह कौन बनेगा करोड़पति सीरियल आ रहा है, वैसे ही अख़बार पिछले 40 दिनों से भरे हुए आ रहे हैं कि कौन बनेगा कोटगेट थाने का थानाधिकारी, और यह हकीकत है कि अख़बार में सब जगह यह आ रहा है 40 दिन से। कोटगेट थाना जो बीकानेर का प्रमुख थाना है, जहां पर सारे बाजार हैं, सारा रेलवे स्टेशन उसके अंदर आता है, इतना बड़ा थाना और उसमें 40 दिन से थानाधिकारी की पोस्टिंग नहीं की जा रही है और नये-नये वह नाम आते हैं चार कि इसमें से कौन बनेगा? तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कहां पर कानून-व्यवस्था जा रही है। पूछने पर यह बातें आती हैं कि वहां के बड़े नेता हैं, उनका परिवारजन जिसको लगाएगा वह ही लगेगा, तो यह तो थानों का हाल है।

मेरे क्षेत्र लूणकरणसर में ही जामसर में कुछ दिन पूर्व एक हत्याकांड हुआ। मैंने पूर्व एस.पी. साहब को निवेदन किया और कई बार जाकर कहा कि इस थानाधिकारी को हटाओ, यह वहां पर बदमाशी करके माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है और जिस दिन वहां पर हत्या हुई, उस थाने के दो सिपाही वहां पर मौजूद थे, पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पूरे प्रदेश में यह हाल है। हम तो यह चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार योगी आदित्य नाथ की सरकार से सीखें कि कानून-व्यवस्था कैसे मेंटेन की जाती है। सीखकर आओ कुछ न कुछ, कैसे बात की जाए। आप भेजो और यदि आपके पास काम्पीटेंट आदमी नहीं है तो जिस तरह हमारी केन्द्र सरकार ने हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर को रखा तो उसी तरह आप भी हरीश मीणा जी या किसी पुलिस अधिकारी को मंत्री बनाओगे तो वह तब कुछ न कुछ तो पुलिस व्यवस्था को सम्भालेगा, नहीं तो सवा दो साल हो गये, मेरे पास बैठे अलवर के विधायक, इनकी गाड़ी ठोक कर हिस्ट्रीशीटर जा रहे हैं। सब जगह यही हाल है, सारा राजस्थान डरा हुआ है और कांग्रेस के विधायक भी सहमत हैं, यह हकीकत बात है, वह भी डरे हुए हैं कि यही राजस्थान की कानून-व्यवस्था का हाल है।

हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन की नीति पर आप कोई विशेष नीति लेकर नहीं आये। मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि मेरे एक मित्र कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश जाकर आये और उनका न कोई राजनीतिक दल से संबंध था। उन्होंने एक बात कही कि यू.पी. में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि, साहब, मैंने गलती से ट्रैफिक लाइन क्रास कर दी, नया

(श्री सुमित गोदारा)

आदमी था, नहीं जानता पर यू.पी. का पुलिस का कर्मचारी आया और मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, पर आइंदा आप ध्यान रखना। वह बोला कि यदि मैं राजस्थान में होता तो बाहर की गाड़ी देखते ही यहां के पुलिस वाले उस पर टूट पड़ते, अधिकारी टूट पड़ते, यह देखो क्या दुर्भाग्य है? क्या राजस्थान की हम छवि बना रहे हैं? पधारो म्हारे देश, किस बात की?

मैं मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण बताता हूं। वहां पर एक पुलिस की इंटरसेप्टर गाड़ी है, दो साल पहले खड़ी होती थी। वह बाहर की जो भी गाड़ी आती, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की, उसको फट रोकते और उससे पैसे लूटते, दिन का लाख रुपये का कलेक्शन करते। वहां मौके पर जाकर मैंने यह कहा कि यहां पर खड़े हो गये तो ध्यान रखना आइंदा से। यह ऐसी लूट मचा रखी है, तो कहां से हमारे यहां पर पर्यटन आएंगे? जब हमारे अधिकारियों पर ही अंकुश नहीं, जब हमने उनको लूट की खुली छूट दी हुई है हम सीखें उत्तर प्रदेश से, हम सीखें दूसरे राज्यों से, हमारे पर्यटन के लिए हम अपने अधिकारियों को भी यह कहें कि जो बाहर से पर्यटक घूमने आ रहा है तो राजस्थान के लिए उसकी भावना ऐसी जाए कि हां, यहां का प्रशासन, यहां की जनता जिस तरह से प्रेम करती है, प्रशासन भी हमारा वैसा स्वागत करता है और यदि किसी ऐसे अधिकारी के खिलाफ, पर्यटकों के साथ कोई दुर्व्यवहार की शिकायत आए तो तुरंत उसको नौकरी से बर्खास्त करने की कड़ी कार्यवाही करने का सरकार आदेश दे।

वैसे हमारे बीकानेर जिले से ऊर्जा व पेयजल मंत्री आते हैं। ऊर्जा और पेयजल में हमारे यह हाल हैं कि बीकानेर में किसान यह कह रहे हैं कि जब से यह सरकार आई है और ऊर्जा मंत्री बीकानेर से बने तो हमें बड़ी आशा थी कि किसानों को पूरी लाइट मिलेगी और ट्यूबवैल नए खुदेंगे और पानी की व्यवस्था सुचारु होगी, पर हालत यह है कि किसान को वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अनेक जगह पर बड़े एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाने की हम बात कर रहे हैं पर कोई कार्य नहीं हो रहा है और आप यह विडम्बना देखें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में लूणकरणसर क्षेत्र में नौरंगदेसर और महाजन में दो ए.ईएन. आफिस खोले गये, पर इस सरकार ने आते ही, न उनको वित्तीय स्वीकृति दी और दोनों को बंद करने के आदेश दे रहे हैं। जब वहां के, बीकानेर जिले के ही मंत्री हैं, और देखिए ग्रामीण जनता का आप क्या ध्यान दे रहे हैं? ट्यूबवैल खुद नहीं रहे हैं, उनके एक एक्स.ईएन. हैं खास, वह सारे के सारे जिले में

(श्री सुमित गोदारा)

पानी की व्यवस्था अपने हिसाब से अलग ही करते हैं। ट्यूबवैल चाहे खुदे या नहीं खुदे पर मंत्रीजी खुश रहें, यह हाल है बीकानेर जिले का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया...एक बात मैं और कहूंगा कि पंचायती राज में जिस तरह आपने जानबूझकर एक साल चुनाव लेट कराये, प्रदेश की जनता ने, प्रदेश अध्यक्ष हमारे सतीशजी पूनियां के नेतृत्व में आपको जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और प्रधान बनाकर कांग्रेस को जो गांवों की पार्टी बताते थे, उनको खतम किया।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री मदन प्रजापत।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया। कई विरोध में और कई पक्ष में अपनी भावना व्यक्त की। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में, समर्थन में खड़ा हुआ हूं। 36 कौम की जनता ने भरोसा करके, आशीर्वाद देकर मुझे दूसरी बार इस राजस्थान की विधान सभा में भेजा है कि यह नौजवान, हमारा बेटा, हमारा भाई हमारे मुद्दे, हमारे क्षेत्र की बात मजबूती से उठाएगा, तो मैं 36 कौम का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा और एक-एक बात उठाऊंगा, गूंगा बनकर नहीं बैठूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो असंभव को संभव किया कि जिस वर्ग और जाति से मैं आता हूं, एक साधारण परिवार के व्यक्ति पर दूसरी बार जो भरोसा किया है और मैं कांग्रेस पार्टी का भी आभारी हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा किया।

आज विधान सभा में कई बातें आईं लेकिन व्यक्ति के लिए पद बड़ा नहीं होता है। चाहे एम.एल.ए. हो, चाहे अन्य पद पर हो, जनता का विश्वास बड़ा होता है। इसी विश्वास के साथ, माननीय सभापति महोदय, एक कहावत भी है और एक समय भी था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। आज किसान की हालत और दुर्दशा देखते हैं तो कई महीनों से सड़कों

(श्री मदन प्रजापत)

के ऊपर, आज इस देश के इतने बड़े लोकतंत्र के ऊपर अपन को गर्व है लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है और आज एक तरह से किसानों के साथ जो मजाक बनाया है, आज किसानों के हालात, आज उनके बारे में ऐसे शब्द कह रहे हैं कि वही किसान, वही व्यक्ति अगर इनके पक्ष में बात करता है तो वह राष्ट्र भक्त, देश भक्त और अगर विरोध में बात करता है तो वही व्यक्ति खालिस्तानी, देशद्रोही और आंदोलनजीवी जैसे अपशब्दों से उसे अपमानित किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे शब्द उनके लिए शोभा नहीं देते। वह अन्नदाता है, वह किसान है, इस प्रकार की जो दुर्दशा और किसानों की जो हालत की है, आज कोई सुनने वाला नहीं है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि विश्व में जो इतना बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में किसान और अन्नदाता की सुनने के लिए कोई नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज रिफाइनरी के बारे में मैं यह निवेदन करता हूं कि स्थानीय लोगों को जो उम्मीद थी कि आज बाड़मेर जिले के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा लेकिन वहां पर बाहरी लोगों को रोजगार ज्यादा होने की वजह से, उदाहरण के तौर पर मैं यह देखता हूं कि गुजरात में खेती की जमीन कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें कानून बन गये कि दूसरे राज्यों के आदमियों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो आज रिफाइनरी में बाहरी लोगों की इतनी भरमार है कि एक मजदूरी पर उनको नहीं लगाया जा रहा है। आज तो शुरुआत है लेकिन धीरे-धीरे जन भावना में ऐसा विद्रोह अगर खड़ा हो गया तो बाद में कानून कंट्रोल में नहीं रहेगा। जनता अगर सड़कों पर आ गयी कि हमारा यह स्थानीय हक है और कम से कम आधे लोग स्थानीय हो, मजदूर हो, उनकी गाड़ी हो, साधन हो लेकिन आज इस तरह से रिफाइनरी में जो न्याय नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि जब जनता का आक्रोश फूटे, विद्रोह हो उससे पहले न्याय किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को मदद मिल सके। आज स्थानीय लोगों को रोजगार देकर न्याय प्रदान कराएं। अधिकारी इसको गंभीरता से लें, कोई मामूली बात नहीं लें, नहीं तो बाहरी लोगों को भारी विद्रोह के साथ में स्थानीय लोग जूतों के जोर से हटाएंगे। इसलिए इसको गंभीरता से लें और 36 कौम को रोजगार दें।

(श्री मदन प्रजापत)

कई ऐसी कम्पनियां हैं, चाहे टाटा है, टोयोटा है, एल.एण्ड टी. है, उनको वे गंभीरता से नहीं लेकर, स्थानीय लोगों को मदद नहीं कर रही हैं। कई बड़े अधिकारियों के फोन के ऊपर सांठगांठ करके यह जयपुर से ही इस तरह के हथकंडे अपनाये जा रहे हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी नहीं समझें कि वे कमजोर हैं, इसलिए हम उनका फायदा ले रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इनके अलावा कल जब मैं सुन रहा था, कई व्यक्ति बोले भी लेकिन पूरे विपक्ष के माननीय वरिष्ठ सदस्य भी हां में हां मिला रहे थे। जब यह ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य हमारे देश की आजादी के आंदोलन में जिनका योगदान रहा और प्रथम शिक्षा मंत्री के बारे में, मौलाना अबुल कलाम जी के बारे में बोले और बाकी कह रहे थे जोहार, शाबाश। उनके बारे में ऐसी हल्की बातें करना, यह शोभा नहीं देता। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और मौलाना साहब के जूतों के बराबर भी मुकाबला आप नहीं कर सकते। उनका देश की आजादी में योगदान है। इस देश में योगदान है। दूसरी बात, वह कह रहे थे 22 सालों से गुजरात में कांग्रेस नहीं है, इसलिए आज दंगे-फसाद नहीं हो रहे हैं। क्या आप नहीं हैं? कांग्रेस नहीं है तो इसका मतलब आन्दोलन में आपकी भूमिका थी।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने सोनिया गांधीजी का जिस तरीके से विरोध किया, भारत की इस बहू ने यह साबित कर दिया कि देश में महात्मा गांधीजी के बाद में किसी ने त्याग का अगर उदाहरण दिया है, त्याग किसी ने किया है तो उनका नाम सोनिया गांधीजी है। सोनिया गांधीजी का विरोध कई बार किया गया। उनके अलावा अभी कल कह रहे थे वह व्यक्ति पैसा नहीं दे सकते। राम के मंदिर में किसी के बाप की बपौती और ठेका नहीं है। भगवान राम किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, भगवान राम विश्व के हैं, पूरे संसार के हैं। हम भी भागीदार हैं। आपको अधिकार नहीं है, कौन पैसा देगा और कौन पैसा नहीं देगा। भगवान राम के नाम पर, कभी सैनिकों के नाम पर, कभी गौ-माता के नाम पर वोटों की राजनीति करने में ही माहिर लोगों को जनता समझ चुकी है। माननीय सभापति महोदय, आपके साथ में है वह देशभक्त। अगर विरोध में बात करता है वही व्यक्ति रातों-रात देशद्रोही हो जाता है। आपके पास में कोई फिल्टर मशीन है कि वह व्यक्ति आपके पक्ष में

(श्री मदन प्रजापत)

है, हां में हां मिलाए, उस देशभक्त को, आपके प्रमाण पत्रों की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज हर बच्चा, हर आम आदमी जब पूछता है कि राजस्थान का विकास पुरुष कौन है? उसका उत्तर होता है लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत। माननीय सभापति महोदय, आपस में इनके होड़ लगी हुई है कि मैं बड़ा भाषण दूं, मैं बड़ा भाषण दूं। मैं बड़ा हो जाऊंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप चार सालों के लिये हैं। एक साल पहले मैडम वसुन्धराजी रथ पर सवार होकर आएंगी और आप पीछे दौड़ोगे कि मुझे पीछे बैठने को जगह मिले। आप सैकण्ड पंक्ति वाले हो। फर्स्ट पंक्ति में तो मैडम आ रही हैं। उनकी तैयारी है, आप फिजूल में क्यों परेशान हो रहे हो?

माननीय सभापति महोदय, आपस में यह होड़ लगी हुई है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, बार-बार यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता तो आज आप भारत सरकार में नहीं होते। यह पवित्र लोकतंत्र है और पवित्र लोकतंत्र में कांग्रेस ने न्याय किया है और न्याय के साथ में देश में राज करने के कारण आज एक साधारण व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री बना है। 70 सालों में जो इमारतें खड़ी कीं, जो संस्थाएं बनायीं, आज आप 6 सालों में बेचने का काम कर रहे हैं। वहीं बातें जब हम सुन रहे थे, ओबामा, ओबामा, लाल आंख दिखाकर बात करनी चाहिए, लाल आंख आज सफेद क्यों हो गयी? ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। झूला झुलाए और झूला झूलने वालों ने देश की धरती के ऊपर जो कब्जा किया है, आज अपन बर्दाश्त नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना महामारी को बढ़ावा मिला नमस्ते ट्रम्प के कारण। डिले हुआ और आनन-फानन में लॉकडाउन लगाने की वजह से रेल को भेजा कहीं जा रहा था, रेल जा कहीं रही थी। यह इनका प्रबन्ध और पोल इनके सामने खुली है। आज कितने ही मजदूरों की मौतें कोरोना में हो गयीं, कितने ही भूखे लोग सड़कों के ऊपर पैदल गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान की जनता आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने आज कोरोना जैसी महामारी में विशेष प्रबन्ध और मेहनत की और उनकी सूझबूझ और उनके अनुभव के कारण राजस्थान आज

(श्री मदन प्रजापत)

देश में मॉडल साबित हुआ है। लोग कह रहे थे कि गुजरात मॉडल, आज गुजरात मॉडल नहीं, देश का अगर कोई मॉडल है और हर क्षेत्र में कोई अव्वल है तो राज्य का नाम राजस्थान है और राजस्थान का नेतृत्व करने वाले लोकप्रिय, गरीबों के मसीहा, उनका नाम अशोक जी गहलोत है। माननीय सभापति महोदय, दिन-रात उन्होंने मेहनत की और महंगाई की बात हो या दूसरी, हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के ऊपर आप चुप क्यों हैं? 300 रुपये की गैस की टंकी के 900 रुपये हो गये। आपकी स्मृति ईरानी जी कहां गयीं, जो आये दिन टंकी ऊपर उठाये बैलगाड़ी के ऊपर नाटक कर रहे थे। आज 900 रुपये में गैस सिलेण्डर मिल रहा है। आप चुप क्यों हैं?

माननीय सभापति महोदय, बार-बार हरियाणा से तुलना की जा रही है। मैं विपक्ष के सम्माननीय साथियों से इज्जत के साथ निवेदन करता हूं कि आप तुलना हरियाणा की करते हैं, आप तुलना मध्य प्रदेश की क्यों नहीं करते? वहां रेट कितनी है, क्या महंगाई है? क्या तेल के भाव हैं, वहां के हालात क्या हैं? आप एक छोटे राज्य हरियाणा की तुलना करके अगर आप इतने ही जनता के हितैषी हैं तो अपन सभी मिलकर प्रस्ताव पारित करें और भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी से निवेदन करें कि गैस के दाम और तेल के दाम कम करें। आज नेपाल में हिन्दुस्तान से तेल जा रहा है और वहां हिन्दुस्तान से सस्ता तेल क्यों मिल रहा है? यह जवाबदारी किसकी बनती है? यह इधर बातें करने से जनता आपको माफ नहीं कर सकती।

माननीय सभापति महोदय, आज यहां आन्दोलनजीवी जैसा शब्द माननीय प्रधान मंत्रीजी के मुंह से शोभा नहीं देता। जीवन भर अटलजी और आडवाणी जी ने आन्दोलन किये। इनके कारण ही आप पहले मुख्य मंत्री बने। केजरीवाल और अन्ना हजारे जी ने, बाबा रामदेव ने मेहनत की और अडाणी और अंबानी के आशीर्वाद से आप प्रधान मंत्री बन गये। आन्दोलन करने वालों के लिये यह शब्द शोभा नहीं देता, अगर आप इनको आन्दोलनजीवी कह रहे हैं तो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज भी बैठे हैं। आडवाणी जी ने जिन्दगी भर आन्दोलन किये और सड़कों के ऊपर मेहनत की, क्या उनके लिये भी यह शब्द लागू हो गये? आज आन्दोलन करना इस लोकतंत्र में आम आदमी का अधिकार है, हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। किसान कह रहा है, हमारा भला

(श्री मदन प्रजापत)

नहीं करो और मेहरबानी करके जो नियम है, वही लागू करो, पर आप कह रहे हैं हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका भला कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मना कर रहा है तो आप जबरदस्ती किसको फायदा देने के लिये कर रहे हैं?

कई बातें आपने कीं। ए फोर आदर्श घोटाला, के फोर कोयला घोटाला, टू जी, फोर जी, सब निर्दोष साबित हुए और आपने इतना बवंडर मचा दिया। आज जनता पूछना चाहती है कहां है आपका जन लोकपाल? हम कहते थे लोकपाल, आप कहते थे जन लोकपाल। आप लोकायुक्त की बात करते हैं। जन लोकपाल कहां है? आपका मुंह चुप क्यों है? गरीबों के मसीहा और लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवा और पेंशन योजना देकर यह साबित कर दिया कि गुजरात के बजाय राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने, आपको मुंह से कहना पड़ा कि यह तो खैरात बांट रहे हैं, यह तो रेवड़ियां बांट रहे हैं। खैरात और रेवड़ियां गरीब का हितैषी बांट सकता है। उन्होंने महसूस किया गरीब की पीड़ा क्या हो सकती है। गरीब अस्पताल में महंगा इलाज नहीं करवा सकता। इन्होंने दवा फ्री करके यह साबित कर दिया कि गरीब, किसान और मजदूर का कोई हितैषी है तो राजस्थान में उस व्यक्ति का नाम अशोक गहलोत है।

माननीय सभापति महोदय, आज कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही इनकी कथनी और करनी में अन्तर रहा है। जब प्रधान मंत्री नहीं बने तो एफ.डी.आई. का विरोध किया, आधार का विरोध किया, नरेगा का विरोध किया, जी.एस.टी. का विरोध किया और बनने के बाद में आज क्या हालात हैं? देश निजी हाथों में जा रहा है। जयपुर का एयरपोर्ट चला गया। कई हवाई अड्डे गये। आज कई रेलें निजी हाथों में दे रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): दो मिनट में, माननीय सभापति महोदय, आज मन की बात कर रहा हूं। लोकतंत्र है, कोई जरूरी नहीं कि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, वही सही है। आम आदमी को भी बोलने का अधिकार है। यह सुनने के बजाय, इतने घूमने के बावजूद भी, झूला झुलाने के बावजूद भी, खुद चाय पिलाने के बावजूद भी आज अपनी विदेश नीति फेल क्यों है? माननीय सभापति महोदय, जनता समझ गयी कि आज के समय नफरत और भय का माहौल है। इतने बड़े लोकतंत्र को एक मजाक

(श्री मदन प्रजापत)

बना दिया है। पत्रकार दबाव में हैं। तानाशाही रवैये के कारण किसानों के साथ जो मजाक किया जा रहा है। लोकतंत्र के बाकी स्तम्भ कमजोर कर रहे हैं।

माननीय राठौड़ साहब कह रहे थे गैंगवार, अपराध, यह ऐसे शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देते, क्योंकि आपके ऊपर दाग लगा है और दाग लगा हुआ व्यक्ति गैंगवार की बात और अपराध की बात नहीं कर सकता। कल सूदखोर और ब्याजखोर की बात आयी। मेरा आरोप है कि केन्द्रीय मंत्री और संजीवनी घोटाले में क्या संबंध है, क्यों नहीं खुलासा कर सकते? माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के साथी महंगाई पर चुप क्यों हैं? ब्याजखोरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही। आप कह रहे हो एक, दो, तीन, दस, दो करोड़ रोजगार कहां हैं, 15 लाख रुपये कहां हैं? जनता पूछ रही है।

बी.जे.पी. के राज में मुकदमे भी दर्ज नहीं हो रहे थे और आप तुलना कर रहे हो मुकदमों की। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी और पूरी सरकार को, पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं कि एक दिन में ए.सी.बी. के धड़ल्ले से छापे पड़ रहे हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यह अगर किसी में हिम्मत है तो वह अशोक गहलोत सरकार में है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री बिहारीलाल जी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपके समय कोई बाबू, पटवारी, लाइन-मैन पकड़ा जाता था, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. के ऊपर हाथ डालने के लिए हिम्मत नहीं थी।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, एक मिनट की बात करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी मांग है कि बालोतरा को जिला बनाया जाए और बालोतरा जिला बनने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल जी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। अभिभाषण संविधान की प्रस्तावना व कर्तव्यों के वाचन से

(श्री बिहारीलाल)

प्रारम्भ हुआ। अधिकारों की तरफ भागती दुनिया में कर्तव्यों का बोध कराने के लिए मैं महामहिम महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा।

अभिभाषण नीति पत्र कहा गया है, सरकार के नीतिगत फैसलों का आईना कहा गया है। नीतिगत बात तो कहीं थी ही नहीं, अनीति ही अनीति, राजनीति ही राजनीति, स्वयं महामहिम भी पश्चाताप कर रहे होंगे कि संविधान की मर्यादाओं में बांधकर एक घंटे तक क्या सफेद झूठ बुलवाया गया। भादरा से आने वाले कामरेड साथी आज यहां उपस्थित नहीं हैं, उनका भला हो कि पूरे एक घंटे तक संविधान की मर्यादा में बांधकर सरकार ने महामहिम से तो सफेद झूठ बुलवाया लेकिन कामरेड साथी ने हमारे किसी के कानों में वो बात पड़ने ही नहीं दी, उस सफेद झूठ को कानों तक आने ही नहीं दिया।

जब कामरेड साथी बोल रहे थे, मुख्य मंत्री जी विराजमान थे तो मुख्य मंत्री जी ने पीछे की बैंच की तरफ मुड़ करके देखा। अब जब मुख्य मंत्री जी पीछे देखते हैं तो पीछे कौन है, पीछे एम स्क्वायर हैं, चीफ व्हिप महेश जोशी जी हैं, डिप्टी चीफ व्हिप महेंद्र चौधरी जी हैं, उनको कहा कि ये कारनामे आपके हैं, चाबी भर के छोड़ दी। वो भागे-भागे आये, कामरेड को मनाने आये, कामरेड माने नहीं, मिसगाइडेड मिसाइल दागी जा चुकी थी, अब वो रुकने वाली नहीं थी। हरीश जी भी आये, शान्ती जी भी आये, रामलाल जी भी आये लेकिन कोई काम नहीं आये, एक घंटे तक वही चलता रहा।

अगले दिन उसी अभिभाषण पर बोलते हुए कामरेड साथी कह रहे थे कि महामहिम का अभिभाषण अद्‌वितीय था। वाह कामरेड भाई, आपने सुना नहीं, किसी को सुनने नहीं दिया फिर भी अद्‌वितीय था। अब अद्‌वितीय कैसे था, सभापति जी, दो बड़ी बातें उन्होंने अपनी बात में कहीं, नरेगा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाई, बम्पर पैसा मिला। किसने दिया? कोरोना काल में हजारों करोड़ का अतिरिक्त बजट केंद्र सरकार ने दिया। यहां काम किसने किया, पायलट ने किया।

दूसरी बात फसल बीमा की, जो अभी हमारे लूणकरणसर से आने वाले साथी ने भी जिक्र किया, कामरेड साहब फसल बीमा पर एक्टिव रहते हैं, फसल बीमा का पूरा फायदा लेते हैं, किसानों को दिलाते हैं, उसके लिए मैं

(श्री बिहारीलाल)

उनका धन्यवाद करता हूं लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा किसने लागू किया? दोनों बातों में जिसके लिए अभिभाषण को उन्होंने अद्वितीय बताया, दोनों बातों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का और केंद्र की सरकार का अहम योगदान है। आज बलवान भाई यहां नहीं हैं, कल मेरी उनसे बात हुई थी, आज मेरे साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते। कामरेड गिरधारी जी बैठे हैं, बलवान जी नहीं हैं तो, गिरधारी जी, आप भी कहिए इन दोनों बातों के लिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देश का प्रधान मंत्री जिंदाबाद।

कल हनुमानगढ़ में अन्तरराष्ट्रीय किसान नेता पधारे लंबे अवकाश के बाद। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि किसानों से, अन्नदाता से, भूमि पुत्रों से, धरती पुत्रों से क्या अदावत है? क्यों उनकी खाट खड़ी करने पर तुले हुए हो? खाट खड़ी करना तो दूर खाट तोड़ने पर तुले हुए हो। कल पीलीबंगा में वो ही खाट टूटी जिस पर सचिन पायलट बैठे थे। जो व्यक्ति विरोध की राजनीति से सत्ता की सीढ़ियों तक लेकर आया, सत्ता की कुर्सी पर, मुख्य मंत्री की कुर्सी तक लेकर आया उसको वहां नहीं बैठाया। खाट पर भी नहीं बैठने दोगे, खाट पर भी एतराज? वहां भी खाट ऐसी लाओगे कि टूट जाएगी? राजेंद्र राठौड़ साहब, सामने बैठे लोगों को चेतावनी दे दो कि वीर गुर्जर है, फिर से हुंकार भरी तो मुश्किल में पड़ जाओगे। दो घंटे पहले पीलीबंगा में खाट टूटी तो श्रीगंगानगर पदमपुर में भी खाट की ही व्यवस्था थी क्योंकि खाट से बड़ा प्रेम है, किसान की खाट खड़ी करने का लंबे समय से, पचासों वर्षों से प्रयास करते आ रहे हैं और कोई किसान का सुधार करना चाहता है, कोई किसान के भले की बात करना चाहता है तो उसके खिलाफ किसान को बरगलाने का काम करने के लिए लगातार तैयार रहते हैं, लेकिन पदमपुर में अनुभवी नेता थे, कुन्नर साहब वहां थे, उन्होंने कहा कि खाट हटाओ, ओ मुंडियों, ई खाट नूं हटाओ मुड्ढे पाओ, तो मुड्ढे लगाए और वहां खाट हटाई।

मैं पूछना चाहता हूं कि दस दिन का कहकर, इसी हनुमानगढ़ में 2018 के इलेक्शन में भी यही नेता जी आए थे और किसानों से वादा किया एक, दो, तीन, आठ, नौ, दस, पूरा कर्जा माफ नहीं तो मुख्य मंत्री साफ, क्या हुआ उन दस दिनों का? आज सूरतगढ़ का किसान, पीलीबंगा का किसान और पदमपुर, गंगानगर का किसान, किसान तो वहां आये नहीं, किसान को तो

(श्री बिहारीलाल)

लाया गया, कोई नरेगा से, कोई सरकारी साधनों से, तो यह स्थितियां हैं। सभापति जी, किसान इस बात को पहचान चुका है और ज्यादा दिन तक यह स्थितियां चलने वाली नहीं हैं। मैं कांग्रेस के साथियों से कहूंगा कि बिना समय, बेमौसम गंगानगर, हनुमानगढ़ आने का कोई औचित्य नहीं है। यह बजट सत्र चल रहा है, मुख्य मंत्री जी और बड़े-बड़े मंत्री जी यहां उपस्थित रहते, बजट सत्र की गरिमा और गंभीरता बनी रहती। मैं आदरणीय गोविन्द जी से कहूंगा कि उनको सलाह दें बंगाल जाएं अमित शाह जी वहां पर हैं, नहीं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, फिर आप ममता दीदी के साथ मिलकर कहोगे कि बंगाल में मोदी जी ने ईवीएम हैक कर दी।

आलू से सोना उगाने वाले वहां आये तो राजस्थान की धरती भी, गंगानगर की धरती भी, उत्तरी भारत की धरती भी हिल उठी। इस धरती को भी अपने धरती पुत्रों के लिए चिंता हुई कि धरती पुत्रों को बरगला के, धरती पुत्रों को भ्रम जाल में डालकर दो साल पहले छोटे से अन्तर से, किसान की सम्पूर्ण कर्ज माफी का वादा करके, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का वादा और मोह जाल दिखाकर छोटे से अन्तर से सत्ता में आये लोग फिर से किसानों को, धरती पुत्रों को बरगलाने और भ्रम में डालने आये हैं, जो केंद्र की सरकार तीन कृषि सुधार बिल लायी है उनके विरोध में जनता को भरमाने आये हैं, लेकिन जो जनता असल मुद्दों पर आंदोलनरत थी उनसे बिना मिले, जो किसान पानी के मुद्दे पर आंदोलनरत थे, इंदिरा गांधी नहर में पानी कम आ रहा है, इंदिरा गांधी नहर का पटड़ा टूट चुका है, आज जो चिंता आदरणीय कासनियां जी ने व्यक्त की, इन बातों के लिए जो किसान अपनी बात कहना चाह रहा था उनकी बात नहीं सुनी, उनके ज्ञापन तक नहीं लिए और व्यर्थ की बातें करने के लिए किसानों के हितैषी बनकर इस बीच में आये।

माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में जो तीन बिल की चर्चा आयी, केंद्र सरकार जो कृषि सुधार के बिल लायी और उसके विरोध में संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाते हुए राजस्थान की सरकार ने जो बिल इस विधान सभा से पारित किये, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 2019 का अपना घोषणा पत्र पढ़े, राहुल गांधी 2015 के संसद में दिये हुए अपने भाषण को सुनें और कांग्रेस पार्टी के पंजाब के मुख्य मंत्री, कांग्रेस पार्टी के तब के मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री, जिस कमेटी में शामिल हैं और जिन्होंने जो

(श्री बिहारीलाल)

अनुशंसाएं कीं उन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर यह कृषि रिफार्म्स लागू हुए हैं। इसलिए अपनी बातों को वापस सुनें और यह जो दोगलापन है, दोगला चरित्र इन पार्टियों का है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय शरद पवार जी जो कृषि मंत्री रहते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत में इन्हीं सुधारों की वकालत करते थे, आज जिस मुंह से वो यू-टर्न लेते हुए इन कृषि रिफार्म्स का विरोध कर रहे हैं तो उनका खुद का मुंह भी पूछ रहा है कि इसी मुंह से आपने वो बातें कही थीं, इसी मुंह से आप यह बातें कह रहे हैं तो यह सवाल खुद उन पर खड़ा होता है।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): डीएमके पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो ... (व्यवधान) माननीय सभापति जी, मेरा 15 मिनट का समय है। माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 5 मिनट का समय हुआ है। 10 मिनट का समय बचा हुआ है। दूसरी बात, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे स्वराज पार्टी हो।

श्री सभापति: अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): कांग्रेस के पंजाब से एक सांसद महोदय का दिल्ली की लोक सभा में कहा हुआ वक्तव्य सुनिए। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के नाम पर जो आग लगाने का काम किया उसमें योगेन्द्र यादव और पूरी टीम शामिल थी। यह लोग जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, किसान इस बात को जानता है।

माननीय सभापति महोदय, यह सब लोग कृषि सुधार पर सरकार को नसीहत देने से पहले अपनी कही बातों पर देश से माफी मांगे। किसान से, धरती पुत्र से माफी मांगें कि हमने जो पहले कहा वह असत्य था और अब जो हम कह रहे हैं वह सही है। फिर नरेन्द्र मोदी और मोदी की सरकार से इनमें सुधार करने की बात करें। नरेन्द्र मोदी और केन्द्र की सरकार किसानों के बताए हुए सुझावों पर सुधार करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन उससे पहले इन लोगों को अपनी कही हुई बातों पर माफी मांगनी चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गोविंद राम।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, बिजली, पानी पर जो भी बातें कही गई हैं।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा): कानून व्यवस्था में राजस्थान की क्या स्थिति है? यह सारी बातें अभिभाषण में कही गई हैं।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा): उन सबका हम विरोध करते हैं। राजस्थान सरकार इस पर चिंतन करे। बहुत समय निकल गया, अब कम समय बचा है। उसमें किसान का, व्यापारी का, मजदूर का जितना हित हो सकता है, उतना करने का प्रयास करें। आदरणीय सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोविंद राम।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। काफी चर्चा हुई काफी मुद्दों पर अपने-अपने पक्ष रखे। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी जो पिछले एक साल से पूरे देश में है और एक नंबर पर जो इन्होंने व्यवस्था की, इसके लिए जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है। यहां हास्पिटल्स बनाये और जो कोरोना वारियर्स थे, इनको भी इन्होंने प्रोत्साहित किया।

इसके अलावा हमारे स्टेट में जो इन्होने कालेज दिये, न्यायालय खोले, स्कूलों को क्रमोन्नत किया, हर विषय पर देखेंगे तो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री का मुकाबला नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलवाई, इस देश का विकास किया, 60 साल तक राज किया, यह स्वयं प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं। आज यह 6 साल से केन्द्र में राज में आये हैं, जो भी आंदोलन कर रहा है उनको नये-नये नाम दिये जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से दिल्ली में जो 2 नेता आये हैं गुजरात के, उन्होंने इस तरह का एक माहौल पूरे देश में क्रिएट कर दिया कि पूरी पार्टी को तो अपनी जेब में की ही है, वह चलो उनकी पार्टी है, लेकिन पूरे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं थीं उनको भी इन्होंने कमजोर किया है। आज अगर

(श्री गोविंद राम)

कोई न्यायालय का न्यायाधीश इनके विरुद्ध में फैसला कर दे तो उसको भी यह दबाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई पत्रकार इनके विरुद्ध में लिखते हैं तो उनकी भी हत्या कराने की साजिश करते हैं। कोई पार्टी इनके विरुद्ध में बोलती है तो उनको भी यह देशद्रोही का नारा देते हैं।

दुर्भाग्य इस बात का है कि आज पिछले 70 दिन से किसान जो इस देश का अन्नदाता है, धरती चीरकर के अनाज पैदा करता है, यह जो 3 काले कानून लाये, वह ऐसे कानून हैं जो आज तक देश में पारित नहीं हुए, इस तरह के कानून हैं। उनका इसमें साफ कहना है कि इससे मंडी सिस्टम खतम हो जाएगा, किसान गुलाम बन जाएगा, पूंजीपतियों से इकरार करना पड़ेगा। यह कह रहे हैं कि जो स्टोरेज की सीमा है, वह सारी लिमिट हटा दी। इसका सबूत है कि जहां इनकी सरकारें हैं, वहां अडाणी और अंबानी लंबे-लंबे 10-10 किलोमीटर में स्टोरेज बना रहे हैं, फिर भी यह मानने को तैयार नहीं हैं। मुझे सबसे बड़ा दु:ख है कि यह पहली बार हुआ है जबकि डेमोक्रेसी में आंदोलन करने का हर आदमी को अधिकार है। आडवाणी जी ने बहुत बड़ा राम मंदिर का आंदोलन किया। उस वक्त भी लालू यादव मुख्य मंत्री थे, उन्होंने गिरफ्तार किया लेकिन आंदोलन के नेताओं को हमारी पार्टी ने कभी भी आतंकवादी की श्रेणी में नहीं दिया, देशद्रोही शब्द कभी नहीं दिया, कभी खालिस्तान का नारा नहीं दिया। लेकिन आज कोई भी आंदोलन करे, उनको यह देशद्रोही का सर्टिफिकेट देते हैं।

हमारे देश में 2014 के बाद एक गोदी मीडिया बन गया। चूंकि अडाणी और अंबानी ने करीब 60 चैनल खरीद लिए। अब इनके जो मन में आती है वह छपवाते हैं। जिसको मन में आए वैसा ही वह शाम को टाई लगाकर के बोलते हैं। जैसे अर्नव गोस्वामी, इनको कैसे पता लगा कि पुलवामा में यह घटना हुई और इन्होंने बहुत खुशी मनाई। उन्होंने अपनी चैटिंग में लिखा है। उसके बाद बालाकोट की घटना, 2 दिन पहले ही पता लग गई, जो प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री के ध्यान में होना चाहिए। अगर हम विचार करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे दुख है कि जितने भी हमारे प्रतिपक्ष के नेतागण बोले हैं उन्होंने राजस्थान के करप्शंस के बारे में बोला, महंगाई के बारे में बोला, लेकिन इनमें एक भी

(श्री गोविंद राम)

व्यक्ति यह नहीं बोला कि 70 दिन से जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, पंजाब के लोग आज दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के लाखों लोग सीमा पर बैठे हैं, शाहजहांपुर की सीमा पर बैठे हैं, सिंघु बार्डर की सीमा पर बैठे हैं। इन्होंने एक में भी यह नहीं माना है कि वह आंदोलनकारी इतनी तकलीफ में हैं, जहां 150 लोग मर चुके हैं।

आज मुझे बड़ा दुःख हुआ, हमारे धारीवाल जी पर इन्होंने एक आरोप लगाया। नारे लगाए कि गिरफ्तार करो। किसी ने सेल्फी ले ली। भले आदमियों, दिल्ली में आपने दंगे करवाए। सरेआम पुलिस उनके साथ में थी। गुजरात में आपने दंगे करवाए। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में दंगे करवाकर आपने यूपी कब्जे में ले ली। आज 150 किसान मर गये तो क्या यह भी नारा लगना चाहिए कि प्रधान मंत्री और +++ को गिरफ्तार करो।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत दूषित वातावरण हो गया। डेमोक्रेसी खतरे में है। पहले ऐसा वातावरण नहीं था जैसा अभी 6 साल के अंदर हुआ है। कोई भी नेता बोलेगा तो उसके घर छापा तैयार। अभी आपने देखा जुलाई में, आप लोगों ने क्या हालत की कि हमें होटलों में रहने को मजबूर होना पड़ा। यही लोग अखबारों में बयान देते हैं कि सरकार होटल से चल रही है। मजबूर किसने किया? इधर ईडी और आयकर के छापे होटलों में डलवा रहे हैं।

(15.07 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश के हालात खतरे में हैं। डेमाक्रेसी खतरे में है। इसके जिम्मेवार मात्र 2 व्यक्ति हैं। हम दो और हमारे दो जैसा नारा दिया। +++ इनका दोष नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है, वह आरएसएस है। आरएसएस का इतिहास पूरा देश जानता है। हमारे सरदार पटेल जी जब गृह मंत्री थे, तब उन्होंने इस पर बैन लगाया था।

आप जानते हैं कि हमारे देश को आजादी मिली 1947 में और 1948 के अंदर जो आजादी के अगुआ थे, आज हमारे सामने उनका फोटो लगा हुआ है। पूरा विश्व जिनके अहिंसा के आंदोलन का लोहा मानता था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाकर भी भारतीयों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने पूरे देश को एक

(श्री गोविंद राम)

विचार दिया, अंग्रेजों को घुटने टेकने को मजबूर किया, हमारा देश छोड़ने को मजबूर किया, उनका नाम महात्मा गांधी था। 1947 में आजादी मिली और 1948 में वही आरएसएस का कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे, उसने गोली मारी और आज यह उसी को राष्ट्र भक्त की संज्ञा दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश की आजादी खतरे में है। यह संसद में नारे लगाते हैं नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। कहीं यह मूर्ति लगाने की तैयारी करते हैं, कहीं मंदिर बनाने की तैयारी करते हैं। हम नहीं चाहते कि यह ऐसे लोगों को पूजें, लेकिन इनकी विचारधारा है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारा प्रजातंत्र खतरे में है।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारा राजस्थान थोड़ा इसलिए आराम से चल रहा है क्योंकि यहां कांग्रेस है। कांग्रेस की विचारधारा थी। आप अगर आजादी के पीछे जाएंगे तो हमारा देश विभिन्न रियासतों में बंटा हुआ था। आपस में बंटा हुआ था। जयपुर चित्तौड़ से लड़ रहा था। बीकानेर किसी और से लड़ रहा था। हम आपस में लड़ते थे। उससे पहले मुगल थे। 300 साल अंग्रेज राज कर गये। उसका मूल कारण यह था कि हमारे यहां जातिवाद था, हमारे यहां छुआछूत थी, हम विभिन्न गोत्रों में बंटे हुए हैं। एक ही जाति में हजारों गोत्र हैं। उस वक्त डा. अंबेडकर ने कहा था कि यह जो हमारी जातियां हैं, आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम सारे के सारे आपस में बंटे हुए हैं। यह हमारी हिन्दू सभ्यता का मूल सिद्धांत है। उस वजह से हमारा बंटवारा है। उस वजह से बाहर से लोग आये और यहां हजारों साल तक राज किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब आजादी के बाद हमें संविधान मिला, उसमें समानता का अधिकार मिला। हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला। हमारे यहां पर एजुकेशन का भयंकर अभाव था। अंग्रेज आये उन्होंने कुछ स्कूलें खोलीं। उस वक्त 1948 में ज्योतिबा फुले, जो कि डॉ. अंबेडकर के गुरु थे, जाति के माली थे, उन्होंने एक बात कही थी कि 'शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना गति नहीं, गति के बिना नीति नहीं, नीति बिना अर्थ नहीं, रुपया नहीं आएगा और अगर अर्थ नहीं है तो आदमी पशु के बराबर है'। आज हमारे देश में अंध भक्त का नारा चल रहा है। अंधभक्त वही बन सकता है जो अज्ञानी हो, जिसके अंदर अज्ञानता हो और वह विवेकशून्य

(श्री गोविंद राम)

हो जाता है। जैसा इनका आदेश मिलता है वैसा ही ये नारा देने लग जाते हैं। आज ये राम के नाम पर खूब जय श्रीराम नारे लगाते हैं लेकिन मेरा नाम गोविंद राम है, मेरे पीछे राम का नाम लगता है, इनको कहो आप राम का नाम लगाकर बता दो। मैं छठी क्लास में हारमोनियम सीख गया था, अच्छा गायक था मैं। स्कूल में, कालेज में एक नम्बर का मारवाड़ी गाना गाता था, भजन गाता था, लेकिन राम के विद्रोही हमें मानते हैं ये, चूंकि हम कांग्रेस में हैं। आज प्रियंका गांधी जाकर स्नान करती हैं तो ये विधान सभा में बोलते हैं कि हमारे मोदीजी ने मजबूर कर दिया है। हमारे राहुल गांधीजी जनेऊ डालते हैं, हमारी बीजेपी ने मजबूर कर दिया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आंदोलन उम्र भर किये लेकिन हमने कभी यह नहीं कहा कि ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तान चले जाओ। आज यह चला-चला कर, जिस तरह से शाहीन बाग़ में महिलाएं बैठीं, उनके ऊपर इन्होंने क्या नहीं किया? आज किसान बैठे हैं, वहां जाकर के आरएसएस के गुंडों ने लाठीचार्ज किया, उनके तम्बू तोड़े, उनके साथ मारपीट की, इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये लोग अगर इसी तरह से करेंगे तो आने वाले समय में हमारा प्रजातंत्र खतरे में हो जाएगा और यह तानाशाह की तरह से सरकार चला रहे हैं, इन्होंने हिटलर को पढ़ा है, क्योंकि हिटलर जब राजा था तो कोई भी उसका विरोध करता उसको देशद्रोही का तमगा दे दिया। इन्होंने मीडिया कब्जे कर लिया, संवैधानिक संस्थाएं हमारी खतम कर दीं, हमारा आरक्षण खतम करने के लिए इन्होंने कम्पनियां बेच दीं क्योंकि इनको पता है कि आरक्षण खतम कर देंगे तो दलित और ओबीसी सारे खतम हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मूल बात पर आना चाहता हूं कि आखिर इन विभिन्न जातियों में लोगों को किसने बांटा? क्या हमने बांटा है? आखिर यह कब खतम होगा? आज गांवों में जाओ, कितनी अनटचेबिलिटी है, कितनी छुआछूत है? आज कोरोना महामारी आई, पूरा विश्व हिल गया, पूरा हमारा देश हिल गया, ये कहते हैं कि गहलोत साहब से कोरोना की व्यवस्था नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं जनवरी के अंदर राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी सरकार, आप सावधान होइए, चाइना में बीमारी आ चुकी है, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और फरवरी में नमस्ते ट्रम्प करते हुए अंग्रेजों ने तीन सौ साल गुलाम रखा, क्या अभी भी उनको नमस्ते ट्रम्प करके

(श्री गोविंद राम)

यहां लाखों लोग आपने बुलाए, वहां बीमारी फैली कोरोना और मार्च के अंदर ये व्यापम घोटाले के आरोपी शिवराज सिंहजी को मुख्य मंत्री बनाने के लिए बेताब थे, इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया जबकि लॉकडाउन का नियम है कि 15-20 दिन पहले हमें चेतावनी देनी चाहिए, सुझाव देना चाहिए, लोगों को सावचेत करना चाहिए। अचानक 22 मार्च को सरकार गिराकर 24 मार्च को इन लोगों ने लॉकडाउन किया, उस कारण से हजारों मजदूर मरने के लिए मजबूर हो गये। हजारों लोगों का एक्सीडेंट हुआ। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज हमारे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में जो अधिकार अमीर को है, वही गरीब को है, मजदूर को है। वही हमारा फैक्ट्री में काम करता है, कारखाने में काम करता है, खेत में काम करता है, उस मजदूर को अधिकार है, जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, ये इनके पास उनको किराया देने के लिए पैसा नहीं था कि इनको अपने-अपने गांवों में पहुंचा दे।

यह कल बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे, आज भी मैंने सुना, योगी आदित्यनाथजी से पूछो, एक जमाना था पार्लियामेंट में विद्वान लोग जाते थे, विधान सभाओं में विद्वान लोग जाते थे। इन लोगों ने पूरे देश से साधुओं को इकट्ठा करके, कोई +++ तो कोई +++, सबको पार्लियामेंट में भेज दिया। आज ये उदाहरण दे रहे हैं, आज हमें ये उदाहरण दे रहे हैं, आदित्यनाथ से सीखो, भले आदमियों, जब मंदिर से निकालकर आप मुख्य मंत्री बना रहे हो, तो मंदिरों के नाम पर क्यों चंदा कर रहे हो? लेकिन इनके ऊपर डंडा है, किसका है? नागपुर वाले आरएसएस का, अगर उसके विरुद्ध में बोलेंगे तो चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता है, उसको आउट कर दिया जाएगा और वही नागपुर, जिस तिरंगे का आज दिल्ली में विरोध किया है, इन्होंने दीप सिंधु को भेजा, प्रशासन ने छूट दे दी, पुलिस ने, क्यों आपने ऊपर तक जाने दिया? वहां जाकर वही केसरी झंडा जिसको लेकर ये दिन भर घूमते हैं, क्योंकि हमारे देश में भगवे की थोड़ी इज्जत है। साधु पहनते थे। शुरू से जो हमारे शिवाजी महाराज थे वह भी भगवा, तो हम लोग भगवा की इज्जत करते हैं, तो इन्होंने उसी को काम में लिया और आज तक नागपुर के अंदर इन्होंने तिरंगे को नहीं फहराया, कभी भी फहराया नहीं, 52 साल तक तिरंगा वहां नहीं फहराया, नागपुर के आरएसएस कार्यालय में।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे, इन्हीं के लोग, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, क्योंकि इनके

(श्री गोविंद राम)

पास में सब तरह के षड्यंत्र हैं। इन्होंने आजकल दो सौ, दो सौ लोगों को आईटी सेल पर बैठा रखा है दिल्ली में, दो सौ को हिन्दू बना देते हैं, दो सौ को मुसलमान बना देते हैं, आपस में करके दंगा फैलाने की साजिश करते हैं। जब ये दिल्ली में हारे तो केजरीवालजी आ गये तो इन्होंने वहां दंगे करवाये, वहां दस हिन्दू मर गये और सौ मुसलमान मार दिये। पूरे देश में वाहवाही लेते हैं, गुजरात में तो हजारों मुसलमान मरवाए क्योंकि अपने देश के अंदर आज भी हम लोग धार्मिक भावना के आधार पर बहते हैं, अंधविश्वास है क्योंकि एजुकेशन का अभाव है। डाक्टर अम्बेडकर बाहर नहीं जाता तो छठे नम्बर का विद्वान नहीं होता, नेहरूजी बाहर नहीं जाकर पढ़ते तो विद्वान नहीं होते, आज हमारे राहुल गांधी, अच्छी एजुकेशन लेकर आगे बढ रहे हैं लेकिन इन लोगों ने मजाक बना रखा है, कभी कोई नाम लेकर पुकारते हैं, कभी कोई नाम लेकर पुकारते हैं। जो हमारे नरेन्द्र मोदीजी, वह कहते हैं कि 35 साल तक मैं तो फकीर बनकर घूम रहा था, 1992 की रैली में आडवाणीजी के साथ में थे, पहले घोषणा कर रहे थे प्रधान मंत्री बनाने की और बाद में खुद वहां जाकर बैठ गये और आडवाणीजी की हालत वह कर दी जैसी घर में विधवा काकी की होती है। कोई नहीं पूछता है उनको, वह हालत कर दी इन लोगों ने। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें इनकी शिक्षा की जरूरत नहीं है और आरएसएस जितना यहां मजबूत बनेगा, देश में उतनी ही नफरत पैदा होगी। आज आप देख रहे हैं कि इन्होंने दो धर्मों के अंदर नफरत की दीवार पैदा कर दी है। 1917 में जो धर्म पैदा हुआ, वह जब कोई आकर हमारे धर्म की महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, हमले करते थे, उनको बचाने का काम गुरू गोविन्दसिंहजी की सेना करती थी, आज उन सरदारों को इन्होंने कलंकित कर दिया है। आज उन पर आरोप लगा रहे हैं खालिस्तान का, आज के आंदोलन पर कह रहे हैं कि विदेशों से पैसा आ रहा है।

आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज विदेशों में 35 एमपी, वहां जाकर विरोध किया है इंग्लैंड में, उन्होंने भी कहा कि वहां प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश पहली बार आकर उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, इनसे हमारा देश खतरे में है। आज नागरिकता के आधार पर इन लोगों ने लोगों को परेशान किया, शाहीन बाग़ में आंदोलन हुआ। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, हमारी आईडी

(श्री गोविंद राम)

के आधार पर एक +++ गृह मंत्री बन सकता है, एक साधारण चाय बेचने वाला प्रधान मंत्री बन सकता है तो हमें यहां आईडी की कौनसी जरूरत है? कौनसे नये तरह के कानून लाकर लोगों को परेशान कर रहे हो? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि हमारी पहले लड़ाई थी गोरे अंग्रेजों से, आज हमारी लड़ाई काले अंग्रेजों से चल रही है। आज हमारी आत्मा है जो देश की, किसान आंदोलन कर रहा है, लाखों लोग सड़क पर हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये वे सरदार हैं, ये जो जाट हैं, ये वे किसान हैं 36 बिरादरी के कि जब वे अंग्रेजों के आगे नहीं झुके तो मोदीजी, आप इनको नहीं झुका सकते। या तो आप ये काले कानून वापस लीजिए अन्यथा आपको सत्ता से बाहर आना पड़ेगा। आप ये जो नई-नई तरह की फितरतें पैदा कर रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर महात्मा गांधी को आपने गोली मारी, आरएसएस ने, लेकिन महात्मा गांधी के विचार आज भी जिंदा हैं। आज पूरा देश महात्मा गांधी का कायल है।

आप आज सोनिया गांधीजी के बारे में बातें कर रहे हो। ऐसी महान आत्मा जो आज 20 साल से अध्यक्ष पद पर रही, आज भी वे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने त्याग किया, प्रधान मंत्री नहीं बनीं, राहुल गांधीजी को उन्होंने प्रधान मंत्री नहीं बनाया और आज राहुल गांधीजी, पढ़े-लिखे व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, और समय-समय पर आपको चेताया लेकिन आपको ट्रम्प नमस्ते की जरूरत थी न आपने कोरोना का इलाज किया, न गरीब पर ध्यान दिया क्योंकि आपको पता है मरेगा तो कोई गरीब मरेगा और सारी की सारी कम्पनियां बेचने में लगे हुए हो जब आप कह रहे हो कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं तो ये कम्पनियां कहां से बनीं? आज रेलवे को बेच रहे हो, आप एयरपोर्ट को बेच रहे हो, आप एलआईसी को बेच रहे हो, बीएसएनएल को बेच दिया, जियो दन दना दन दन चला दिया और जो आईडी इकट्ठी की इन्होंने नोटबंदी के अंदर, उन्हीं आईडी के माध्यम से दो नम्बर का पैसा निकालकर इन लोगों ने पैसा बनाया। आज राफेल के अंदर जो पांच सौ करोड़ का था, इन्होंने सोलह सौ करोड़ में खरीद कर लाए और कल बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, लड़ाकू जहाज हमने खरीदा है तो ये साठ साल, 1971 में पाकिस्तान को हरा दिया था, बांग्लादेश अलग बन गया था और आज आप जो बातें कर रहे हो, आज हमारा प्रजातंत्र मजबूत है। ये डाक्टर अम्बेडकर को धन्यवाद दो, नेहरूजी को धन्यवाद दो, महात्मा गांधी को धन्यवाद दो, सरदार

(श्री गोविंद राम)

पटेल को दो, जिनकी तीन-तीन सौ फीट की मूर्तियां बना रहे हो, वे कांग्रेस के नेता थे। आरएसएस ने आजादी में कहीं अंगुली भी नहीं कटाई, आरएसएस ने और ये जो जनसंघी है इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, आजादी में खून का कतरा नहीं बहाया और आज आप बड़ी-बड़ी बात कर रहे हो। आपको इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। साठ साल का हमारा राज जा सकता है तो राज आपका भी जा सकता है। आप बिलकुल दरवाजे पर खड़े हो, आपने पूरे देश को एक बारूद का ढेर बना दिया है। आज हमारे नौजवानों में इन्होंने जहर भर दिया है हिन्दू मुसलमान का। आप देख लो व्हाट्सएप पर लोग किस तरह से लड़ रहे हैं। आज हमारा नौजवान बेरोजगार हो गया है। इन्होंने कहा था कि हम दो करोड़ को रोजगार देंगे लेकिन रोजगार सारे घटा दिये। नारा दे दिया तुम तो पकौड़े तलने का काम करो, कभी अमित शाहजी कहते हैं, हम अच्छे दिन की जो बात कह रहे थे वह तो हमारा जुमला था, वह मात्र हमारा जुमला था। हद हो गई, आप देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे हो, आज हमारे देश की आत्मा किसान, आपकी छाती पर बैठा है, डेढ़ सौ किसान मर गये, आपको बात करने के लिए समय नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है डैमोक्रेसी में, छह साल में प्रधान मंत्रीजी, आज तक कभी मीडिया के सामने आकर बोले नहीं हैं, मन की बात करते हैं, वे भी रेडियो पर करते हैं। +++ आपको क्या पता बेरोजगारों की स्थिति के बारे में? आप दिन भर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। पूरे देश में इन्होंने आग पैदा कर दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, हमारे नियमों में प्रावधान है कि उच्च पदस्थ लोगों पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं हो सकती। प्रधान मंत्री जी का बार-बार नाम लिया जा रहा है।

श्री सभापति: यह डिलीट कर दें। डिलीट करवा दिया मैंने।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): यह राजेन्द्र राठौड़ जी बोल रहे हैं। कल जब ये बोले, मैं बीच में नहीं बोला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कल तक भारतीय जनता पार्टी के +++, आज बोल रहे हैं। इधर से निकलकर ही वहां गये हैं। कल फिर आना पड़ेगा आपको। यह क्या बात हुई? कहां की बात कहां तक चली गयी।

श्री सभापति: माननीय Deputy Leader of Opposition, I have deleted it. (व्यवधान) कृपया व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार): सभापति महोदय, इस तरह माननीय सदस्य को धमकाने की आवश्यकता नहीं है। जवाब हम भी देना जानते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ये इतने सीनियर मैम्बर होकर डरा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह भी डिलीट किया जाए इसमें से।

श्री सभापति: यह पाइंट आफ डिस्कशन नहीं है। I have deleted it. Please sit down. I have deleted. बैठिए, बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, भाजपा में किसके +++ राजनीति करने के लिए, यह पूछें इनसे? किसके +++ बीजेपी के अन्दर? पहले यह बताएं आप। (व्यवधान) और +++?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अपने गिरहबान में झांककर देखें आप कहां हैं? (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार): सभापति महोदय, माननीय सदस्य को प्रोटेक्शन दिया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने डिलीट करवा दिया है। प्लीज आप बैठिए। Please sit down. Please sit down. (व्यवधान) आप बैठिए, मैंने डिलीट करा दिया है। (व्यवधान) यह मैंने डिलीट करा दिया है। व्यक्तिगत नहीं करें आप। आप बहुत seasoned हैं। आप बैठिए प्लीज। Please sit down. (व्यवधान) माननीय सदस्य, तशरीफ रखें। (व्यवधान) माननीय, matter is finished now. मैटर फिनिश हो गया है अब। Sit down. Please continue.

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, इन्होंने जो कार्यालय बनाया है दिल्ली में होटलों से भी बड़ा, इतना चंदा कहां से आया? हमने साठ साल तक राज किया, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है इतना। पूरे देश में बनाये हैं कार्यालय। यह एक प्रश्न खड़ा होता है कि इतना पैसा इनके पास कहां से आया?

दूसरा, हम जो भाषण देते हैं, उनके वीडियो बनाकर उन्हें एडिट करवाते हैं। ऐसी टीमें बना दीं, जिससे कि पूरे देश में मतभेद पैदा हो, इसलिए मैं कह रहा हूं, यह देश न हिन्दू राष्ट्र बन सकता है, न मुस्लिम राष्ट्र बन सकता, न ही सिख राष्ट्र बन सकता। इस देश के संविधान निर्माता बहुत बुद्धिमान थे, यहां के डीएनए को जानते थे, इसलिए उन्होंने यह संविधान सोच-समझकर बनाया है। आज कोरोना से भी बड़ी बीमारी हम झेल रहे हैं, हमारे गांव में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग झेल रहे हैं, वे इसलिए झेल रहे हैं कि वर्षों से, सदियों से हमें अछूत बना रखा है इन्होंने।

(श्री गोविंद राम)

आज भी गांव की मीटिंग में वे बराबर में नहीं बैठ सकते। उनमें ये और दीवारें पैदा कर रहे हैं। कोई दलित अपने अधिकार के लिए लड़ता है, उन्हें ये नक्सलवादी कहते हैं। कोई मुसलमान लड़ता है, उसे ये आतंकवादी कहते हैं। कोई सिख लड़ता है, उसे ये खालिस्तानी कहते हैं। यह चलने वाला नहीं है। इस देश के अन्दर 80 परसेंट हम लोग हैं। जो ये भिड़ाने की बातें करते हैं, उसी का परिणाम है कि यह देश हमारा हजारों सालों तक गुलाम रहा और ये वापस वहीं ले जा रहे हैं। ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय, प्लीज कनक्लूड करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): इसलिए हम कह रहे हैं, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे हमें लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। संविधान को नहीं टूटने देंगे। इन्होंने डा. भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस के बनाये हुए सिद्धांतों को जलाने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब कनक्लूड करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मेरा टाइम भी इन्हीं को दे दें।

श्री सभापति: अच्छा ठीक है, ठीक है। (व्यवधान) आपका लिस्ट में नाम नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): हमारे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ीं, ये इन्हीं की देन हैं। इनका जो यह षड्यंत्रकारी संगठन है, इसी की देन है। ये चाहे न बोलें, लेकिन इनकी नीतियां सारी नागपुर में बनती हैं और वहां कहते हैं कि दलितों के घरों में गंदगी होनी चाहिए, मुसलमानों के घरों में कचरा होना चाहिए, पिछड़े वर्ग के आदमी को आगे नहीं आने दो। अब इनकी मजबूरी है, बोल नहीं सकते। बोले तो अगली बार टिकट कट जाएगी, इसलिए इस पार्टी में ढंग का आदमी नहीं रह सकता।

श्री सभापति: माननीय, अब कनक्लूड करें। Please conclude.

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): इनका 2003 में बीकानेर में सुहाग रखने वाला गोविन्द चौहान था। अकेला जीता था मैं 27000 वोटों से और मैंने इसलिए छोड़ी, इनकी नीतियां पसंद नहीं थीं। मैंने इस्तीफा दिया।

श्री सभापति: Please conclude, please conclude.

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): और राठौड़ साहब, जिंदगी में संकल्प है,

(श्री गोविंद राम)

कभी अगर इस पार्टी की तरफ, आपकी तरफ देख जाऊं तो मेरे मुंह पर थूक देना।

श्री सभापति: Please conclude. समाप्त करें। माननीय, समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): राम का सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। आप लिखते हैं राजेन्द्र सिंह राठौड़, मैं लिखता हूं गोविंद राम मेघवाल। भगवान के भजन सबसे ज्यादा गाता हूं। यहां ले आएं हारमोनियम, भजन गाकर बताऊं। नहीं गा पाऊं तो मेरी नाक काट लेना और विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): मैं जानता हूं, आपकी भावना नहीं है। जो आपके पीछे षड्यंत्रकारी संगठन काम कर रहा है, उसकी देन है यह।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अब प्लीज। प्लीज समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): साहब, इनकी वजह से तो यह कोरोना हुआ है पूरे देश में। अगर ये हवाई जहाज रोक देते, कोरोना होता ही नहीं। 'नमस्ते ट्रम्प' करते रहे और जहां-जहां गये, ''जहां-जहां पड़े पांव भगतन के, वहां-वहां बंटाधार''। ये गये अमेरिका, ट्रम्प साफ। ये गये पाकिस्तान, नवाज शरीफ साफ। ये कहते थे, कांग्रेस के नेता बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान के साथ, लाल आंख दिखाने की जरूरत है। आपकी वह लाल आंख चाइना में कहां चली गयी? अरुणाचल में शहर बस गया और इनकी लाल आंख पूछें, कहां चली गयी? आपका छप्पन इंच का सीना कहां है?

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें प्लीज। प्लीज कनक्लूड करें। आखिरी एक मिनट।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): यह केन्द्र की सरकार अम्बानी और अडाणी की कठपुतली है। सभापति महोदय, ये नेता नहीं हैं। नेता होते तो चाइना से लड़ते, किसानों को नहीं मरवाते। आज इनके एमएलए जाकर धरना स्थल पर कहते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर सदन को इसी तरह अखाड़ा बनाकर रखा गया तो गाली-गलौज के अलावा क्या बचा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर वाद-विवाद है क्या? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): किसान की परिभाषा समझते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: Please sit down, Please sit down. आप फिनिश करें, मैं दूसरा नाम पुकारता हूं। प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। आलरेडी 25 मिनट्स हो चुके हैं। (व्यवधान) प्लीज मैं फिनिश कर रहा हूं। अब इसको एक्सटेंड न करें। (व्यवधान) जनाब, आप तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें। मैं आपको लास्ट एक मिनट देता हूं।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, यह भारतीय दंगा पार्टी बन चुकी है। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी नहीं है यह। राठौड़ साहब, मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बस फिनिश करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सभापति महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। कोरोना काल में प्रदेश की जैसी अव्यवस्था हुई, वह जनता से छिपी हुई नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, Please finish it. अब मैंने इनको समय दे दिया है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): राजस्थान सरकार ने अलग-अलग राज्यों के लिए सरकार के आईएएस-आईपीएस की को-आर्डिनेटर के लिए नियुक्ति की। सभापति महोदय, मैं खुद साक्षी हूं, मुख्य मंत्री आवास में बीस बार टेलीफोन करने के बावजूद जितने अधिकारी लगाये हुए थे, उनमें से एक भी फोन नहीं उठाता था। परदेसियों के आवागमन के लिए आंध्र प्रदेश से लेकर, गुजरात से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर मेरे बाड़मेर जिले के भी प्रवासी अपने धंधे के लिए, व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं। राजस्थान सरकार ने दो आफिसर तय किये थे। उनके नम्बर भी व्हाट्सएप पर डाले थे ग्रुप में। एक भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया और कोराना काल में प्रवासियों के लिए ऐसी

(श्री हमीर सिंह भायल)

हालत कर दी कि वास्तव में वे पंद्रह-पंद्रह दिन तक पैदल चलकर आये। कोई टेलीफोन उठाने वाला नहीं था। वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह तीसरा बजट है, दो बजट में जो घोषणा की है वह आज की तारीख में एक भी धरातल पर लागू नहीं हुई है। चाहे आप शिक्षा विभाग में ले लो, ऊर्जा विभाग में ले लो। सड़कों में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना या नेशनल हाईवे जो चल रहे हैं, उनका काम चल रहा है, बाकी एक किलोमीटर भी मिसिंग लिंक सड़क नहीं बनाई है। ग्रामीण गौरव पथ की जगह विकास पथ का नाम दिया पर आज दिन तक कहीं पर भी एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी। या तो सभी विधान सभा क्षेत्रों में नहीं बनी है या बाड़मेर जिले में सिवाना से मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं इसलिए मेरे यहां नहीं बनी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था सड़कों से लेकर किसी भी तरह का काम, यहां तक ग्रामीण गौरव पथ, प्रधान मंत्री योजना के सैकण्ड फेज की सड़कें भी अभी तक चालू नहीं की। इसके अलावा जो पूर्व में सड़कें सैंक्शन थीं, उनका कुछ काम हो गया और कुछ काम अधूरा पड़ा है। ठेकेदारों को आज तक पैसा नहीं दिया गया तो जो सड़क का काम हुआ वह भी वापस टूटकर बिखर गई और जो पहले सड़कों की हालत थी वह हो गई है।

शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि शिक्षा में हमने बहुत तरक्की की है। मैं यह ईमानदारीपूर्वक कह सकता हूं कि राजस्थान में शिक्षा के प्रति अगर किसी ने ध्यान दिया है ग्राम और ढाणी तक तो स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने एक साथ में राजस्थान में पंचायत हैडक्वार्टर में 5वीं से 8वीं तक की स्कूल करने का कार्य किया था। 2008 में राजस्थान की मुख्य मंत्री जी ने एक साथ पूरे राजस्थान में बिना भेदभाव के 8वीं से 10वीं में करने का कार्य किया, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि 2013 से 2018 में करीब 8 हजार स्कूलों को राजस्थान के गांव और ढाणी तक पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर सैकण्डरी करके राजस्थान में शिक्षा के लिए कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी जितने भी स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं उनमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं हुआ है, इसलिए शिक्षा के प्रति आप ध्यान दें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

सिंचाई के अन्दर हमारा जो क्षेत्र है वहां अरावली की पहाड़ियां हैं और वहां पर सिंचाई विभाग के एनिकट के टेंडर हो रखे थे, वे भी सारे दो साल में कैन्सिल होकर पड़े हैं और दो साल में एक नये पैसे का कार्य नहीं हुआ है।

पानी की बात करें तो 2003 में जो पोकरण-फलसूंड और उम्मेद सागर-धवा योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू की थी और 2017-18 में पोकरण-फलसूंड योजना का कार्य पूरा होना था, उसमें 103 गांव सिवाना के हैं, 57 गांव सिणधरी के हैं और 15 गांव नर्मदा से है, परन्तु आज की तारीख में सिवाना में इस सर्दी के अन्दर भी 20 से 25 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। यह हालत हो गई है कि जिस दिन आचार संहिता 6 तारीख को लगी थी उस दिन काम बन्द हुआ था, वह आज की तारीख में 12 किलोमीटर की लाइन पड़ी है और पीने के लिए पानी नहीं है। कई बार मंत्री जी को निवेदन कर चुके, कई बार मुख्य मंत्री जी को निवेदन कर चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी तीन पंचायत समितियां है, तीन तहसीलें हैं, दो उपखण्ड अधिकारी बैठते हैं पर वहां पेयजल के लिए दो ए.ईएन. हैं उनमें एक डेपुटेशन पर है और चार जे.ईएन. में से एक जे.ईएन. था, उसको भी उठाकर ले गये और एक पम्प ड्राइवर के भरोसे पूरा विधान सभा क्षेत्र चल रहा है तो इससे ज्यादा सरकार क्या काम कर सकती है। पटवारी नहीं, ग्राम सेवक नहीं है। आज एक साल से सिवाना हैडक्वार्टर पर तहसीलदार नहीं है। समदड़ी में तहसीलदार नहीं था और अभी 15 दिन पहले एक तहसीलदार लगा है तो ऐसी स्थिति कर दी गई है।

शिक्षा के बारे में कहेंगे तो 2018 से 15 करोड़ रुपये से सिणधरी में आईटीआई भवन बना हुआ है पर कई बार मंत्री जी को निवेदन करने के बाद में भी वह 15 करोड़ की लागत से बना हुआ भवन जर्जर हो रहा है और आज दिन तक उसको चालू नहीं किया, स्टाफ नहीं लगाया।

आप कह रहे हैं कि हमने कॉलेज खोल दीं, कहां है भवन आपका? एक भी भवन नहीं है। मेरे समदड़ी में कॉलेज खोल दी, सिवाना में प्रोफेसर नहीं है। सिवाना में तीन करोड़ सैंक्शन हो गये, काम चालू हो गया पर पेमेंट नहीं दिया है, जिसके कारण आज वह काम बन्द पड़ा है। पेयजल की सुविधा वहां नहीं है। हालांकि बिजली में जरूर आपने बिलों में रेट बढ़ाने का, वीसीआर भरने का, शीटें भरने का कीर्तिमान स्थापित किया है। आप यह तो बताओ कि

(श्री हमीर सिंह भायल)

जो ट्यूबवैल फेल हो जाते हैं, पीने के पानी वाले पम्प जो जल जाते हैं वे 10-15 दिन में रिपेयर होकर आना चाहिए लेकिन 4-4 माह में नहीं होते हैं। एक पाइप का जोइंट आपके पास में नहीं है तो किस तरीके से आज राज चल रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है।

परिसीमन करके जरूर आपने तोहफे के रूप में 304 की पंचायत बना दी। जैसलमेर में 304 की पंचायत बना दी और आपने भेदभाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे नगर निगम हो, नगरपालिका हो, आज आप कह रहे हैं कि हम जीत गये पर आपने एक वार्ड 400 का बना दिया, एक वार्ड 28 हजार का बना दिया, एक 1800 का और एक 3200 का बना दिया, तो पता नहीं कैसे आपने परिसीमन किया है? कोई पारदर्शिता नहीं, कोई लाइन नहीं कि किस तरीके से आपने किया है और फिर आप वाहवाही लूट रहे हैं कि हमारी नगरपालिका बन गई या नगर निगम बन गये। एक तरफ तो आपके 18 हजार का वार्ड है, एक तरफ आपके 314 का वार्ड है, तो किस तरह से आपने बनाया है? कोई तरीका, कोई गाइडलाइन तो होती आपकी। परिसीमन हमारी सरकार में भी हुआ था पर आपने देखा होगा कि तब पारदर्शिता के हिसाब से सारा परिसीमन हुआ था।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल का पानी मिल जाए, सड़क का कार्य शुरू हो जाए और शिक्षा में भी तरीके से नवीनता करें। आप कह रहे थे, अभी फरमा रहे थे एमएलए साहब कि युवराज ने यह किया, तो भाजपा की खिलाफत करने के अलावा युवराज ने कुछ नहीं दिया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेश मोदी।

सूचना

शंखवाली (आहोर) में बच्चे की हत्या

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में शंखवाली गांव में....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी मैंने अलाउ नहीं किया है।

श्री छगनसिंह (आहोर): पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन का है।

श्री सभापति: फिनिश करें आप एक मिनट में। इट इज नोट रूलिंग।

श्री छगनसिंह (आहोर): मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में शंखवाली में मासूम बच्चे लक्ष्मण मीणा की हत्या हुई है। वह गुरुवार को स्कूल गया था, शुक्रवार को उसकी लाश मिली और उसके पूरे परिवारजन उपखण्ड स्तर पर धरने पर बैठे हुए हैं कि न्याय कब होगा। कालूराम इसके पिताजी हैं और परिवार सहित वहां पर बैठे हैं। वह लक्ष्मण मीणा जो मासूम बच्चा था और स्कूल गया था। बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए इसकी पुख्ता जांच करवाई जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह ली। माननीय श्री सुरेश मोदी।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद में भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा होता है और मैं इसके समर्थन में अपनी बात रखता हूं।

राज्य सरकार ने पिछले एक साल में कोरोना जैसी महामारी का सुन्दर ढंग से मुकाबला किया एवं इसके बावजूद हर क्षेत्र में अच्छा काम किया। कोरोना में राज्य सरकार के किये गये कामों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया इसके बारे में जानती है, परन्तु हमारे देश में यदि केन्द्र सरकार सही समय पर सही निर्णय लेती तो शायद हमें ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़तीं, जो इस देश ने झेली। श्री राहुल गांधी ने समय रहते महामारी की गम्भीरता की जानकारी केन्द्र सरकार को दी थी, परन्तु सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह बीमारी विदेश से आई थी और यदि समय रहते अन्तर्देशीय विमान सेवाएं बन्द कर दी जातीं तो बीमारी का प्रवेश हमारे देश में नहीं होता। इस कार्य में केन्द्र सरकार ने देरी करके बहुत बड़ी भूल की है। इसका कारण भी सब लोग जानते हैं। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, शायद यह ज्यादा जरूरी था इस देश की जनता की स्वास्थ्य के मुकाबले, इसका फैसला

(श्री सुरेश मोदी)

इन्होंने उनका दौरा करके करवाया। मैं राज्य सरकार को देश में सबसे पहले लॉकडाउन लागू करने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, भामाशाह कार्डधारकों का मुफ्त इलाज सीकर जिले में नहीं हो रहा है। कारण बताते हैं कि राज्य सरकार ने महामारी के बावजूद, सरकार से समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण डाक्टरों ने भामाशाह कार्ड का बहिष्कार किया हुआ है और उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और सीकर जिले के भामाशाह कार्डधारकों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाए।

राज्य सरकार ने महामारी के बावजूद युवाओं को सरकारी नौकरी देने के क्षेत्र में भी इस साल अच्छा काम किया है। इस वर्ष सरकारी नौकरियां हर विभाग में दी गई हैं और दी जा रही हैं। लगभग 2 हजार डाक्टरों को नियुक्ति दी गई है। इसके विपरीत बीजेपी के सत्ता में आने पर दो करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का जो वादा किया था, उस वादे की पूर्ति में केन्द्र सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, ये सब लोग जानते हैं। उल्टे जिन युवाओं के पास नौकरियां थीं, उनकी नौकरियां भी चली गईं, उनके गलत फैसलों के कारण नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के प्रभाव की बदौलत।

राज्य सरकार ने खेल मैदानों के विकास को नरेगा में शामिल किये जाने वाले कार्यों में शामिल कर युवाओं को बड़ी सौगात दी है। मैं सीकर जिले से आता हूं, जहां से काफी बड़ी संख्या में नौजवान सेना व पुलिस की भर्ती में जाते हैं और इस भर्ती की तैयारी में सड़कों पर दौड़ लगाकर अभ्यास करते हैं। कई बार इस दौरान उनके एक्सीडेंट होते हैं, अब उन्हें अपनी पंचायत पर विकसित खेल मैदान मिल जाएंगे, जहां ट्रैक की सुविधा होगी, कसरत करने की सुविधा होगी, खेल खेलने की सुविधा होगी।

मेरा सरकार से निवेदन है कि सभी जिला परिषदों को स्पष्ट निर्देश नहीं है कि वे खेल मैदान की चारदीवारी एवं अन्य विकास के कार्यों को स्वीकृत करें। अत: उन्हें खेल मैदान के विकास हेतु चारदीवारी, ट्रैक निर्माण, कसरत संबंधी सुविधा जुटाने एवं विभिन्न खेलों के कोर्ट एवं जिम आदि के कार्यों की स्वीकृति पंचायतों को देने का निर्देश दें।

मैं सरकार से मनरेगा योजना को शहरी क्षेत्र में भी लागू करने का निवेदन करना चाहता हूं। युवाओं के अलावा किसानों के हित में भी राज्य

(श्री सुरेश मोदी)

सरकार ने गत वर्ष में बहुत अच्छा काम किया है। कर्ज माफी, कृषि कार्यों के लिए दिन में बिजली दिया जाना, नये नलकूपों की खुदाई पर लगा प्रतिबंध हटाना, खाद का अधिक भंडारण कर सही समय पर किसानों को उपलब्ध करवाना, बिजली की सप्लाई व्यवस्था में सुधार जैसे कई कार्य राज्य सरकार ने किसानों के हित में किये हैं। इसके विपरीत केन्द्र सरकार की बीजेपी सरकार ने किसानों से उनकी आय दुगुनी करने का जो वादा किया था, उसका क्या हाल है, यह सभी जानते हैं।

स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर कृषि की लागत पर लाभ जोड़कर एमएसपी पर कृषि उत्पादों की खरीद का वादा किया था, उसका क्या हुआ, ये भी सारी जनता जानती हैं। जो किया वह तीन काले कानून लागू करके किया। जिनके विरोध में लम्बे समय से लाखों अन्नदाता सड़क पर कड़कड़ाती सर्दी में बैठे हैं, सैकड़ों किसान प्राणों की आहूति दे चुके हैं पर सरकार उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है। कानून आने से पहले इनके मित्रों ने नोएडा और सोनीपत में और अन्य जगहों पर खाद्यान्न भंडारण के बड़े-बड़े सायलो का निर्माण कर लिया। इससे जाहिर होता है कि इन कानूनों के लागू होने में इन उद्योगपतियों की मिलीभगत है। मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग करता हूं एवं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन कानूनों का असर राजस्थान के किसानों पर न पड़े, इसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाकर तीन अध्यादेश पारित किये, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक राज्यपाल महोदय ने इन पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

मैं राज्य सरकार से छोटे किसानों को मुफ्त बिजली दिये जाने का निवेदन करता हूं ताकि उनकी तकलीफों को कुछ कम किया जा सके। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में नियमित विद्युत सप्लाई हेतु तीन नये 33/11 जीएसएस स्वीकृत कर बनाये जाने का भी निवेदन करता हूं, एक डाबला में, एक मंडोली में और एक माउंडा में।

मैं मेरे क्षेत्र की पीथमपुरी पंचायत में एक कृषि महाविद्यालय खोलने का भी सरकार से निवेदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि डाक्टर का बेटा आगे चलकर डाक्टर बनने की इच्छा रखता है, सीए का बेटा सीए बनने की इच्छा रखता है और नेता का बेटा नेता बनने की इच्छा रखता है लेकिन

(श्री सुरेश मोदी)

किसान का बेटा खेती करने की इच्छा नहीं रखता। सरकार को निश्चित रूप से कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे किसान का बेटा कृषि करने की तरफ आकर्षित हो, कृषि में नवाचार हों, कृषि को सुविधाएं मिले और अन्नदाता को उसका हक मिले। उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो है, वो मिले ताकि लोगों का, किसानों के बेटों का कृषि की तरफ रुझान वापस चालू हो।

किसानों को सौर ऊर्जा पर जो सब्सिडी मिलती है, उस पर वैटिंग चल रही है। मेरे यहां आज कोई सौर ऊर्जा लगाता है तो उसे सब्सिडी के पैसे दो साल-तीन साल बाद मिलते हैं। ऐसे में किसान कैसे सौर ऊर्जा लगाएगा, कहां से उसका पैसा लायेगा? मेरा सरकार से निवेदन है कि सब्सिडी सिस्टम लगते ही मिल जाए, इस तरह की व्यवस्था करें।

महोदय, आपके माध्यम से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए पीने की पानी की समस्या के बारे में सरकार को बताना चाहता हूं। आप स्वयं उस विभाग के मंत्री रह चुके हैं और आपके समय में पिछले कार्यकाल में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना चालू की गई थी। उसके फेज-I का काम पूरा भी कर दिया गया था। फेज-II का काम किया जाना बाकी है। पानी के बंटवारे में भी राजस्थान को फेज-II का पानी आबंटित है। बरसात हो नहीं रही, हैंडपम्प सूख रहे हैं, बोरिंग फेल हो रहे हैं। आज पानी 1200 फीट नीचे मिल रहा है और वह भी फ्लोराइड युक्त मिल रहा हैं। कैंसर, घुटनों में दर्द जैसी भयंकर बीमारियां इस पीने के पानी की वजह से मेरे इलाके में हो रही है, डार्क जोन पहले से ही घोषित किया जा चुका है। इस सबका इलाज केवल और केवल शुद्ध जल कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना या यमुना के पानी से हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसी बजट में पैसा देकर कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना फेज-II का काम चालू करवाया जाए, जिससे कि सीकर जिले की कई तहसीलों की जनता को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

नीम का थाना को जिला बनाने की बहुत समय से मांग चल रही है। नीम का थाना जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है। अत: जल्द से जल्द इसे जिला घोषित किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रकृति ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है खनिज

(श्री सुरेश मोदी)

भंडारों के रूप में, खनिज संपदा के रूप में। हम इसका समुचित दोहन करके ग्रामीण रोजगार का और सरकारी राजस्व का बड़ा साधन बना सकते हैं। जरूरत है अवैध खनन को रोकने की और वैध खनन को संरक्षण देने की। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन का बोलबाला है, ओवरलोडिंग का बोलबाला है। रेला और मीणा की नांगल आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां के नागरिक इन ओवरलोड ट्रोलों से, डीप होल ब्लास्टिंग से परेशान हैं। आये दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन को ज्ञापन देते हैं। सड़कें बनते ही ओवरलोड ट्रकों से टूट जाती हैं। दिन-रात एक्सीडेंट होते हैं। मैंने खनिज मंत्री जी से व परिवहन मंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिये परंतु कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई। विस्फोटक सामग्री ऐसे पड़ी रहती है जैसे आलू-प्याज की बोरियां पड़ी रहती हैं। प्रशासन एवं विभागों में शिकायतों का असर नहीं होता है। रॉयल्टी के ठेके देकर सरकार अवैध खनन को वैध का जामा पहना देती है। सरकार की खनिज विजिलेंस शाखा भी ठेका क्षेत्रों में कार्यवाही नहीं करती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरकार प्रभावी कार्यवाही करे।

अभी मेरे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि राजस्थान की सरकार को योगी जी की सरकार से सीखना चाहिए कि कानून-व्यवस्था कैसे स्थापित की जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हाथरस कहां है? यूपी में है या नहीं? उन्नाव कहां है? वहां क्या हुआ? टोल टैक्स पर क्या हुआ जहां महिला को जिंदा जलाया गया था, यह सब किसके शासन में हो रहा है? मैं फाजिल दोस्त से कहना चाहूंगा कि हमें ऐसा सुशासन नहीं चाहिए, हमें ऐसी कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए पुन: धन्यवाद। जय हिंद।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बून्दी): सभापति महोदय, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने 10 तारीख को यहां अभिभाषण पढ़ा, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने इस अभिभाषण को दोतीन बार पढ़ा तो न तो इसकी कोई दिशा है न कोई दशा है। इसके पैरा नंबर-4 में इन्होंने लिखा, 'वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद कठिन दौर में भी विकास के पहिये को निरंतर गतिमान रखा। आपदा

(श्री अशोक डोगरा)

को अवसर में बदलते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ सभी क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये।' जब कोरोना काल पीक पीरियड पर था तब तो यह अपनी सरकार बचाने के लिए बाड़ेबंदी में थे। माननीय मुख्य मंत्री जी अपने डिप्टी सीएम को +++ बता रहे थे। ...(व्यवधान)

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): ...(व्यवधान)... इसको डिलीट किया जाए ...(व्यवधान) आप गलत नहीं बोलोगे। मर्यादित भाषा में बोलें।

श्री सभापति: प्लीज। मंत्री जी।

श्री अशोक डोगरा (बून्दी): अपने एसओजी और दूसरी एजेंसीज से अपने डिप्टी सीएम, कुछ मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे थे। बार-बार हरियाणा पुलिस भेज करके उनको अरेस्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। जनता पर तो आपका ध्यान ही नहीं था। आपको डर लग रहा था कि एमएलए नहीं भाग जाएं इसलिए सारी पुलिस तो वहां लगा रखी थी। हालत ऐसी कर रखी थी। यदि कोरोना में कुछ किया है तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के मैनेजमेंट की वजह से ठीक हुआ है और हमारे यहां के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों की मेहनत से कंट्रोल हुआ है, आपकी वजह से कंट्रोल नहीं हुआ है। भारत का नाम हुआ है। भारत के साइंटिस्टों ने आज दो तरह की वैक्सीन यहां पैदा की जो विश्व में आज तेरह देशों में काम में ली जा रही है।

आपने कोरोना काल में हॉस्पिटल्स की यह हालत कर दी कि दूसरी बीमारी के पेशेंट लेने ही बंद कर दिये। सब तरह के ऑपरेशन बंद कर दिये। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भामाशाह योजना में जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसकी स्कीम ही बंद कर दी। गरीब आदमी को तो मरने के लिए मजबूर कर दिया आपने, या तो मरेगा या अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर इलाज करवाएगा और आयुष्मान योजना को आपने 2 साल तक लटका कर रखा। आपने गरीब आदमी को टोटल भगवान के और मौत के भरोसे छोड़ दिया। सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया। हमारी केंद्र सरकार ने आपको क्या नहीं दिया? आपको करोड़ों रुपये के वेंटिलेटर दिये, आइसोलेशन बैड दिये, पीपीई किट्स दिये, दवाइयां दी, मास्क दिये, लेकिन यह कह रहे हैं न कि हमने उसको बदल दिया, कुछ काम नहीं किया।

(श्री अशोक डोगरा)

प्रवासी भारतीयों के लिए, जो प्रवासी राजस्थानी थे, मेरे से पहले के वक्ता अभी बता रहे थे कि हमने खुद ने महसूस किया, हमारे यहां के भी कुछ लोग बाहर थे जो पहले तो सरकार सोयी रही, बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की, जो नंबर दिये, जो अधिकारी लगाये, मैंने खुद ने ट्राई किया, किसी अधिकारी ने फोन ही नहीं उठाया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कराये, वह नंबर ही नहीं लगते थे। वह तो कुछ दानदाताओं की मदद से, वहां के लोगों की मदद से वह अपने घर पहुंचे हैं। सरकार का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है।

मैं पूछता हूं सरकार ने कितने पैसे का राशन लॉकडाउन में बांटा है? यह तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी हैं जिन्होंने हर शख्स को जो खाद्य सुरक्षा में है, उसको 5 किलो गेहूं और हर राशन कार्ड पर 2 किलो चना अप्रैल से नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में उन्होंने उसके लिए उपलब्ध करवाया है। उन्होंने उज्ज्वला योजना में जिन लोगों को गैस कनेक्शन दिये थे उनको तीन-तीन बार रीफिल कराने के लिए पैसे उनके खाते में डाले ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं आये। सरकार ने कुछ नहीं किया। जो भी जनधन खाते थे और दूसरे खाते थे उनमें हमारी केंद्र सरकार ने पैसा डाला। आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने, आपके अधिकारियों ने हमारे एमएलए फंड से राशन किट के नाम पर हमसे लाखों रुपये की अनुशंसा करवा ली और उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जो, अपात्र लोग थे पात्र नहीं थे, उनके घरों पर वह किट्स पहुंचा दी और हमने अधिकारियों को मना भी किया कि यह पात्र नहीं हैं। एक-डेढ़ महीने बाद जिस दिन दारू के ठेके खुले तो वह, जिनको किट बांटे थे, वह दारू खरीदने की लाइन में सबसे आगे खड़े हुए मिले वहां। बिलकुल सही कह रहा हूं। एक लोकल अखबार में दारू की दुकान के बाहर की फोटो आई थी, मैंने एसडीएम को बुलाकर कहा था कि, देख लो इन लोगों को, यह जो बाहर लाइनों में खड़े हैं, इन लोगों को आपने फ्री के किट हमारे विधायक कोष से बंटवाए हैं, तो सरकार ने कोई काम नहीं किया है।

आज राजस्थान में आपके बहुत बड़े नेता आये हुए हैं जिन्होंने 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात कही थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लोगों ने नहीं चाहते हुए भी किसान जो इतने कर्जे में थे, लोगों ने सोचा कि सारी तो केसीसी माफ हो जाएगी, लोगों ने यहां तक सोच लिया है कि हमारे ट्रैक्टरों का फाइनेंस है यह भी कृषि लोन में आता है, यह भी फ्री हो जाएगा। लोगों ने नहीं चाहते हुए भी कांग्रेस को वोट दे दिया। आज

(श्री अशोक डोगरा)

26 महीने होने को आये, राजस्थान में एक भी केसीसी माफ नहीं हुई। आज किसान वापस आत्महत्या करने को मजबूर है। मैं कांग्रेसी नेताओं को कहना चाहता हूं कि आज आपका जो नेता आया हुआ है उससे कहो कि भैया, तुम दो-ढाई साल पहले वादा करके गये थे, आज तो कम से कम उसको पूरा कर जाओ। जनता आने वाले चुनाव में फिर पूछेगी कि भैया, कर्जे का क्या हुआ।

आज बिजली की क्या स्थिति है? कोरोना काल में जो गरीब आदमी था, जो ठेलेवाला था, जो मजदूर था, जो रोज कमाता था रोज खाता था, उन सबको उम्मीद थी कि सरकार कम से कम 3 महीने के बिजली-पानी के बिल तो इनके माफ करेगी, लेकिन सरकार ने बिल नहीं माफ किये। पैनल्टी और ब्याज के साथ ही वापस लिये हैं। आज बिजली की यह हालत है कि आपने किसान से कहा था कि हम 5 साल तक बिजली के पैसे नहीं बढ़ायेंगे, अब रोज कोई न कोई नया टैक्स लग जाता है, कभी तो फ्यूल चार्ज आ जाता है, कभी स्थायी शुल्क आ जाता है, कभी सैस सा जाता है, कभी कोई आडिट आ जाता है, मतलब इतनी बिजली महंगी है और जो 10,833 रुपये महीना पिछली सरकार ने सब्सिडी किसानों के लिए दी थी, उसको भी आपने बंद कर दिया। आज 50 यूनिट पर जो राजस्थान में साढ़े चार रुपये यूनिट आप चार्ज करते हो, बाकी टैक्स अलग लगाते हो, वह हरियाणा में 2 रुपये लग रहा है, दिल्ली में 3 रुपये लग रहा है, गुजरात में 3 रुपये 5 पैसे लग रहा है तो यहां राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। इतनी सर्दी में भी आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में थ्री फेज बिजली किसानों को इतनी ठंड में रात को दी है, उनको मरने को मजबूर कर दिया। आज भी वहां सुबह 7:00 से 11:00 तक किसी भी गांव में बिजली नहीं मिलती है, यह स्थिति कर रखी है।

डीजल और पेट्रोल की स्थिति यह है कि आज हरियाणा में चले जायें, गुजरात में चले जायें, वहां यहां से 8-10 रुपये कम है। हम भी दिल्ली जाते हैं तो सोचते हैं कि हरियाणा बॉर्डर से भरवा कर जाएंगे। आज यह हालत है कि आपने बार-बार वैट बढ़ा दिया। अभी लास्ट में 2 परसेंट वैट कम करने से क्या हुआ? आज सबसे ज्यादा वैट यदि है तो राजस्थान सरकार ने लगा रखा है जिससे आम जनता पर इसका भार पड़ रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। विकास के सब काम आपने बंद कर दिये, जो पुरानी सरकार ने काम मंजूर किए थे उन ठेकेदारों की पेमेंट नहीं, कम से कम हजारों-करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों की बाकी है।

(श्री अशोक डोगरा)

(16.00 बजे)

उन्होंने भी काम बंद कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा देगी तो करेंगे। आपने सब तरह के काम बंद कर दिये। विकास पथ की बात की थी, तो विकास पथ भी कहीं नहीं बने। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार में पांच करोड़ की सड़कें मंजूर हुई थीं, सरकार पैसे की भी व्यवस्था करके गई थी लेकिन आपने वह भी कैंसिल कर दी। कृषि मंडी से कोई सड़कें नहीं बनीं। आपने विकास के सारे काम बंद कर दिये।

दो साल से ज्यादा हो गया पंचायतों में एक नया पैसा भी नहीं डाला। पंचायतों के विकास के सारे काम बंद हैं। पुराने सरपंचों को भी नहीं मिले। फिर चुनाव हुए नये सरपंच आए, उनको भी जनता जूते मार रही है। पैसा आप दे ही नहीं रहे। मेरे यहां तो यह स्थिति हो गई कि पेयजल का पैसा नहीं दे रहे, आरएसईबी वाले कनेक्शन काट रहे हैं, लोगों को पेयजल भी नहीं मिल रहा और पैसा आप लोग डाल नहीं रहे हो। गौशालाओं का आपने अनुदान बंद कर दिया। आपने पिछली बार कहा था कि हर पंचायत समिति में एक नंदी शाला बनेगी। आज राजस्थान में कितनी पंचायत समितियों में नंदी शाला बनीं? कहीं नहीं बनी।

सरकार में आज यह हालत है कि पटवारी हड़ताल पर हैं, आशा सहयोगिनी धरने पर बैठी हैं, विकास अधिकारी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, सब कुछ बंद है। लेबर डिपार्टमेंट के जितने काम पिछली सरकार ने सैंक्शन किये, इतने जनप्रिय, लोकप्रिय काम थे, आपने उसमें पैसा डालना बंद कर दिया। उसमें सीधी-सी बात थी, किसी गरीब मजदूर की बच्ची 18 साल की हो जायेगी, आठवीं में पास हो गई तो उसकी शादी के लिये उसको 55 हजार रुपये मिलेगा, आपने वह स्कीम बंद कर दी। यदि उसके पास मकान नहीं होगा तो डेढ़ लाख का प्रावधान था, आपने वह स्कीम बंद कर दी।

लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि महिलाओं और दलितों पर अत्याचार में राजस्थान हिन्दुस्तान में पहले या दूसरे स्थान पर है। इतनी स्थिति खराब है। कहीं गैंग रेप हो रहा है, कहीं गैंगवार हो रहा है, बजरी माफिया प्रशासन से मिला हुआ है। कलेक्टर भ्रष्ट, एसपी भ्रष्ट, एसडीएम भ्रष्ट, थानेदार भ्रष्ट, पूरा प्रशासन भ्रष्ट हो रहा है। आपने इसमें लिखा कि नरेगा में हमने 69 लाख लोगों को काम दिया। इसमें आपका क्या लेना देना, यह पैसा तो आपको केन्द्र सरकार ने दिया है। आपका तो कुछ लेना देना नहीं। आपने इसके पैरा नंबर 11 में..

श्री सभापति: माननीय, कनक्लूड करें।

श्री अशोक डोगरा (बून्दी): एक मिनट, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है। मेरे एक थानेदार जी थे, वह बहुत अच्छे थे। वह कोरोना में पब्लिक की सेवा करते करते मरे हैं। आपने इसमें 11 नंबर पर दिया है कि कोरोना वॉरियर्स, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी एवं संविदाकर्मी शामिल हैं, की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि बुद्धिप्रकाश जी एक एसएचओ थे, वह पब्लिक की बहुत सेवा करते थे, उसी से उसको कोरोना हुआ। 18.09.2020 को कोटा के मेडिकल कॉलेज में उनकी डैथ हुई। मैंने आज ही सुबह उसके भाई को और उसके बच्चे को फोन करके पूछा है कि आपको मुआवजा मिला है? उन्होंने कहा, अंकल जी, हम तो जयपुर तक हो आये, न तो हमको 50 लाख मुआवजा मिला, न अनुकंपा नौकरी मिली और न अभी तक पेंशन चालू हुई कुछ भी नहीं मिला तो मेरा यह सरकार से निवेदन है कि कोरोना वॉरियर्स की पूरी मदद करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें प्लीज।

श्री अशोक डोगरा (बून्दी): आपने बच्चों के लिये दूध बंद कर दिया। स्टेट हाई-वे पर टोल लगा दिया, जनता को परेशान करने में कुछ भी नहीं छोड़ा। हाड़ौती में मक्की की फसल बहुत थी, आपने सरकारी खरीद पर मक्की की फसल नहीं खरीदी। जो 1800 रुपये में खरीदनी चाहिये थी, वह किसान 800-900 रुपये में बेचने को मजबूर हो गया। हर तरफ से यह पूरी सरकार फेल है। मैं इस अभिभाषण की निंदा करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री संदीप कुमार।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। वैश्विक महामारी के इस दौर में प्रदेश की सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में देश ही नहीं, पूरी दुनिया में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। लगातार वीसी के जरिये अधिकारियों के साथ-साथ पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों से भी लगातार संवाद करके पूरे प्रदेश में कोरोना को फैलने से रोका। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री जी के साथ-साथ ही हमारे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री जी का, सभी डाक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस प्रशासन, आशा सहयोगी और सफाईकर्मी, जिन्होंने इस महामारी

(श्री संदीप कुमार)

में अपनी जान की परवाह किये बिना सब लोगों ने मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा की। कोरोना महामारी के समय में कोई जनहानि नहीं हो, इस लक्ष्य को लेकर कोरोना संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों की आरटीपीसीआर जांच सहित सभी जांचें और उपचार नि:शुल्क उपलब्ध कराये गये। बाकी राज्यों में कोरोना के इलाज के लिये लोगों को जहां लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, वहां हमारे संवेदनशील सरकार के द्वारा लोगों को नि:शुल्क जांच और नि:शुल्क दवा उपलब्ध करवाई जा रही है। जो सैम्पल पुणे भिजवाये जाते थे, सभी जिला मुख्यालयों पर उपलब्ध कराये गये हैं। कोरोना रोगियों के लिये 140 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, कोविड हैल्थ सेंटर के साथ-साथ 43 हजार आइसोलेशन बैड, 1899 वेंटिलेटर्स, 3170 आईसीयू बैड के अलावा पीपीई किट्स और दवा व उपकरणों की व्यवस्था की गई।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी के द्वारा चलाई गई दवा योजना के द्वारा कोरोना काल में 86 करोड़ से अधिक रोगियों को लाभान्वित किया गया। राज्य सरकार के प्रयासों से प्लाज्मा थैरेपी में भी प्रदेश अग्रणी रहा। इसके अलावा कोरोना रोगियों के नि:शुल्क इलाज में गंभीर रोगियों की जान बचाने के लिये जो 40 हजार के इंजेक्शंस हैं, वह भी फ्री दिये जा रहे हैं और चैस्ट इंफेक्शन के लिये एचआरसीटी सहित सभी जांचें नि:शुल्क की जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के द्वारा 90 प्रकार की जांचें नि:शुल्क, करीब 33 करोड़ 86 लाख जांचें अभी तक की जा चुकी हैं। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र चिह्नित किये गये हैं। 80 हजार स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर उनको प्रशिक्षण दिया गया है ताकि इस महामारी के समय में वह लोगों का सहयोग कर सकें। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये दो हजार अतिरिक्त पद सृजित करके 2020 में कुल 2727 चिकित्सकों के साथ 11 हजार नर्सिंग कर्मियों को भी नियुक्तियां दी गई हैं। कोरोना वारियर्स की मृत्यु पर सरकारी कर्मचारी के साथ-साथ संविदा कर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर परिजनों को 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी। इसके साथ-साथ पंचायती राज के द्वारा 4372 करोड़ रुपये खर्च करके 9300 कार्य पूरे कराये गये। मनरेगा में 1960 करोड़ रुपये खर्च करके 69 लाख से अधिक परिवारों को कोरोना महामारी के समय में रोजगार दिया गया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार की महिलाओं का सम्मान और उनको

(श्री संदीप कुमार)

आत्मनिर्भर बनाने के लिये आजीविका योजना में 184000 स्वयं सहायता समूहों को रोजगार प्रदान किया गया। इसमें 1805 करोड़ रुपये का संबल प्रदान करके 21 लाख 50 हजार परिवारों को लाभान्वित किया गया। कोरोना महामारी के समय में जब मजदूर साथियों को बड़ी दिक्कत हो रही है, उनकी नौकरियां छूट गई हैं, ऐसे समय में राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने इंदिरा रसोई योजना चलाकर 8 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराई है, जिसमें अभी तक करीब 1 करोड़ 55 लाख लोग भोजन कर चुके हैं।

इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को करीब 2 वर्ष में 81893 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा 50865 पदों की भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है। लॉकडाउन के बाद मई, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक 188 ऑनलाइन कैम्प लगाकर 7104 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये मुख्य मंत्री जी के द्वारा युवा संबल योजना 1 फरवरी, 2019 से अमल में आ चुकी है। करीब 800 करोड़ की राशि बेरोजगारों को भत्ते के रूप में प्रदान कर दी गई है, जिससे ढाई लाख युवाओं को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही 31 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिये रीट का आयोजन 25 अप्रैल, 2021 को कराने का निर्णय लिया। जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की योजना का विस्तार करके उनको ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी विद्यालय खोले गये, जिसमें 2020-21 में कुल 168 ब्लॉक में विद्यालय खोले जा चुके हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिये 29 अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पदक विजेताओं को विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। सितम्बर, 2020 में संपन्न जेईई और नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को बसों के टिकट में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई। उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिये 2020-21 में 38 नये महाविद्यालय खोले गये। 12 महाविद्यालय स्नातक से स्नातकोत्तर किये गये। हमारे राज्य में शायद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महाविद्यालय खोले गये हैं। इसके साथ ही साथ नये आईटीआई खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्य में देव भाषा संस्कृत के 49 वरिष्ठ अध्यापक, 10 प्रवेशिका एवं 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करके 5 नये संस्कृत विद्यालय भी खोले गये हैं।

(श्री संदीप कुमार)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने युवाओं एवं किसानों की सभी मांगों को लगातार ध्यान में रखते हुए लगातार दो वर्षों के बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इन बजटों में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो राजस्थान में जो बड़ा रेवेन्यू प्रदान करता है, हमारा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, वहां वर्षों से जो मांग चली आ रही थी, हमारे क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय और एक नवीन महाविद्यालय का काम दो वर्षों में किया और तीसरा महाविद्यालय है, उसको पीजी करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि जो किसान सड़कों पर बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से उनको आतंकवादी और उग्रवादियों की संज्ञा दी गयी, वह निंदनीय है। हमारे सभी किसान साथी तिरंगा लेकर दिल्ली के चारों तरफ तिरंगे के सम्मान में निकले थे, भारत माता के सम्मान में निकले थे, अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए निकले थे। जिस तरह का कायराना हमला वहां हुआ, जिस तरीके से उन किसानों पर कायराना हमला कराया गया, उनको उग्रवादी और आतंकवादी कहा गया, वह निंदनीय है। उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री गोतमलाल।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में सबसे ज्यादा कोरोना की बात आयी है। कोरोना महामारी के जब पहली बार तीन केस आये थे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष, माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया साहब एवं माननीय श्री राजेन्द्र जी राठौड़ साहब ने सरकार को यह कहा कि इस महामारी में हम सरकार के साथ में हैं, आप जो भी कदम उठाएं। सबने मिलकर काम किया, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने सरकार की प्रशंसा की, यह अच्छी बात है, लेकिन अच्छा तब होता जब महामहिम के अभिभाषण में एक लाइन लिखवाते कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, तो यह बहुत अच्छी बात होती, परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

महामहिम ने जो अभिभाषण दिया है, उसमें सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया। गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ किया, मुख्य

(श्री गोतमलाल)

मंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी जल संचय योजना, अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इन्दिरा रसोई कर दिया। अन्नपूर्णा तो माता जी हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, फिर भी आपने नाम बदला, कोई बात नहीं। काम जो होने चाहिए थे, वे काम नहीं हुए।

माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 24 लाख 23 हजार किसानों को लाभ दिया, अच्छी बात है, लेकिन विधान सभा क्षेत्र धरियावद में कृषकों का नाम जो रिकार्ड में, वह उदयपुर जिले में बताया जा रहा है, उनको क्लेम नहीं मिला है, तो इसका ध्यान रखें। दूसरी बात और है, गत बजट सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने धरियावद कृषि मंडी खोलने की जो घोषणा की, उसके लिए धन्यवाद। कृषि मंत्री जी, आपको आपके अधिकारी जो जानकारी देते हैं वह बिलकुल गलत है। धरियावद में कृषि मंडी महामहिम उप राष्ट्रपति और पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने 25 साल पहले खोल दी थी और कृषि मंडी के नाम से जमीन भी अवाप्त हो गयी थी और जिनके खाते की जमीन थी, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था। तो 25 साल से वह मुकदमा चल रहा है। यह बात पहले भी मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रखी थी। श्री प्रभु लाल जी सैनी मंत्री थे। मैंने उनको कहा, उन्होंने अधिकारियों को कहा, उनको कहा कि जानकारी गलत दी है। वर्तमान कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपके अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं। वहां कृषि मंडी की जमीन भी कृषि मंडी के नाम से हो गयी और कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहां वकील करके उसका जो भी निपटारा करना है, करें। एक बीघा जमीन के ऊपर तो स्टे नहीं है, वहां सिंचाई विभाग के जाखम बांध की कालोनी की जमीन पड़ी है, उसमें जो भी निर्णय आये, वह कराकर कम से कम वहां कृषि मंडी का काम करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके ये अधिकारी आपको गलत जानकारी देते हैं। इस पर आप विशेष ध्यान दें।

बिंदु संख्या 21 में अंतिम लाइन में लिखा है कि यूरिया की आपूर्ति निरंतर जारी है। मैं सहकारिता मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे धरियावद क्षेत्र में कालाबाजारी हो रही है, लोग ज्यादा पैसे से खाद खरीद रहे हैं। किसी लैम्पस में या किसी सहकारी समिति में कोई खाद या बीज नहीं मिल रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र धरियावद से लस्याड़ा जो सड़क है, उसमें तीन

(श्री गोतमलाल)

साल से काम चल रहा है। सिर्फ उसके ऊपर यह रोक थी कि चौड़ी करने पर रोड दी, लेकिन पुरानी जो 60 मीटर सड़क थी, उसके ऊपर कोई रोक नहीं थी, लेकिन वह काम भी पड़ा है, उस पर गिट्टी कर दी है, लेकिन डामरीकरण नहीं होने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। लस्याड़ा में एक कालेज है, उसका भी ढाई साल से काम चल रहा है। ढाई साल में उसका छत लेवल तक भी काम नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा केवल बात करने एवं अभिभाषण में केवल वाहवाही लूटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विकास का काम नहीं हो रहा है। सलूम्बर से भेड़ावल सड़क, जिसका मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था, लेकिन उस सड़क में गड्ढे हैं। वहां पर कोई सड़क का काम नहीं हुआ है। पुरानी जितनी भी सड़कें हैं, वे सारी की सारी खुर्द-बुर्द हो गयी हैं। वहां कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, न ही लोगों को नरेगा में ज्यादा रोजगार मिल पा रहा है।

(16.15 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

2013 में ए.एन.एम. और सूचना सहायकों की भर्ती निकाली गयी थी, उसका क्या हुआ? सरकार इसका जवाब दे। उस प्रक्रिया को तो बंद कर दिया और नयी भर्ती 2018 में निकाल दी गयी। 2013 के अभ्यर्थी हताश होकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, कुछ तो ओवर एज हो गये हैं। आये दिन आंदोलन कर रहे हैं। सरकार इस पर भी ध्यान दे। बिंदु संख्या 41 में मां-बाड़ी केंद्रों का संचालन कर लाभान्वित किया जा रहा है। सोचने का विषय यह है कि कई जगह तो भवन ही नहीं हैं और कई जगह हैं तो जर्जर अवस्था में हैं। कई जगह पर पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके भवन की भी सरकार व्यवस्था करे। हैंडपम्प मिस्त्रियों की हमारे यहां पर ज्यादा समस्या है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोतमलाल (धरियावद): शुरू ही किया है तो कैसे समाप्त करें? मैं जो बात कह रहा हूं वह बिलकुल सही बात कह रहा हूं। सरकार की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार की आलोचना के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं।

हमारे क्षेत्र में एक हैंडपम्प मिस्त्री के पास पांच-सात पंचायत हैं और

(श्री गोतमलाल)

गर्मी का समय आने तक वहां हालत यह खराब हो जाएगी कि वह हैंडपम्प मिस्त्री किसी पंचायत में नहीं जा पाएगा, तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि हैंडपम्प मिस्त्रियों की नयी भर्ती करें या पंचायतों को कहें कि वे अपने स्तर पर करें।

सभापति महोदय, देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से लॉकडाउन करके पूरे हिंदुस्तान की जनता को जो महामारी से बचाया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी नहीं होते तो 130 करोड़ का आंकड़ा और कम हो जाता, उनको धन्यवाद देना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार को दो साल पूरे हो गये हैं और दो साल में करीब एक साल कोरोना महामारी में चला गया। ऐसी स्थिति में भी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, वह बड़ा शानदार और जानदार रहा है। गरीबों के हितैषी माननीय अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं लागू की हैं, वे बहुत अच्छी योजनाएं हैं।

कोरोना महामारी के बारे में जो प्रबंध किये गये, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कोरोना महामारी में जो प्रबंध किये, जो संवाद किये, चाहे कोई राजनेता है, चाहे कोई सरपंच है और चाहे कोई भी जन प्रतिनिधि है, सबसे संवाद किये। करीब 100 से ऊपर वी.सी. करके जो प्रबंधन किया गया, वह बड़ा शानदार प्रबंधन किया गया, जिससे राजस्थान का नाम देश व दुनिया में मॉडल के रूप में जाना गया और विपक्ष के माननीय सदस्य कुछ भी कहें, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी तारीफ की है। यह मानना पड़ेगा कि कोरोना का जो प्रबन्ध किया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत शानदार किया। इस मौके पर किसी भी प्रकार की कहीं भी किसी को कमी नहीं आने दी, भूखा किसी को सोने नहीं दिया। हर गरीब, जो मजदूर बाहर से आए, उन सबके लिए प्रबन्धन किया गया। कोरोना महामारी के बचाव में 40 हजार का भी एक इंजेक्शन लगाया गया। 4 इंजेक्शन 4-4 हजार के, इस तरह फ्री में सारी जांचें की गईं और सारी जांचों के बाद में इलाज किया गया।

(श्री लाखन सिंह)

वर्ष 2013 में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने फ्री दवा देने की जो योजना बनाई, वह भी एक गरीब परिवार के लिए बहुत सार्थक हुई। जिस गरीब के घर में 100 रुपये भी नहीं रहते, वह भी अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करा सकता है। यह गरीब के लिए बहुत अच्छी योजना है। करीब 90 जांच हैं, जो फ्री होती हैं। चाहे कैंसर की है, चाहे हार्ट की है, जो भी जांचें हैं, वह सारी फ्री में की जाती हैं। इस तरह की योजना मुख्य मंत्री जी ने की है, यह बहुत सराहनीय है।

कोरोना महामारी के समय पर जिस तरह के प्रबन्ध किये हैं, बड़े अच्छे प्रबन्ध किये हैं। चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए भी 2020 में करीब 2 हजार 727 चिकित्सकों एवं 11 हजार नर्सिंगकर्मियों की भी नियुक्ति की गई। प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए 5 हैक्टेयर तक कृषि भूमि को कुर्की से मुक्त रखने संबंधी कानून पारित किया गया। साथ ही किसानों एवं आमजन की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ट्यूबवैल खुदाई के लिए आवश्यक एनओसी के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। जो नीति बनाई, जो एक गरीब, जो पत्थर का काम करता है, सिलिकोसिस जैसी बीमारी उसको हो जाती है, जो सिलिकोसिस पीड़ित हैं, उनके परिवारों के लिए नीति बनाई गई है। इसमें उनके लिए तीन लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। अगर मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो दो लाख और दिये जाते हैं। कुल 5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। उस परिवार के लिए बहुत कल्याणकारी योजना है। इसके अलावा उसके बच्चे पालनहार योजना में शामिल किए जाते हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं उनके उनका नाम रखने का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, नरेगा में जिस तरह से काम करने के लिए 'एक गांव-चार काम' के तहत चारागाह विकास, मॉडल तालाब, श्मशान व कब्रिस्तान तथा खेल मैदान के कुल 42 हजार 468 कार्य स्वीकृत किये गये, जिसमें से 11 हजार 615 कार्य पूर्ण कर लिये गये। प्रदेश में जो गरीब है, उसके खाने का प्रबन्ध नहीं होता, इसके लिए सभी नगर निकायों, हैडक्वार्टर पर इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। इस योजना में जो गांव से गरीब शहर को जाता है, उसका खाने का प्रबन्ध नहीं होता, वह आठ रुपये में एक फर्स्ट क्लास जगह कुर्सियों पर बैठकर, जिस तरह से होटल होता है, ऐसी व्यवस्था वहां पर की गई है और वह आठ रुपये में वहां खाना खा लेता है। यह एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें 12 रुपये का अनुदान दिया गया है।

(श्री लाखन सिंह)

बिजली के अंदर भी गत दो साल में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 400 केवी का एक जीएसएस, 220 केवी के 3 व 132 केवी के 19 ग्रिड सब-स्टेशन तथा 33 केवी के 387 सब-स्टेशन स्थापित कर 1 लाख 63 हजार कृषि कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्र में 9 लाख 71 हजार व शहरी क्षेत्र में 2 लाख 28 हजार घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं।

किसानों को कड़ाके की सर्दी में रात को सिंचाई नहीं करनी पड़े, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन साल के लिए योजना बनाई है। जो खेत में पानी मोड़ता है, सर्दी के समय पर उसको बड़ी दिक्कत होती है, जो बिजली दी जायेगी, वह 2023 तक दिन में दी जायेगी। अभी करीब 15 ऐसे जिले हैं जिनमें आज भी दिन में बिजली दी जाती है।

विगत दो वर्षों में जो बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार देने का काम किया है। इन दो वर्षों में 81 हजार 993 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है एवं 50 हजार 865 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। 800 करोड़ रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित कर लगभग 2 लाख 50 हजार बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में 31 हजार शिक्षकों के लिए रीट की परीक्षा लेने का कार्यक्रम घोषित किया गया है।

सभापति महोदय, गांव का एक गरीब परिवार, एक गरीब व्यक्ति जो यह सोचता है कि मैं भी मेरे बेटे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊं, ऐसी सोच के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय' प्रत्येक मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम से खोले हैं। उनमें इतनी संख्या में एडमिशन हुए हैं क्योंकि पैसे वाले का बच्चा तो अच्छे स्कूल में प्राइवेट में शहर में जाकर पढ़ लेता है, एक गरीब का बेटा नहीं जा सकता, यह गरीब के लिए बहुत अच्छी सोच है। अंग्रेजी माध्यम में वह बच्चा पढ़ सकता है। शिक्षा के रूप में ही करीब 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं एवं 12 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया है। पशु चिकित्सालय खोले गये हैं। करीब 571 पशु चिकित्सा उप-केन्द्र हैं। पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 12 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 8 हजार 261 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर 5 लाख 11 हजार घरेलू पेयजल कनेक्शन किये जा चुके हैं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो साल की योजना बनाकर गरीबों के लिए दी है। जब यहां कोरोना महामारी चल रही थी तब जो

(श्री लाखन सिंह)

केन्द्र की सरकार है, उसने चुनी हुई सरकार गिराने का काम किया। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जिस तरह से खरीद-फरोख्त के लिए चर्चाएं रही, यह भी एक बहुत निदंनीय काम है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने दो साल के अंदर लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है, भत्ता देने का काम किया है, उसी तरह से केन्द्र सरकार ने भी घोषणा की थी कि एक साल में दो करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा लेकिन यह खोखली घोषणाएं की गई, बेरोजगार आज दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं, उनको रोजगार देने का काम नहीं किया गया। जिस तरह से काला धन लाने की बात कही गई कि काला धन लाया जाएगा, सब के खाते में 15-15 लाख रुपये जमा कराए जाएंगे, महिलाओं ने खाते खुलवा लिए लेकिन 15 पैसे भी नहीं पहुंचे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री लाखन सिंह (करौली): मैं आपको तीन काले क़ानूनों के बारे में बताना चाहता हूं। आज देश का किसान दिल्ली के बोर्डर पर बैठा है। 200 के करीब किसान मर गये। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि जब-जब देश में क्रांति आई है, या तो उनकी बात मानी जाती है, नहीं तो उनको भगना पड़ता है। अंग्रेजों ने भी इसी तरह से तानाशाही की और उनको भगना पड़ा। या तो केन्द्र की सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, नहीं तो निश्चित है कि जिस तरह से जाग्रति आई है इस सरकार को भगना पड़ेगा और मोदी जी को यह गद्दी छोड़नी पड़ेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री लाखन सिंह (करौली): मेरी कुछ समस्याएं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री गिरधारीलाल जी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका मिला, बड़ी देरी से मिला। जिस तरह से खाजूवाला से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी अनदेखी की जा रही है, उसी तरह का सदन में नजर आ रहा है कि छोटे दलों को नजरंदाज किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं केन्द्र व राज्य, दोनों सरकारों का धन्यवाद करूंगा। कोरोना महामारी में दोनों ने मिलकर साझा प्रोग्राम, चाहे किसी पार्टी का लीडर हो, जनता हो, तमाम सरकारों को मैं धन्यवाद देता हूं।

(श्री गिरधारीलाल)

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में सर्वप्रथम राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासकों व सभी के द्वारा समन्वय स्थापित कर सराहनीय कार्यों के लिए मुख्य मंत्री के साथ-साथ केन्द्र के प्रधान मंत्री महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूं। अपने-अपने क्षेत्र में बेहतरीन भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं की भी पूरी प्रशंसा करता हूं। कोरोना काल में राजस्थान के प्रत्येक नागरिक ने अपनी सहनशीलता, समन्वय स्थापित करते हुए परिचय दिया, इसका ही परिणाम है कि राजस्थान कोरोना प्रबंधन में मॉडल बनकर उभरा है।

सभापति महोदय, लगतार तीन दिन से मैंने पक्ष और विपक्ष की चर्चा सुनी, एक की बड़ाई और दूसरे की आलोचना। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह पवित्र ग्रंथ है जो राज्यपाल द्वारा पेश किया गया है। राजस्थान की जनता को बहुत आस है। राजस्थान की जनता देख रही है कि राजस्थान की बड़ी पंचायत में हमारे लिए क्या होने जा रहा है। बिन्दु संख्या 26, मेरी नज़रों में सरकार ने सबसे बड़ा काम किया कि 5 हैक्टेयर की जमीन कुर्की मुक्त करने का कानून पारित किया। मगर मैं यह बताना चाहता हूं आज भी 6 हैक्टेयर, 5 हैक्टेयर, 5 हैक्टेयर से कम है, उसकी भी कुर्की हो रही है, उसको अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, ट्रेजरी बैंचेज की हालत देखिए, आठ आदमी बैठे हैं। यह तो हम लोग हैं जो कोरम पूरा किये हुए हैं। अगर मैं मेरे माननीय सदस्यों को यह कहूं कि यह भी एक बार बाहर जाएं, तो कोरम की घंटी आपको अभी बजानी पड़े। यह लोग कोरम भी नहीं कर सकते। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मैं अगर इनको इशारा करूं कि यह सब बाहर चले जाएं, तो कोरम कम नहीं पड़ जाएगा? सत्तारूढ़ दल का यह रवैया है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो, आप गिन लिजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ और नौ। हम जाते हैं बाहर, आप कोरम देख लीजिए। कोरम नहीं है ...(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय उपनेता से कह देता हूं संख्या 35 हैं मैंने गिन ली है। 35 संख्या मैंने गिनी है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग क्यों नहीं आते टाइम पर?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आप कांग्रेस की बात नहीं सुनना चाहते।...(व्यवधान)

श्री सभापति: हाउस का मजाक मत बनाइये, बुलाओ उनको सबको बाहर से, बुलाओ जल्दी। यह क्या तरीका है? ...(व्यवधान) आप अपनी बात जारी रखें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए 5 हैक्टेयर की अच्छी घोषणा की है, उसको कानूनी जामा पहनाया जाए ...(व्यवधान) बिन्दु 117. सितम्बर, 2020 में सम्पन्न जेईई व नीट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को निगम की साधारण ...(व्यवधान) एवं द्रुतगामी बसों में आने-जाने के लिए किराये में 100 प्रतिशत छूट देकर लाभान्वित किया गया।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): कांग्रेस की बात नहीं सुनना चाहते ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): घर में सोने की जगह नहीं है, सोकर आई हो अभी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): राज्य सरकार के इस फैसले के लिए तमाम परीक्षार्थियों की ओर से मुख्य मंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही राज्य सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान में आयोजित होने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने की घोषणा कर बेरोजगार विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया जाए।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड......

श्री सभापति: नहीं, अब विराजिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): मेरी पार्टी का 10 मिनट होता है। ...(व्यवधान) कोरोना काल के विकट दौर में राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में

(श्री गिरधारीलाल)

नाम जोड़ने की प्रक्रिया बंद कर दी थी, जिससे कुछ लोगों के नाम नहीं जुड़ पाए और कोरोना काल में इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गये, इसके विपरीत बड़ी संख्या में अपात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): खाद्य सुरक्षा में जुड़े अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए राज्य सरकार कोई ठोस रणनीति अपनाए। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज, सहयोग करे। अंकित नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, अब आप विराजिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):000

श्री सभापति: समय की अपनी पाबंदी है, अब आप विराजिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, अब आप विराजिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। विराजिये आप। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। कुछ सीख लीजिये। विराजिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान) विराजिये, माननीय सदस्य, अब आप खड़े हो गये।

(श्री सभापति)

मैं चीफ व्हिप से अनुरोध करूंगा। चीफ व्हिप साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया अपने सभी माननीय सदस्यों को कहें, लॉबी में बैठने के बजाय हाउस में बैठें। आप लोग भी, कुछ वरिष्ठ भी हैं, कुछ नये आये हैं। हाऊस में बैठने से आप छोटे नहीं हो जायेंगे। आप कुछ न कुछ सीखेंगे। यह तरीका गलत है। मुझे विपक्ष ने यह बताया कि आपके, सत्ता पक्ष के लोग नहीं बैठे हुए हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। यह गलत है। आप सब जिम्मेदार लोग हैं। जिन लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, वे आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सदन में बैठें और सदन की पूरी कार्यवाही में भाग लें। मुझे अच्छा नहीं लगता है। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा और आने वाले समय में सरकार क्या करने वाली है, इसका रोड मैप माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। इस अभिभाषण को जब माननीय राज्यपाल महोदय पढ़ रहे थे, यह महामहिम राज्यपाल महोदय जब पढ़ रहे थे, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत उनको पढ़ना होता है, सत्तापक्ष के एक भी सदस्य ने एक बार भी मेज नहीं बजाई, एक बार भी मेज नहीं थपथपाई। यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के लोगों की प्रतिक्रिया थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कैसा अभिभाषण था और कैसा सरकार का कामकाज था और आने वाले समय में सरकार किस तरह का रोड मैप तैयार करके जनता के बीच में जाना चाहती है। यह मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं।

हम लोग बात करें, आहोर से आने वाले मेरे माननीय साथी ने एक मासूम की हत्या का जिक्र किया, मन व्यथित हो गया। मैं समझता हूं कि पूरे सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों का मन व्यथित हुआ होगा। यह लोमहर्षक घटना आहोर के एक शंखवाली गांव में नहीं हुई है बल्कि राजस्थान का कोई ऐसा कोना बता दीजिये जिसके अन्दर इस तरह की लोमहर्षक घटनाएं नहीं हो रही हों। मेरे चूरू जिले से शुरुआत करूं तो चौपाल पर बैठे हुए लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे

(श्री अभिनेश महर्षि)

रहती है। रतनगढ़ की बात करूं, थाने के अन्दर हत्या हो जाती है। सरदारशहर की बात करूं, एक व्यक्ति के नाखून नोच लिये जाते हैं। राजगढ़ की बात करूं तो सी.आई. स्तर के एक अधिकारी को आत्महत्या करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। यह सरकार की बानगी है।

माननीय, अपराध की बात के अन्दर चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, यह अभी-अभी बताया गया है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षजी की मौसी, उससे ज्यादा आपके लिये कोई क्या वी.आई.पी. हो सकता है, आज राहुल गांधीजी दो दिन से राजस्थान में हैं और उनकी मौसी का घर लगातार दो दिन से चोरों के द्वारा साफ किया गया। एक बार नहीं, दो-दो बार चोरों ने, यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो जो मर्जी आये सज़ा दे देना और अगर सत्य कह रहा हूं तो आगे आने वाले समय में राजस्थान में कोई चोरी की घटना नहीं हो, इस बात का इंतजाम, सरकार में बैठे हुए लोगों, कर देना। यह मैं कहना चाहता हूं।

कोटा के अन्दर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के ऊपर हमला होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अपराध करने वाले व्यक्ति के 000 तो सरकार के ऊपर से इकबाल उठ जाता है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): और यह इकबाल तब उठ जाता है जब वे यह बयान देते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): नहीं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: किसी अख़बार की फोटो का जिक्र सदन में लहरा करके नहीं कर सकते। इसलिये आप बिलकुल सीमाओं में रहिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: सदन की परम्परा नहीं है यहां पर।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): यदि यह बात असत्य कह रहा हूं तो जो मर्जी आये, सज़ा दे देना, लेकिन अपराध को रोकने के लिये हमको आगे आना पड़ेगा और उसके अन्दर सरकार को भूमिका निभानी पड़ेगी। यह मैं बहुत मजबूती के साथ में कहना चाहता हूं।

शब्द कोई मर्जी आये वह लिखो, कोई मर्जी आये वह मत लिखो, लेकिन जनता ने जो हमको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जिम्मा दिया है, उसके अन्दर किसी तरह का अंकुश कोई सरकार लगा नहीं सकती है, मैं यह कहना चाहता हूं।

क्या घटना घटी, अपराध के अन्दर एस.सी., एस.टी. के ऊपर राजस्थान राज्य अव्वल है। कह दीजिये सरकार, कि मैं असत्य बोल रहा हूं। आपके माननीय सदस्य, पूर्व लोक सभा सदस्य, राजस्थान सरकार के पूर्व डी.जी.पी. एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिये धरने पर बैठते हैं। आप लोग बयान करते हैं कि एफ.आई.आर. दर्ज हो रही है। इतने प्रभावशाली व्यक्ति की एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं की जा सकती है, यह राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था की बानगी है। आम आदमी किस तरह से दर-दर की ठोकरें खा रहा है, यह आप लोगों से छिपा नहीं है। आप अपने सीने पर हाथ रख करके, भगवान की सौगंध खा करके कह दीजिये कि सब कुछ सही चल रहा है। क्यों अपने आपको धोखे में रख रहे हो? क्यों सरकार, सरकार को कहां फुर्सत है। खाट टूट गई, टूट गई होगी। आप लोगों ने बहुत गीत गाये, सचिन पायलटजी को हम ले गये थे, तो अब भी कह दें कि खाट भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दी, लेकिन, सभापति महोदय, सरकार आने पर इस बात की जांच भी होगी। अभी तो नहीं होगी, सरकार आने पर इस बात की जांच भी होगी।

बहुत बातें कर रहे थे, आपके माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे, पूर्व डी.जी.पी., वे कह रहे थे कि डीजल, अन्य राज्यों से ज्यादा यहां पर रेट है डीजल और पेट्रोल की। तो सोचिये न, विचार कीजिये न कि हरियाणा के अन्दर क्यों कम है? केन्द्र सरकार को दोष देंगे, लेकिन आपका कोई कसूर नहीं है, यह बहुत सीना चौड़ा करके कह देते हैं आप लोग। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एम.पी. में क्या है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में मत बोलिये आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सब जगह।

श्री सभापति: कृपया बीच में न बोलें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सड़कों के हाल, ग्राम पंचायतों के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब बजट पेश किया था, बहुत गर्व के साथ में कहा था कि आपने गौरव पथ बनाये, बिना नालियों के बनाये, बिना फेरो कवर लगाये बनाये, हम फेरो कवर लगायेंगे और कहां बनाएंगे, एक विधान सभा में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनके हैड-क्वार्टर्स के ऊपर डेढ़ किलोमीटर की सड़क बनायेंगे। मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में 38 ग्राम पंचायतें हैं, आपने 38 ग्राम पंचायतों में से कितनी ग्राम पंचायतों के अन्दर विकास पथ बना दिये? एक में बनाया, वह भी डेढ़ किलोमीटर की जगह एक किलोमीटर और एक किलोमीटर का भी पूरा पैसा नहीं दिया। 37 बाकी हैं, पांच साल में से आपके दो साल बीत गये, ढाई साल, आप कब बनायेंगे? क्यों असत्य का पुलिंदा जनता के सामने रख कर जनता को धोखे में रखने का काम करते हैं आप? मिसिंग लिंक, धन्यवाद देता हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): समाप्त नहीं, माननीय सभापति महोदय, सिर्फ छह मिनट हुए हैं जिसमें एक मिनट आपने मुझे टोक दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें। ...(व्यवधान) समाप्त करें, माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): एक साथ क्या एक बात नहीं हुई।

श्री सभापति: आपने जो मुझे लिख कर दिया है, उसी के अनुरूप बुला रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पांच मिनट ही हुए हैं।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): पांच मिनट नहीं हुए।

श्री सभापति: मुझे पता है कितने मिनट हुए हैं। प्लीज सहयोग करें। अलाऊ नहीं करूंगा।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को कितना समय दिया गया था, कितना बोल चुके और कांग्रेस के कितने सदस्य, कितना समय दिया गया था, कितना बोल चुके, यह धमकाने की जो प्रवृत्ति

(डा. महेश जोशी)

राजेन्द्र राठौड़जी ने इस सदन में डाली है, मैं इसकी निंदा करता हूं। यह सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है। हमारी भी है और आपकी भी है।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, सहयोग करें आप। माननीय सदस्य।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, ये जितना समय आज बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, सारे का सारा कांग्रेस के समय से बोल रहे हैं, पांच मिनट को छोड़कर। आपके कुल पांच मिनट बचे थे। हमने सहृदयता दिखाई। जितना समय चाहिये, आपको देते हैं और ऐसे धमकाने की राजनीति करते हैं, समय गिनाने की बात करते हैं।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है ... (व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरे जैसा निरीह आदमी और किसी को धमका दे, यह हो सकता है कभी? आप मेरे चेहरे पर नजर डालो। क्या यह चेहरा ऐसा है जो किसी को धमका सकता है?

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): पूरा विश्व जानता है आपकी निरीहता को। आपकी निरीहता को ... (व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सदन हम चलाएंगे। एक मिनट। ... (व्यवधान) ... मैं आपसे यह वादा करता हूं कि ... (व्यवधान) ...

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): नो-नो, आपने अनेक बार वॉक-आउट किया तब भी सदन चला है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के वॉक-आउट करने के बाद भी सदन चला है, आप धमकाएंगे नहीं। आप यह धमकी देकर कि हम चले जाएंगे, सदन नहीं चलेगा। आप बाहर चले जाएंगे तो भी सदन चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं यह वादा करता हूं कि सत्ता पक्ष के सारे माननीय सदस्य नहीं रहेंगे, इनको सदन चलाने में इंटरेस्ट नहीं तो मैं यह वादा करता हूं कि प्रतिपक्ष के लोग बैठे रहेंगे।

श्री सभापति: विराजिये। सहयोग कीजिए। विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कोरम का सवाल ही नहीं आने देंगे क्योंकि इनको सदन में रुचि नहीं है। हम बोलेंगे। जनता के मंदिर में पवित्रता को नष्ट हम नहीं होने देंगे।

श्री सभापति: प्लीज, आप सहयोग करें, विराजिये आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं कनक्लूड कर देता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में आप सम्पूर्ण कर दीजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): दो मिनट में कनक्लूड कर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, विधायक विकास निधि का पैसा समय पर जारी नहीं किया जाता है। ई.डब्ल्यू.एस. में महिला की आय पिता और पति दोनों की जोड़ी जाती है, इसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। नई ग्राम पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल कब खोलोगे, यह सरकार ने नहीं बताया है। आपणी योजना के पी.एस.पी. पाइंट के बारे में मैंने पिछली बार भी पूछा था, लीकेज और अवैध कनेक्शंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज के कारण, 15 जनवरी से उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर रखा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। 35 में से 14 मेरे रतनगढ़ के अंदर पद रिक्त पड़े हैं।

श्री सभापति: विराजिये। श्री जगदीश चन्द्र। विराजिये, अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये आप। एक मिनट, विराजिये आप। माननीय सदस्य, सहयोग करें। आप विराजिये। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिये।

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं समय बढ़ा रहा हूं।

श्री सभापति: एक मिनट आप भी विराजिये। विराजिये आप। अंकित

नहीं हो रहा है कुछ भी। ... (व्यवधान) ...

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: उप नेता महोदय, आप अपने माननीय सदस्य को कहें कि वह संयम में रहें। आप विराजिये। कुछ सीखने से छोटे नहीं हो जाएंगे आप। आप विराजिये। विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): 000

श्री सभापति: विराजिये। कोई नहीं धमका रहा है। विराजिये आप। एक मिनट विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: एक मिनट। विराजिये, विराजिये। आसन पैरों पर है, विराजिये आप। विराजिये। आसन पैरों पर है, विराजिये। आप बैठिये। माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये। राठौड़ साहब, इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। बैठिये। आप विराजिये। बैठिये। माननीय सदस्य, विराजिये। सत्ता पक्ष के माननीय जोशीजी और ... (व्यवधान) ...

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: एक मिनट आप चुप रहेंगे?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: आप अपने माननीय सदस्य को कहें कि वह अपनी सीमा में रहें। सीमा में रहें। अपने सदस्य को वॉर्न करिये आप। आसन को पता है उसके अधिकारों का, बैठिये आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री सभापति: बैठिये, आप भी बैठिये। विराजिये। आप विराजिये।

(श्री सभापति)

विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज सहयोग करें।

दोनों दलों के माननीय नेताओं ने, माननीय जोशीजी ने और माननीय राठौड़ साहब ने जो समय सीमा निर्धारित की है, वह समय सीमा माननीय अध्यक्ष के निर्देश से तय की गयी है। इन्होंने जो मुझे लिस्ट दी है, उसमें जिन लोगों के नाम पर 15 मिनट है उनको 15 मिनट दिया, जिन लोगों के नाम पर 20 मिनट है उनको 20 मिनट दिया, जिन लोगों के नाम पर 8 मिनट है उनको 8 मिनट दिया। महर्षिजी के नाम पर 8 मिनट आपने लिखे हैं। 4 बजकर 41 मिनट पर इन्होंने शुरू किया और 4 बजकर 50 मिनट पर मैंने इनको बैठने के लिए कहा है। इसके बावजूद भी यदि इस तरह आसन पर आक्षेप लगाकर सदन में इस तरह से आप सनसनी पैदा करेंगे, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता। जिम्मेदारी न केवल आसन की अकेले की है, जिम्मेदारी न केवल सत्ता पक्ष की है, जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी की उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। आप अपने माननीय सदस्य से कहिये, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि मैं किसी को टाइम कम दूं या किसी को ज्यादा दूं। आपने मुझे जो लिखकर दिया यह आठ मिनट, यह आपने लिखकर दिया है। तदनुरूप मैंने यह सारी व्यवस्थाएं दी हैं। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य जो बोल लिये, वह बोलकर चले गये। जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, दस आदमी आपकी तरफ से बोलने बाकी है, तो आप यही चाहते हैं कि वह नहीं बोलें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं-नहीं।

श्री सभापति: बोलें तो समय का ध्यान रखें। आठ मिनट का आपका समय तय किया गया है। आठ मिनट में मैं आपको निर्देश करूंगा, कृपया, सहयोग करें। आपको जो समय दिया गया है, कृपया आप भी सहयोग करें ताकि सात बजे सदन की कार्यवाही पूरी हो सके।

मैं अपेक्षा करता हूं सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से, आसन आपको निर्देश देता है, वह आसन की अपनी व्यवस्थाएं हैं। आपके दोनों दलों के नेताओं ने आकर मुझे जो लिस्ट दी है, मैं उसी के अनुरूप आपको बोलने के लिए कहूंगा। या तो आप यह तय कर लें कि दोनों तरफ से दो-दो, चार-चार घंटा जितनी मर्जी हो खुले में ही यह बोलेंगे और खुले में ही

(श्री सभापति)

यह बोलेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन यदि आपने सुबह मुझे यह लिस्ट दी और उसके अनुरूप आप यदि नहीं बोलेंगे तो मुझे बाध्य होकर आपको रोकना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): राठौड़ साहब, एक मिनट समय बढ़ा लूं? सर, समय बढ़ा लूं?

श्री सभापति: मेरा निवेदन आपसे भी है कि प्लीज, सहयोग करें, एक मिनट, आप विराजिये। एक मिनट, आप विराजिये। आप लोगों के वार्तालाप में यदि समय जाया होगा, सात बजे मुझे सदन की कार्यवाही समाप्त करनी पड़ेगी और जो लोग बोलने से बाकी रह गये, उनकी पीड़ा को मैं महसूस कर सकता हूं। जो लोग बोलने बाकी हैं कृपया आप सहयोग करें दोनों को। दोनों को मैंने अपनी बात बता दी। कृपया, आप सहयोग करेंगे और मैं दोनों से यह अपेक्षा रखता हूं कि तय समय सीमा में मेरे कहने के बाद आप मुझे सहयोग करेंगे। प्लीज, सहयोग करें। श्री जगदीश चन्द्र।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर रहा था कि आज जब समय का विभाजन हो रहा था तो निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य हमसे ज्यादा हैं, इनका समय कुछ ज्यादा था। पर, माननीय सभापति महोदय, जिस दिन यह बहस प्रारंभ हो रही थी, उस दिन सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था और हमारे माननीय सदस्य बोल गये। आज सुबह जब इन्होंने यह कहा कि आपका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समय लगभग समाप्त हो रहा है, तब भी मैंने मुख्य सचेतक महोदय को पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा था कि समय का बंटवारा निश्चित तौर पर होता है परंतु यह कभी नहीं होता कि सत्ता पक्ष की ज्यादा मैजोरिटी है इसलिए सारा वह ही बोलें, हमें अकोमोडेट करो और उसके बाद, माननीय सभापति महोदय, यह माननीय सदस्य तो बिलकुल ही छह मिनट ही बोले, इसलिए आप थोड़ी सहृदयता रखें।

श्री सभापति: 4 बजकर 41 मिनट पर उन्होंने शुरू किया और 4 बजकर 50 मिनट पर कहा। एक मिनट, माननीय सदस्य, आपकी तरफ से आठ माननीय सदस्य बोलने बाकी हैं। आप मेरी बात सुनिये। आपकी तरफ से आठ माननीय सदस्य बोलने बाकी हैं, इधर से चार माननीय सदस्य बोलने बाकी हैं। आपके जो चार माननीय सदस्य हैं, उनका समय आप आठ में दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरी अपनी मजबूरी यह है कि आपने जब मुझे आठ व्यक्तियों के बोलने की लिस्ट दी तो मैं यह चाहता हूं आठ के आठ व्यक्ति यहां पर अपनी बात रखें। आप यह चाहते हैं कि केवल चार व्यक्ति ही बोलें तो मैं उनको चार में डिस्ट्रिब्यूट कर देता हूं। आप बताइये क्या करना है? ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप चाहें जैसा करें। जैसे आसन की व्यवस्था है। हम तो आज्ञाकारी लोग हैं पर इन +++ को समझाओ। इनको समझाओ।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, आपने मुझे आठ व्यक्तियों को बोलने के लिए लिस्ट भेजी है। ... (व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप जैसा कहें। माननीय सभापति महोदय, जैसा आप उचित समझे नाम पुकारें, पर आप इन +++ को समझाओ। यह बैठी-बैठी जब से +++ बोल नहीं रही हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र। माननीय मंत्री महोदया, कृपया, सहयोग करें। प्लीज, सहयोग करें। श्री जगदीश चन्द्र।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का मौका

दिया, उसके लिए धन्यवाद। पिछले दो दिन से सदन ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है, विराजिये आप।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): 000

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

(17.00 बजे)

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): 000

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): 000

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। आप वरिष्ठ मंत्री हैं। आप बैठिए। बैठिए। माननीय सदस्य, बैठिए। वह सक्षम हैं अपनी बात कहने के लिये, आप बैठिए। प्लीज सहयोग करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, सदन में दो दिन से बहुत महत्त्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं उम्मीद करता था कि हमारे विपक्ष के साथी अपने अच्छे सुझाव देंगे। किसी भी सरकार का मूल्यांकन पांच बिन्दुओं पर होता है। पहला बिन्दु प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरा बिन्दु कृषि, पशुपालन और तीसरा बिन्दु कानून-व्यवस्था और चौथा बिन्दु सामाजिक न्याय और पांचवां बिन्दु औद्योगिक वातावरण और रोजगार।

माननीय सभापति महोदय, सरकार का दो साल का जो काम-काज है, यह राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री भी राजस्थान सरकार की तारीफ कर चुके, जो कोरोना के समय में प्रबन्ध किया गया था। वर्ल्ड का जो हैल्थ ऑर्गनाइजेशन है WHO, उसने भी राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई दी है और धन्यवाद इस बात के लिये, कि 61 पर्सेंट कोरोना वैक्सीनेटेड हमने राजस्थान को कर दिया है। यह बहुत बड़ी बात है कि पिछले सात-आठ महीनों में, समय-समय पर जब भी सरकार के विकास के काम शुरू हुए कभी चुनाव की आचार संहिता, कभी भारतीय जनता पार्टी की वजह से सवा महीना क्वारंटाइन कांग्रेस के एम.एल.एज. और कभी सरकार को

(श्री जगदीश चन्द्र)

वित्तीय संकट में खड़ा करने की दिल्ली सरकार की जो कोशिश रही है, उसके बावजूद करीब-करीब सवा साल हुए हैं सरकार को काम करते हुए। मैं सुमिरन कराना चाह रहा हूं हमारे विपक्ष के साथियों से, माननीय राठौड़ साहब चले गये, मैं उनसे ही निवेदन करना चाह रहा था। अगर आपको याद हो, 2013-2018 तक का आपका पांच साल का जो कार्यकाल था, राजस्थान की हिस्ट्री में वह एक आन्दोलनकारी कार्यकाल था। हर दिन समाज का कोई न कोई तबका उस सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करता था। कभी किसान पानी के लिये धरना-प्रदर्शन करते थे तो कभी नौजवान रोजगार के लिये धरना-प्रदर्शन कर रहे थे, कभी पटवारी हड़ताल पर थे, कभी डॉक्टर हड़ताल पर थे। पांच साल के बाद राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को मेंडेट दिया और कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया और मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार जो घोषणा पत्र जनता के बीच में लेकर गयी थी और जनता ने उस पर मोहर लगायी। इस आशा और विश्वास के साथ मोहर लगायी कि आने वाले जो पांच वर्ष हैं, वह राजस्थान के लिये सुखद हों और राजस्थान की जो विकास की गति रूक गयी थी, वह दुबारा से स्टार्ट हो।

मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि ऐसा अभिभाषण, जो परसों पेश किया गया, हमारे एक साथी चले गये, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने ताली नहीं बजायी। मैं उनको संवैधानिक मर्यादा के लिये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जरा संविधान को ठीक तरह से पढ़ लें और असेम्बली के रूल्स पढ़ लें। जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा होता है, जब प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट में भाषण होता है तो कभी सत्ता पक्ष के लोग ताली नहीं बजाते। सरकार का लेखा-जोखा, सरकार का क्या विजन है, पाँच वर्षों में सरकार क्या करने जा रही है, यह सदन के समक्ष पेश किया जाता है। राजस्थान की सात करोड़ जनता इस बात पर विश्वास करती है कि जो लोग सदन में बैठे हैं, वह हमारी बात करेंगे, हमारे विकास की बात करेंगे। इस बात की चर्चा सदन में होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहली बार पिछले पांच वर्षों के बाद में हमने दो हजार डाक्टर्स की भर्ती की। राजस्थान का जो स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा था, उसको मजबूत करने का प्रयास किया गया और कोरोना का इतना बेहतरीन प्रबन्ध किया कि 07 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री ने जब अपना वक्तव्य दिया था, उस समय हमारे यहां दो मरीज कोरोना के थे। उस समय हमारे पास टेस्ट की कोई लैब नहीं थी, दोनों

(श्री जगदीश चन्द्र)

इटालियन नागरिकों के टेस्ट के लिये सैम्पल पुणे गये थे, लेकिन आज इस बात की खुशी है कि एक साल का हमारा एम.एल.ए. लैड फण्ड का जो पैसा था, वह पूरा का पूरा हमने मेडिकल में दिया, इसकी वजह से राजस्थान सरकार का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ, मेडिकल का ढांचा मजबूत हुआ। कहीं पर डॉक्टर नहीं थे, कहीं नर्सिंग स्टॉफ नहीं था, कहीं पर जांच की मशीनें नहीं थीं, कहीं दवाइयां नहीं थीं। आज आप देखो राजस्थान के अंदर जाकर तो 735 टाइप की दवाई राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं और जहां 100-150 की ओ.पी.डी. होती थी, वहां पर 500-500 की ओ.पी.डी. हो रही है। इस कोरोना काल के अंदर जहां एक लाइट नहीं थी, आज राजस्थान के 33 जिलों में हमारे टेस्टिंग लैब हैं और 70 हजार के आस-पास हमारे यहां कोरोना के टैस्ट रोज हो रहे हैं। कहीं नर्सिंग की भर्ती हो रही है, कहीं दूसरे स्टॉफ की भर्ती हो रही है। एक आदर्श सी.एच.सी. की जो कल्पना की थी मुख्य मंत्रीजी ने, उस पर भी राजस्थान सरकार का काम शुरू हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य में जो बेहतरीन काम किया है, वह एक ऐतिहासिक काम किया है। राजस्थान की जो आने वाली जनरेशन है, वह मुख्य मंत्रीजी को याद रखेगी, सरकार को याद रखेगी। हमने पिछले बजट के अंदर निरोगी राजस्थान में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, इसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बार-बार विपक्ष के साथी इस बात को लेकर चिल्ला रहे हैं तो वह जरा दिल्ली की तरफ तो ध्यान दें। जी.एस.टी. की किस्त आज तक बकाया है। इस सरकार को वित्तीय संकट खड़ा करने की जितनी कोशिश हो सकती थी दिल्ली के माध्यम से, वह करने की कोशिश की गयी थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे कि सरकार के जो मुखिया हैं वह इतने अनुभवशाली हैं, इतने सक्षम हैं, इतने कल्पनाशील हैं और इतने संकल्पशील हैं कि जो फैसला उन्होंने कर लिया, निश्चित तौर पर उनके फैसले को कोई डिगा नहीं सकता। मैं बधाई देना चाहूंगा सदन के माध्यम से, एक दृढ़ निश्चय के साथ में, जिस तरह से संकल्प के साथ में राजस्थान सरकार ने कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया है, आज राजस्थान उससे उबरने में कामयाब हुआ है। इसके लिये मुख्य मंत्रीजी को बधाई और सारे सदन को इस बात की बधाई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

(श्री जगदीश चन्द्र)

दूसरा विषय है कृषि का। कृषि के क्षेत्र के अंदर राजस्थान ने पिछले दो वर्षों में जो बेहतरीन तरक्की की है, वह अपने आप में एक मिसाल के तौर पर अच्छा काम किया है। एक तो राजस्थान सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार है। आज 75 दिन हो गये किसानों को, 75 दिन हो गये अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। अभी एक साथी चर्चा कर रहे थे कि पुलिस कस्टडी में किसी की डैथ हो गयी। मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि उसी आन्दोलन के दौरान गंगानगर के एक नवरीत सिंह, एक नौजवान की 26 तारीख को डैथ हो गयी थी, उसका हिसाब-किताब दिल्ली की सरकार दे। इस बात पर सरकार को जवाब देना चाहिए, 75 दिन हो गये डेमोक्रेसी के अदंर।

1936 के अंदर हिन्दुस्तान में जब कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारें बनी थीं तो जमीन का किसी आदमी को अधिकार दिया गया था तो किसान को कांग्रेस की सरकारों ने दिया था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं जब इस देश के अंदर पहली सरकार 1952 में बनी, पहला भूमि सुधार कानून इस कांग्रेस की सरकार ने दिया था और किसान को मालिकाना हक कांग्रेस की सरकार ने दिया था। पटना हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने एतराज जताया था। पार्लियामेंट में बिल आया और पार्लियामेंट में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने कहा कि किसान जमीन का मालिक है, यह उसकी मां के समान है, इसको मातृत्वता का हक दिया जाना चाहिए। इस बात के लिये मैं कांग्रेस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। किसान की जब-जब कोई बात आयी है तो कांग्रेस सरकार किसान हितैषी होकर किसान के पक्ष में रही है। अगर आप याद करो 1974 को, 1974 में जब हरित क्रांति के पहले बाहर से ही गेहूं आया करता था, हरित क्रांति कांग्रेस पार्टी ने की, जिसकी वजह से देश सम्पन्न हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि 1965 में एफ.सी.आई. बनी थी। एफ.सी.आई. किसलिए बनायी गयी थी कि, इस देश में हमारा जो PDS सिस्टम था, उसको चालू करने के लिये फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की हमने स्थापना की थी और इस सरकार ने उस किसान का समर्थन मूल्य, उस किसान की फसल का वाजिब हक खतम करने का जो प्रयास किया है, मैं इस सदन के माध्यम से उसकी निन्दा करता हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में उस किसान को अच्छी फसल मिले, अच्छा बीज मिले, अच्छा यूरिया मिले,

(श्री जगदीश चन्द्र)

अच्छे फर्टिलाइजर की व्यवस्था सरकार ने की है। 2008 से लेकर 2013 के बीच में, अगर आपको याद हो, यही बीजेपी की सरकार थी, किसान यूरिया के लिये लाइन लगाते थे। डी.ए.पी. ब्लैक में बिकती थी। हमारी सरकार ने 2021 में 24 लाख 23 हजार किसानों को 3 हजार 947 करोड़ रुपये का बीमे का भुगतान किया और 2020-21 में खरीफ और रबी की फसल के लिये 18 लाख 33 हजार मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवाया और 7 लाख 18 हजार मीट्रिक टन डी.ए.पी. की आपूर्ति को निरन्तर जारी रखा गया। आज भी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब से अशोक गहलोत जी की सरकार आयी है, एक दिन भी किसान को यूरिया के लिये लाइन नहीं लगानी पड़ी। पंजाब में जब ट्रैफिक बंद था, रेल बंद कर दी गयी थी, उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने पंजाब के किसानों को भी यूरिया उपलब्ध करवाया। इस बात के लिये सरकार को बधाई है और वहां के किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार ने स्प्रिंकलर सिस्टम के लिये दो हजार करोड़ रुपये से किसान कल्याण कोष की स्थापना की, ताकि किसान का जो सिंचाई का प्रबन्धन है, उसको ठीक किया जा सके। उसके लिये बैंक से लोन की व्यवस्था की गयी है। यह सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, सभापति महोदय, यह राजस्थान सरकार है। हमने अपने घोषणा पत्र में बात कही थी कि समर्थन मूल्य की अगर बात करती है तो वह राजस्थान की सरकार बात करती है। हमारे घोषणा पत्र में यह बात थी। हमने स्पेशल सत्र बुलाकर 2 नवम्बर को तीन कानून पास किये थे। पहला कानून था कि राजस्थान सरकार इस बात की गारंटी करती है कि किसान को उसकी फसल का समर्थन मूल्य मिले। अगर नहीं मिलता तो पांच लाख रुपये का जुर्माना और सात साल की सज़ा का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया है। यह पहली सरकार है हिन्दुस्तान की।

दूसरा, समर्थन मूल्य के माध्यम से पिछली सरकार जो खरीद नहीं कर पायी थी, हमारी सरकार ने उसको इन्श्योर किया और 18 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जो पिछले साल की फसल है वह राजस्थान की सरकार ने खरीद की है।

दूसरा, राजस्थान सरकार ने सी.पी.सी. में जो बदलाव किया गया है,

(श्री जगदीश चन्द्र)

पहली दफा 1958 के बाद में अगर सी.पी.सी. में, सिविल प्रोसीजर कोड में अगर चेंज किया गया है तो वह कांग्रेस की सरकार ने किया, अशोक गहलोत की सरकार ने किया कि 5 एकड़ जमीन, जिस पर किसी किसान के ऊपर ऋण होता था, उसकी जमीन किसी भी तरीके से कुर्क नहीं की जाएगी। यह कानून भी हमारी सरकार ने पास किया, इसके लिए मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं और किसान की आने वाली पीढ़ी भी मुख्य मंत्री जी की उस बात को याद रखेगी जो फैसला उन्होंने किसान हित में किया है।

तीसरा, इन मंडियों को खतम करने की जो कोशिश की गई थी, इन कृषि उपज मंडियों को खतम किया गया था, गांव की नाली, गांव की सड़कें और गांव की पुलिया, जिसके बारे में एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पिछले एक साल के अन्दर कोई सड़कें नहीं बन रही हैं, कोई पुलिया नहीं बन रही हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने दिल्ली में कानून पास कर दिया और कृषि उपज मंडी को और अनाज मंडियों को आपने परमानेंट बंद करने की व्यवस्था कर दी है लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने यह फैसला किया है कि किसी भी कीमत पर राजस्थान की इन 350 मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। हम उस मजदूर का भी ख्याल रखेंगे, उस किसान का भी ख्याल रखेंगे और आढ़तिया का भी ख्याल रखेंगे और निश्चित तौर पर गांव की जो पुलिया और सड़कें जो कृषि उपज मंडी के माध्यम से बनती थीं, वह काम जारी रहेगा।

एक साथी ने चर्चा की कि डिग्गियों पर पैसे नहीं आ रहे। पिछली सरकार ने डिग्गियों के लिए जो वित्तीय व्यवस्था की थी वो 2700 डिग्गियों की व्यवस्था थी और 5700 डिग्गी चुनाव से पहले अनाउंस कर दी गई। हमने तो हमारे हिस्से का पैसा दे दिया, हमने कृषि कल्याण कोष से पैसा दिया है लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि जो 60 और 40 का हिस्सा है, केंद्र सरकार तो डिग्गियों का पैसा दे। अभी तक तो बीमा की राशि भी नहीं दी गई, जो हमारी फसल बीमा योजना की बात थी, उसकी भी राशि बाकी पड़ी है दिल्ली सरकार की और आप हमारे पर सवाल उठा रहे हो। मेहरबानी करके आपके पास जो स्टेटिस्टिक्स है उस स्टेटिस्टिक्स को दुरुस्त करिये, आपका वह स्टेटिस्टिक्स ठीक नहीं है उसको दुरुस्त करियेगा और दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करिये कि राजस्थान पर रहम करे, इस राजस्थान की मदद करे।

(श्री जगदीश चन्द्र)

राजस्थान का जो व्यापारी है, राजस्थान का किसान है जो हिंदुस्तान की सरहद पर लड़ने के लिए तैयार रहता है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि 1965, 1971 और 1999, यही किसान था जिसने देश की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान की सरहद पर लड़ाई लड़ी। यही वह किसान है जिसने 1965 की लड़ाई लड़ी है और केंद्र सरकार इस किसान को अण्डरएस्टीमेट कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं, प्रधान मंत्री जी, आप पंजाबी को भी समझें, पंजाबियत को समझने की कोशिश करिये। एक नारा याद करो, अब्दाली के जमाने में एक नारा था कि "खालो पीलो लाहिदा बाके दूहले साहिदा," यह पंजाब का किसान, यह राजस्थान का किसान अपना हक लिए बगैर किसी भी कीमत पर बॉर्डर से नहीं जाएगा। अभी समय है, कृपा करके इसको सुधार करने का प्रयास करें, राज हठ नहीं करनी चाहिए। आप 2002 को याद करिये, देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और गुजरात में 2002 में जो हुआ था उसको याद करियेगा। प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि गुजरात की सरकार को राज धर्म निभाना चाहिए। अभी मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी राज धर्म को निभाएं, वे महसूस करें कि हिंदुस्तान का किसान क्या मांग रहा है।

राहुल गांधी पर जिस तरह की टिप्पणी की जा रही थी, टिप्पणी करने से पहले सोच लें। ये राहुल गांधी का क्या मुकाबला करेंगे, जिस परिवार ने इस देश के लिए तीन-तीन कुर्बानी दी है, जिस परिवार का देश को आजाद कराने में योगदान रहा ...(व्यवधान) सबसे ज्यादा आपको राहुल गांधी से डर है, सबसे ज्यादा राहुल गांधी से डरे हुए हैं। हिंदुस्तान का किसान राहुल गांधी के साथ है, हिंदुस्तान का नौजवान राहुल गांधी के साथ है इसलिए आपको राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप ही रखो, हमें नहीं करना। आप रखो, हमें नहीं करना। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजें। ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अगर आपको टिप्पणी करनी है तो

(श्री जगदीश चन्द्र)

टिप्पणी करिये जे.पी. नड्डा पर, टिप्पणी करनी है तो नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करिये, टिप्पणी करनी है तो अमित शाह पर टिप्पणी करियेगा। आपको राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जरा गिरेबान में झांके और इस बात को सोचें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, तीसरा बिंदु है प्रदेश की कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के मामले में मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर पहली बार व्यवस्था की गई है कि जिस फरियादी की अगर पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो तो एस.पी. को मेंडेटरी बाउंड किया गया है कि उसकी एफ.आई.आर. दर्ज करके उसकी सुनवाई करे। इसके साथ-साथ, हमने गांवों में 30 हजार पुलिस मित्र बनाये हैं ताकि वे पुलिस का सहयोग करें और महिला अपराध के लिए भी अलग से सेल का गठन किया है, ताकि अपराध की कमी हो।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर याद है 2013 के बीच में यही राजस्थान है जो गंगानगर, हनुमानगढ़ नशे की मंडी हुआ करता था, आज मुख्य मंत्री जी को इस बात की बधाई है कि हमने सौ परसेंट तो कंट्रोल नहीं किया, कम से कम 40-45 परसेंट कंट्रोल करने का प्रयास किया है। राजस्थान पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, इसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह पहली सरकार है जिसने प्रत्येक थाने में जनता की फरियाद के लिए, जनता की सुनवाई करने के लिए एक स्वागत कक्ष की स्थापना की है और करीब-करीब सारे थानों में स्वागत कक्ष की स्थापना कर दी गई, ताकि फरियादी जाकर अपनी बात रख सकें। हमारी माताएं-बहनें जाएं, अलग से अपना काम कर सकें। इसकी स्थापना की गई है, इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाह रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा। अगर याद हो कि कोरोना काल में किस तरह से बाहर से राजस्थान के जो हमारे प्रवासी भाई आये थे, वे रोटी के लिए, रोजगार के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे थे, राजस्थान सरकार के मुखिया ने 3500 रुपये की उन गरीबों के लिए व्यवस्था की है, स्ट्रीट वेन्डर के लिए व्यवस्था की, हाथ से दस्तकारी का काम करने वाले के लिए 3500-3500 की व्यवस्था करके उनको संबल देने का प्रयास किया, यही राजस्थान की सरकार है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी रोजगार योजना है, यह रोजगार योजना बेसिकली केंद्र सरकार का एक्ट है, लेकिन कोरोना की महामारी में जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने नरेगा का प्रबंध करके राजस्थान में 7196 करोड़ रुपये व्यय करके 59 लाख परिवारों को संबल देने का प्रयास किया, यह ऐतिहासिक फैसला राजस्थान की सरकार ने किया है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज में 2020 और 2021 में 4372 करोड़ रुपये खर्च करके गांव के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। एक साथी कह रहे थे कि गांवों में सड़कें नहीं बनी हैं। आप याद करो, अगर गांव जाकर देखो और महसस करो कि कौन-कौनसी सड़कें बन गई हैं। पब्बाराम जी, अगर ठीक से आकलन नहीं हो तो ध्यान से वह पढ़ो, मैं आपको भी देख रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): इसलिए जरा ठीक से पंचायती राज विभाग में देखियेगा, राजस्थान की सरकार ने कितनी सड़कें दी हैं। जितनी सड़कें हमें दी हैं उतनी सड़कें आपको भी दी गई हैं। सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। इसलिए राजस्थान सरकार ने इसमें आधारभूत परिवर्तन करके एक ऐतिहासिक फैसला किया है।

इसके साथ-साथ आपको याद होगा कि कोरोना काल में रोटी की बड़ी दिक्कत हो गई थी। गरीब व्यक्ति को इंदिरा रसोई के नाम से आठ रुपये में खाना हिंदुस्तान में किसी कोने में मिलता है? लेकिन राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री की संवेदनशीलता है, इंदिरा रसोई में आठ रुपये के हिसाब से खाने का प्रबंध किया गया, जिसमें अब तक एक करोड़ 55 लाख थालियां लोग खा चुके हैं और हम उसको आगे भी जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश की 213 नगरपालिका में इसका संचालन किया जा रहा है।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा क्योंकि मेरा एक मिनट पहले खराब कर दिया था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर रोजगार की बात करें तो जिस दिन से सरकार बनी थी,

(श्री जगदीश चन्द्र)

सरकार बनने के दो महीने के अन्दर 25 हजार थर्ड ग्रेड टीचर की हमने भर्ती की थी। आज सरकार का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, जो काम पिछली सरकार के जमाने में रुके हुए थे, कोई हाई कोर्ट में पैंडिंग था, कोई जिले की अदालत में पैंडिंग था, तरीके से पैरवी करके वह सारे स्टे वेकेट कराये हैं और हमने राजस्थान में करीब-करीब एक लाख लोगों को रोजगार दिया है।

श्री सभापति: आप विराजिये, विराजिये। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यक्रम हुए हैं। हायर एजुकेशन में काम हुए हैं। 8 आईटीआई खोलने का प्रावधान है, विचाराधीन है, हमारा काम चल रहा है।

सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रिलाइजेशन करने के लिए सरकार इंडस्ट्री की नई नीति लेकर आई है। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बैठिये। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिंदु संख्या 2 से लेकर के 19 तक स्वास्थ्य, कोरोना महामारी एवं कोरोना काल में राज्य के विकास की बात कही। कोरोना काल में सरकार ने कहा कि कोई जन हानि नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोये, सबको उपचार के लिए सभी सुविधा मिलें एवं जांचें नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाएंगी। इस संदर्भ में मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करके मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की बात करता हूं जहां दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं रायसिंहनगर और विजयनगर, दोनों ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन जर्जर अवस्था में हैं। अभी मेरे से पहले सादुलशहर से आने वाले मेरे साथी विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र के सभी अस्पतालों में डॉक्टर और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं उनको बताना चाह रहा हूं, सदन को बताना चाह रहा हूं कि मेरे दोनों ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन जर्जर अवस्था में हैं। साथ ही विशेष जांच उपकरण, मशीन, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन चालू अवस्था में नहीं हैं और ना ही वहां

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जिसके कारण मरीजों को अधिक पैसे देकर निजी अस्पतालों में जांच करवानी पड़ती है। विजयनगर चिकित्सालय में वर्तमान में 8 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिसकी एवज में 4 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। साथ में, उक्त चिकित्सालय में न तो कोई सर्जन चिकित्सक है, न ही कोई गायनी स्पेशलिस्ट है, न ही कोई मेडिसिन चिकित्सक है, न ही कोई शिशु रोग विशेषज्ञ है।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल के दौरान जहां-जहां कोविड सेंटर बनाए गए थे, वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण कोरोना और अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को जिला मुख्यालय पर रैफर करना पड़ता था। कोरोना काल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के विजयनगर कस्बे में कोरोना ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई। इसकी ड्यूटी उपखंड कार्यालय में थी। मृतक कर्मचारी के परिवार को राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है जबकि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बिन्दु संख्या 11 में ड्यूटी के दौरान किसी भी राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आने वाले बजट में रायसिंहनगर और श्री विजयनगर में ट्रोमा सेंटर स्थापित किया जाए ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इलाज की समुचित व्यवस्था हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री एवं देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुत ही जल्दी कोरोना महामारी की कारगर वैक्सीन तैयार कर पूरे भारत में नहीं, दुनिया के सभी जरूरतमंद देशों को देकर दुनिया में सिद्ध कर दिया है कि भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने कहा कि कोई भूखा नहीं सोये, इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा कुछ विशेष नहीं किया गया। यह तो भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं और गुरुद्वारों के सेवादारों ने अपनी नि:स्वार्थ सेवाएं देकर भूखे व्यक्ति तक भोजन पैकेट उपलब्ध करवाने का काम किया। इसके साथ-साथ मैं अपने किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों एवं दानदाताओं को भी सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

कि इन्होंने इन संस्थाओं को गेहूं, दालें, सरसों का तेल, नकदी देकर के भूखे एवं जरूरतमंद व्यक्तियों का पेट भरने का काम किया। इस पुण्य के काम में आम नागरिकों द्वारा भी बहुत सहयोग किया गया। हमारी बहनों द्वारा मास्क बनाकर के घर-घर में बांटने का काम किया। इसके विपरीत राज्य सरकार ने इतना जुर्म किया कि जिन सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा राशन के पैकेट, भोजन पैकेट, मास्क वितरण किये गये, उनकी सूचनाएं एकत्र करके सरकारी आंकड़ों में जोड़ लिये गये।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने की पात्रता रखते थे, किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम इस योजना में नहीं जोड़ा गया। सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जो भी गरीब परिवार किसी भी जन कल्याणकारी योजना से नहीं जुड़ा हुआ है उन्हें सरकार सर्वे करवाकर एकमुश्त एक परिवार को 3500 रुपये देगी। अगर मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो यहां हजारों की संख्या में ऐसे पात्र परिवार हैं, जो किसी भी जन कल्याणकारी योजना से नहीं जुड़े हुए हैं। सरकार ने मात्र 220 परिवारों को लाभ देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे गरीब परिवारों को, जो खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रह गये, पुन: इस योजना में शामिल कर इस योजना की समयावधि को फरवरी, 2021 तक बढ़ाया गया।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 20 से 32 तक किसान कल्याण संबंधी बात कही गई। सरकार द्वारा किसानों की सम्पूर्ण कर्जा माफी की बात कही गई थी। किसानों का न तो सम्पूर्ण कर्जा माफ किया गया, उलटा राज्य सरकार ने कृषक कल्याण कोष के नाम से एक प्रतिशत मंडी टैक्स और लगाकर किसानों पर अतिरिक्त भार लाद दिया। राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि ऋण वसूली के लिए 5 हैक्टेयर तक किसी भी किसान की भूमि नीलाम, कुर्क नहीं की जाएगी, जबकि सरकार द्वारा अभी भी किसानों के कुर्की आदेश जारी किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एनपीए खातों की वसूली के लिए एक मुश्त भुगतान योजना लाया था, जिसमें 15 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट का लाभ देकर किसानों से बकाया राशि भरवाई जा रही थी। मगर उपखंड कार्यालय द्वारा जारी किये गये एक्ट में कुर्की आदेश में समस्त बकाया राशि पर 5 प्रतिशत इनसेंटिव राशि

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

की मांग की जा रही है, जबकि इनसेंटिव राशि बैंक में जमा होने वाली राशि पर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार कांग्रेस के शासन काल में किसानों का शोषण एवं प्रताड़ित किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार होने वाली वसूली में एसडीएम और तहसीलदार का क्या रोल है? उनके द्वारा किस बात का इनसेंटिव लिया जा रहा है? यदि किसी किसान की बैंक में बकाया राशि 20 लाख रुपया है तो 5 परसेंट के हिसाब से इनसेंटिव एक लाख रुपये बनता है, बैंक उसको 2 लाख रुपये भरवाता है। उस पर 5 परसेंट के हिसाब से 10 हजार रुपये बनता है। इसमें 90 हजार का अंतर बनता है। इससे किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। इस प्रकार से अधिकारी इनसेंटिव मांगते हैं। हद हो गई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की सम्पूर्ण कर्जा माफी करें। किसानों से वसूली के नाम पर यह इनसेंटिव लेना बंद करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारे गरीब परिवार सरकारी जमीन पर, वन विभाग की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर अथवा किसी अन्य विभाग की भूमि पर पिछले कई वर्षों से घर बनाकर के अपने परिवार का गुजर-बसर कर रहे हैं, जो अब बड़ी-बड़ी कालोनियों में विकसित हो चुकी हैं, जहां पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, स्कूल, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं, मगर उन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना में लाभ मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करने की बात कही गई थी, मगर बिजली के बिलों में भारी वृद्धि कर आम आदमी की कमर तोड़ दी। हमारे सूरतगढ़ में थर्मल की 7 इकाइयां हैं, जो 2160 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती हैं। जहां रोज 518 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है, फिर भी यहां के उपभोक्ताओं को 11 से 13 रुपये तक प्रति यूनिट बिजली मिलती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): किसानों की गलत तरीके से वीसीआर भरी जाती हैं। हमारे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

रहा है। किसानों की लगातार 2-2, 3-3 बारियां पिट रही हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से, असमान रूप से पानी का वितरण किया जा रहा है, जिस वजह से किसी किसान की 2-3 बारियां पिट रही हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): दो मिनट। किसी की लगातार 2-3 बारियां पिट रही हैं। किसानों को मार्च माह में गेहूं की फसल के लिए एक बारी पानी की आवश्यकता है। सिंचाई अधिकारियों द्वारा पानी दिये जाने के लिए असमर्थता जाहिर की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मार्च में एक पानी की बारी अवश्य दें..

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सके अन्यथा श्री गंगानगर के किसान पानी के लिए धरना, प्रदर्शन के लिए तैयार हैं।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): एक मिनट, एक मिनट। सभापति महोदय, श्री गंगानगर जिले में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है। इसका कारण यह है कि यहां की राजस्थान सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल पर 36 परसेंट और डीजल पर 26 प्रतिशत वसूलती है। वहीं पड़ौसी राज्य पंजाब में यह दर 24.79 और 15.94 है। दामों में 10 परसेंट का अंतर है। श्री गंगानगर में आज पेट्रोल 98 रुपये 30 पैसे है एवं डीजल 89 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तेल पर वैट कम करके हनुमानगढ़ डिपो फिर से शुरू करे।

श्री सभापति: श्री रूपाराम। विराजिए, विराजिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): बस एक ही है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, बस एक मिनट। सभापति महोदय, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछली बार ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य खड़े हैं।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए माननीय सदस्य। दे दिया एक मिनट आपको। विराजिए आप। सहयोग करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बाकी लोग रह जाएंगे। वह नहीं बोल पाएंगे। प्लीज आप सहयोग करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री सभापति: धन्यवाद आपको भी।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तीन दिन से चर्चा चल रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तीन दिन से लगातार पक्ष और विपक्ष के सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे से पहले दो या तीन दिन में जो माननीय सदस्य बोले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आप जरा आफिसर्स लॉबी की तरफ देखो। हम किसके लिए बोल रहे हैं? एक अधिकारी है तो देख लें आप। श्रीमान, आप खुद ही मुलाहिजा फरमा लें। एक अधिकारी आफिसर्स लॉबी में नहीं है। क्या है सभापति महोदय, आपकी सदारत में इस सदन की अवमानना कितनी होगी?

श्री सभापति: विराजिए। आपने आसन के संज्ञान में ला दिया। अब आप विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई अधिकारी यहां मौजूद नहीं रहे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इससे बुरी बात क्या हो सकती है?

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, सभापति महोदय, यह नहीं। पहले आप अधिकारियों को बुलाएं।

श्री सभापति: आसन के संज्ञान में आ गया। अब आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप पहले अधिकारियों को बुलाओ। कोई अधिकारी नहीं, सभापति महोदय। आपके होते हुए नहीं है। आप आसन पर विराज रहे हैं। क्या हो रहा है यह?

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस सदन की गरिमा कितनी गिरेगी ...(व्यवधान) कितनी गरिमा गिरेगी?

श्री सभापति: क्यों बुला रहे हैं उनको?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ऐसा नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे। आपने आसन के संज्ञान में ला दिया ...(व्यवधान) मैं सुन रहा हूं न ...(व्यवधान) प्लीज, प्लीज। यह इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आप यहां वैल में आएं ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

प्लीज सहयोग करें ...(व्यवधान) प्लीज, सहयोग करें ...(व्यवधान) बाकी लोग रह जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे।

एक माननीय सदस्य: यह देखें।

श्री सभापति: समाप्त करें? (व्यवधान) सदन की कार्यवाही स्थगित करूं? (व्यवधान) सोमवार तक के लिए स्थगित कर दूं, क्योंकि आप लोगों को नहीं बोलना है। (व्यवधान) गलत मत कहिये। जो लोग बोलने से रह गये, क्यों इनको उकसा रहे हो? प्लीज। (व्यवधान) प्लीज सहयोग करें, माननीय सदस्य, सहयोग करें। (व्यवधान) आपने आसन के संज्ञान में ला दी बात। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ये सब चाहते हैं स्थगित करना, जाना चाहते हैं। (व्यवधान) राजेन्द्र राठौड़जी आज जल्दी जाना चाहते हैं। (व्यवधान) इसलिए बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सरकार कहीं नहीं जा रही है। (व्यवधान) प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, विराजिये, आप अपने आसन पर जाएं। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आज जल्दी जाना चाह रहे हैं सारे, रुकने के मूड में नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जो लोग बोलने से रह गये हैं वे नहीं बोल पाएंगे। प्लीज इनको लेकर जाएं, प्लीज सहयोग करें, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं अपेक्षा करता हूं आपसे कि आप अपने आसन पर जाएं। (व्यवधान) रूपाराम जी।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन दिन से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है, मैं इस अभिभाषण पर कहना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने 40 पृष्ठीय अपने अभिभाषण में 148 बिन्दुओं में राजस्थान सरकार ने जो कार्य किये, उसका और आगे की क्या कार्य योजना है, उसके बारे में बताया।

श्री सभापति: एक मिनट। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, एक मिनट सुनिए आप। (व्यवधान) माननीय उप नेता महोदय, आप तो खेली खायी में हो, ये नए जो बच्चे आये हैं इनको तो बोलने दो, आप तो खेली खायी में हो। (व्यवधान) आप बैठिए, आप विराजिये, आप अपने आसन पर जाइए। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ये माननीय सदस्य जाना चाहते हैं जल्दी छुट्टी करके। (व्यवधान) राजेन्द्रजी सोचते हैं कि जल्दी छुट्टी हो जाए, सात बजे से पहले नहीं जाने वाले हैं।

श्री सभापति: आपने आसन के संज्ञान में ला दिया है। (व्यवधान) सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य तो खेली खायी में हैं, आप नए हो। ये तो खेली खायी में है, इनके तो क्या फर्क पड़ता है। (व्यवधान) आप विराजो। (व्यवधान) आपकी बात बिलकुल नहीं सुनूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सवाल इस बात का नहीं है। (व्यवधान) कभी तो कोरम की घंटी बजे, एक अधिकारी नहीं लॉबी में, एक अधिकारी नहीं, सीनियर एक अधिकारी नहीं, मतलब क्या हो गया ये?

श्री सभापति: माननीय उप नेता प्रतिपक्ष, आपने आसन के संज्ञान में यह बात ला दी। अब इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आप वैल में आ जाएं और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं लगातार दो दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस सदन की बहस को निरर्थक बहस बनाकर छोड़ा है। सदस्य भी सीरियस नहीं हैं, जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, उनकी तो जिम्मेदारी है कि वे रहें हाउस में और एक भी जिम्मेदार अधिकारी, आपने कभी ऐसी विधान सभा देखी है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बिलकुल खाली।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हम यहां पर भाषण दे रहे हैं तो केवल और केवल ये रिकार्ड पढ़ेंगे, इनमें से एक भी ऐसा बहादुर नहीं है जो रिकार्ड पर निकालकर चार लाइन भी पढ़ेगा, यह गारंटी मेरी है। केवल और केवल जिनके डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है तो कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण में सभी विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि हो सकता है कि कौनसा सदस्य कौनसे विभाग के बारे में कोई बात बोले, तो उसके बारे में कुछ देना चाहिए, वह तैयारी कहां से करेंगे जब रिप्लाई करेंगे? हम बोलें क्या निरर्थक? उनको लिखा लिखाया भाषण दे देंगे, वे यहां आकर पढ़ देंगे। यह तो धन्यवाद प्रस्ताव का मकसद नहीं है। यह मैं प्रारम्भ से आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक भी नहीं था।

श्री सभापति: आप विराजें। एक मिनट, आप विराजिये, माननीय सदस्य। आसन आपकी भावनाओं से अवगत हुआ। विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह परम्परा गलत है। नेता प्रतिपक्ष ने बोल दी अपनी बात और आप अब क्यों खड़े हो रहे हैं? (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये आप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात कही है, आसन के संज्ञान में कोई बात आई है, मैं निश्चित रूप से आपकी बात को बहुत गम्भीरता से लेता हूं और मैं निर्देशित भी करता हूं कि जो भी जरूरी अधिकारी हैं वे यहां रहें, लेकिन मैं बराबर आपसे भी यह अपेक्षा करता हूं कि जो लोग बोल लिए, अधिकतर लोग चले गये, जो लोग बोलने से वंचित रह गए, उनको बोलना है, उनको बोलना है, इसलिए थोड़ा समय का आप भी मुझे सहयोग करें। (व्यवधान) प्लीज सहयोग करें। जो बोलने से वंचित रह गये उनको बोलने का मौका मिले, कृपया सहयोग करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल की शादियां हैं और उसके कारण से कुछ लोग पूछ कर गये हैं बाकी हमारे अधिकांश लोग उपस्थित हैं।

श्री सभापति: कोई बात नहीं। (व्यवधान) अब जो बचे हुए हैं वह बोल लें, मेरा कहने का मतलब यह है। सात बजे तक का टाइम हमको दिया हुआ है। जो बच गये हैं, वे लोग भी अपना समय पूरा कर लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सत्ता पक्ष के लोग तो हैं ही नहीं।

श्री सभापति: कृपया सहयोग करें। श्री रूपारामजी।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, अभिभाषण पर मेरी बात शुरू थी, बीच में थोड़ी कट गई। मैं निवेदन कर रहा था कि सभी सदस्य महानुभाव जो मेरे से पहले बोले, अभिभाषण पर सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, अभी क्या कार्ययोजना है, उस पर काफी बहस हो चुकी है। मेरा निवेदन इसमें यह रहेगा कि विपक्ष की तरफ से कहा गया कि यह नहीं किया, कोई भी राज चलाता है, मौका मिलता है, एक भी काम सही नहीं करे, ऐसा होता नहीं है। 73 वर्ष पहले देश आजाद हुआ, अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी बारी-बारी से जिस-जिस पार्टी का राज आया, राज किया। देश आजादी से पहले राजस्थान के करीब 90 परसेंट लोग जो गांव में रहते हैं, आदिवासी हैं, एससी-एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, उनको पता नहीं था कि राज का टैस्ट क्या होता है, स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है या मीठा होता है, कोई पता नहीं था। कोई सुविधाएं नहीं थी। जैसलमेर बाड़मेर के अंदर कई गांव ऐसे थे जो लोग कुंवारे रह जाते थे कि यहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। पीने का पानी औरतें चालीस से पैंतालीस किलोमीटर दूर सिर पर घड़ा उठाकर लाती थीं, उनको चोटी करने को बाल नहीं बचते थे, घड़ा और इण्डाणी रखते थे सिर पर इससे सिर के बाल उखड़ जाते थे। उन परिस्थितियों से आज अपन जहां तक पहुंचे हैं, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन यह कहना कि कुछ भी नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं पहले अलग सैक्टर में था, अधिकारी था, यहां आने के बाद में फील हुआ कि किये हुए काम का तो दुश्मन का भी बखान करना चाहिए। यहां कोई भी नहीं कह रहा है, सब तैयारी करके आते हैं

(श्री रूपाराम)

कि कैसे मीन मेख निकाली जाए, मेरे ख्याल से यह ज्यादा ठीक नहीं है। देश जब आजाद हुआ, 1977 तक राजस्थान में कांग्रेस का ही शासन रहा, तो क्या उन 30 वर्षों में कुछ नहीं हुआ? वह एक उजाड़ खेत था, कोई भी नया खेत शुरू करता है तो उसको बहुत तकलीफें आती हैं। पहले किसी ने कर दिया, दो चार बार तो क्या सीधे हल चलाना है, तो आप कल्पना कीजिए कि जब देश गुलाम था, उसको आजाद कराया, किसने कराया था, किनके पूर्वज थे, किस पार्टी से सम्बन्धित थे? वे वास्तविकता सब जानते हैं, यहां हो सकता है कि बहस में ज्यादा तेज बोल जाए पर वास्तविकता सब घर जाकर सोएंगे तो सोचेंगे कि मैंने जो कहा वह गलत है, जिसने सही किया, वह सही रहेगा। उस वक्त जिन लोगों ने जानें दीं, त्याग किया, अपने घरबार छोड़े, तब देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में उन विपरीत परिस्थितियों में, राज्य में कुछ नहीं था, उसको इस स्टेज पर लाए। मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब गांव जाता था, मैं खुद करीब 35 किलोमीटर दूर मीठा पानी लाने के लिए ऊंट पर बखाळ लेकर आता था, फिर मैं खुद चीफ इंजीनियर बना पीएचईडी में था, स्कीमें बनाई तो अपन एक ही लाइन में कहना कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अगर किसी ने भी किया हो, आज 73 वर्ष में चार बार मुख्य मंत्री भाजपा के पांच बार मुख्य मंत्री रहे, भैरोंसिंहजी का ढाई-ढाई साल का, एक बार पांच साल का राज रहा, वसुन्धराजी पांच-पांच वर्ष के लिए दो बार रहे। हम लोग कांग्रेस में हैं और कह दें कि कुछ नहीं किया तो यह तो सरासर गलत है। देश की आजादी के बाद में यह अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर देश जब गुलाम था तो राज्य की क्या स्थिति थी और आज जहां पहुंचे हैं, उसमें कम से कम 70 से 75 परसेंट कोई भी सैक्टर ले लें, वह कांग्रेस के शासन में हुआ है। इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हिसाब-किताब निकालकर भी देखा जा सकता है। हम लोग अधिकारी थे तो आप लोग लीडर्स के निर्देशों में ये आंकड़े निकालते थे और 20 से 25 परसेंट भाजपा के राज में हुआ। भाजपा को कम समय राज करने को मिला। अगर उन्हें ज्यादा मिलता तो वे भी ज्यादा काम कर लेते।

अशोक गहलोत जी के बारे में सभी ने बोला कि कोरोना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सौ वर्ष के बाद महामारी आती है। सन् 1975 में हमारे मारवाड़ में उसको बड़बड़ी कहते थे, लोग इतने खतम हो गये कि गांव

(श्री रूपाराम)

में, हमारे बाड़मेर-जैसलमेर में जो अग्निदाह करते थे, वे एक जगह ही लकड़ियां जलाकर रखते थे और एक लाश को ले जाकर वहां रखते और वापस गांव आते थे, फिर दूसरी को ले जाकर रखते थे। जो जमींदार देते थे, लगातार एक टांका टाइप खोद दिया, उसमें डालकर आते थे और कंधों पर उठा-उठाकर चमड़ियां कट गयी थीं। भय का वातावरण पैदा हो गया था। सौ वर्ष बाद कोविड-19 आया। पूरे विश्व के कई देशों में जो कोरोना का पेशेंट था, उससे लोग घृणा करने लगे। घरवाले उसके नजदीक नहीं जाते थे। हमने कई देशों में देखा, जो हम से बहुत ज्यादा विकसित थे। राज्य में बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन खुले मन से कई बार माननीय कटारिया साहब ने भी अशोक गहलोत साहब की इसके लिए प्रशंसा की और अन्य लोगों ने भी की। मोदी साहब ने भी की। वास्तव में स्टेट का अशोक गहलोत साहब ने विपरीत परिस्थितियों में जो मैनेजमेंट किया, राजस्थान में किसी गांव, ढाणी या शहर में ऐसा वातावरण निर्मित नहीं हुआ कि इंसान इंसान से घृणा करे कि इसे कोरोना हो गया है, अब इसके नजदीक कैसे जाएं। प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हों, व्यवसायी हों, दानदाता हों, सब इस संकट में एकदम जुड़े हुए रहे और संकट आज लगभग निकल चुका है। शुरू से ऐसी प्लानिंग रही। उनका जो दृढ़ निश्चय था और मानवता थी और आप व हमने मिलकर जो इस लड़ाई को लड़ा है, यह विश्व में एक अनूठा उदाहरण है, यह हम सबको मानना चाहिए।

इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा, आज हम जहां तक पहुंच गये हैं, वह किसकी वजह से पहुंचे, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, यहां पर राज में आने वाली दो ही पार्टियां हैं, किसी भी तरह एक स्थान पर पहुंच गये। अब इसके आगे जाना कहां है और उसके लिए करना क्या है, अगली बार बारी हमारी आएगी या किसी और की आएगी या जो भी होगा, तो एक कार्ययोजना बनाकर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम करें।

आज राजस्थान की आठ करोड़ के आसपास की आबादी है, पशुधन भी इससे दुगुना है। आज हम 200 लोग हैं, 200 में से आज भगवान ने हमारे चार साथियों को हमारे साथ नहीं रखा। पूरे राज्य में, 33 जिले हैं, हजारों ढाणियां हैं, 40 हजार गांव हैं, करीब 300 शहर हैं, इनका करने वाला कौन है, हम ही तो हैं। हमारे द्वारा ऐसी कोई कार्ययोजना बने, बहस चले, उसके अंदर

(श्री रूपाराम)

एक पाइंट भी ऐसा आये कि आज हम यहां खड़े हैं और यहां जाना है, उसमें कोई दो मत हो सकते हैं, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम पीढ़ियों से एक-दूसरे के दुश्मन हों। ऐसा तो है नहीं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): सर, मैं एक मिनट में सिर्फ दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। एक तो पेयजल के सम्बन्ध में जो हम सबको साथ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस महकमे में मैं रहा हूं। अभी भारत सरकार ने घोषणा की है जल सम्बन्ध घर-घर दिये जाएं। राजस्थान में अगर घर-घर जल सम्बन्ध दिये जाएंगे तो लगभग 3 लाख करोड़ का एस्टिमेट है और वह 2024 तक किसी भी सूरत में आना नहीं है जो फण्ड का फ्लो है। वर्तमान में जो सिस्टम है, उसका कम्प्लीट सुदृढ़ीकरण हो। जो सतही सोर्स से जुड़े हुए सिस्टम नहीं हैं उन्हें जोड़ा जाए। तीसरी स्टेज पर जल सम्बन्ध वाला करना चाहिए ताकि सबको उसका लाभ मिले।

इस हिसाब से जो इसमें फैमिन रिलीफ कोड है, पुराना बना हुआ था, अभी भारत सरकार ने और करेक्शन कर दिया, आज गोवंश को बचाने के लिए रिलीफ कोड में ओरिजिनल में करेक्शन कर दिया कि लघु और सीमान्त किसान की गायों को ही अकाल में बचाया जाएगा। यह तो हास्यास्पद है। जैसलमेर, बाड़मेर जैसे कई जिलों में मिनिमम अलाटमेंट ही 75 बीघा का होता था और गायें सब रखते हैं। फैमिन कोड में अभी संशोधन की आवश्यकता है। इसमें जो भी गोपालक हैं, उनकी गायों को अनुदान मिलना चाहिए और अनुदान...

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र मोची।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): थैंक यू, सर।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने राज्य सरकार के माध्यम से हर विभाग के द्वारा किये गये विकास कार्य का आंकड़ा पढ़ाया, वह धरातल पर असत्य साबित हो रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं। सभापति महोदय, पेयजल, चिकित्सा, सड़क, विद्युत, सिंचाई, कानून-व्यवस्था, राज्य सरकार इन सब में फेल हो चुकी है और आम आदमी में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले पेयजल से शुरुआत करता हूं। महोदय, हनुमानगढ़ जिले की जनसंख्या गांवों के साथ 30 से 40 प्रतिशत ढाणियों में निवास करती है। इस एरिया के लोग दूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे वहां के लोगों में कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और वहां के लोगों को इस संकट से उबारने के लिए कोई योजना नहीं बना रही है। अत: मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार सम्बन्धित समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये और राहत प्रदान करे।

जल जीवन मिशन हमारे यहां अभी तक लागू नहीं हुआ है, ऐसे में एक योजना जिसका नाम ''आपणी योजना'' है, जो एशिया की सबसे बड़ी योजना है, वह लड़खड़ा रही है और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस योजना के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के बाहर भी अन्य जगह पानी जा रहा है, हमें उससे आपत्ति नहीं है, परंतु खोडा, धनासर, केसर-देसर, रामपुरा मटोरिया, किकरालिया, रायको वाली ढाणी, हरदासवाली डेर इत्यादि जगहों पर योजना का विस्तार करते हुए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना का सही ढंग से उपयोग हो ताकि जैसा मिनरल वाटर हमें मिल रहा है, वह आम आदमी को भी मिले।

कोरोना काल का समय प्रकोप भरा समय रहा। आम जनता में भय का वातावरण रहा। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा राजस्थान सरकार को भारी मात्रा में सहायता राशि भेजी गयी। अन्य दवाइयां, मशीनों, उपकरणों हेतु बजट आबंटित किया। इसके साथ-साथ गरीब परिवारों के खाते में सीधी राशि बैंकों में जमा की जाती रही है एवं खाद्य सामग्री के रूप में गेहूं, दाल भी भेजी। ऐसा वातावरण हुआ कि मोदी जी ने जो पैसा भेजा है, वह रुपया हमें दे देना। महिलाएं बैंकों में जाकर परिवार की घरेलू जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा लाती थीं और सरेआम कहती थीं कि मोदी तेरा भला हो, हमें राहत प्रदान की। मोदी गरीबों का दास है।

हनुमानगढ़ जिले में कोरोना जांच की सरकार ने देरी से व्यवस्था की, जिसके कारण जनता जांच हेतु बीकानेर या जयपुर इलाज के लिए जाती थी, सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए व्यवस्था नहीं होती थी। प्राइवेट इलाज का खर्चा भारी मात्रा में होता था, जिससे कई परिवारों पर भारी आर्थिक संकट

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

आया। सरकारी मदद नाम मात्र की मिलती थी। कोरोना काल में हनुमानगढ़ जिले में राशन किट 327 रुपये में सरकार द्वारा खरीदी गयी थी, जबकि मात्र 295 रुपये में बाजार में मिलती थी। सरेआम भ्रष्टाचार हुआ।

कोरोना काल में एमएलए कोटे के जो पैसे हमें रावतसर, पीलीबंगा, गोलुवाला, डबली में दिये थे, आज तक वे लगे नहीं हैं। जनहित में उपयोग के लिए दिये थे, परंतु आज तक नहीं लगे हैं। प्रवासी जो पैदल जा रहे थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। मैं भामाशाहों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने उनके रहने-खाने की व्यवस्था की। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, पीलीबंगा, गोलुवाला, रावतसर आदि जो कस्बे हैं, यहां के हास्पिटलों को क्रमोन्नत कर दें इस बजट में तो बहुत अच्छी बात रहेगी।

शिक्षा की दृष्टि से भी हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारा एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ है, परंतु फिर भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में पीलीबंगा, रावतसर, गोलुवाला जो बड़े क्षेत्र हैं और जहां विद्यार्थियों की बहुत अधिक संख्या है, यहां कालेज खोलने की घोषणा करें ताकि मेरे क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

सड़क तंत्र को मजबूत करने का गुणगान माननीय राज्यपाल महोदय से करवाया गया, लेकिन धरातल पर इसके विपरीत स्थिति है। सरकार ने जिला हनुमानगढ़ में कुछ नहीं किया। प्रदेश में लगभग 60 हजार किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त व टूटी-फूटी स्थिति में हैं। मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की समस्त ग्रामीण सड़कें टूटी-फूटी स्थिति में हैं। गत दो वर्षों में सड़कों की मरम्मत के लिए नाम मात्र भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। चाईया से गन्धेली सड़क, पीलीबंगा से गोलुवाला सड़क, पीलीबंगा से सुरावाली सड़क, रावतसर से सूरतगढ़ वाया जाखड़ा वाली सड़क, रावतसर से न्योलखी सड़क, नूरपुरा से भाम्बूवाली ढाणी, चक एलजीडब्ल्यू, चक 9-10, एमओडी सड़क, पीलीबंगा से वाया हंसलिया सड़क, लिखवीसर सड़क क्षतिग्रस्त है। इन दोनों की चौड़ाई बढ़ाना जरूरी है। दावा किया जा रहा है कि विकास का काम लगातार हो रहा है पर सरकार झूठे दावे कर रही है। क्षेत्र में लगभग 20 सड़कें गांवों को जोड़ने के वास्ते जरूरी हैं, पर गत दो वर्षों में एक पैसा भी पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में नहीं लगाया गया है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर स्थित पुल जो क्षतिग्रस्त है, जहां हादसा हो सकता है, तो ऐसे पुलों का भी ध्यान दिया जाए।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

बिजली की बात है तो सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से आह्वान किया था कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी पर सरकार ने बिजली के नाम पर भारी मात्रा में सरचार्ज लगा दिया है। पूर्व सरकार द्वारा जो किसानों को 833 रुपये सब्सिडी दी जाती थी उसको बन्द कर किसानों को लाभ से वंचित कर दिया गया। वीसीआर के नाम पर आम जनता को लूटा जा रहा है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ए.ईएन. और जे.ईएन. के अधिकार एस.ई. को दे दिये गये हैं, जिसके कारण से आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। फ्यूल चार्ज, स्थायी शुल्क में वृद्धि की गई है। ये सारे फैसले आम जनता के विरुद्ध हैं और सरकार लगातार ये फैसले करती आ रही है। जनता कोरोना काल में दु:खी थी और जनता का, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का काम-धन्धा बन्द था लेकिन सरकार ने हाथ में तलवार लेकर फैसला किया और भय दिखाकर वीसीआर के नाम पर कनेक्शन काटे गये। रामपुरा रंग महल, पीलीबंगा, नूरपुरा डबली, हरदासवाली और खीदासरी में 33 केवी जीएसएस स्थापित हो जाए तो काश्तकारों को लाभ मिल सकता है। सरकार ने सौभाग्य योजना और दीनदयाल उपाध्याय योजना बन्द कर आम जनता के साथ कुठाराघात किया है। मैं इसका विरोध करता हूं।

सिंचाई में पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में सेम समस्या पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सेम क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछली सरकार द्वारा सेम का समाधान करने के लिए 39 करोड़ रुपयों का बजट देकर किसानों को राहत प्रदान की थी, जिससे फसलों में सुधार हुआ लेकिन अब सरकार ने किसानों की समस्या के लिए सेम क्षेत्र में पैसा नहीं दिया। अब तो सेम निकासी के 99 आरडी, बड़ोपल पर पम्प से निकासी के लिए विद्युत बिल की राशि भी नहीं भरवाई गई है, जिससे बिजली के कनेक्शन काट दिये हैं। सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। भैरूंसरी से बड़ोपल, रावतसर से 99 आरडी सेम नाले की सफाई भी गत दो वर्षों से बन्द है, जिससे नाला भी बंद होता जा रहा है। इसके कारण से सेम का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और फसलों को नुकसान हो रहा है। सरकार किसान विरोधी काम करती नजर आ रही है। पिछली सरकार इन्दिरा गांधी, भाखड़ा नहर के पक्के खालों का निर्माण करा रही थी पर इस सरकार ने पक्के खालों का निर्माण ही बन्द कर दिया है। मुख्य बैराज इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर कुछ डैमेज हो गई है और उसकी कोई सम्भावना नहीं है और

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

सरकार भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नहर का पंजाब से पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है और सरकार किसान विरोधी होती जा रही है। सरकार जागे और पंजाब सरकार से बात करे और क्षतिग्रस्त नहर का पुन: निर्माण हो सके, ताकि काश्तकारों की फसल बच सके। 1985 में नहर बनी थी और डबली लखवली और आरडी 84 पर पुल बने थे जो क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): एक मिनट, थोड़ा-सा रह गया, साहब। एक पाइंट रह गया। हनुमानगढ़ जिले में कानून व्यवस्था के तहत क्षेत्र में सरेआम नशीली दवाइयां, चिट्टा, अफीम, डोडा-पोस्त व चोरियां होना आम बात हो गई है। नशे का कारोबार आये दिन होता जा रहा है। प्रशासन पूर्णतया उदासीन हो चुका है और क्षेत्र में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, गौ वंश की तस्करी भी लगातार बढ़ रही है, शराब की तस्करी बढ़ रही है और जगह-जगह शराब की अवैध दुकानें खोली जा रही हैं। पुलिस सरेआम रिश्वत ले रही है। रावतसर में एक गम्भीर मामला भी आया कि 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी और अपहरण किया गया। रावतसर में दो व्यक्ति गुम हैं। एक सतपाल सुथार एफआईआर नं. 577/2018 और दूसरा अभिषेक विश्नोई एफआईआर नं. 156/2019 है। दो सालों में पुलिस इन आदमियों का पता नहीं चला पाई और एक भी चोरी बरामद नहीं हुई। यहां पर खुला चिट्टा बिक रहा है और वहां सरेआम नशीली दवाइयां बिक रही हैं। यह सरकार किसी भी प्रकार से आम आदमी का साथ नहीं दे रही है तथा चिट्टे और गोलियों का धन्धा इतना बढ़ रहा है। अवैध नशे का कारोबार हनुमानगढ़ जिले में खूब बढ़ रहा है। इसके लिए मैं निन्दा करता हूं और इस अभिभाषण का विरोध भी करता हूं।

श्री सभापति: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, पिछले दो दिन से लगातार महामहिम के अभिभाषण पर पक्ष और प्रतिपक्ष में चर्चा चल रही है। आज इस देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश का अन्नदाता लाखों की संख्या में सड़कों पर बैठा हुआ है। जो पूरे देश का पेट पालन करता है, आज उसकी आंखों में आंसू है। पक्ष और प्रतिपक्ष को राजस्थान की विधान सभा में इस बात की चर्चा करनी

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

चाहिए कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं लेकिन इस देश का किसान जब जिन्दा है तो हम सब लोग जिन्दा हैं।

सभापति महोदय, पिछले दिनों हम लोग अखबारों में पढ़ते थे, टी.वी. चैनल पर देखते थे कि किराये के ऊपर किसान को लेकर आये हैं। सभापति महोदय, किसान कभी अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता, कभी नहीं बेच सकता अपना स्वाभिमान। वह गरीब किसान, जो रात-दिन मेहनत करता है, पूरी रात खेतों में पानी देता है फिर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करता है लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी नहीं बेचता। शर्म आनी चाहिए इस देश को, हम सब जन-प्रतिनिधियों को। देश के नेताओं को और देश के जन-प्रतिनिधियों को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि लगातार दो-ढ़ाई महीनों से हमारा किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। किराये का आदमी इतने दिन कभी भी नहीं बैठ सकता। कोई हजार रुपये रोज के, दो हजार रुपये रोज के दे तो भी इतनी कड़ाके की सर्दी के अन्दर कोई किसान नहीं बैठ सकता और किसी भी सरकार को इस बात का घमण्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि स्थायी कोई नहीं होता है, यह जनता जिसको लाना जानती है उसको पटकना भी जानती है।

सभापति महोदय, इस देश की डेमोक्रेसी में हर पांच साल में सरकारें बनती हैं और घमण्ड रावण का ही नहीं चला तो हम तो इन्सान हैं, हमारा घमण्ड तो जीवन में कभी चल ही नहीं सकता। गलतियां हमसे भी होती हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से गलतियां होती हैं लेकिन सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई गलती हो तो उसको ठीक करने में कहीं वह नीचा नहीं पड़ जाता, इस बात से कोई स्वाभिमान नहीं गिरता। कई बार विधान सभा में हम लोग भी बिल लेकर आते हैं और अगर उनमें त्रुटियां होती हैं तो उन बिलों को फिर ठीक भी करते हैं। क्या हालात हैं देश के? लाखों लोग सड़कों पर बैठे हैं, सड़कें बन्द पड़ी हैं, व्यापार ठप हो रखा है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के आस-पास जो दिल्ली से माल ट्रेवल होता है, हमारे यहां पत्थर की रोड़ी का अच्छा काम चलता है और अभी पिछले दिनों दो-तीन क्रेशर वाले मुझे मिले और कहा कि महीने का 50 लाख रुपये का लोस हो रहा है। वे लोग थोड़े-बहुत दिनों में बर्बाद हो जाएंगे। अगर यही स्थितियां चलती रहीं तो वे लोग बर्बाद हो जाएंगे। सभापति महोदय, गरीब की हाय जब लगती है तो गांवों में कहावत है कि जड़ा-मूल से खो देती है गरीब की हाय। सभापति महोदय, इस सदन में बैठे हुए काफी लोगों ने, काफी लोग

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

किसान परिवार से आते हैं, मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं, मैंने खुद ने खेती-बाड़ी की है, पूरी-पूरी रात खेत में पानी दिया है। उस खेत में कितनी ठण्ड लगती है, वह किसान का बेटा महसूस कर सकता है। इस ठण्ड के अन्दर किसान दो-ढ़ाई महीने से बैठा है तो मैं पक्ष और प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर केन्द्र सरकार से यह निवेदन करें कि अपने घमण्ड को छोड़े और किसानों की बात को सुनकर, किसानों को राहत देने का काम करे।

सभापति महोदय, यह सबको पता है, पूरे सदन को पता है और पूरे राजस्थान को पता है कि पिछले दो साल में राजस्थान प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ा है। पिछले साल पूरे विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने हमारे प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की, पूरे विश्व की विकास की गति को रोकने का काम किया है। उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को मुख्य मंत्री महोदय को कि एक अच्छा प्रबन्धन कोरोना काल में किया कि इस राजस्थान में व्यक्ति भूखा जगेगा लेकिन भूखा सोयेगा नहीं। अच्छा प्रबन्ध हुआ और उसकी सराहना पूरे देश ने की, प्राइम मिनिस्टर महोदय ने भी की। इस बात को, सच्चाई को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय, पिछले दो साल में जब मैं जीतकर विधान सभा में आया तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रशासनिक सिस्टम को देखा तो सभी हास्पिटल खाली पड़े थे, स्कूलें खाली पड़ी थीं। विराट नगर में घुसते ही पता चलता था कि सड़कों के कैसे हालात थे, डेढ़-डेढ़, दो-दो फीट के गड्ढे थे।

(18.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि पिछले दो साल में, मैं अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं 144 करोड़ रुपये सड़कों के मुझे मिले और आज उनमें से 70 करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं। हम सब लोगों को मिलकर प्रतिपक्ष के नेता और उप नेता बैठे हैं, एक बात सदन को बताना चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था, अभी सड़कों की बात चल रही थी, हमारे सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि सड़कों के हालात क्या हैं।

सभापति महोदय, सीआरआईएफ (सेन्ट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) जो हमारा हिस्सा है केन्द्र की सरकार में, पिछले दो साल से केन्द्र की सरकार

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

उसको रोक करके बैठी है। पिछले दो साल से, मैं रिकार्डेड बात कर रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। 723 करोड़ रुपये 6 महीने पहले अलाट किये, इस जनवरी में वापस राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव भेज दिये, मंजूरी आ गई, टेंडर लग गये और टेंडर लगने के बाद फिर उनको होल्ड कर दिया गया। जवाब देना चाहिए इस बात का केन्द्र सरकार को कि हमारे हिस्से को होल्ड करने का क्या कारण था?

मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक 40 करोड़ की सड़क थी, बाकायदा आफिस से लैटर आया केन्द्र सरकार का कि इस टेंडर को अभी होल्ड कर दिया जाए। टेंडर लगने के बाद, टेंडर खुलने के बाद, उस पैसे को होल्ड किया गया। क्यों नहीं बात करते हम लोग, हमारे 25 सांसद वहां पर क्यों नहीं बात करते इस बात की? हमारे सांसद हैं राज्यवर्धन जी, फोटो का बहुत बड़ा शौक हैं उनको, जहां भी आये दूसरे दिन प्रेस विज्ञप्ति, कई बार तो उनको ये ही नहीं पता चलता स्कीम केन्द्र की है या राज्य सरकार की है। प्रेस विज्ञप्ति लगाने का बहुत बड़ा शौक है उनको भी, मैंने उनसे कहा कि इस रोड की प्रेस विज्ञप्ति तो आप बड़ी-बड़ी लगा रहे थे, अब केन्द्र सरकार ने होल्ड किया, अब इस होल्ड को भी आप तुड़वाइये, लेकिन कोई जवाब नहीं है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार के द्वारा हमारे राजस्थान का हिस्सा जिस तरीके से काटा जा रहा है, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए क्योंकि पैसा हमारे विकास का है, किसी की जेब से पैसा नहीं जा रहा है। हमारे विकास का पैसा है, हमारा पैसा है, जो हमारा अधिकार बनता है, केन्द्र सरकार द्वारा उसको दो साल से रोकने का काम किया जा रहा है।

डाक्टर्स के हालात क्या थे? आज बात कर रहे हैं, उप नेता महोदय भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 44 पोस्ट थीं डाक्टर्स की, जिनमें से जब मैं चुनाव जीतकर आया तो 19 पोस्ट भरी हुई थीं। हम डाक्टर के पीछे-पीछे भागते थे कि, डाक्टर साहब, आ जाओ, आपको हमारे विराटनगर में लगवाएंगे, डाक्टर आने को तैयार नहीं थे। आज हमारी सरकार ने डाक्टरों की भर्ती की और आज शायद एक, दो सीट खाली हैं, बाकी कोई सीट हमारे यहां खाली नहीं है, जयपुर जिले में सीट खाली नहीं है। आस पास के विधान सभा क्षेत्रों में सीट खाली नहीं है, क्योंकि डाक्टरों की भर्ती की। मैं सच्चाई बोल

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

रहा हूं आपको। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। मैं विराटनगर की बात कर रहा हूं, रिकार्डेड है।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): निकलवाकर आप देख लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। सभापति महोदय, महंगाई की बात आप लोग करते हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, मैं तो छोटा भाई हूं आपका, थोड़ा टाइम दें, कभी-कभी मौका मिलता है बोलने का।

श्री सभापति: मिलते रहेंगे।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंहजी की सरकार थी जब डीजल पेट्रोल का एक रुपया बढ़ता था, गैस में 10 रुपये बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी का फोटो, आज भी मैं दिखा सकता हूं, किस तरीके के हालात थे, आंदोलन करते हुए। आज आप क्यों नहीं बोलते? रोज सुबह से शाम तक हम देखते हैं, कभी दस पैसे बढ़ते हैं, कभी बीस पैसे बढ़ते हैं और सौ-सौ रुपये डीजल-पेट्रोल के हो गये। कच्चे तेल का दाम गिर रहा है, पेट्रोल-डीजल का भाव बढ़ता जा रहा है। कौन ध्यान देगा इस बात के ऊपर?

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि पहली बार तहसीलों को ऑनलाइन करने का काम किया, पटवारियों का जो राज था, जो किसान पटवारियों के चक्कर काटता घूमता था, पांच सौ रुपये के बिना जमाबंदी नहीं मिलेगी, हजार रुपये के बिना गिरदावरी नहीं मिलेगी, आज ऑनलाइन करने के बाद सभी पटवारियों को, जमाबंदी, गिरदावरी सब ऑनलाइन होने के बाद इतना अच्छा फायदा हुआ है। हमारी सरकार को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, और सबसे बड़ा धन्यवाद, बेरोजगारी की आप लोग बात करते थे, रीट की 31 हजार भर्तियां खोलकर हमारी सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इस बात के लिए मैं मुख्य मंत्री जी को और पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती संतोष बावरी।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण पूरे वर्ष के कार्यकाल का लेखा-जोखा एवं आगामी वर्ष की भावी योजनाओं को दर्शाता है लेकिन इस बार के अभिभाषण में ऐसी कोई नई योजना को नहीं दर्शाया गया है जिससे कि आमजन को राहत मिल सके।

देश में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण से उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, मजदूरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या भी आई, मेरे क्षेत्र के भामाशाहों और सामाजिक संस्थाओं को मैं धन्यवाद देती हूं कि इस समय में समर्पण भाव से सहयोग किया।

बेरोजगारी इस कदर हो गई कि स्किल एवं अनस्किल्ड लेबर को भी काम नहीं मिल रहे हैं, जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सकें। कोरोना के समय वास्तविक तौर पर जिन जरूरतमंद परिवारों को भोजन सामग्री वितरित की जानी थी, उनको लाभ नहीं मिला जबकि हमारे मुख्य मंत्री जी की अवधारणा थी कि कोई भूखा न सोये। वह अवधारणा भी जरूरतमंदों के लिए असहाय रही।

माननीय सभापति महोदय, मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, अनूपगढ़, घड़साना और रावला, जिनमें डाक्टरों की कमी, चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सदन में मांग रखी थी मैंने बार-बार, जो भाईसाहब अभी बोल रहे थे, मेरे द्वारा बार-बार मांग रखने के बावजूद भी वहां अभी तक एक भी डाक्टर नहीं लगाया गया है। इसको लेकर मैं मुख्य मंत्री और मंत्री जी से भी मिली थी लेकिन, अभी तक पद रिक्त पड़े हैं, न ही सहायक स्टाफ की कोई नियुक्ति की गई है। इस महामारी में मेरे क्षेत्र की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। चिकित्सालयों में दवा नहीं है, जांच मशीन पर टैक्नीशियन नहीं है और बीमार को संभालने के लिए स्टाफ नहीं है। गंभीर रोगी का एक प्रकरण मैं सदन में बताना चाह रही हूं। मेरे क्षेत्र के मुखराम पुत्र हरचंदराम, निवासी 15 एलएम, तहसील अनूपगढ़ के लीवर की पथरी का आपरेशन था। 18 अगस्त, 2020 को संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, आपरेशन हुआ और 31

(श्रीमती संतोष)

अगस्त, 2020 को कोराना बताकर मृत घोषित कर दिया। परिवार को अस्पताल प्रशासन के दबाव में लगभग 7 लाख रुपये का बिल चुकाना पड़ा। ऐसा हाल मेरे प्रदेश का है।

सभापति महोदय, कोरोना काल में अनूपगढ़ के चिकित्सालयों में आइसोलेशन वार्ड तो तैयार किये, लेकिन डाक्टर और टैक्नीशियन स्टाफ के अभाव में इन वार्डों को बनाने का कोई औचित्य नहीं रहा।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आर्थिक संबल के लिए चलाई जा रही है, लेकिन इस योजना से सरकारी अस्पतालों में पैदा हुई बच्ची को ही लाभान्वित किया जाता है। किसी बच्ची का रजिस्टर्ड निजी चिकित्सालय में प्रसव हो जाए तो उसे इस लाभ से लाभान्वित नहीं किया जाता है। एक रजिस्टर्ड निजी चिकित्सालय में सभी सुविधाएं होने के बावजूद भी सरकार इस पर गंभीर नहीं है। यदि एक उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एएनएम बिना जनाना चिकित्सक के प्रसव करवा सकती है तो निजी चिकित्सालयों में भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगी सिंचाई पानी पर। राजस्थान की मरुधरा की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर पर प्रदेश के करोड़ों लोगों का जीवन आश्रित है। केवल मात्र मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे बीकानेर संभाग का किसान वर्ग इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण द्वारा उपलब्ध सिंचाई पानी के सहारे अपने जीवन का ताना-बाना बुनता है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के हित के लिए कांग्रेस बड़ी चिंतित है। किसानों के हमदर्द होने का बहाना बनाकर, राहुल गांधी जी कल पदमपुर पधारे थे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में किसानों को सिंचाई पानी दिये जाने के संबंध में रोटेशन प्रणाली से किसानों की मांग के आधार पर पानी वितरित करने की मांग मैं लम्बे समय से कर रही हूं। किसानों भाइयों द्वारा फसलों की यदि बुवाई करवा दी जाती है तो पकाने के लिए धरना-प्रदर्शन और आंदोलन तक करके सिंचाई पानी लेना पड़ता है। आज रबी की फसल पकाव की ओर है, लेकिन हमारा सिंचाई पानी राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है।

मैं आपको रैगुलेशन अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को सदन में

(श्रीमती संतोष)

बता रही हूं कि तय रैगुलेशन के आधार पर 9 फरवरी, 2021 को सुबह पानी अनूपगढ़ शाखा में पूरा हो जाना था लेकिन रैगुलेशन अधिकारी ने 48 घंटे बाद सिंचाई पानी देने का आदेश जारी कर किसानों के होश उड़ा दिये लेकिन राहुल गांधी जी के प्रस्तावित दौरे का विरोध न हो, उनका दौरा जैसे ही निश्चित हुआ, वैसे ही पुन: आदेश जारी कर सिंचाई पानी 12 घंटे बाद ही छोड़ दिया गया। इसका अर्थ है कि सरकार प्रयास करे और चाहे तो किसानों को उनके हक का पूरा पानी दिया जा सकता है। इस दौरान कई किसानों की बारियां पिट गईं, जैसे मेरे क्षेत्र की गोमांवाली और सुरजनसुर माइनर के किसान हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): 7 मार्च, 2021 से 70 दिन की प्रस्तावित नहरबंदी भी है, लेकिन मेरे किसान भाइयों की गेहूं की फसल एक सिंचाई पानी के बारी के अभाव में नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हूं कि इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के किसानों को एक अतिरिक्त सिंचाई पानी दिया जाये जिससे उनकी रबी की फसल का पकाव हो सके।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सट्टे और नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। पुलिस अधीक्षक को फोन करते हैं तो वह फोन भी नहीं उठाते हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे क्षेत्र रोजड़ी में हुई थी। वहां एक ट्रोले से दो बच्चों को कुचल दिया गया था और वह मर गये थे। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं वहां पहुंची और जो रोड जाम था उसके लिए कलेक्टर साहब को फोन करके और प्रशासन को बुला करके उसको खुलवाया। बाद में मुझे पता चला दो दिन बाद कि पुलिस अधीक्षक के दबाव में ग्रामीणों पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ऐसी हालत हमारे अधिकारियों की है। राजस्थान में अपराध किस कदर बढ़ रहे हैं, वह हमारे सामने है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि हमारी भामाशाह योजना, जिसको बंद कर दिया गया है, जिससे काफी गरीब लोगों को लाभ मिल रहा था, आज वह उस लाभ से वंचित हैं। डिग्गी अनुदान का पैसा किसानों को राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे काफी किसान मेरे पास रोज आते हैं कि इसका समाधान करवायें। मैं राज्य सरकार से कहूंगी कि जो

(श्रीमती संतोष)

डिग्गियां बना ली गई हैं उनका अनुदान दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में टिड्डी दल के आक्रमण के कारण जो फसलें नष्ट हुई थीं उनका मुआवजा दिया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी देश में और पूरे विश्व में जब हाहाकार मच रहा था, ऐसी विषम परिस्थितियों में राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय गहलोत साहब ने जो कुशल और बढ़िया तरीके से काम किया है, 21-21 घंटे वीडियो कान्फ्रेंसिंग करके 1-1 गांव, शहर, जिले की जो मानिटरिंग की है, जिस प्रकार से यहां जब सदन चल रहा था तो कोरोना की वजह से उसको स्थगित किया। माननीय राहुल गांधी जी ने कोरोना की देश में एंट्री होने से पहले अवगत करा दिया था लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी नमस्ते ट्रम्प करते रहे और मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार गिराने के षड्यंत्र रचते रहे, उसी का परिणाम है कि पूरा देश आज ऐसी विकट परिस्थिति से गुजरा है। गहलोत साहब ने जिस प्रकार से समय से पूर्व लॉकडाउन लगाया और मोदी जी ने लॉकडाउन लगाने से पहले यह विचार नहीं किया कि देश की स्थिति क्या है, राज्य किस प्रकार से काम करेंगे, व्यवस्थाएं बराबर हैं कि नहीं है। हमारे क्षेत्र के मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात और सभी जगह फंस गये और इधर से लॉकडाउन लागू कर दिया। उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं की और न ही उनके खाने-पीने के कोई इंतजाम किये।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को कि राजस्थान रोडवेज की बसें लगाकर अधिकारियों को निर्देशित करके सारे मजदूरों को लाया गया। कोई भूखा नहीं सोये, अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरेगा योजना जो लागू उस समय की थी, जिसको माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी खड्ढा खोदने की स्कीम बोलते थे, उसी नरेगा योजना ने आज राजस्थान के गरीब मजदूरों को सहारा दिया और आज जो केंद्र सरकार का बजट आबंटित हुआ है उसमें नरेगा योजना का बजट गत वर्ष तो इन्होंने किया था 1,11,500 करोड़ रुपये और इस बार इन्होंने 77 हजार करोड़ करके

(श्री रामलाल मीणा)

34.52 परसेंट बजट नरेगा का घटाया है। यह भारतीय जनता पार्टी की मजदूरों के प्रति क्या भावना है, यह दर्शाती है। उस समय सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने गरीब क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए राइट टू फूड जो रोजगार योजना चालू की थी उसी का परिणाम है, आज मजदूरों को सही समय पर रोजगार मिल जाता है। आज उन्होंने नरेगा को धीरे-धीरे बंद करने का काम किया है। आज आपने देखा होगा, अगर राइट टू फूड माननीय मनमोहन सिंह जी के टाइम पर लागू नहीं होता तो आज स्थिति क्या बनती? लोगों की कोरोना काल में भूखे मरने की स्थिति बनती लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि लोग भूखे उठ सकते हैं लेकिन भूखे सोएंगे नहीं। सभी जगह दानदाताओं ने, सभी ने मिलकर जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों की सेवा की है, मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जिस प्रकार से राजस्थान मॉडल की, भीलवाड़ा मॉडल की माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी प्रशंसा की है और पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व ने राजस्थान की महिमा का गुणगान किया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और पूरी सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूं।

आज आपने देखा होगा राजस्थान की सरकार ने जगह-जगह कालेज खोलने का काम किया। मेरे प्रतापगढ़ जिले में भी दो कॉलेज देकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रतापगढ़ की जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और गरीब क्षेत्र के लोगों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ना नसीब नहीं था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जगह-जगह पहले तो जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले और उसके बाद में ब्लाक मुख्यालय पर भी महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले, जिससे गरीब बच्चों को भी बढ़िया तरीके से शिक्षा मिल सके।

आज आपने देखा होगा, राजस्थान के अंदर आवासीय विद्यालय खुले हैं। प्रतापगढ़ में 3 आवासीय विद्यालय मेरे 2 साल के कार्यकाल में खुल चुके हैं, जिनमें 700 बच्चे पढ़ेंगे।

आज नौकरियों के मामले में देख लीजिये, 2013 के भारतीय जनता पार्टी की सभा के भाषण को आप देखें, उसमें हमारे देश के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि, भाइयों-बहनों, अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और मैं प्रधान मंत्री बन जाता हूं तो युवाओं को दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, लेकिन आज जगह-जगह हर डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन करके

(श्री रामलाल मीणा)

नौकरियों को खतम किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को कि सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्तियां कर-कर के कम से कम 80 से 81 हजार युवाओं को नौकरियां लगा दी हैं और कई भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। आने वाले समय में हमारे युवाओं पर ध्यान देते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी जिस प्रकार से भर्तियां कर रहे हैं, आज आपने देखा होगा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि डाक्टर्स की कमी है लेकिन प्रतापगढ़ जिले में कोई डॉक्टर आना पसंद नहीं करता था, डिलीवरी करने के लिए कोई डाक्टर नहीं था, आर्थोपैडिक का कोई डाक्टर नहीं था, एनेस्थीसिया का कोई डाक्टर नहीं था लेकिन मैं चिकित्सा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय पहले रैफरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, जाते ही हाथ देखकर डाक्टर रैफर कर देते थे लेकिन आज स्त्री रोग विशेषज्ञ के 5 डॉक्टर हैं, 2 हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और एनेस्थीसिया के भी डाक्टर वहां हैं और सभी प्रकार से बराबर तरीके से इलाज हो रहा है। राजस्थान के गत बजट में 500 बैड स्वीकृत किये गये और 500 में से 150 बैड प्रतापगढ़ जिले को देकर 150 से डायरेक्ट 300 का हॉस्पिटल किया। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर आपने चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़िया तरीके से काम किया है। आज आदिवासी क्षेत्र के अंदर जहां सुदूर क्षेत्रों में पीएचसी, सीएचसी है, वहां पर भी डॉक्टर्स की व्यवस्था इन्होंने की है।

आज आपने देखा होगा, माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्थान सरकार ने आते ही बड़ी-बड़ी पंचायतों को छोटा करने का काम किया। हमारे आदिवासी क्षेत्र में दूर-दूर गांव हैं, तो 4000 की आबादी की पंचायतें थीं, उनको कम करके 25 सौ की आबादी की पंचायतें की हैं। आज 25 सौ की आबादी की पंचायतें होने के बाद में प्रतापगढ़ जिले में 70 नई पंचायतें और तीन पंचायत समितियां देकर प्रतापगढ़ जिले के आदिवासियों और सम्पूर्ण क्षेत्र के लोगों का जो उपकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के इस उपकार को जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता।

आपने देखा होगा प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जब भी हमारे मेहमान कोई उस क्षेत्र में आते थे, प्रतापगढ़ में आते ही प्रतापगढ़ की सीमा में आते ही लग जाता था कि सड़कें टूटी हुई हैं आटोमेटिक उनकी नींद खुल जाती थी। वहां के जनप्रतिनिधियों को गालियां देते थे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा

(श्री रामलाल मीणा)

कि 70% सड़कों का आपने नवीनीकरण करके काम पूरा कर दिया। यह तो अगर कोरोना नहीं आया होता तो प्रतापगढ़ की सड़कों के ऊपर एक खड्ढा नहीं होता। आज सभी टूटी सड़कों का नवीनीकरण भी किया है।

दूसरी बात आज हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने गत बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, लेकिन आप सबको पता है पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान रात के 12:00 बजे, 1:00 बजे, 2:00 बजे, 3:00 बजे कड़ाके की ठंड में पाणत करता था। उन परिस्थितियों को देखते हुए किसानों की समस्याओं को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिन में लाइट देने की घोषणा की। दूसरी बात, सबसे पहले प्रतापगढ़ में दिन में लाइट देकर के प्रतापगढ़ के किसानों पर और पूरे राजस्थान के क्षेत्र के किसानों पर जो उपकार किया है, 15 जिलों में दिन में लाइट आयी। प्रतापगढ़ में घोषणा होने से पहले राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिन में लाइट की है, 16 नये जीएसएस उन्होंने स्वीकृत किये हैं। 10 जीएसएस का काम चालू हो गया। एक 132 केवी जीएसएस नया चालू किया और तीन 132 केवी जीएसएस को डबल-ट्रिपल कैपेसिटी के किये हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

आज आप काले कृषि कानूनों की बात करते हैं, देश के किसी किसान ने माननीय नरेन्द्र मोदी जी को यह नहीं कहा कि हमारे किसानों के बिल लाए जाएं, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी ने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन कानून लागू किये, इसी तरह माननीय मोदी जी के विचार में भी आया होगा राइट टू अडाणी प्रोटेक्शन, राइट टू अंबानी प्रोटेक्शन नाम पर तीन काले कानून लाए और तीनों काले कानूनों में गरीब, व्यापारी, मजदूर और किसानों का गला घोंटने का काम किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान के किसानों को ध्यान में रखते हुए तीनों कानूनों में सुधार करके विशेष सत्र चलाकर राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा दिया। मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्यपाल महोदय के पास जो हमारे किसानों के कानून पड़े हुए हैं उनको आगे भिजवाइए, उसको पारित करवाइए ताकि कम से कम राजस्थान के किसानों का गला तो नहीं घोंटे।

माननीय राज्यपाल महोदय ने बढ़िया तरीके से एक बात कही, उसमें

(श्री रामलाल मीणा)

एक बात और थी कि क्रूड आयल का भाव अन्तरराष्ट्रीय बाजार में बहुत कम हो गया है, उसके बाद भी केन्द्र सरकार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाये जा रही है। आप सबको पता है जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब बाबा रामदेव जी, अन्ना हजारे, सारे लोग आंदोलन करते थे कि महंगाई खतम करें। उस समय तो कांग्रेस की सरकार ने, प्रधान मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि यह महंगाईजीवी हैं लेकिन आज जिस प्रकार से देश का किसान आंदोलन कर रहा है, उस आंदोलन से घबरा कर मोदी जी कह रहे हैं यह तो आंदोलनजीवी हैं। मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 'जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा परिवर्तन के नारों से।' जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं, यह आंदोलनजीवी नहीं हैं, इस किसान आंदोलन से देश में परिवर्तन आयेगा। जिस प्रकार से बाबा रामदेव जी चुनाव से पहले कहते थे, युवाओं, 40 रुपये वाला पेट्रोल चाहिये या नहीं चाहिये? युवा कहते थे, चाहिये लेकिन वह 40 रुपये का पेट्रोल आज 100 रुपये पार करने वाला है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार में पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हुआ, चाहे कोई-सी भी बैंक हो। अभी विपक्ष के साथी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात की थी। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार और राजस्थान के किसानों को ध्यान में रखते हुए आपने किसानों का भूमि विकास बैंकों और लैम्पस का कर्जा माफ किया और केन्द्र को चिट्ठी भी लिखी थी, अगर मोदी जी भी उस चिट्ठी को मान लेते तो सभी बैंकों का कर्जा भी माफ हो जाता लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। आप सबको पता है 2013 से पहले की भारतीय जनता पार्टी की सभाएं, आपने तो नहीं सुनी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुनी होगी, उसमें माननीय मोदी जी कहते थे, भाइयों और बहनों,...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और मैं देश का प्रधान मंत्री बन जाता हूं तो पहली ही मीटिंग में देश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया जायेगा। आज कहां गये मोदी जी, दूसरी बार आ गये, उसके बाद भी देश के किसानों का एक फूटी कोड़ी कर्जा माफ नहीं किया। विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी, नीरव

(श्री रामलाल मीणा)

मोदी भाग गये, उनके कर्जे डिफाल्ट हो रहे हैं लेकिन देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है।

आदिवासियों को नक्सली कहने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इस सदन में आजकल एक माननीय सदस्य बहुत सिंसियर हो गये हैं क्योंकि उनको अभी पार्टी ने बहुत बड़ी नसीहत दी है, नहीं तो हर सदन में, हर सत्र में वह बहुत उछलकूद करते हैं। दक्षिण राजस्थान में आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में वह आये और हाबड़तोड़ में एक बयान उन्होंने जारी कर दिया कि उदयपुर संभाग के आदिवासी तो नक्सली हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं डिस्टर्ब हो गया इसलिए वह बयान दे दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वह आदिवासी माफ नहीं करेगा जो आदिवासियों को नक्सली कहते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस आंदोलन में युवाओं ने जो मांगें रखी थीं, उन मांगों को पूरा किया जाये। जिस प्रकार से अधिकारियों ने उन आदिवासियों पर, आदिवासी युवाओं पर, कर्मचारियों पर जो गलत तरीके से केस दर्ज किये, उन केसों को भी वापस लिया जाये और आदिवासियों की जो मांग हैं, उन मांगों को भी पूरा किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के काम हुए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): लेकिन माननीय अशोक गहलोत साहब ने भ्रष्टाचार रोकने का जो काम किया है, उसका ताजा उदाहरण आप सबको देखने को मिल रहा है। आज आईपीएस, आईएएस और आरएएस भी भ्रष्टाचार के काम में जेल में जा रहे हैं, यह इसी की वजह से है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): आपने देखा होगा आज एक सदस्य कह रहे थे कि केस बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री

(श्री रामलाल मीणा)

जी ने हर थाने में स्वागत कक्ष खोलकर हर फरियादी के लिए जो रास्ते खोले हैं, एसपी आफिस में भी कार्यवाही सुनने के लिए बात की है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुतबहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूं और राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल के श्रीमुख से जो बुलवाया गया है वह असत्य है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार से आपने कोरोना महामारी का जिक्र किया, कोरोना महामारी में जो लोगों के साथ हुआ, मैं प्रशासन को, पूरी टीम को और भामाशाहों को धन्यवाद देता हूं। सरकार में यह था कि कोई भूख से नहीं मरे। यह तो भामाशाहों को धन्यवाद है कि हमारे सारे भामाशाह, स्वयंसेवी संस्था की वजह से भूख से कोई नहीं मरा। ऐसे समय में आप लोगों ने क्या किया, अन्नपूर्णा रसोई योजना को अगर बंद नहीं किया होता तो कम से कम आने-जाने वाले लोगों को चलता-फिरता भोजन तैयार मिलता, कम से कम वह नाश्ता करते। सभापति महोदय, सरकार को शर्म नहीं आई, ऐसे मौके पर बंद किया जब प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे थे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को देखो, उन्होंने सारी बसों का किराया वहन किया, बड़ी मुश्किल से अपने आने-जाने की व्यवस्था करके आए? कोरोना महामारी में भी आप कह रहे हो कि सरकार घाटे में है। क्या सरकार घाटे में है? कोरोना महामारी में कौनसा आपने बजट खर्च किया। सभापति महोदय, सरकार ने कुछ खर्च नहीं किया, उलटा एमएलए फंड का जो पैकेज था उसमें भी इन लोगों ने राजनीति की। खुद के खजाने से किया होता और कहते हैं कि शिक्षा में हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। शिक्षा का क्या आमूलचूल परिवर्तन किया? आप जनजाति क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो जनजाति क्षेत्र में अगर 10वीं तक स्कूल है, जैसे मैं पाबा की बात करूं, 4 तारीख को एक प्रधानाध्यापक लगाया गया है और 10वीं तक पूरी स्कूल बिना अध्यापकों के चल रही थी, खाली दो पैराटीचर्स लगे हुए थे। दो पैराटीचरों के भरोसे चल रही थी। क्या आमूलचूल परिवर्तन करेंगे? शिक्षा का मामला पूरे जनजाति क्षेत्र में बिलकुल ठप है। कहीं एक अध्यापक है तो कहीं दो अध्यापक हैं। पहले

(श्री समाराम गरासिया)

शिक्षा अधिकारी को पावर दिये जाते थे डेपुटेशन करने के लेकिन वह पावर भी आप लोगों ने छीन ली है, ताकि सरकार खुद स्थानांतरण करे।

सड़कों के मामले में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार में सड़कों का जाल बिछा था। गौरव पथ देकर पंचायतों का गौरव बढ़ाया। नगरपालिकाओं में ढाई किलोमीटर की सड़कें दीं। आप लोगों ने तो कहा कि मिसिंग लिंक सड़क देंगे, गौरव पथ की जगह विकास पथ देंगे, दो साल हो गये हैं, क्या किया? आपने कहा कि हम पूर्व सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। पूर्व सरकार की कौनसी योजना आपने चालू रखी है? 'शुभलक्ष्मी' योजना जिसमें शादी के लिये 50 हजार रुपये मिलते थे, वह भी आप लोगों ने बंद कर दी। आप बार-बार कहते हैं सिलिकोसिस बीमारी में हम पैसे देते हैं, सिलिकोसिस बीमारी में पैसा देने की योजना शुरू किसने की, यह भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने लागू की। आप लोग वाहवाही लेते हो, नकल करते हो, नकल करके आप सरकार में आओ और बड़ी-बड़ी घोषणा करते हो कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, थोड़ी बहुत शर्म करो। पूर्व सरकार में 50-50 हजार पंचायत मुख्यालय जाकर माफ किये थे। ऐसी सरकार को धन्यवाद देना चाहिये लेकिन पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि यह सरकार वादे कुछ करती है और घोषणा अलग करती है।

जिस प्रकार से शिवगंज, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्यों ने जिक्र किया, लीलूड़ी बड़ली के शहीद स्मारक का। वह तो मैं दो साल से चिल्ला -चिल्लाकर थक रहा हूं कि लीलूड़ी बड़ली के शहीद स्मारक के तीन करोड़ कहां गये? वहां तो सिर्फ कुत्ते ही पेशाब करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में लीलूड़ी बड़ली का कोई उद्धार होगा। जिस प्रकार से अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी, यह सब कागजों में ही रहने वाला है। पूर्ववर्ती सरकार ने वह काम कर दिखाया, घोषणाएं तो नहीं कीं, लेकिन काम करके दिखाया। जिस प्रकार से हमारी सरकार में कालेज स्वीकृत हुई, वह कालेज अभी भी यूं की यूं ही पड़ी हुई, प्राइवेट बंगलों में कालेज चालू है।

मेडिकल कालेज के संबंध मैं यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की थी। 60:40 का रेशो है, इसमें भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम न करें, क्योंकि यह केंद्र सरकार की योजना है।

(श्री समाराम गरासिया)

ये किसानों की बात करते हैं। इनको शर्म करनी चाहिए, किसानों का आंदोलन, प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किसानों के लिए जो कुछ किया, जिस प्रकार से 26 जनवरी को लाल किले पर घटना हुई, क्या वे किसान थे? कांग्रेस वाले हमेशा कहते हैं कि हम किसान थे। लाल किले पर 26 जनवरी को तिरंगे का जो अपमान किया, क्या उसे भारत की जनता सह सकेगी? आप कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। राष्ट्रवादी होती तो इस प्रकार से बहला-फुसलाकर किसानों के साथ में, कई वीडियो वायरल हुए हैं कि हमको तो बुलाकर ले जाते हैं, हम किसान नहीं हैं। हमारे भी वहां नेता हैं। वे शर्मिंदगी तो जरूर महसूस करते हैं कि वास्तव में आपकी सरकार कानून तो सही लायी है, पर हम तो क्या करें, हम तो आखिर में 'जिसकी खाते हैं बाजरी, उसकी ही बजाते हैं हाजिरी' वे कहते हैं, मजबूरी है, क्योंकि ये सत्तापक्ष में बैठे हैं।

ये जोर-जोर से वाहवाही करते हैं, लेकिन क्या किया? दो साल में कुछ भी नहीं किया। कुछ किया होता तो अभी भाषण में बताते। प्रदेश की जनता तो जानती है कि ये करने वाले कुछ नहीं हैं, जिस प्रकार से ये तीन साल बाकी बचे हैं, यह तीसरा बजट हो गया, दो बजट और बाकी हैं। पंचायती राज के चुनाव, इंतजार करते रह जाएंगे, बाकी कुछ होने वाला नहीं है।

हमारी सरकार में पशुपालकों का भी ध्यान रखा था। हर वर्ग को चुना था। ऊंट को राज्य पशु घोषित करके, एक ऊंट के प्रसव के दौरान दस हजार रुपये दिये जाते थे, वे भी आपने बंद कर दिये। आपने कुछ दिया ही नहीं। बिजली का बिल आता है तो करंट आ जाता है। कम से कम इतनी तो शर्म करते कि आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। 833 रुपये जो हर महीने माफ होते थे, कम से कम वे तो माफ करें। आपने जो स्टेट हाईवे पर टोल चालू किया, वह कम से कम नहीं चालू करना था, फिर भी आपने चालू कर दिया। जिस प्रकार से आपने हमेशा कटौती की है और जिस प्रकार से हमारी पूर्ववर्ती सरकार में घटना होती थी, जिसमें कोई पानी में बह जाता था तो पांच-पांच लाख रुपये सरकार की ओर से दिये जाते थे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि सोलर प्लेट लगे थे, वे सोलर प्लेट कम से कम मेरे आबू रोड क्षेत्र में 18 बैटरियां विस्फोट हुईं निम्न कंपनियों से लायी गयी थीं। लोगों के झोपड़े जले।

(श्री समाराम गरासिया)

कलेक्टर साहब के पास भी लोग गये थे। कम से कम उन लोगों को सहयोग राशि भी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि गरीब के पास पहनने के लिए जो कपड़े थे, वे भी जल गये, उनके खाने का अनाज जल गया। इसमें कौन दोषी है, उनके खिलाफ कार्यवाही भी करनी चाहिए।

श्री सभापति: कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): हमारी पूर्ववर्ती सरकार में यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी के समय पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना में जिनको लाभ दिया और उसमें जो वंचित रहे हैं, कम से कम उसमें हर घर को कनेक्शन मिले। लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहें। वह हमारी पूर्ववर्ती सरकार की देन थी, लेकिन आपकी सरकार में ऐसी कोई योजना नहीं है कि आम जनता के साथ में काम आए और आम जनता के सहयोग में रहे। ऐसी कोई योजना नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने समय दिया।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज दो दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। इसमें पक्ष में व विपक्ष में सब अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। मैं भी इस अभिभाषण के समर्थन में बात करूंगा, क्योंकि इसमें 138 पाइंट हैं और वे सत्य एवं ईमानदारी से लिखे गये हैं। माननीय राज्यपाल के मुख से जो शब्द निकले हैं, वे सरकार के और इस विधान सभा में हमारे 200 विधायक बैठे हैं, उन सबको समझ में आ रहा है कि ये सत्य बातें आदरणीय राज्यपाल महोदय के मुख से सुशोभित हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी में प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश में माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा अभिभूत प्रयास किये गये हैं। यह आप लोगों ने भी देखा है। प्रतिपक्ष के विधायक बोल रहे थे कि आपके प्रबंध ठीक नहीं रहे। मुख्य मंत्री जी पहली बार बाहर गये हैं। ये बातें सोचने की नहीं हैं। जब कोरोना चल रहा था तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने वी.सी. के द्वारा चाहे बीजेपी का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे कर्मचारी हों, चाहे

(श्री गोपाल लाल मीना)

एनजीओ हो, उन सब से बात की है। उन्होंने प्रबंध करवाया और ऐसा प्रबंध करवाया कि भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश ने बनाया। पूरे देश ने मॉडल बनाकर राजस्थान की प्रशंसा की, आदरणीय मुख्य मंत्री जी की भारत सरकार ने प्रशंसा की कि इन्होंने अच्छा प्रबंध किया। आप लोग सब यहां इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि जैसे राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ। आप लोगों ने भी काम किया, आप लोगों को भी धन्यवाद है। जिन लोगों ने कोरोना में काम किया, उन लोगों को भी। कोरोना की इस महामारी में सब लोगों ने मिलकर एक साहस दिखाया और कोरोना का प्रबंध जिस प्रकार से सरकार ने किया और सरकार ने हर व्यक्ति के भूखा नहीं रहने का जो वादा किया था, निश्चित रूप से हम, हमारे क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, सब विधायकों ने अपने कोटे से भी पैसे दिये, सरकार ने भी पैसे दिये और सब लोगों को किट पहुंचाने का काम किया ताकि कोई भूखा नहीं रहे। जितने भी तमाम एनजीओ हैं, उन लोगों ने भी इस महामारी में सहयोग किया।

मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जब देश के सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो सबको खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। कोरोना के बारे में समझता हूं कि विपक्ष के लोग कुछ बोलने लायक नहीं हैं। फिर भी जिस प्रकार से आज कोरोना के साथ-साथ देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का चल रहा है, किसानों के मुद्दे पर अभी मेरे से पूर्व साथी बता रहे थे कि किसानों को बहकाकर बैठाया जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया ऐसा चल गया कि आप किसी को भी सोशल मीडिया पर कुछ भी बुला सकते हैं। बाकी जो किसान हैं, वे किसान अपने आप अपने हक के लिए, जो तीन काले कानून केंद्र सरकार ने पास किये हैं, उनके विरुद्ध में हैं। तीनों काले कानूनों को जिस प्रकार से इस देश के किसान, जो कि हमारे अन्नदाता हैं, आज इस देश में 85 प्रतिशत किसान हैं और उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। सरकार भूमि अधिग्रहण बिल भी लेकर आयी थी, लेकिन हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया और केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल भी वापस लेना पड़ा। आपको पता है कि इस देश में ईस्ट इण्डिया कंपनी आयी थी, उसने भी इसी प्रकार से काम किया था, जिस प्रकार से ये तीन काले कानून हमारे किसानों पर करेंगे। ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। चाहे मजदूर हों, किसान हों, छोटे व्यापारी हों, हर व्यक्ति के लिए ये बिल नुकसानदायी है। आप लोगों को इस सदन में मैं

(श्री गोपाल लाल मीना)

यह बात बताना चाहूंगा कि किसान जिस प्रकार सड़कों पर बैठे हैं और सरकार हिटलरशाही की तरह इनकी बात नहीं सुन रही है, यह अच्छी बात नहीं है। सरकार किसानों की बात सुने और किसानों की जो मांग है, तीन काले कानूनों की, उनको सरकार को वापस लेना चाहिए।

प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत सारे वादे किये थे कि किसानों की आय हम दुगुनी कर देंगे, किसानों के लिए यह कर देंगे, किसानों के लिए वह कर देंगे। भाषण में तो यह भी कहते थे कि 15 लाख रुपये दे देंगे और इस देश को भी बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और इन किसानों की बात को मानकर, प्रधान मंत्री जी इनकी बात सुनें। हिटलरशाही नहीं रहें। हिटलरशाही रहेंगे तो निश्चित रूप से इस देश के किसान, जो आज 70 दिन से भी ज्यादा समय हो गया, सड़कों पर इस कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। ये किसी के बहकाने या किसी के कहने से वहां नहीं बैठे हैं। दो दिन से मैं सुन रहा हूं, किसानों के लिए ऐसी बात करना अच्छा नहीं है क्योंकि आप भी किसान और हम भी किसान। तमाम 85 परसेंट लोग किसान हैं इस देश के। उनकी बात तो सुननी चाहिए। आज तक इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसानों की कोई बात नहीं सुन रहा है। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद में यह पहला इतना बड़ा आन्दोलन किसानों का है। यह शर्म की बात है कि इस देश के किसान सड़कों पर बैठे हैं। यह हमारी सोच नहीं है। हमारी यह सोच होनी चाहिए कि किसान सड़कों पर नहीं बैठें। जिस प्रकार किसानों के साथ अभी 26 जनवरी को जो काम हुआ, आप लोगों को भी पता है कि देश के झंडे के साथ में झंडा पहनाया गया, हम भी चाहते हैं उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? इसको दबाना नहीं चाहिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है, उनके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून को काम करना चाहिए व सरकार को काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का इस देश से वादा किया था, मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकार इस देश की संस्थाओं को प्राइवेट सैक्टर में देने का काम कर रही है, बेरोजगारी को और बढ़ाने का काम कर रही है। रेलवे को प्राइवेट, एयरलाइंस को प्राइवेट, बीएसएनएल को बंद करना, एलआईसी को बेच रहे हैं। बीएसएनएल जैसी संस्था है, जिसको हमारे

(श्री गोपाल लाल मीना)

देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर अब तक चलाया और देश को अच्छी सेवाएं दीं, उस संस्था को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी जो मशीनरी है, वह जियो कंपनी के काम आ रही है। निश्चित रूप से इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों ने 60 साल में इन संस्थाओं को खड़ी किया और इन संस्थाओं को खड़ी इसलिए किया था कि देश आगे बढ़े, देश आगे जाए, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री, हमारी भारत सरकार जिस प्रकार से इन संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है, निश्चित रूप से यह हमारे लिए दुर्भाग्य होगा।

बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रेलवे ही एक ऐसी संस्था है जो सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करती है, जब वह प्राइवेट सैक्टर में चली जाएगी तो सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। संस्थाएं जब प्राइवेट सैक्टरों में चली जाएंगी तो आरक्षण का भी महत्व खतम हो जाएगा। जिस प्रकार से दलितों के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट सैक्टर में जाएंगे। आज गांवों में बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट सैक्टर में लिया जाएगा। जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे कहां रोजगार ले पाएंगे?

मैं इस सदन में यह भी बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी के साथ में एक और काम हो रहा है कि यूपीएससी, जिसमें आईएएस भर्ती किया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इतना इंटेलीजेंट होना पड़ता है कि वह एक बार में, दो बार में, तीन बार प्रयास करने से आईएएस बन पाता है, लेकिन आज हमारे देश की सरकार जिस प्रकार से 15 आईएएस सीधी भर्ती ले रही है, यह उन बच्चों के लिए बेरोजगारी का काम होगा। वह जो भर्ती ले रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर बना रहे हैं। यह बेरोजगारी नहीं है तो और क्या है? अपने चहेतों को, अपनी पार्टी के लोगों को, अपने लोगों को आईएएस बनाने का काम कर रही है। जो हमारी सबसे विश्वसनीय संस्था है यूपीएससी, उसमें भी घोचा करने का काम किया है। मैं इस विधान सभा में यह बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी, किसानों के साथ में धोखा और जितने भी वादे किये, उन सबमें फेल होते जा रहे हैं।

(श्री गोपाल लाल मीना)

सभापति महोदय, आज पैट्रोल के दाम की बात कर रहे हैं। 60 साल की बात कर रहे हैं। 60 साल में इस देश में पैट्रोल-डीजल के भाव 65 रुपये, 70 रुपये से ज्यादा नहीं हो पाये जबकि उस समय 140 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड आयल था।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): आज 45 रुपये प्रति बैरल क्रूड आयल है तो आप अंदाज लगा लो कि 2013-14 में इतना महंगा क्रूड आयल होने के बाद भी 70 रुपये से ज्यादा पैट्रोल-डीजल का भाव नहीं बढ़ा। लेकिन आज जब 45 रुपये से 50 रुपये लास्ट होगा, इसके बावजूद भी 100 रुपये लीटर पैट्रोल-डीजल मिलने का काम इस सरकार में हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे बुरी बेरोजगारी, इससे बुरी महंगाई क्या होगी?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, पैट्रोल-डीजल की बहुत बात हो रही थी कि हमारे 60 साल में 70 रुपये और आपके 6 साल में 30 रुपये बढ़ा दिये। आप यह अंतर देख लें कि सरकार ने 60 साल में क्या किया और आपके 6 साल में क्या किया? ये दूरी आप लोगों की और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में रही है कि महंगाई आपके कितनी हो रही है और हमारे कितनी थी। बैलेंस करके हमारी सरकारों ने चलाया। किसानों के लिए कर्जा माफ करने की बात अभी प्रतिपक्ष के सदस्य बोल रहे थे जब हमारी मनमोहन सिंह जी सरकार थी, उस समय देश में 85 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया था। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को भी यह सोचना चाहिए और देश के किसानों के लिए कर्जा माफ करना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। श्री गुरदीप सिंह।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): इस अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका मिला, मैं इसका पुरज़ोर समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री गुरदीप सिंह (अनुपस्थित)। श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से जो भाषण करवाया, उनके विरोध में मैं बोल रहा हूं। मेरे

(श्री जगसी राम)

से पूर्व वक्ताओं ने और मैंने जो पूरी पुस्तक पढ़ी है, उसमें पूर्ववर्ती सरकार का दो साल का जिक्र किया है। सरकार ने एक साल तो महामारी कोरोना का बहाना लेकर निकाल दिया और इन्होंने कोरोना के बहाने वाहवाही ली है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र रेवदर, आबू रोड दोनों गुजरात सीमा से लगते हुए है। प्रवासियों की बात कही है, हमने उस समय मुख्य मंत्री जी से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमने पूरे बोर्डर्स पर व्यवस्था करवा रखी है, साधनों की व्यवस्था करवा रखी है। प्रवासियों ने जिस प्रकार से कठिनाई व कष्ट झेला है, मैं हमारे कांग्रेसी साथियों से कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो भी प्रवासी थे, वह आपको निश्चित तौर पर बताएंगे। मैं विभिन्न संगठनों के व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। अपने बलबूते पर आबू रोड व रेवदर के व्यापारियों ने गुजरात व मावल बोर्डर पर प्रवासियों की खाने की, पीने की व उनको वहां तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि महामहिम के अभिभाषण में ज्यादातर यही बताया है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहूं क्योंकि समय मात्र दस मिनट है और आप अभी मुझे बैठा देंगे।

मैं रेवदर क्षेत्र की बात कहूं, पीएचसी और सीएचसी में एक-एक, दो-दो डाक्टर ही हैं। हमारे क्षेत्र में डाक्टर्स के अलावा दूसरे पद हैं वह भी सारे रिक्त हैं। रेवदर व मंडार की एम्बुलेंस तक खराब पड़ी हुई है। यह सरकार की बात कर रहे हैं कि हमने यह-यह काम किए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारा एमएलए ग्रांट का एक करोड़ रुपया हास्पिटल के अंदर मशीनरी के लिए रोका था, एक रुपया भी पूरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर, एक भी हास्पिटल में नहीं लगाया गया है। जब भी मैं सीएमएचओ साहब को पूछता हूं, कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार से आएगा जब वहां मशीनरी लगाएंगे। एक साल हो गया, कोरोना भी निकल गया, मशीनरी आज तक नहीं लगी।

सभापति महोदय, सड़कों की बात कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में सारी सड़कें बनी हुई थीं, उनकी वाहवाही लेने के लिए, सरकार आने के बाद उन्होंने बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाए, उद्घाटन किए। वर्तमान में अभी जो कुछ सड़क के काम चालू थे, वह सारे काम ठप पड़े हैं, आधे-अधूरे पड़े हुए है काम बंद हैं, क्योंकि ठेकेदार के खाते में एक रुपया भी नहीं डलवाया गया। उन्होंने काम

(श्री जगसी राम)

बंद कर दिया। उदाहरण के तौर पर रेवदर से जीरावल के बीच हमारी एक धार्मिक सड़क है, वहां स्वीकृत काम चालू है। प्रभारी मंत्री जी भी अभी यहां थोड़ी देर पहले विराजमान थे, वह काम भी बंद पड़ा है। बड़े-बड़े खड्ढे हैं, आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। यह सिर्फ झूठी वाहवाही लूटते हैं। डीएमएफटी का भारतीय जनता पार्टी के समय का पैसा पड़ा था। मंत्री जी ने आनन-फानन में, कुछ एरिया में मनमर्जी से घोषणा करके वह सड़क दी है। मैं कहना चाहूंगा कि डीएमएफटी वाली जो सड़के हैं, वहां सेलवाड़ा माइंस से रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अंदर, ज्यादातर माइनिंग हो रही है, वहां का पैसा वहां पर लगे। मकावल वाली सड़क जो गुजरात निकलती है, वहां एक-एक फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, एक रुपया भी वहां नहीं दिया। रेवदर से सेलवाड़ा रोड पर जो महाविद्यालय बना हुआ है, वहां पर सड़क स्वीकृत की है, वहां छोटी सड़क बनने से नहीं बैठेगा, कम से कम 8-10 इंच सड़क बनेगी, सीमेंट की पक्की सड़क बनेगी तो वह मजबूती देगी।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कहना चाहूंगा। अभी मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे। शिक्षा के अंदर पूर्ववर्ती सरकार में 12वीं तक की स्कूल प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनी थी। सरकार बदलने के बाद पूरे रेवदर और सिरोही जिले के अंदर ज्यादातर स्कूलें खाली पड़ी हैं। अपने-अपने गृह ज़िले में ट्रांसफर कराकर वह पहुंच गये।

घोषणा पत्र में खेल मैदान के लिए बताया गया था। खेल मैदान के लिए एक भी ग्राम पंचायत तक, क्योंकि वहां गोचर है या बिलानाम है, सरकार उसको नियमों में बदलकर स्कूलों की चारदीवारी के लिए, खेल मैदान के लिए एक रास्ता निकाला, ताकि आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा।

महाविद्यालय के अंदर स्टाफ की कमी है। मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे ट्राइबल आदिवासी एरिया है, वहां पर आबू रोड क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी के समय मां-बाड़ी खोली गई थी, आज की तारीख में सारी बंद पड़ी थी। दो साल के कार्यकाल में, इस सरकार के आने के बाद एक स्कूल भी नहीं खोली गई है। यह हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं यह सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा।

विद्युत में बिलों के भाव आसमान छू रहे हैं। तीन महीने के बिल माफ करने का वादा किया गया था कि कोरोना के समय तीन महीने के बिल

(श्री जगसी राम)

नहीं लेंगे, अभी तुरंत प्रभाव से जोड़े हैं। सबके कनेक्शन काट रहे हैं। किसी की वीसीआर भरी जा रही है। इसके बाद दीनदयाल योजना महत्वपूर्ण योजना थी। गांवों के अंदर किसानों, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने व्यवस्था की थी, चार ग्रुप के अंदर बिजली की व्यवस्था के लिए, वह स्कीम बंद करने के बाद आज गांवों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि इस योजना को वापस चालू करेंगे तो आने वाले समय में ग्रामीण जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यह सिंगल फेज वाले कनेक्शन वापस जोड़ें। क्षेत्र के अंदर ढीले तार हैं। सिरोही के अंदर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तार झूल रहे हैं लेकिन अधिकारी कागजों के अंदर खानापूर्ति करके आगे तक आंकड़े दे रहे हैं। हम सरकार की जानकारी में लाना चाहेंगे कि इनको भी मद्देनजर रखते हुए, जन हानि नहीं हो, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

मैं पेयजल के बारे में कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में गर्मियों के अंदर स्कीम बनती है, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सिंचाई विभाग और दोनों में, पूर्ववर्ती सरकार ने इर्रिगेशन, एनिकट, एमआई टैंक बांधे थे, फूटे हुए हैं एक भी आज तक रिपेयर नहीं हुआ। कोरोना के समय मुख्य मंत्री जी ने जिला कलेक्टर महोदय को खुद को अवगत करवाया कि प्रत्येक विधायक को 25 लाख के ट्यूबवैल और हैंडपम्प, परन्तु आज तक एक भी नहीं लगाया गया। सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। सामने वाले भी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी नहीं हुए। इन बातों को ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता है।

मैं सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के लिए सम्पूर्ण खसरा नम्बर एक को देखते हुए खेत के चारों तरफ यदि तारबंदी की स्कीम को सब्सिडी के माध्यम से जोड़ा जाए, काश्तकार पूरी रात जगते हैं क्योंकि जंगली सूअर, जंगली जानवर काश्तकार के खेतों को डेमेज कर देते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि तारबंदी ज्वाइंट, काश्तकार के लिए यदि एक ही खसरा के लिए चारों तरफ से की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।

अभी सामने से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि तहसील को ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन तो किया है लेकिन तहसील के अंदर स्टाफ नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर पटवारियों को, तीन-तीन, चार-चार एक-एक को राजस्व ग्राम पंचायत

(श्री जगसी राम)

दी है, इन सबको देखें तो बहाना निकालते हैं कि आज हम वहां गये हैं, आज वहां गये हैं, तो काश्तकारों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वाहवाही लेना बहुत आसान है लेकिन मैं समझता हूं कि धरातल पर जाकर आप लोगों ने मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया।

अभी मेरे से पूर्व कुछ साथी प्रधान मंत्री जी के बारे में अलग टाइप से बोल रहे थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि मोदी जी आने के बार इस देश और प्रदेश में, किसानों के अंदर, आम जनता के, कांग्रेसियों ने 60 साल तक इनको गिरवी रख रखा था, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का शासन आने के बाद में सबको एक जागृति का रूप मिला है। जनता को एक अच्छे तरीके से जीने का मौका मिला है।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था के बारे में अभी हम लोगों ने अच्छा काम किया, वो किया, वो किया लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे आबू रोड और रेवदर वाले क्षेत्र में जो घटना हुई पुलिस के ऊपर अपराधियों के द्वारा, गुंडों के द्वारा फायरिंग हो रही है। कई लोग ऐसे है जिनको गाड़ियों में बैठाकर शह दी जाती है।

श्री सभापति: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे सोमवार, दिनांक 15 फरवरी 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

मावली की जनजाति बस्तियों में आवश्यक सुविधाएं

60. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मावली के गांवों की कितनी जनजाति बस्तियों में सामुदायिक भवन, पाइपलाइन, सड़क व विद्यालय भवन नहीं हैं? सरकार उक्त जनजाति बस्तियों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मावली के अनुसूचित क्षेत्र के 21 गांवों में सामुदायिक भवन, 31 गांवों में पाइपलाइन, 17 गांवों में सड़क निर्माण तथा 5 गांवों में विद्यालय भवन नहीं हैं। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र मावली के गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 47 गांवों में सामुदायिक भवन, 52 गांवों में पाइपलाइन, 30 गांवों में सड़क उपलब्ध नहीं है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। विद्यालय भवन समस्त में उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र मावली के गांवों की जनजाति बस्तियों में सामुदायिक भवन, पाइपलाइन, सड़क व विद्यालय भवन की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता, कार्य की उपादेयता व क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्राथमिकता का निर्धारण कर उचित कार्यवाही की जाती है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अन्तर्गत राज्य में निवेश

62. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के पश्चात् कौन-कौनसे औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि के उद्योग स्थापित हुए हैं? औद्योगिक क्षेत्रवार निवेश का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला झुंझुनूं के कौन-कौनसे औद्योगिक क्षेत्रों में उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि के उद्योग पंजीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत उद्योग स्थापना के पश्चात् देय परिलाभों हेतु आवेदन करने वाले स्थापित उद्योगों में हुए निवेश के विवरण की औद्योगिक क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट "अ" पर सलंग्न है।

(2) जिला झुंझुनूं में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत निम्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रस्ताव (स्थापना से पूर्व देय परिलाभों हेतु) प्राप्त हुए हैं-

औद्योगिक क्षेत्र	**इकाई का नाम**	**निवेश (लाख रुपये में)**
चिड़ावा	मै. कंचन एन्टरप्राइजेज	50.00
	मै. गोयल इण्ड.	140.00
	मै. शुभलक्ष्मी इण्ड.	210.00
	मै. मंगल मूर्ति चिलिंग सेन्टर	250.00
		650.00

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

केबल नगर में संचालित फैक्ट्री

63. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा झालावाड़ मार्ग पर केबल नगर फैक्ट्री किस वर्ष में स्थापित हुई थी व कितने वर्ष चलने के बाद बंद हो गई? किस व्यक्ति या समूह ने उक्त केबल नगर की फैक्ट्री को खरीदा है? खरीदने वालों के नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फैक्ट्री में किस प्रकार की वस्तु का निर्माण होता है तथा प्रतिवर्ष कुल कितना उत्पादन होता है तथा सरकार को कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है?

(3) उक्त फैक्ट्री कितनी भूमि पर लगी हुई है तथा उक्त को पानी की आपूर्ति कहां से होती है?

उत्तर

(1) कोटा झालावाड़ मार्ग पर केबल नगर में ओरियन्टल पावर केबल लिमिटेड नामक फैक्ट्री वर्ष 1963 में स्थापित हुई थी। उक्त फैक्ट्री 23 वर्ष चलने के बाद बन्द हो गई और माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा उक्त कम्पनी को दिनांक 01-03-1990 को रूग्ण घोषित किया गया था। उक्त फैक्ट्री को किसी व्यक्ति या समूह द्वारा नहीं खरीदा गया है। जिस कम्पनी द्वारा यह स्थापित थी उसी कम्पनी द्वारा वर्तमान में भी संचालित है। वर्तमान में कम्पनी के निदेशक निम्नानुसार हैं:-

1. श्री हेमचन्द्र छाजेड़
2. श्री मुकेश कसेरा
3. श्री आशीष माहेश्वरी
4. श्री सिद्धार्थ जैन
5. दिव्या रिजवानी

(2) उक्त फैक्ट्री में वर्तमान में ए.ए.सी. ब्लाक्स, पैनल, अरीफिनिश, ओरीफिक्स तथा फर्नीचर का निर्माण होता है। उक्त कारखाने की उत्पादन क्षमता 300000 क्यूबिक मीटर है तथा उक्त फैक्ट्री से वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक कुल राजस्व राशि रुपये 1,55,99,426/- सरकार को प्राप्त हुई है।

(3) कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा 371 एकड़ भूमि की लीज डीड

(उद्योग मंत्री)

निष्पादित की गयी थी। पानी की आपूर्ति 1986 से पूर्व स्थापित पानी के स्रोतों से होती है।

लघु उद्योग मंडल समिति बालोतरा के प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में लम्बित आवेदन

64. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा में लघु उद्योग मंडल समिति द्वारा एक सौ छह इकाइयों के समिति के माध्यम से रा.रा. प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 7 जिगर की कनेक्टिविटी हेतु आवेदन विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त के लंबित रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त इकाइयों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(स्थगित)

सीकर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना

65. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर में कहां-कहां औद्योगिक क्षेत्र कब-कब विकसित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण करने हेतु जिला कलेक्टर को रीको द्वारा लिखा गया है। उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्ताव का निगम स्तर पर परीक्षण करवाया जाकर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि

(उद्योग मंत्री)

उपयुक्त पाये जाने पर भूमि का आरक्षण/आबंटन कराने हेतु लिखा जायेगा तथा भूमि आबंटन के बाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना

66. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2020-21 के बजट में उक्त के लिए अठारह करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो उक्त मद में अब तक कितना व्यय हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की अनुपालना में दो राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय केकड़ी-अजमेर एवं जोधपुर में स्थापित किये जा रहे हैं। वित्त विभाग द्वारा दोनों महाविद्यालय खोलने की सैद्धान्तिक सहमति आई.डी. क्रमांक 152000702 दिनांक 31.08.2020 द्वारा जारी करने के पश्चात् इस विभाग द्वारा महाविद्यालय खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में दोनों महाविद्यालयों पर लगभग 18 करोड़ रु. खर्च संभावित होने का उल्लेख किया गया है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्येक महाविद्यालय हेतु 50-50 लाख रुपये की राशि प्रावधित की गई है।

रामगंज मण्डी के भवन विहीन स्वास्थ्य केन्द्र

67. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्र हैं, जिनके भवन नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन विहीन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(3) क्या यह सही है कि कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनसे कभी भी जनहानि हो सकती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों की मरम्मत व नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य कार्मिक कार्यरत नहीं होने अथवा अन्यत्र लगे होने से बंद हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां पर स्वास्थ्य कार्मिक कार्यरत नहीं हैं? केन्द्र के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन सीएचसी, पीएचसी, सब-सेंटर, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं एनयूएचएम के अधीन 1 अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में भवन विहीन 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एनयूएचएम के अधीन 1 अबरन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माणाधीन हैं। 11 भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 7 उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि उपलब्ध है, जिनके निर्माण हेतु आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा। शेष 4 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन किये जाने के पश्चात् वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नही है। 23 उप स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत योग्य एवं 3 उप स्वास्थ्य केन्द्र जर्जर अवस्था में हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

जी हां। उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की मरम्मत/नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र क्रमश: देवली कलां एवं गादिया पर प्रसाविका के पद रिक्त हैं, परन्तु उक्त दोनों उप स्वास्थ्य केन्द्र बन्द नहीं हैं, क्योकि उप स्वास्थ्य केन्द्र, आलोद तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लखारिया पर पदस्थापित प्रसाविका अपने कार्य के साथ-साथ क्रमश: उप स्वास्थ्य केन्द्र देवली कलां एवं गादिया पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्य सम्पादित कर रही हैं।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खीमच एवं अरनियांकलां पर कार्यरत प्रसाविकाओं को कोविड-19 वैक्सीन के कार्य सम्पादन हेतु क्रमश: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विज्ञान नगर, कोटा एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नान्ता कोटा में कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है। उक्त दोनों केन्द्र खीमच एवं अरनिया कलां पर क्रमश: उप स्वास्थ्य केन्द्र हिरियाखेडी एवं रिछडिया पर कार्यरत प्रसाविकायें अपने कार्य के साथ-साथ उक्त दोनों उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्य सम्पादित कर रही हैं।

विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के अन्तर्गत पंचायत समिति लाडपुरा एवं खैराबाद का क्षेत्र आता है।

विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में नॉर्म्स अनुसार 59 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 67 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में खोला/क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(6) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में आगामी वित्तीय वर्षो में गुणावगुण व आवश्यकता के आधार पर जनता क्लिनिक खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दर्ज प्रकरण

68. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती मीना कंवर)

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में खाद्य पदार्थों में हो रही भारी मिलावट को रोकने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? वर्ष 2018 से 25 जनवरी, 2021 तक मिलावटी प्रकरणों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्ष 2018 से 25 जनवरी, 2021 तक खाद्य पदार्थों की जांच हेतु किस-किस जांच अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा कब-कब, किस-किस स्थान पर किन-किन खाद्य पदार्थों की जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में मिलावटखोरों द्वारा नकली उत्पाद बनाने वाले प्रतिष्ठानों, फर्मों व अन्य द्वारा प्रत्येक खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य पदार्थों की जांच में लगे कार्मिकों को सूचना भिजवाई जा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2018 से 25 जनवरी, 2021 तक किस-किस फर्म, प्रतिष्ठानों, दूध-मावा-पनीर-घी व अन्य खाद्य सामग्री उत्पादक विक्रेताओं के नमूने असफल हुए हैं? उक्त के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये विभाग द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं तथा जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकने के लिए निरन्तर नमूनीकरण कार्य के साथ-साथ समय-समय पर विभाग द्वारा विशेष अभियान जैसे- शुद्ध के लिए युद्ध अभियान (होली, रक्षाबंधन, दीपावली के त्यौहार, ऋतु परिवर्तन एवं अन्य विशेष खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत प्राप्त होने पर) चलाये जाकर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2018 से जनवरी 2021 तक खाद्य पदार्थों के कुल 838 नमूने लिये गये जिनमें से 224 नमूने मिलावटी पाये गये, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	सब-स्टैण्डर्ड	मिथ्याछाप	असुरक्षित
2018	33	15	25
2019	36	20	18

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष	**सब-स्टैण्डर्ड**	**मिथ्याछाप**	**असुरक्षित**
2020	31	21	21
जनवरी 2021	00	04	00
योग	**100**	**60**	**64**

सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले में वर्ष 2018 से अब तक खाद्‌य पदार्थों की जांच हेतु वर्तमान में अधिकृत खाद्‌य सुरक्षा अधिकारी द्‌वारा ही खाद्‌य पदार्थो के नमूने जांच हेतु लिये गये हैं। उक्त अवधि में लिये गये खाद्‌य पदार्थों की जांच का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जोधपुर जिले में वर्ष 2018 से जनवरी 2021 तक फर्म, प्रतिष्ठानों, दूध-मावा-पनीर-घी उत्पादक/विक्रेताओं के नमूने असफल हुए एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(विवरण, सूची पुस्तकालय में रखे गये)

सिलिकोसिस की पहचान के लिए आयोजित कैम्प

69. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी की पहचान के लिए माह जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक कुल कितने कैम्प आयोजित किये गये? कैम्पों में स्क्रीनिंग के बाद कितने संभावित रोगी चिन्हित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिन्हित मरीजों में से बड़ी संख्या में मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी के लिए देय मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो कितने मरीजों को कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बड़ी संख्या में सिलिकोसिस के चयनित मरीजों का प्रमाणीकरण नहीं होने से उन्हें देय मुआवजा राशि नहीं मिली है? यदि हां, तो कितने मरीजों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक कुल 1236 कैम्प आयोजित किये गये एवं कैम्पों में स्क्रीनिंग के बाद 22123 संभावित रोगी चिन्हित किये गये, जिनकी सूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

श्रम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, श्रम विभाग द्वारा जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 के दौरान 15 स्वास्थ्य जांच शिविर लगाये गये, जिनमें से 12 विशेष शिविर सिलिकोसिस प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु तथा 3 शिविर सिलिकोसिस चिन्हित करने हेतु लगाये गये। इन शिविरों में 545 हिताधिकारियों को जांच के उपरान्त 372 सिलिकोसिस के प्रकरणों को सत्यापन एवं चिन्हित किया गया।

(2) जी हां। श्रम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित एवं चिन्हित ज्यादातर मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों को राहत सहायता दी जा चुकी है। दिनांक 31.01.2021 को श्रम विभाग में केवल 46 हिताधिकारियों के प्रकरण भुगतान हेतु लम्बित थे तथा इस दौरान 1576 हिताधिकारियों को 43 करोड़ 7 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

सिलिकोसिस ऑनलाइन पोर्टल की रिपोर्ट (दिनांक 11.02.2021) के अनुसार खान विभाग के 2122 प्रकरण भुगतान हेतु लम्बित हैं। प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। सिलिकोसिस ऑनलाइन पोर्टल की रिपोर्ट (दिनांक 11.02.2021) के अनुसार 599 सिलिकोसिस में चयनित मरीजों के प्रमाणीकरण नहीं होने से उन्हें देय मुआवजा राशि नहीं मिली है। प्रति परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(सूचना, प्रति पुस्तकलय में रखे गये)

नीमोदा हरिजी (दीगोद) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का हस्तांतरण

70. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की दीगोद तहसील के ग्राम नीमोदा हरिजी में दानदाता डीसीएम कोटा के द्वारा दिये गये भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है?

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन को विभाग को हस्तांतरित किया जाना है? यदि हां, तो क्या उक्त भवन डीसीएम से विभाग को हस्तांतरित हो गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं व इसे कब तक हस्तांतरित कर दिया जाएगा?

(3) क्या यह भी सही है कि भवन होने पर भी विभाग द्वारा नया भवन निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त भवन को डीसीएम द्वारा चिकित्सा विभाग को हस्तांतरित किये जाने संबंधी विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) डीसीएम द्वारा उपलब्ध करवाया गया भवन नोर्म्स के अनुसार नहीं होने के कारण, नवीन भवन निर्माणाधीन है।

(विवरण पुसतकालय में रखा गया)

रानीवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

71. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीवाड़ा में आउटडोर व इनडोर रोगियों की प्रतिदिन संख्या कितनी है एवं वर्तमान में कितनी शय्याएं स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों का भारी दबाव है जिससे चिकित्सा सुविधाएं कम पड़ रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सीएचसी में शय्याओं की संख्या बढ़ाने अथवा उक्त को सैटेलाइट हास्पिटल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीवाड़ा में वर्ष 2020 में बाह्य व आंतरिक रोगियों की प्रतिदिन की ओपीडी एवं आईपीडी संख्या निम्न प्रकार है:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष	प्रतिदिन की संख्या	
	ओपीडी	आईपीडी
2020	166	17

कस्बा रानीवाड़ा जिला जालोर में वर्तमान में 30 शय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं। कस्बा रानीवाड़ा जिला जालोर में वर्तमान में 30 शैयाओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। स्वीकृत शय्याओं का वर्ष 2018 में 41.41, वर्ष 2019 में 60.24 एवं वर्ष 2020 में 56.54 प्रतिशत उपयोगिता (बीओआर) रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीवाडा की शय्याओं में वृद्धि अथवा सैटेलाइट हास्पिटल में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

देवखेडा ग्राम (अजमेर) एवं अखेगढ़ ग्राम (राजसमंद) का सीमा विवाद

72. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम देवखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर एवं ग्राम अखेगढ़ तहसील भीम जिला राजसमंद में उक्त दो जिलों का सीमा विवाद कितने वर्षों से चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दो गांवों के बीच चल रहे सीमा विवाद का निपटारा करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों को दी गई है? उक्त सीमा विवाद नहीं निपटाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दोनों जिलों के गांवों का सीमा विवाद शीघ्र निपटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम देवखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर एवं ग्राम अखेगढ तहसील भीम जिला राजसमंद के मध्य सीमा विवाद लगभग 08 माह से चल रहा है। उक्त दोनों ग्रामों के बीच चल रहे सीमा विवाद के निपटारे का प्रार्थना पत्र ग्रामवासी देवखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर द्वारा तहसीलदार भीम

(राजस्व मंत्री)

को दिनांक 30.06.2020 को एवं तहसीलदार ब्यावर को दिनांक 29.06.2020 प्रस्तुत हुआ।

(2) तहसीलदार भीम के आदेश क्रमांक भू.अ./20/402 दिनांक 30.06.2020 द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक लगेतखेडा व पटवारी हल्का लगेतखेडा को ग्राम अखेगढ़ तहसील भीम से लगती हुई सीमा व ग्राम देवखेडा तहसील ब्यावर की सीमा की जानकारी करवाने हेतु आदेशित किया गया, जिसमें दोनों राजस्व ग्रामों के राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में संयुक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तकनीकी टीम का गठन कर सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। दोनों ग्राम अलग-अलग जिलों से संबंधित होने के कारण एवं दोनों ग्रामों के मध्य नक्शों में भिन्नता होने के कारण सीमा विवाद है, जिसे निपटाने की कार्यवाही जैकरकार है। सीमा विवाद नहीं निपटाने के लिए किसी अधिकारी कर्मचारी का दोष प्रतीत नहीं होता है।

(3) जी हां। उक्त दोनों जिलों के गांवों के सीमा विवाद के निस्तारण हेतु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तकनीकी टीम का गठन किया जाकर दिनांक 12.02.2021 से सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सायरा (गोगुन्दा) उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन

73. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की उप तहसील सायरा को तहसील में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस प्रकार के प्रस्तावों पर राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति, परस्पर प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर यथोचित निर्णय लिये जाते हैं।

पिंडवाड़ा तहसील की बनास भूमि अनियमितता की जांच

74. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पिंडवाड़ा तहसील के बनास भूमि घोटाले की 19 फरवरी, 2020 को राजस्व सचिव से जांच करवाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त के संबंध में जांच करने हेतु जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच के संबंध में सरकार द्वारा गत एक वर्ष में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच रिपोर्ट किस स्तर पर कब से लंबित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रकरण की जांच प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्रदत्त आदेशानुसार की गई है। इस हेतु पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

(2) प्रदेश में मार्च, 2020 से कोविड-19 लॉकडाउन एवं प्रोटोकाल लागू रहने तथा कार्यालयों के नियमित रूप से कार्य करने में आई कठिनाइयों व तत्पश्चात् अधिक कार्यभार के कारण जांच प्रक्रिया में समय लगा है।

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व द्वारा प्रस्तुत जांच के उपरान्त माननीय राजस्व मंत्री ने दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं दो बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु पुन: पत्रावली पर निर्देश दिये हैं, जिस पर जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया गया है।

(3) प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही दिनांक 24.02.2020 से निरन्तर प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर, सिरोही को लिखा जा चुका है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है तथा उपरोक्त उल्लेखित दो बिन्दुओं पर अन्तिम निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

माधव विश्वविद्यालय, भूजेला (पिंडवाड़ा) द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

75. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा 25 फरवरी, 2020 को माधव विश्वविद्यालय, भूजेला (पिंडवाड़ा) की आबंटन शर्त संख्या 4 के उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माधव विश्वविद्यालय, मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मौजा भूजेला के खसरा नम्बर 1/146 में रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर बहुमंजिला भवन व अवैध कब्जे के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मौजावाड़ा के खसरा नम्बर 2750/146 में 4 बीघा 15 बिस्वा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण बाबत 25 फरवरी, 2020 के निर्देश के पश्चात् अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मौजा भूजेला के खसरा नम्बर 2856/146 में तरमीम बाबत दो उपखंड अधिकारियों द्वारा अलग-अलग आदेश करने के मामले में नियम विरुद्ध आदेश करने वाले उपखंड अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभागीय पत्रांक प04(34)राज-3/2020 दिनांक 25.02.2020 के द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री संयम लोढ़ा, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के क्रम में जिला कलेक्टर सिरोही से प्राप्त सूचना के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट से सचिव, राजस्थान विधान सभा को अवगत कराया गया था। परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

आबंटन शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर जिला कलेक्टर स्वयं के संज्ञान से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम हैं।

(2) माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में विचाराधीन सिविल रिट पिटीशन संख्या 4328/2020 मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम

(राजस्व मंत्री)

राज्य सरकार व अन्य द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी है। परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 2 अनुसार।

(4) मौजा भूजेला खसरा नम्बर 2856/146 में तरमीम बाबत उपखण्ड अधिकारियों द्वारा अलग-अलग आदेश प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दिये गये हैं। जिला कार्यालय रिकार्ड अनुसार तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाना नहीं पाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पिंडवाड़ा एवं आबूरोड की सोलर प्लेटों का रखरखाव

76. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला सिरोही के जनजाति क्षेत्र पिंडवाड़ा और आबूरोड में जहां बिजली नहीं पहुंची है वहीं पर सोलर प्लेट लगाई गई है? क्या सरकार सोलर प्लेट लगाने व इनकी मेंटीनेंस नहीं करने पर एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रावै. सहा. अधीक्षण अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्काम, सिरोही के अनुसार सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा और आबूरोड में जहां बिजली नही पहुंची है वहा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) स्कीम में सोलर प्लेट लगाकर बिजली उपलब्ध करवाई गई है।

कार्यादेश की शर्त अनुसार सोलर प्लेट लगाने की दिनांक से आगामी पांच वर्ष तक इनका मेंटीनेन्स एजेंसी द्वारा ही किया जाना है।

थानागाजी के राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास भवन का निर्माण

77. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावास भवन निर्माण के क्या प्रावधान हैं?

(श्री कान्ति प्रसाद)

(2) क्या सरकार थानागाजी उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावास निर्माण के संबंध में कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।

(2) वर्तमान में थानागाजी उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय, थानागाजी में छात्रावास भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रामगंज मण्डी के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद

78. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में संचालित राजकीय महाविद्यालय में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मंडी में स्थित राजकीय महाविद्यालय, रामगंज मंडी व राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(2) रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कला शिक्षक को विशेषज्ञ डिग्री

79. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कला शिक्षक (चित्रकला, संगीत) में प्रशिक्षण लेकर कला शिक्षक विशेषज्ञ की डिग्री, डिप्लोमा

(श्री छगनसिंह)

प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को माध्यमिक स्तर तक बीएड व बी.एस.टी.सी. (डी.एल.डी.) डिग्री करना अनिवार्य है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में बीएड. यथा बीएसटीसी (डी.एल.एड) डिग्री में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला शिक्षक अनिवार्य कला शिक्षा (चित्रकला, संगीत) विषय के कला शिक्षक विशेषज्ञ की योगयता डिग्री प्राप्त करता है? यदि हां, तो उक्त सभी बीएड. व बी.एस.टी.सी. (डी.एल.एड) महाविद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

बाड़मेर के इंजीनियरिंग कालेज में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति

80. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि इंजीनियरिंग कालेज, बाड़मेर को शुरू हुए तीन वर्ष होने के उपरान्त भी एक भी टीचिंग एवं नोन टीचिंग पदों पर स्थायी कार्मिक नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार व्यवसायिक हब बनने जा रहे बाड़मेर जिले में स्थित इंजीनियरिंग कालेज के सफल संचालन हेतु टीचिंग एवं नोन टीचिंग पदों पर स्थायी भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। इंजीनियरिंग कालेज, बाड़मेर स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित है, जिसमें शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर भर्ती संबंधित निर्णय प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या एवं कालेज में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर कालेज के Board of Governors (BoG) द्वारा लिया जाता है।

वर्तमान में कॉलेज के Board of Governors (BoG) द्वारा 52 शैक्षणिक व 35 अशैक्षणिक पद स्वीकृत हैं, इन पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं होने के कारण 17 शैक्षणिक पदों पर through empanelment व 17 अशैक्षणिक पदों पर services hire with fix pay के तहत कार्मिक कार्यरत हैं।

अलवर में संचालित संस्कृत विद्यालय

81. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में कुल कितने राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर में नये संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में संस्कृत शिक्षा विभाग के कुल 73 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग में नये संस्कृत विद्यालय खोलने हेतु मानदण्ड निर्धारित है। जनप्रतिनिधियों की मांग, भूमि, भवन की उपलब्धता, बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर विद्यालय खोलने का निर्णय लिया जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)